राजस्थान विधान सभा

१३वीं बैठक, मंगलवार, दिनांक—२३ मार्च, सन् १९५४ ई.

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८ बजकर ३५ मिनट पर प्रारम्भ हुई ।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ३७७

श्री चन्दनमल वैद (उप मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, आपसे इस प्रश्न को पोस्टपोन करने की प्रार्थना की गई थी ?

श्री अध्यक्ष—This will be taken tomorrow.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—What has happened to that, Sir ?

श्री अध्यक्ष—It was to be replied by Skri Tikaram Paliwal who is laid with fever.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Then certainly there must be somebody else to deputise him. The work cannot come to a standstill. If this is the state of affairs in Rajasthan only God help the people, the Government and the Assembly.

श्री मथुरादास माथुर—Help you as well.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—If you don't consider me a Member of the Assembly, well it is your privilege.

प्रश्न संख्या ३७८

किशनगढ़ म्युनिसिपैलिटी के चेयमैरन के यहाँ की चोरी की बरामदगी

श्री चाँदमल मेहता—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री चाँदमल मेहता]

(क) क्या यह सत्य है कि किशनगढ़ म्युनिसिपैलिटी के चेयरमेन के यहाँ चोरी करने वालों का पता चल जाने पर भी न तो कोई गिरफ्तारी हुई और न माल ही बरामद कराया गया ?

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(ग) क्या यह सही है की उक्त चोरी से सम्बन्धित व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिये विशेष फोर्स की माँग की जाने पर भी नहीं दी गई ?

श्री नरसिंह कछवाहा (उप मंत्री)—(क) किशनगढ़ म्युनिसिपैलिटी के वर्तमान चेयरमैन के यहाँ कोई चोरी नहीं हुई। भूतपूर्व चेयरमेन श्री घनश्यामदास जी चौधरी के यहाँ पर १३-८-५३ को एक नकबजनी हुई थी। नयाबास तथा नीम के मीनों पर इस नकबजनी का सन्देह है, किन्तु अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

(ख) यह केस अभी तक जेर तफतीश है।

(ग) यह सही नहीं है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि किशनगढ़ में बढ़ती चोरियों की तफतीश के वास्ते किसी ऑफिसर की नियुक्ति की गई थी ?

श्री नरसिंह कछवाहा—इसका कोई ध्यान नहीं।

श्री चाँदमल मेहता—जिस विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई थी क्या उसने इस मामले की जाँच पड़ताल के लिए कुछ फोर्स की माँग की थी ?

श्री नरसिंह कछवाहा—कोई विशेष फोर्स की माँग नहीं की गई, श्री ओंकारसिंह डी. वाई. एस. पी. को भूतपूर्व चेयरमेन के दर्ख्वास्त पर भेजा गया था।

श्री चाँदमल मेहता—क्या इस सम्बन्ध में कोई विशेष फोर्स की माँग नहीं की गई ?

श्री नरसिह कछवाहा—कोई माँग नहीं की।

प्रश्न संख्या ३७६

श्री अध्यक्ष—श्री जगतसिंह झाला।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३८०

श्री हनवन्तसिह—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.3

[श्री हनुवन्तसिंह]

(क) जैसलमेर सिटी में म्युनिसिपल चुनाव अब तक किन कारणों से नहीं हुए हैं ?

(ख) क्या अब चुनाव की उम्मीद रखी जाय।

(श्री स्वायत्त शासन मंत्री अनुपस्थित)

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—Again what is the matter ? Either we adjourn the Assembly and whenever it is convenient to the Ministers we can again come here or appoint more Ministers who can reply. This is a state of affair which no normal man can consider satisfactory. Though some of the Members on the other side apparently support this state of affairs yet in the heart of their hearts they do not approve of it.

श्री मथुरादास माथुर—We do'nt support it.

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—It is a very serious thing and we do hope that the Speaker will be pleased to realise that a stage has reached when the Ministers, how so big they may be, are not allowed to ignore the Assembly with contempt, and it is high time that some action is taken and if the Speaker still thinks that the high time has not reached, we mey wind up the business and go

श्री अध्यक्ष—The Speaker is completely in the hands of the House.

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—Whether it is the Chief Minister or anybody else, if they do not attach importance to their duties and functions it is really serious and a bad affair and I have no words to express myself or in which I can say except that this House is no House, not an Assembly; but it is anything else but Assembly.

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—(क) इलेक्टररोल्स ठीक न होने के कारण उनकी मुश्तहरी नहीं हो सकी थी।

(ख) चुनाव की कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है और तिथियाँ निश्चित हो चुकी हैं।

प्रश्न संख्या ३८९

श्री अध्यक्ष—श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

Page No.4

प्रश्न संख्या ३८२

श्री अध्यक्ष—श्री चाँदमल मेहता

(स्थगित)

प्रश्न संख्या ३८३

श्री अध्यक्ष—श्री गुरूदयालसिंह संधु

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थिति)

प्रश्न संख्या ३८४

रिड ग्राम पंचायत के सरपंच व पंचों के विरुद्ध पुलिस के मामलों का चालान किया जाना

श्री चाँदमल मेहता—मैं इसको वापिस लेता हूँ।

(वापिस लिया गया)

प्रश्न संख्या ३८५

रिड ग्राम में सार्वजनिक उपयोग में आने वाली कुछ भूमियों का कुचामन ठाकुरों द्वारा बेचा जाना

श्री चाँदमल मेहता—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री इस बात से परिचित हैं :

(अ) क्या रिड ग्राम में सार्वजनिक उपयोग में आने वाली कुछ ज़मीनें कुचामन ठाकुरों ने बेच दी हैं ?

(आ) यदि हाँ, तो क्या उक्त जमीनें एक्वायर की जाकर सार्वजनिक उपयोग में लाने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—(अ) हाँ।

(आ) इस सम्बन्ध में जाँच करवाई गई थी जिसकी रिपोर्ट इस समय सरकार के विचाराधीन है।

प्रश्न संख्या ३८६

महाराणा संस्कृत कालेज, उदयपुर में आचार्य कक्षाओं का बन्द किया जाना

श्री जगतसिंह भाला—क्या शिक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(अ) क्या यह सही है कि महाराणा संस्कृत कॉलेज, उदयपुर में आचार्य कक्षाएँ बन्द कर दी गई हैं ?

(आ) यदि यह सच है, तो सरकार ने ऐसा क्यों किया ?

Page No.5

[श्री जसवन्तसिंह]

(इ) सरकार क्या इस निर्णय पर पुनः विचार करेगी ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—(अ) नहीं ।

(आ) प्रश्न नहीं उठता ।

(इ) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न संख्या ३८७

सन् १६५३ में राजस्थान में हत्याएँ तथा डकैतियाँ

श्री चाँदमल मेहता--क्या गृह मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :-

कि सन् १६५३ में राजस्थान में कुल कितने कत्ल व डकैतियाँ हुई ? पिछले वर्षों से इनमें वृद्धि हुई या कमी ?

श्री नरसिंह कछवाहा (उप मंत्री)—सन् १६५३ में १६२ डकैतियाँ हुई तथा ३७३ कत्ल हुए । पिछले वर्ष के मुकाबले में ये बहुत कम थे ।

श्री चाँदमल मेहता--क्या यह सही है कि इस वर्ष ५३-५४ में किशनगढ़ सब डिवीजन में जितने कत्ल हुए उतने कभी नहीं हुए ?

श्री नरसिंह कछवाहा—पिछले साल इससे बहुत ज्यादा हुए ।

श्री चाँदमल मेहता—क्या पिछले साल की संख्या माननीय मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे ?

श्री नरसिंह कछवाहा—५११ ।

श्री चाँदमल मेहता— क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही नहीं है कि ५३-५४ में ऐसे केसेज़ जितने हुए उतने किसी वर्ष में नहीं हुए ?

श्री नरसिंह कछवाहा—इसके लिए तो अलग पूछिये ।

कुँ. श्री जसवन्तसिंह--क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किशनगढ़ उपचुनाव होने के बाद में कत्ल ज्यादा हुए ?

श्री नरसिंह कछवाहा—इसका तो कोई ध्यान नहीं है ।

कुँवर श्री जसवन्तसिंह--फिर आप किस लिए पधारे हैं ?

श्री नरसिंह कछवाहा--इसका तो अलग सवाल पूछेंगे तो बतावेंगे।

कुँवर श्री जसवन्तसिंह--तो आप यह फरमाइये।

(हँसी)

एक माननीय सदस्य—जोधपुर में एक मन्त्रीजी की दावत के वक्त एक लड़की की हत्या हो गई और इन्क्वायरी नहीं हुई......

श्री अध्यक्ष—Next. Question No. 388.

प्रश्न संख्या ३८८

लादू जाट, भँबाडा, किशनगढ़ तहसील का अनाज जागीरदारों द्वारा बलात् ले जाना।

श्री चाँदमल महता—क्या गृहमन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सही है कि लादू जाट भंबाडा, किशनगढ़ तहसील का अनाज कुछ जागीरदार जबरन उठाकर ले गये ?

(ख) उसकी पुलिस में रिपोर्ट कब दर्ज हुई और मुकद्दमा कब चालान किया गया ?

श्री नरसिंह कछवाहा (उप मंत्री)—लादू पुत्र फत्ता जाट, वासी ग्राम भवाड़ा ने थाना कोतवाली किशनगढ़ में ता० १०-१-५४ को एक रिपोर्ट इस अमर की दर्ज कराई कि ठाकुर अनेसिंह और गोपालसिंह उसका ६ मन मक्का ले गये हैं जिस पर अमराज क्रम सं० ३ धारा ३७६ भारत दंड संग्रह, उसी दिन और उसी समय लिपिबद्ध किया गया। अनुसंधान के अन्तर्गत यह पाया गया कि लादू जाट उक्त ठाकुर साहब का केवल वेतन पर नौकर था और वास्तव में अनाज भी उन्हीं का था। इससे स्पष्ट है कि लादू जाट ने यह रिपोर्ट ठाकुर साहब की खुदकाश्त जमीन पर अपना अधिकार दृढ़ करने की नीयत से दर्ज करवाई थी।

उपरोक्त हालात के कारण इस सम्बन्ध में Final report इस घटना के घटित न होने का लेख करते हुये ता० १३-२-५४ को पेश की जा चुकी है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि उक्त किसान की मक्की ले जाने के लिए किशनगढ़ से गाड़ियाँ गईं और कई आदमी लाठियाँ ले ले कर गये ?

श्री नरसिंह कछवाहा—यह सही नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या मैं यह निवेदन करूँ कि आप स्वयं पूरी जानकारी इस बारे में हासिल करें कि यह गलत जानकारी आपको दी गई है कि यह वाक़या गलत है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—यह जानकारी बिलकुल सही है।

श्री चांदमल मेहता—तो क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि इस सम्बन्ध में जो बयान कोतवाल ने लिया था उनका वह बयान इन्क्वायरी में से निकाल दिया गया है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—हमारे पास इसकी सूचना नहीं है। अगर आप सूचना देते हैं तो मालूम कराया जा सकता है।

श्री चाँदमल मेहता—आपने जो कुछ भी कहा उसको मैं चेलेंज करता हूँ और साथ ही निवेदन करता हूँ कि इसके बारे में फिर से ठीक जाँच कराई जावे और फिर आइन्दा असेम्बली में बताई जावे।

प्रश्न संख्या ३८६

श्री अध्यक्ष—श्री गुरुदयालसिंह सन्धु।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३६०

श्री अध्यक्ष—श्री भोपालसिंह।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३६१

श्री अध्यक्ष—श्री हरिकृष्ण व्यास।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३६२

जोधपुर की कृषि तथा उद्योग प्रदर्शनी में व्यापारियों से नालीदार कलई की चद्दरें लेना

श्री हनवन्तसिंह—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) जोधपुर की उद्योग एवं कृषि प्रदर्शनी में किस व्यापारी से कितने रुपयों की लागत की कितने टन नालीदार कलई की चद्दरें जो इस प्रदर्शिनी के काम में आई थीं प्रदर्शिनी के संयोजक को किस-किस शर्त पर दिलाई गई ?

(ख) प्रदर्शनी के समाप्त होने के पश्चात् ये चद्दरें किसको किस-किस शर्त पर (व्यापारी को अथवा संयोजक को) वापस दी जायँगी अथवा किसके द्वारा नीलाम की जायँगी ?

(ग) क्या सरकार इन चद्दरों को परमिट से बिकवायगी अथवा खुले आम ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(नागरिक रसद मन्त्री)—(क) जोधपुर की उद्योग एवं कृषि प्रदर्शिनी को मेसर्स जीवनलाल गणेशदास आइरन व स्टील स्टॉकिस्ट, जोधपुर से ७० टीन की चद्दरें दिलाई गई । इन चद्दरों का मूल्य लगभग ५३५००) रुपये होता है । ये चद्दरें प्रदर्शनी समाप्त होने के पश्चात् स्टॉकिस्ट को वापिस कर दी जावेंगी ।

(ख) प्रदर्शनी समाप्त होने के पश्चात् ये चद्दरें डीडवाना और नागौर की जनता को कन्ट्रोल की कीमत पर परमिट के द्वारा स्टॉकिस्ट से दिलाई जावेंगी ।

(ग) उपर्युक्त चद्दरें परमिट के द्वारा कन्ट्रोल की कीमत पर वितरण की जावेंगी ।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—इसका क्या किराया किस हिसाब से दिलाया गया उस व्यापारी को ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जब इस तरह की प्रदर्शनी होती है, तो जनता के हर व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है कि वह उसमें यथाशक्ति सहयोग दे । यह तो सबका कर्तव्य होता है । इसी प्रकार से उन्होंने भी यह सहयोग दिया था ।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—तो इसका मतलब यह हुआ कि उसका किराया, टूट-फूट या इतने दिनों तक इन चद्दरों में जो रुपया पैसा उसका ब्याज वगैरह कुछ नहीं मिलेगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह तो उस व्यापारी को सोचना है । यदि उसे जोधपुर में होने वाली इस प्रदर्शनी से प्रेम है तो यह प्रेम ही आधार है और इसी के अनुसार उसने प्रदर्शनी वालों से बात कर ली होगी ।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—जब ये चद्दरें सरकार ने दिलाई हैं तो सरकार ने उस व्यापारी का नुमाइश वालों से एग्रीमेन्ट कराया होगा या नहीं कराया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह चूँकि कन्ट्रोल की चीज़ है और इस चीज़ का कोई दुरुपयोग न करे इसलिए इस तरह का एग्रीमेंट सरकार ने कराया कि प्रदर्शनी का काम समाप्त होने पर ये चद्दरें वापिस उसी व्यापारी को लौटा दी जावेंगी और कन्ट्रोल भाव से परमिट द्वारा डीडवाना और नागौर की जनता को ये दिलवाई जावेंगी ।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—प्रदर्शनी खत्म हो गई है और अब भी ये चदरें व्यापारी को नहीं लौटाई गई हैं, आधी के करीब खो गई बताई जा रही हैं और काफी खराब हो गई हैं, क्या सरकार को यह मालूम है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने पहले बताया कि यह व्यापारी का काम है । अगर वह व्यापारी हमें सूचना देगा, तो ये चद्दरें उसे बराबर दिलाई जावेंगी और इसके लिए एक तीन आदमियों की कमेटी भी बनाई गई है । वह यह सारा मामला देखेगी और खोने-करने की बात तो अलग, पर

[श्री भोगीलाल पंड्या]

अगर मामूली से छेद भी हो जावेंगे तो वह कमेटी जो निर्णय देगी और जो हर्जाना दिलावेगी तो उसका प्रदर्शनी वालों को जवाब देना पड़ेगा और अगर कम हो गई हैं तो वे भी दिलाई जावेंगी। अगर कमेटी ने कोई हर्जाना भी दिलवाया तो वह हर्जाने की कीमत भी देगी, प्रदर्शनीवालों को यह देना पड़ेगा। ऐसा पहले हम एग्रीमेंट (agreement) कर चुके हैं।

श्री किशनलाल शाह—ये चदरें अब किनको दिलाई जावेंगी?

श्री भोगीलाल पंड्या—पहले बता चुका हूँ डीडवाना और नागौर की जनता को दिलाई जावेंगी।

श्री किशनलाल शाह—इन दोनों तहसीलों को या नागौर डिस्ट्रिक्ट को?

श्री भोगीलाल पंड्या—माननीय मित्र ने प्रश्न का उत्तर सुना होगा। डीडवाना और नागौर की जनता में कन्ट्रोल भाव से ये वितरित की जावेंगी।

श्री शम्भूसिंह—वह जो कमेटी बनाई गई है उसमें सरकारी अधिकारी भी हैं या सभी प्राइवेट लोग हैं?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार ने अपनी ओर से असिस्टेन्ट कमिश्नर, सिविल सप्लाइज़ और इन्डस्ट्री वालों, दोनों को रक्खा हैं।

श्री किशनलाल शाह—इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नहीं हुआ कि ये नागौर तहसील और डीडवाना तहसील की जनता को दिलवाई जावेंगी या नागौर डिस्ट्रिक्ट को यानि सारे नागोर क्षेत्र को दिलवाई जावेंगी?

श्री भोगीलाल पंड्या—जिनके लिए सरकारी ग्रान्ट है उनको पहले मिलेगा।

श्री किशनलाल शाह—दोनों तहसीलों या जिले को होगा, किसको होगा?

श्री भोगीलाल पंड्या—जिसका कोटा है उसको मिलेगा।

श्री किशनलाल शाह—इसका आधार क्या है?

श्री भोगीलाल पंड्या—कोटा जिसके लिए देते हैं उसी को देते हैं। कोटा हैडक्वार्टरवाइज़ (Head Quarterwise) होता है। यह डिवीजनवाइज है, इस तरह जिले के हिस्से में होगा तो जिले को और तहसील के हिस्से का होगा तो उसको अर्थात् जिसके हिस्से का होगा उसको मिलेगा। मैं ध्यान दिलवा दूँ माननीय सदस्य का कि डिवीज़नल सप्लाई ऑफिस जोधपुर में है और यह सीमेन्ट व लोहे का कोटा डिस्ट्रिक्टवाइज़ होता है, तहसीलवाइज़ नहीं होता।

Page No.10

श्री किशनलाल शाह—क्या इसकी छानबीन की जावेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इसका प्रश्न ही नहीं रहता। डिवीज़नल हैडक्वार्टर से तो डिस्ट्रक्ट को ही कोटा मिलेगा। अब यह काम तहसीलों का है कि वे डिस्ट्रिक्ट के पास जायें, जहाँ से डिस्ट्रिक्ट ऐसी व्यवस्था करता है कि तहसीलवाइज़ और आबादी के हिसाब से कोटा सबको मिले।

श्री किशनलाल शाह—डिवीज़नल सप्लाई ऑफिसर जोधपुर से हमने सीमेंट और लोहे का सामान माँगा था, तो उन्होने कहा था कि सामान का कोटा डिस्ट्रिक्टवाइज़ होता है, तहसील वाइज़ नहीं दिया जाता है, क्या इसको छानबीन की जावेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—छानबीन करने का प्रश्न ही नहीं आता है। अगर वह सप्लाई ऑफिसर के पास जाते हैं तो फौरन ही ऐसी व्यवस्था करते हैं कि उनको तहसीलवाइज़ आबादी के हिसाब से कोटा मिलेगा।

श्री किशनलाल शाह—हमारे यहाँ आग लग गई थी और टीन की चद्दरें माँगी थीं तो यह जवाब दिया गया था कि उनको कई अरसे से टीन नहीं दिया जा रहा है।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने आपको बतलाया कि यह ठीक नहीं है। कुछ थोड़े समय पहले कुछ लोगों ने यह शिकायत की थी तो एग्रीकल्चर वालों और कलेक्टर के मारफत लिखवा देंगे तो जिस तहसील में नहीं पहुँचे होंगे वहाँ पहुँचाने की व्यवस्था की जायगी, ऐसा मैंने उनको विश्वास दिलवाया था।

श्री किशनलाल शाह—सप्लाई डिपार्टमेंट की स्थापना के बाद से आज तक वहाँ एक भी टीन नहीं मिला है, इसकी वजह बताई जा सकती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नावा शहर में ज्यादा जरूरत नहीं होगी लेकिन फिर भी अगर उनकी शिकायत आती है तो सरकार द्वारा उनको टीन दिलाया जायगा, किसी को टालने की कोशिश नहीं की जायगी।

श्री किशनलाल शाह—तो वहाँ सारी तहसील में जरूरत नहीं है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं आपको निवेदन कर चुका हूँ कि अगर इसकी कोई शिकायत आयेगी तो तुरन्त व्यवस्था की जायगी।

श्री अध्यक्ष—Next, Shri Sugan Chand Jain.

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—आपने जैसा बताया कि......

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !! Shri Sugan Chand.

प्रश्न संख्या ३६३

राजस्थान में पत्थर की खानों पर रोयल्टी के नियम।

श्री सुगनचन्द जैन—क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान में पत्थर की खानों पर जो रोयल्टी वसूल की जाती है उसका कोई नियम बना हुआ है ?

(ख) यदि नहीं तो क्या सरकार इसका नियम बनाने का इरादा रखती है ?

(ग) अलग-अलग जगहों पर जो रॉयल्टी वसूल होती है वह किस आधार पर की जाती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (नागरिक रसद मन्त्री)—(क) सरकार गौण खनिज पदार्थों की रौयल्टी के विषय में नियमों का निरीक्षण कर रही है और उन नियमों को वह शीघ्र ही प्रकाशित करेगी।

(ख) पारस्परिक सहायक राज्यों में राजस्व के नियम कार्य में लाये जाते हैं और राजस्व भी उसी के अनुसार वसूल किया जाता है।

श्री सुगनचन्द जैन—कब तक यह नियम बनाये जायेंगे ?

श्री भोगीलाल पंड्या--उसकी एक कमेटी बनाई गई और सेक्रेटेरियेट में एक कमेटी है, उसने यह तय किया है कि ५४ के अन्त तक वह तैयार करके प्रकाशित कर सकेगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह माइनर मिनरल्स के नियम अभी तक क्यों नहीं लागू किये गये ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने आपको बताया कि भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न नियम थे इसलिए उन लोगों ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो गई है। उसके तैयार होते ही प्रकाशित कर दी जायगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा प्रश्न माइनर मिनरल कन्सेशन के मुताल्लिक है।

श्री भोगीलाल पंड्या—यह मैंने पहले ही आपको बताया है कि जहाँ कहीं अलग-अलग नियम मालूम हुए हैं, उन सारों का अध्ययन करना पड़ता है और अध्ययन के बाद में एक जगह एक पत्थर निकलता है दूसरी जगह दूसरा पत्थर निकलता है, कई तरह के मिनरल्स होते हैं, उसकी जाँच कर ली गई है और उसके तैयार होते ही उसकी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी जायगी।

प्रश्न संख्या ३६४

घरेलू उद्योग-धन्धों को चलाने की योजना

श्री सुगनचन्द जैन—क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे: —

(क) क्या राजस्थान सरकार के पास घरेलू उद्योग धन्धों को चलाने की कोई योजना है ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या योजना है और नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—हाँ राजस्थान सरकार के पास गृह-उद्योगों के विकास एवं संगठन की योजनाओं की एक बड़ी संख्या है, जो परिशिष्टों में दर्ज है। परिशिष्ट 'क' में दी गई योजनाएँ कार्यान्वित हो रही हैं और परिशिष्ट 'ख' में दी गई योजनाएँ सरकार के विचाराधीन हैं।

परिशिष्ट 'क'

१. भेड़ और ऊन उद्योग का विकास।

२. ताड़गुड़ उद्योग का विकास।

३. कुटीर उद्योगों के सम्बन्ध में टेक्निकल शिक्षा।

४. कुटीर उद्योगों के लिये उन्नत औजारों का प्रदर्शन।

५. कुटीर उद्योगों में लाभकारी ट्रेनिंग देने वाली कुछ संस्थाओं को वित्तीय सहायता।

६. नमक और खस के विकास की योजनाएँ।

७. कुटरी उद्योगों के उत्पादनों के बेचने के लिए योजना।

परिशिष्ट 'ख'

१. खादी और हाथ करघे के उत्पादनों का संगठन, प्रमाणीकरण और विक्रय।

२. चमड़ा कमाने के उद्योग का विकास।

३. जूता-उद्योग का विकास।

४. लोहारगिरी का विकास और याँत्रिक क्रियाओं के प्रचार द्वारा काम के ढङ्ग में सुधार।

५. कपड़ा छापने के उद्योग का संगठन।

६. चटाई बुनने और खिलौने बनाने के उद्योग का संगठन और विकास।

[श्री भोगीलाल पंड्या]

७. कुटीर उद्योग के रूप में छोटे पैमाने पर नमक बनाना।

८. राजस्थान में बर्तन बनाने के उद्योग का संगठन।

९. हाथ से बनाये जाने वाले कागज उद्योग का पुनःसंगठन।

१०. मधुमक्खी पालन उद्योग।

११. कम्बल बुनने की योजनाएँ।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—यह सब कहाँ पर हो रहे हैं?

श्री तेजमल बापना—राजस्थान में हो रहे हैं।

श्री भोगीलाल पंड्या—यह बड़ी-बड़ी योजनाएँ राजस्थान के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में हो रही हैं। माननीय सदस्य फिर पूछें तो सदन की टेबल पर एक लम्बी सूची रखी जा सकती है।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—यह कहाँ-कहाँ चल रही हैं, यह जरा जानकारी हो जाती तो ठीक था, कि यह योजनाएँ किस-किस स्थान पर लागू हैं?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने पहले आपको बताया कि भिन्न-भिन्न स्थानों पर हैं। कई जगह कताई होती हैं, कई जगह बुनाई, उसके बाद में लुढाई और पींजने का काम होता है। इसका अलग से प्रश्न पूछिये तो सूची तैयार करके हाउस की टेबिल पर रख दी जाय।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—जोधपुर डिवीज़न में क्या होगा; बीकानेर डिवीज़न में क्या होगा?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने आपको बताया कि जहाँ ऊन होता है वहाँ ऊन का काम होगा, जहाँ रुई होती है वहाँ रुई का काम होगा, जहाँ खजूर के पेड़ होते हैं वहाँ ताड़गुड़ का काम किया जायगा।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—जो आपने अलग से लिस्ट बताई है तो उसके कहाँ-कहाँ क्या काम चल रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—Next, Shri H. K Vyas.

प्रश्न संख्या ३९५

नागौर नगरपालिका की अवधि की समाप्ति तथा म्युनिसिपल कमेटी का अवधि विस्तार

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Local Self-Government be pleased to answer: –

Page No.14

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

(a) When did the term of the Nagaur Municipality expire ?

(b) Has the Government been granting extensions to the life of the Municipal Committee of Nagaur ? If so, how many extensions have been granted so far and for what aggregate period and for what reasons ?

(c) How many members were originally elected to this Committee ?

(d) How many from amongst them are still continuing in the office ?

(e) Is the Government aware that there is strong public resentment in Nagaur against such postponement of Municipal elections ?

(f) Will the Government order an immediate municipal election in Nagaur ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(अ) फरवरी सन् १९५३ ।

(ब) हाँ। तीन। १६ माह के लिये पालिका की प्रार्थना पर यह निर्णय करना उचित समझा गया कि पालिका की सीमा में परिवर्तन कराकर वहाँ का चुनाव कराया जाय।

(स) २१ ।

(ड) १३ ।

(ई) ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है।

(फ) नगर की सीमा में विस्तार कराने का निर्णय होते ही चुनाव तुरन्त कराने की कार्यवाही की जायगी।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—कितने दिनों में यह कार्यवाही की जायगी ?

श्री रामकरण जोशी—अब जितना एक्स्टेन्शन मिला है उतने दिनों में।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—कितने दिनों का एक्स्टेन्शन मिला है ?

श्री रामकरण जोशी—जून तक का।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार के ध्यान में है कि कुल १३ सदस्य जो चुने हुए हैं उनमें से १० तो किसी न किसी रूप में वहाँ से निकल चुके हैं।

श्री रामकरण जोशी—कुल २१ थे जिनमें से अब १३ काम कर रहे हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास--१० निकल चुके हैं, यह बात सरकार के ध्यान में है ?

श्री रामकरण जोशी—बिल्कुल, तभी तो जवाब दे रहे हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसके बावजूद भी एक्स्टेन्शन करना सरकार की दृष्टि में गैरवाजिब नहीं है ?

श्री रामकरण जोशी—एक्स्टेन्शन के बारे में रीज़न (कारण) दिया जा चुका है। उनकी आवश्यकता के मुताबिक सीमाओं में परिवर्तन करने की जरूरत थी। जब तक सीमाओं में परिवर्तन न हो जाय; इस वक्त जो सीमाएँ हैं उनसे चुनाव करवाना असंगत होगा, इसलिए सरकार ने उसको एक्स्टेन्शन दिया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उस म्युनिसिपैलिटी को जो लोन दिये जाते हैं, तो जिस बात के लिए दिये जाते हैं उनके अलावा वे दूसरे काम में लाये जाते हैं; क्या यह बात सरकार के ध्यान में है ?

श्री रामकरण जोशी—यह बिल्कुल गलत बात कही जा रही है। वे उसी काम में आ रहे हैं और वहाँ की म्युनिसिपैलिटी ने अभी मलेरिया के अवसर पर जो काम किया है वह सराहनीय है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार ने वहाँ की म्युनिसिपैलिटी के एकाउन्ट्स ऑडिट करवाने की व्यवस्था की है ?

श्री रामकरण जोशी—ऑडिट बराबर अपने समय में होता है। आप अलग से सवाल पूछिये तो इसका उत्तर देंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—एक्स्टेन्शन देते समय क्या सरकार ने इस बात की जाँच की है कि उस म्युनिसिपैलिटी के एकाउन्ट्स का ऑडिट किया गया है या नहीं।

श्री रामकरण जोशी—एक्स्टेन्शन देने की बात दूसरी है, जिसका जिक्र किया जा चुका। वह इस समय इस वजह से उनको नहीं दिया गया है कि उनका एकाउन्ट ठीक रहता है, काम ठीक रहता है। एक्स्टेन्शन उन्हें, सीमा परिवर्तन करने के पहले चुनाव करवाना असंगत मालूम हुआ है, इसलिए दिया गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या कभी आपने इस बात की जाँच की है कि एकाउन्ट्स का आडिट किया गया है या नहीं ?

श्री रामकरण जोशी—इस मामले की कोई शिकायत नहीं आई कि वहाँ का एकाउन्ट खराब है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अगैर ऑडिट के ही जो एक्स्टेन्शन दिया गया है वह सरकार की दृष्टि से गैरवाजिब नहीं ?

(घंटी)

प्रश्न संख्या ३६६

श्री अध्यक्ष—श्री रघुवीरसिंह।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३६७

चित्तौड़ जिले में सीमेन्ट फेक्टरी

श्री सुगनचन्द जैन—क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राजस्थान सरकार चित्तौड़ जिले में सीमेंट फेक्ट्री खोलने का विचार रखती है ?

(ख) यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं ?

(ग) क्या इस क्षेत्र में काफी तादाद में सीमेंट के पत्थर मौजूद हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या (नागरिक रसद मन्त्री)—(क) यदि कोई फर्म सीमेंट फेक्ट्री चित्तौड़ में खोलने के लिये उचित पूंजी और विशिष्ट टेक्नीकल ज्ञान के साथ सरकार से सहायता चाहती है तो सरकार ऐसे प्रस्ताव पर पूर्ण ध्यान देगी।

(ख) इसका उत्तर उपरोक्त प्रश्न (क) में आ जाता है।

श्री सुगनचन्द जैन—'ग' का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री भोगीलाल पंड्या—'हाँ' वहाँ पर सीमेंट के अच्छे पत्थर निकलते हैं।

प्रश्न संख्या ३६८

चित्तौड़ जिले में चोरियें, डकैतियें इत्यादि और उनके सम्बन्ध में पुलिस कार्यवाही

श्री सुगनचन्द जैन—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) चित्तौड़ जिले में इस साल कितनी चोरियाँ हुईं जिनमें नकबजनी कितनी हुई और कितनी डकैतियाँ हुईं जिनमें कितनी बरामद हुईं और कितनी का अदालत में चालान किया और कितनी पेन्डिग हैं।

[श्री सुगनचन्द जैन]

(ख) इसी प्रकार बेगू सब डिवीज़न के सम्बन्ध में भी बतावें।

श्री नरसिंह कछवाहा (उपमन्त्री)—इस साल चित्तौड़ जिले में चोरियाँ इस प्रकार हुई :

	संख्या	बरामद हुए	चालान किया	पेन्डिंग
(क) चोरियाँ	२८६	१६,६७६	१०१	८१
(ख) नकबजनी	४५२	६,७००	२१६	८६
(ग) डकैतियाँ	११	८०८	२	१
बेगू सब डिवीज़न का इस प्रकार है :				
(क) चोरियाँ	४३	५,६८६	२३	४
(ख) नकबजनी	८७	३,६५४	१२	६
(ग) डकैतियाँ	१			१

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्षजी, यह कथा पढ़ी गई है या जवाब दिया गया है।

श्री कानसिंह—क्या मन्त्रीजी बतायेंगे कि चोरी, डकैतियां और नकबजनी में जो माल गया उसमें से सरकार ने कितने पर्सेन्ट बरामद किया ?

श्री नरसिंह कछवाहा—परसेन्टेज नहीं निकाला गया है।

श्री किशनलाल शाह—कितना पर्सेन्ट माल बरामद हुआ ?

श्री नरसिंह कछवाहा—पर्सेन्टेज नहीं निकाला गया है।

प्रश्न संख्या ३६६

श्री अध्यक्ष—श्री रघुवीरसिंह।

(प्रश्न-कर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४००

श्री अध्यक्ष—श्री कँवरलाल जेलिया।

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४०१

जयपुर शहर में सन् १६५३-५४ में शराब के ठेके

श्री भैरूँ सिंह (वि० सं० १६)—क्या पृथक राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) जयपुर शहर में सन् १६५३-५४ में कितने रुपयों में शराब की बिक्री का ठेका हुआ है?

(ख) इस वर्ष कितने गैलन कितने रुपयों की शराब ठेकेदारों को दी गई?

(ग) इस शराब का ठेकेदारों को कितना कमीशन मिलेगा?

(घ) ठेके की रकम का कमीशन में कितना अन्तर है?

(ङ) उपरोक्त प्रश्नावली के आधार पर सन् १६५२-५३ व ५१-५२ में कितना अन्तर रहा है?

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मन्त्री)—(क) जयपुर शहर में मदिरा की दुकानों का ठेका १६५३-५४ के लिये २५६३८५) का हुआ है।

(ख) अभी वर्ष की समाप्ति में एक मास अवशिष्ट है, अतः ११ मास में विभिन्न प्रकार की ४१,०६२ गैलन मदिरा ठेकेदारों को दी गई है जिसका मूल्य १,६०,०१६ रु० ८ आ० है।

(ग) उपरोक्त मदिरा की बिक्री पर ठेकेदारों को ८८५६४ रु० ४ आ० कमीशन मिलेगा।

(घ) ठेके की धन-राशि एवं कमीशन में १,७०,८२० रु० १२ आ० का अन्तर है।

(ङ) इसी प्रकार सन् १६५२-५३ एवं १६५१-५२ में ठेके की धन-राशि और कमीशन का अन्तर क्रमशः १,८७,२७२ रु० १० आ० एवं २,१२,८०३ रु० १२ आ० है।

श्री भैरूँ सिंह (दांतारामगढ़)—क्या माननीय मन्त्री महोदय को मालूम है कि इस ठेके की रकम और कमीशन के अन्दर लगभग १ लाख का अन्तर होने के कारण ठेकेदार लोग नाजायज फायदा उठाते हैं, जिनमें अधिकारियों का भी हाथ होता है?

श्री भोलानाथ—यदि ऐसा होता है, तो नियमानुसार कार्यवाही की जाकर सजा दी जाती है।

Page No.19

श्री भैरूँसिंह—क्या यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष किसी मुख्य ठेकेदार की कोई इस प्रकार की शिकायत हुई थी ?

श्री भोलानाथ—यह आपने दूसरा प्रश्न किया है। इसका उत्तर अलग प्रश्न के रूप में दिया जा सकता है।

श्री भैरूँसिंह—क्या कमीशन की रकम और ठेके की रकम में इतना अन्तर रहते हुए भी यह संभावना नहीं है कि ठेकेदार कुछ गड़बड़ करते हैं ?

श्री भोलानाथ—ठेका बोली लगाकर लेते हैं। अगर फायदा नहीं हुआ तो अगले साल नहीं लेंगे।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या हम यह समझें कि ठेकेदार लोग १ लाख रुपयों का नुकसान उठा रहे हैं ?

श्री भोलानाथ—बोली लगाकर ठेका लेते हैं, आयन्दा नहीं लेंगे।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या वे नाजायज फायदा नहीं उठाते हैं ?

श्री भोलानाथ—सरकार के ध्यान में ऐसी कोई बात नहीं है। कोई ठेकेदार यदि मकान बनाने का ठेका लेते हैं तो उसमें भी उसको नुकसान हो सकता है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या ठेकेदार लोग इतने फिलेन्थ्रोपिक (philanthropic) हो गये हैं कि वे नुकसान उठाकर भी सरकार की मदद करते हैं ?

श्री भोलानाथ—अगर नुकसान उठाकर ठेका लेते हैं तो गलती करते होंगे, दुबारा नहीं लेंगे।

श्री भैरूँसिंह—ठेकेदारों को कमीशन के रूप में नुकसान होता है, लेकिन वे अधिकारियों से मिलकर नाजायज शराब बनाकर फायदा उठाते हैं, क्या यह सच है ?

श्री भोलानाथ—यह आपकी राय है। हमको इसका पता नहीं है।

प्रश्न संख्या ४०२

राजस्थान में लघु खनिज नियमावली का बनाया जाना

श्री मुक्तिलाल मोदी—क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में माइनर मिनरल रूल्स कब तक बन जाने की संभावना है ?

(ख) अभी तक न बनाने में सरकार को क्या कठिनाई थी ?

Page No.20

श्री भोगीलाल पंड्या— (क) सन् १९५४ के अन्त तक।

(ख) खनिज ठेकों के विभिन्न नियमों तथा उनकी अलग-अलग परिस्थितियों का भारत के अन्य प्रदेशों में व्यहृत ऐसे नियमों के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया गया। प्रस्तावित नियमों के मसविदे की अन्तिम रूप से अब जाँच की जा रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह प्रश्न सरकार के सामने कब से विचाराधीन है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मुझे तारीख तो याद नहीं है लेकिन काफी लम्बे समय से है।

प्रश्न संख्या ४०३

भूगर्भ खनिज विभाग द्वारा एकीकरण के बाद शासकीय व्यापारिक आय

श्री मुक्तिलाल मोदी—क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(ख) क्या राजस्थान में भूगर्भ व खनिज विभाग की व्यवस्था एक योग्य व अनुभवी संचालक के उत्तरदायित्व में है ?

(ख) एकीकरण के बाद इस महत्वपूर्ण विभाग की वजह से सरकार में इन ४ साल में व्यापार की आय में कितनी बढ़ोत्तरी हुई ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(ग) मेजर मिनरल कन्सेशन रूल्स के अन्तर्गत कितनी आय हुई और खास कर नीचे लिखे मिनरल्स से:—

१. आइरन ओर, जयपुर
२. बैरीमल उदयपुर, जोधपुर
३. मेन्गेनीज उदयपुर, जयपुर
४. सोप स्टोन जयपुर, उदयपुर
५. अन्य मिनरल्स।

(घ) मिनरल कन्सेशन रूल्स व डेवलपमेंट एक्ट के अन्तर्गत क्या माइनर मिनरल रूल्स बन गये हैं ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ? इसके न बनने से सरकार की आय में जो कमी हुई है उसका उत्तरदायित्व किस पर है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) हाँ।

(ख) एकीकरण के बाद राजस्थान के खनिज विभाग की आय के आँकड़े इस प्रकार हैं:—

१६५०–५१	रु० ३६,०८,४७४
१६५१–५२	रु० ४७,६१,७६६
१६५२–५३	रु० ४४,२६,६८६

वर्ष १६५३–५४ के अभी तक आँकड़े पूर्ण नहीं हुए हैं। वर्ष ५२–५३ में कुछ कमी का कारण यह है कि भोडल के व्यापार में मंदी थी। उसके अलावा वर्ष ५१–५२ के आँकड़ों में भीलवाड़ा क्षेत्र में भोडल के नये लीज़ दिये जाने की टेंडर की रकम भी शामिल है।

(ग) इस प्रश्न में पूछे गये आँकड़े निम्न प्रकार हैं:—

१. आयरन ओर, जयपुर	५०–५१			
	५१–५२	५२०)		
	५२–५३	३५६०) लगभग		
		उदयपुर	जोधपुर	
२. बेरिमल, उदयपुर, जोधपुर	५०–५१	३००)	०	
	५१–५२	६६८३)	०	
	५२–५३	१८,४८०)	०	
		उदयपुर	जयपुर	
३. सोप स्टोन उदयपुर, जयपुर	५०–५१	३१,५०३)	४७,६३४)	
	५१–५२	३६,५६०)	४६,०२७)	
	५२–५३	४१,७२३)	४८,०१३)	
		उदयपुर	जयपुर	
४. मेनगेनीज़ जयपुर, उदयपुर	५०–५१	४,६११)	०	
	५१–५२	२०,५६६)	०	
	५२–५३	२३,६१०)	०	
५. अन्य मिनरल	साथ में लगी लिस्ट देखें।			

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

(ख) नहीं। गौण खनिजों के खान के बारे में विभिन्न डिवीजनों में व्यहृत होने वाले विभिन्न नियमों को और दूसरे राज्यों में व्यहृत नियमों का अध्ययन करने के बाद जो नियम बनाये गये हैं वे सरकार के विचाराधीन हैं। नये नियमों को अब तक लागू न करने से सरकार की आमदनी में कोई कमी नहीं हुई है। एक लिस्ट लम्बी है उसे पढ़ने में समय लगेगा, इसलिये यदि इजाजत हो तो सदन की मेज पर रखदूँ।

श्री अध्यक्ष—मेज पर रखदी जाय।

श्री संतोषसिंह—प्रश्न के (क) भाग का उत्तर 'हाँ' में जो दिया गया है, तो क्या आप उनकी योग्यता बता सकते हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—वे आर. ए. एस. के ऑफीसर हैं।

श्री संतोषसिंह—भूगर्भ के मुतल्लिक उनकी योग्यता क्या है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने प्रश्न नहीं सुना।

श्री संतोषसिंह—उनकी क्वालिफिकेशन क्या है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मिस्टर सेठी आर. ए. एस सर्विस के हैं और भूगर्भ के लिये जितनी योग्यता चाहिये उतनी उनकी योग्यता है।

श्री संतोषसिंह—क्या आपके विभाग में उनसे ज्यादा क्वालिफाइड आदमी और भी हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मेरे ख्याल से आप इस बारे में कोई अलग प्रश्न पूछें तो मैं उनकी क्वालीफिकेशन आदि के बारे में सारी बातें बता दूँगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार के ध्यान में यह भी है या नहीं कि माइनिंग के लिये स्टेन्डर्ड क्वालिफिकेशन क्या होती है ?

श्री तेजमल बापना—सन् ५२-५३ में आमदनी में जो कमी हुई है वह क्या खनिज नियमावली के न होने के कारण हुई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं अपने जवाब में बता चुका हूँ कि भोडल के भाव नीचे चले गये थे और नया-नया लीज़ लिया था, उसकी रकम जमा हुई थी पहले साल में, इसलिए ५२-५३ में आमदनी कम मालूम हुई।

श्री संतोषसिंह—क्या भोडल के भाव में कमी हुई है या चोरी हुई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—भोडल के भाव में कमी हुई है।

प्रश्न संख्या ४०४

बीकानेर क्षेत्र की गंगानगर सुगर मिल को चलाने का भार शासन पर

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

[श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री]

(क) क्या यह सत्य है कि बीकानेर एरिया में जो गंगानगर सुगर मिल है, उसे सरकार ने रन (run) करने का भार अपने ऊपर ले लिया है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि इस मिल के प्रोफिट में से एक लाख रुपये सालाना उस मिल के मालिक को देना निश्चित किया गया है ? यदि हाँ, तो किस आधार पर ?

श्री भोगीलाल पंड्या (नागरिक रसद मन्त्री)—(क) हाँ, सरकार ने इस फेक्टरी को एक साल के लिए लीज़ पर लिया है। दूसरे साल लीज़ पर लेने का निश्चय सरकार पर निर्भर रखा गया है।

(ख) एक लाख रुपये की कोई शर्त नहीं हुई है। कितनी रकम देना है यह अभी निश्चय नहीं किया गया है।

(ग) हाँ।

प्रोफिट देने का प्रश्न नहीं उठता। भिन्न-भिन्न उद्योगों के साथ शर्त आवश्यकतानुसार व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए की जाती है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—आपने अभी फरमाया कि एक लाख रुपया देने का तय नहीं किया है, तो क्या मिल मालिक को और कोई रकम देने का तय किया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह प्रश्न बार-बार उठाया जाता है, अगर माननीय सदस्य पूछें तो सारी शर्तें पढ़ कर सुना दूँ।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह--इस वक्त कितनी रकम देने का तय किया है, यह प्रश्न पूछा गया है।

श्री भोगीलाल पंड्या--ऐसी बात है कि मेनेजिंग एजेन्ट को २४०००) रुपये मिलते थे, अब केवल ५०००) रुपये मिलेंगे; नोमीनली (nominally) रकम दी जायगी। बाकी जितनी होती है उतनी दी जायगी।

प्रश्न संख्या ४०५

सन् १९५३-५४ में राजस्थान की नगरपालिकाओं की अवधि-वृद्धि

श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) सन् १९५३-५४ में किन-किन नगरापालिकाओं के कार्यकाल की अवधि-समाप्त होत है ?

[श्री भैरूँसिंह]

(ख) किन-किन नगरपालिकाओं की किन-किन कारणों से कार्यकाल की अवधि में वृद्धि की गई ?

(ग) नगरपालिका के चुनाव क्षेत्र में साधारणतया मतदाता-सूची तैयार करने में कितना समय लगता है ?

श्री रामकरण जोशी—(स्वायत्त शासन मन्त्री) (क) १. टोंक, २. निम्बाहेड़ा ३. कपासन, ४. झालावाड़, ५. अलवर, ६. लछमनगढ़, ७. निवाई, ८. उनियारा, ९. भीनासर, १०. बीदासर, ११. बालोतरा, १२. नागौर ।

(ख) सूची सदन की मेज पर रखी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

(ग) तीन मास ।

श्री शिवदानसिंह—क्या निम्बाहेड़ा (अश्रव्य) नगरपालिका की अवधि समाप्त नहीं हुई है ?

श्री रामकरण जोशी—२८-१-५४ को समाप्त हो गई है ।

श्री शिवदानसिंह—क्या सरकार को यह मालूम है कि वहाँ पर अपर्याप्त मात्रा में सदस्य लम्बे अर्से से काम चला रहे हैं । सदस्यों की जितनी संख्या होनी चाहिये उतनी नहीं है ?

श्री रामकरण जोशी—पर्याप्त संख्या है ।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या बीदासर म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हो चुके हैं ?

श्री रामकरण जोशी—हो चुके हैं ।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या मेम्बर्स नामजद कर दिये गये हैं ?

श्री रामकरण जोशी—सब हो चुके हैं ।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या कोई शिकायत नामजदगी के सम्बन्ध में सरकार के पास आई है ?

श्री रामकरण जोशी—मैं समझता हूँ कि इस तरह के सवाल का जवाब देना सम्भव नहीं हो सकता । शिकायतें आती हैं तो जाँच हो सकती है ।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—मैंने प्रश्न यह पूछा है कि शिकायत आई या नहीं ?

श्री रामकरण जोशी—राजस्थान में इतनी म्युनिसिपैलिटियाँ हैं, उनकी कई शिकायतें आती हैं। किस-किस की शिकायत आई है, इसका एट रेंडम (at random) जवाब देना नामुमकिन है ?

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—'एट रेंडम' से आपका क्या मतलब है।

श्री अध्यक्ष—Order !

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या अलवर म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हो चुका है।

श्री रामकरण जोशी—जी, अभी हुए हैं।

प्रश्न संख्या ४०६

सन् १९५३-५४ में सीकर-झुँझुनू डिस्ट्रिक्ट में अध्यापकों की नियुक्ति

श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६)—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे--

(क) सन् १९५३-५४ में सीकर झुँझुनू डिस्ट्रिक्ट में अध्यापकों की श्रेणी में कितनी नयी नियुक्तियाँ हुई ?

(ख) इनमें कितनी नियुक्तियाँ इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स द्वारा की गईं ?

(ग) क्या यह सही है कि ये नियुक्तियाँ आई. एस. द्वारा मनमाने ढंग से की गईं और यदि ऐसा नहीं तो किन नियमों के आधार पर ये नियुक्तियाँ की गईं ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)--(क) सन् १९५३-५४ में सीकर-झुँझुनू जिले में नये प्राइमरी स्कूलों को खोलने के सिलसिले में १०६ नये अध्यापकों की नियुक्तियाँ की गईं।

(ख) ये नियुक्तियाँ इन्सपेक्टर सीकर द्वारा की गईं, जो नियुक्तियाँ उनके अधिकार में थी।

(ग) नहीं। मनमाने तौर पर नहीं की गईं। समस्त रिक्त स्थानों के लिये योग्य व्यक्तियों के प्रार्थनापत्र विज्ञापन द्वारा माँगे गये थे। प्रार्थना पत्र आने पर समस्त उम्मीदवारों को इन्टरव्यू के लिये बुलाया गया और इन्टरव्यू लेने के बाद उनमें से योग्यतम व्यक्तियों का चुनाव किया जाकर उनकी नियुक्तियाँ की गयीं।

श्री कानसिंह—इन्टरव्यू में सिलेक्ट करने के लिये कौन-कौन बैठे थे ?

श्री अध्यक्ष—Order !

श्री श्रीदास गोयल—क्या, जो अध्यापक पहले से सर्विसेज़ में हैं और जो इस प्रकार की या इससे ज्यादा योग्यता रखते हैं तो क्या उनको भी इन उच्च जगहों के लिए नई उम्मीदवारी के लिये मौका दिया गया था ?

श्री भोलानाथ—नहीं, उनको तो प्रोमोशन से लिया जाता है।

श्री संतोषसिंह—ये जो १०६ नये अध्यापक लिये गये, उनमें कितने छठी कक्षा पास हैं ?

श्री भोलानाथ—मिडिल से कम को नहीं लिया जाता।

श्री श्रीदास गोयल—जो अध्यापक मेट्रिक्युलेट्स थे और उसी ग्रेड में थे उन्होंने आगे पढ़ाई करके बी. ए. पास कर लिया, क्वालिफिकेशन बढ़ा ली; तो क्या उनको प्रोमोशन नहीं मिलता ?

श्री भोलानाथ—केवल क्वालिफिकेशन बढ़ाने से ही प्रोमोशन नहीं मिलते।

श्री श्रीदास गोयल—एक मेट्रिक पास अध्यापक जो मेट्रिक्युलेट के ग्रेड में है व सर्विस करते हुए एम. ए. हो चुका है तो क्या उसको बी. ए. पास की जगह का मौका दिया जायगा ?

श्री भोलानाथ—धीरे-धीरे दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—Individual Cases will be considered.

(हँसी)

प्रश्न संख्या ४०७, ४०८ तथा ४०६

श्री अध्यक्ष—बी. एन. जोशी।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४१०

राजस्थान के विभिन्न शहरों तथा नगरों के लिविंग इन्डेक्स नम्बर्स

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Labour be pleased to answer:—

(a) Has the Rajasthan Government taken any steps for calculating and maintaining Cost of Living Index Numbers for the main towns and cities in Rajasthan ?

Page No.27

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

(b) Has it ordered or conducted any Family Budget enquiry at any industrial or urban centre ?

(c) If not, why not ?

(d) Will the Government now take early steps to get Cost of Living Index Numbers calculated and published for the main industrial and urban centres of Rajasthan ?

श्री रामकरण जोशी—(अ, ब और स) नहीं ।

(ड) इस वर्ष यह कार्य प्रारम्भ करने के विषय में सरकार विचार कर रही है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार ने निर्णय दे दिया है ?

श्री रामकरण जोशी—विचार कर रही है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—(अश्रव्य)

श्री रामकरण जोशी—इसके लिये सरकार विचार कर रही है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या भारत में राजस्थान को छोड़ कर और जगह इस तरह इन्डस्ट्रियल केल्कुलेशन किया जाता है ?

श्री रामकरण जोशी—इसका पता नहीं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह समझा जाय कि यह कार्य करने का सरकार निर्णय कर चुकी ?

श्री रामकरण जोशी—सरकार विचार कर रही है ।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—कब तक ?

श्री रामकरण जोशी—शीघ्र ही ।

कुँ० श्री जसवन्तसिह—क्या एक माह के अन्दर-अन्दर ?

श्री रामकरण जोशी—इससे पहले भी और बाद में भी ।

प्रश्न संख्या ४११

शराब की बिक्री कराने की वर्तमान प्रणाली के अनुसार ठेकेदारों को लाभ

श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६)—क्या पृथक राजस्वमन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि सरकार की शराब की बिकी करवाने की वर्तमान प्रणाली के अनुसार ठेकेदार कमीशन में मिलने वाली रकम से कहीं अधिक ठेके की रकम जमा कराते हैं ?

[श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६)]

(ख) क्या यह सही है कि इसी कारण आबकारी महकमा ठेकों द्वारा असली शराब की बिक्री करवाने में असमर्थ रहा है ?

(ग) यदि नहीं, तो इस वर्ष ठेकेदारों पर असली शराब की बिक्री न करने के कारण आबकारी विभाग ने कितने मुकद्दमे बनाये और उनका क्या परिणाम रहा ?

श्री भोलानाथ—(क) ठेके की बोली के मुताबिक जमा करते हैं, कमीशन का कोई सवाल नहीं पैदा होता ।

(ख) यह ठीक नहीं।

(ग) १-१-५३ से ३१-१२-५३ तक १८५ मुकद्दमे पकड़े गये, परिणाम अच्छा रहा ।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—क्या सरकार ने जांच की है कि कमीशन से ठेकेदार को कितनी आमदनी होती है ?

श्री भोलानाथ—पहले मैं डिटेल में जवाब दे चुका हूँ ।

श्री भैरूँसिंह—१८५ केसेज़ में से कितने केसेज़ में सजा मिली ?

श्री भोलानाथ—यह तो बड़ा लम्बा सवाल है । हाँ, जयपुर डिवीज़न के केसेज़ के डिटेल्स मेरे पास हैं । १-१-५३ से ३१-१२-५३ तक लाइसेन्स के शर्तनामे के विरुद्ध आचरण करने पर कुल (अश्रव्य) मुकदमे तैयार किये गये (अश्रव्य) ४ का न्यायालय में चालान किया गया, ६ का निर्णय विभाग में पेंडिंग है ।

श्री भैरूँसिंह—क्या इनके ठेके भी रद्द किये गये ?

श्री भोलानाथ—सजा दी जाती है ।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—महज २०), २५) रुपये जुर्माना ही कर दिया जाता है और मुकद्दमा तय कर दिया गया है या कड़ी सजा दी गई है ?

श्री भोलानाथ—जैसा कुसूर होगा, वैसी सजा दी गई ।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या किसी के ठेके केन्सिल किये गये हैं ?

श्री भोलानाथ—इस वक्त मेरे पास सूचना उपलब्ध नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Is the Hon'ble minister in a position to contradict the statement that not a single contract has been cancelled ?

श्री भोलानाथ—नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे पास ऐसे केसेज़ हैं जिनके ठेके केन्सिल किये गये हैं; पर मेरे पास इस वक्त सूचना नहीं है।

प्रश्न संख्या ४१२

श्री अध्यक्ष—राजा श्री मानसिंह।

[प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित]

प्रश्न संख्या ४१३ तथा ४१४

श्री अध्यक्ष—श्री कँवरलाल जेलिया।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४१५

जयपुर म्युनिसिपल कौंसिल भंग करना तथा पुनः चुनाव

श्री भैरूँ सिंह (वि सं० १६)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जयपुर म्युनिसिपल कौंसिल को भंग किये कितना समय हो गया ?

(ख) इसके चुनाव कब होंगे और अब तक उसकी तिथि घोषित न करने का क्या कारण है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(क) लगभग ६ मास।

(ख) निश्चित समय की समाप्ति पर अभी तक तिथि की घोषणा करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई।

श्री भैरूँ सिंह—यह प्रश्न सरकार के पास कब से विचाराधीन है और कब तक सरकार के पास विचाराधीन रहेगा।

श्री रामकरण जोशी—जब से उसकी जरूरत हुई और जब तक रहेगी।

श्री भैरूँ सिंह—क्या यह सही है कि सरकार जयपुर म्युनिसिपल कौंसिल का चुनाव कराने की जरूरत अभी नहीं समझती ?

श्री रामकरण जोशी—(अश्रव्य) मैंने कहा है कि यह मामला सरकार के विचाराधीन है ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—जब-जब प्रश्न पूछा जाता है, यह मामला सरकार के विचाराधीन हो जाता है क्या ?

श्री भैरूँसिंह—इस प्रकार के प्रश्न को विचाराधीन रखने की आवश्यकता क्यों पड़ गई है ? क्या इससे जनता में असंतोष है ?

श्री रामकरण जोशी—यह आप कहते हैं कि जनता में असंतोष है ।

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble member should ask the time when the Elections are going to take place.

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसका निर्णय कब तक हो जावेगा ?

श्री रामकरण जोशी—निर्णय होते ही आपको जवाब दे दिया जायेगा ।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Will the elections ever take place.

श्री भैरूँसिंह—इस प्रश्न को विचारधीन रखने की आवश्यकता क्यों आई ?

श्री रामकरण जोशी—यह प्रश्न अलग से पूछा जाना चाहिये ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कब तक चुनाव हो जावेंगे, उसके बारे में कोई निश्चित तिथि मुकर्रर हुई है ?

श्री रामकरण जोशी—यह मामला सरकार के विचाराधीन है, विचार होने के बाद तिथि तय होगी ?

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या जयपुर म्युनिसिपल कौंसिल के चुनाव कभी आप करावेंगे या नहीं ?

श्री रामकरण जोशी—जितनी अवधि है उसकी समाप्ति के बाद ।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—अभी तो ६ महिने ही हुए हैं ।

श्री भैरूँसिंह—क्या सरकार को यह मालूम है कि सरकार के पास इस प्रकार के मामलों को विचाराधीन रखने का कोई प्रोविजन नहीं है ?

श्री रामकरण जोशी—सरकार के पास कोई महत्त्वपूर्ण मामले विचाराधीन रहते हैं ।

श्री भैरूँसिंह—यह कब तक सरकार के विचाराधीन रहेगा ?

श्री रामकरण जोशी—यह सरकार के विचाराधीन है और जब तक विचार नहीं होगा तब तक विचाराधीन रखना पड़ेगा ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस जयपुर म्युनिसिपल कौंसिल के चुनाव में पब्लिक को भी मौका मिलेगा ?

श्री रामकरण जोशी—पब्लिक को ही मौका मिलेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कितने समय के अन्दर यह मौका पब्लिक को मिल जावेगा ?

श्री रामकरण जोशी—यह अवधि जिस समय समाप्त हो जावेगी।

श्री जसवन्तसिंह—क्या यह सही है कि जयपुर की जनता इस चुनाव के लिये बहुत उत्सुक है ?

श्री रामकरण जोशी—आपके द्वारा समझी जावे तो जनता बहुत उत्सुक है, अन्यथा नहीं।

श्री भैरूँसिंह—अगर अगले महिने में यह चुनाव कराया जावे तो आपको क्या आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !! Next.

प्रश्न संख्या ४१६

श्री अध्यक्ष—श्री कँवरलाल जेलिया।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४१७

राजस्थान में बेकार व्यक्तियों के आंकड़े तथा बेकारी को रोकने की शासकीय योजना

श्री भैरूँसिंह (वि०सं० १६)—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) राजस्थान में बेकार व्यक्तियों के आँकड़े तैयार किये गये हैं या नहीं ?

(ख) यदि हाँ, तो इस समय राजस्थान में कितने बेकार हैं और प्रति वर्ष बेकारों की संख्या बढ़ने की क्या औसत है ?

(ग) राजस्थान में बढ़ती हुई बेकारी की समस्या को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

(घ) क्या सरकार इस सम्बन्ध में एक विस्तृत रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत करेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) हाँ।

(ख) बेकारी के आँकड़े जनवरी, १९५३ से फरवरी, १९५४ तक २५,४५४ है। प्रतिवर्ष बेकारों के बढ़ने की संख्या औसतन ३ हजार है।

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(ग) बेकारी को दूर करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये सरकार ने एक कमेटी बनाई है, उसकी रिपोर्ट आने पर सरकार उस पर विचार करेगी।

(घ) उपरोक्त कमेटी की रिपोर्ट आने पर उसे सरकार प्रस्तुत करेगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस कमेटी के कौन-कौन मेम्बर्स हैं?

श्री भोगीलाल पंड्या—इस कमेटी के कन्वीनर एज्युकेशन सेक्रेटरी है। इनके अलावा निम्नलिखित सदस्य हैं—

१.	डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज़ एन्ड कोमर्स	सदस्य
२.	जियोलोजी एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर ऑफ माइन्स एन्ड	सदस्य
३.	श्री जी. आर.	सदस्य
४.	एम. वी. माथुर.	सदस्य

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या लेबर के रिप्रेजेन्टेटिव को भी इस कमेटी में रखा है?

एक सदस्य—क्या यह संख्या, आवेदन पत्र जो आये हैं एम्पलोयमेंट एक्सचेन्ज में, उनके अनुसार है?

श्री भोगीलाल पंड्या—एम्पॅलायमेंट एक्सचेन्ज के आधार पर ही......

श्री भैरूँसिंह (वि. नं. १६)—क्या इसमें किसी बेकार व्यक्ति को भी सदस्य बनाया गया है?

श्री भोगीलाल पंडया—अभी नहीं।

कुँ० जसवन्तसिंह—क्या बनाने का विचार है?

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !!

We now come to Demand No. 25

श्री हरिकृष्ण व्यास—There are five minutes yet in the close of the question-hour and some of the questions which remain un-replied can be answered now.

श्री अध्यक्ष—Let them be placed tomorrow.

कुँ०श्री जसवन्तसिंह—Sir, there is one point. The House is very anxious to know about the whereabouts of our Hon'ble Chief Minister. What has happened to him: I hope he is quite safe. We would like to know where he is; whether in Delhi, Jaipur or elsewhere?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वे दिल्ली में हैं। उनके लिये चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं वे शाम तक आने वाले हैं।

माँग संख्या २५–निर्माण कार्य इत्यादि (क्रम से)

श्री हरिदेव जोशी—(To discuss the contract system of the public works department.)

अध्यक्ष महोदय, पी. डब्ल्यू. डी. विभाग के अन्दर जो काम होते हैं उनमें अधिकांशतः सारे के सारे काम ठेकेदारों के द्वारा करवाये जाते हैं और इन ठेकेदारों के ज़रिये जो काम होते हैं उनके बारे में कई बार कई प्रकार की शिकायतें आती हैं। मूलतः यह ठेकेदारी प्रथा अपने आप में एक दोष-पूर्ण प्रथा है और इसी कारण से आज के समाज में एक विशेष प्रकार की खराबी आ गई है। इस ठेकेदारी प्रथा के कारण यह कहा जाता है कि हम जो काम जिस समय में करना चाहते हैं, नहीं हो पाता। इसी प्रथा के कारण कई बार पक्षपात होते हैं और भ्रष्टाचार भी फैलता है। अभी हम देखते हैं कि इस ठेकेदारी प्रथा को मद्रास में हटाकर इसका परीक्षण किया जा रहा है। पिछले दिनों जब मैं कोटा में था तब वहाँ कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट के ऑफिसरों का सम्मेलन हुआ था। उस समय सरकार के ऑफिसरों ने यह माँग की थी कि इन सब कामों को अमानी में कराया जावे और इस बात को बड़े–बड़े अधिकारियों ने, यहाँ तक कि कलेक्टर ने भी इस बात को वाजिब माना था, क्योंकि डेवलपमेन्ट के कामों में जहाँ तक तेजी न हो, लोगों में उत्साह न हो, काम न हो, विश्वास नहीं होता और जब तक विश्वास नहीं होता तब तक सारे काम ठीक तरह से नहीं किये जा सकते। इसलिये इस दोषपूर्ण प्रथा को दूर किया जावे। इसके कारण कई बार बुरी तरह यह सुनने को आता है कि कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास न तो पैसा है और न वे अच्छा काम करते हैं, मगर फिर भी उनको ठेका मिल जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि अधिकारियों द्वारा उनको बेजा ढंग से सहायता करने के कारण कई काम खराब हो जाते हैं।

मेरे पास एक जीता जागता उदाहरण है। डूँगरपुर में सड़क का ठेका एक ऐसे ठेकेदार को दिया गया था जो कानूनन ठेका लेने का हकदार नहीं था। उसने पहले–पहल सड़क की खुदवाई करवा दी और वह सड़क खुदी हुई तीन महीनों तक पड़ी रही। जब बहुत शिकायतें की गईं तो उस पर मिट्टी के ढगले डाल दिये और उसके कारण लोगों को महीनों तक खुले पाँव चलना पड़ा। लोगों ने शिकायतें की मगर न तो ठेकेदार ने इस पर कोई ध्यान दिया और न डिपार्टमेंट ने इस ओर ध्यान दिया। मैंने अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि किसी प्रकार से मिट्टी के ढेले हटाये जाकर लोगों को मदद दी जावे, लेकिन अफसोस का विषय है कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। यह एक मिसाल है और इसको बतला कर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ कि यह प्रथा अपने आप में दोष भरी है। जब हम पर्टीक्युलर केस की ओर ध्यान दिलाते हैं तो उसके अन्दर तेज़ी से सुधार करने की कोशिश की जाती है। फिर भी कई दफा काम खराब हो जाते हैं। होता यह है कि जितना गहरा मेटीरियल डाला जाना चाहिये उतना गहरा डाला नहीं जाता। कई बार तो ऐसा होता है कि एक दो फर्लाङ्ग काम हुआ और फिर उस काम को खत्म कर दिया जाता है और दूसरी तरफ काम शुरू कर दिया जाता है। इससे होता यह है कि पहला जो काम अधूरा छोड़ दिया जाता है वह भी चौपट हो जाता है और पिछली सड़क खराब

[श्री हरिदेव जोशी]

हो जाती है और वह उस तरह दिखाई देने लगती है जैसे कि बनने वाली सड़क। इस तरह से पैसा व्यर्थ जाता है। सब से अच्छा तरीका इस को मिटाने का यह है कि सरकार को इस ठेकेदारी प्रथा को दूर करना चाहिये। अपने डिपार्टमेंट के आधीन काम करवाये। उससे स्थानीय बेकारी भी दूर होगी और काफी लोगों को काम मिल सकेगा; क्योंकि वह डिपार्टमेंटल काम होगा और डिपार्टमेंट की अपनी उसके लिये जिम्मेवारी होगी। कई बार यह कहा जाता है कि हमारे पास पैसे की इतनी इफरात नहीं है कि हम अपने ज़रिये इन कामों को करवा सकें, किन्तु देखने का विषय यह है कि जब ठेकेदार इतने टेक्निकल हैन्ड्स रख सकता है, तो कोई कारण नहीं कि डिपार्टमेन्ट्स को इतने टेक्निकल हैन्ड न मिल सकें और वे अपने ज़रिये काम को पूरा न करवा सकें। यह केवल बहाना मात्र है। कई बार ऐसा सुना जाता है कि कई अधिकारियों को ठेकेदारों के अन्दर इन्ट्रेस्ट होता है। मैं सब के लिए यह बात नहीं कहता, क्योंकि कई अधिकारी बहुत ऊँचे केरेक्टर (Character) के आपको मिलेंगे, किन्तु उनमें भी कई ऐसे लोग हैं जिनका उन ठेकेदारों के अन्दर इन्ट्रेस्ट रहता है। आज यह बात आमतौर पर कही जाती है कि पी० डब्ल्यू० डी० के ठेकेदारी के अन्दर आधा अधिकारियों का हिस्सा होता है, अमुक परसेन्टेज पर ठेके दिये जाते हैं, जब तक उनका हिस्सा नहीं दे दिया जाता तब तक बिल का पेमेन्ट नहीं होता, ठेके का पेमेन्ट नहीं होता। यह सही है या गलत इसकी बहस में मैं नहीं जाना चाहता। घूसखोरी को रोकने का एक ही इलाज हो सकता है और वह यह कि सरकार अपने डिपार्टमेन्ट के आधीन यह काम करावे तभी कहीं जाकर करप्शन में बहुत हद तक कमी हो सकती है। वैसे तो इस डिपार्टमेन्ट को कई नामों से पुकारा जाता है। जनता का यहाँ तक खयाल है कि जनता के पैसे का बहुत अधिक दुरुपयोग इस डिपार्टमेन्ट के ज़रिये होता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वे इस ठेकेदारी की प्रथा को समाप्त करने पर विचार करें, और इसको शीघ्र दूर करने की कोशिश करें।

दूसरी ज़रूरत इस बात की है कि जो भी कार्य सरकारी विभाग से होने हों वे जल्दी से जल्दी पूरे हों। इस दृष्टि से जो भी काम हों उन पर जल्दी ही निर्णय ले लिया जाय। निर्णय लेने के बाद में वे काम अच्छे ढंग से किये जांय। मिसाल के तौर पर मैं बताऊँगा कि डूँगरपुर के अन्दर पंच-वर्षीय योजना में एक मात्र आइटम कोलार से आस-पास की सड़क बनाने का प्रोग्राम रखा गया था, किन्तु थोड़े दिनों के बाद में वह बदल कर डूंगरपुर से आसू कर दी गई।

श्री अध्यक्ष—यह तो इस कट मोशन से बाहर की बात है: 'To discuss the contract system of the Public Works Department." This is the cut motion of the Hon'ble Member.

श्री हरिदेव जोशी—मैं यह निवेदन कर रहा था कि अमुक इन्ट्रेस्टेड जो लोग हैं वे कन्ट्रेक्टर्स के अन्दर इन्ट्रेस्ट रखते हैं इसलिए बार-बार इधर-उधर एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह काम को बदलवाते रहते हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर यह जरूरी है कि पी. डब्ल्यू. डी. विभाग एक ऐसी योजना बनावे जिसके अन्दर वे स्वयं अपना कार्य पूरा करें और अपने लोगों

[श्री हरिदेव जोशी]

से काम करावें। तभी इस प्रकार के करप्शन पर चेक रखा जा सकता है और फिर यह स्थिति भी होने की संभावना नहीं रहेगी कि एक सड़क इधर बन रही है तो दूसरी तरफ जो सड़क बना चुके हैं वह फिर टूट-फूट रही है। डूँगरपुर में जो सड़क बनायी गयी है उसके ठेके के बारे में कहा गया है कि वे किसी अमुक ऑफिसर के फेवेरिट (Favourite) हैं। जो गाडरें पड़ी हुई हैं वे ओवरसाइज़ की पड़ी हुई हैं, ऐसा भी कहा जाता है। ठेकेदारी प्रथा अपने आप में दोषपूर्ण है। अतः इस ठेकेदारी प्रथा को जितना जल्दी हो समाप्त किया जाना चाहिये।

श्री सोहनलाल भटनागर—(To discuss the failure of the Government to provide amounts for constructing Government Buildings at Saluembar.)

माननीय अध्यक्षजी, वैसे तो राजस्थान के बनने के पहले से ही स्टेट बिल्डिंगों की हालत बहुत खराब थी, लेकिन राजस्थान के निर्माण के बाद और भी खराब हो गई है। इससे भी दयनीय अवस्था उदयपुर डिवीज़न में सरकारी बिल्डिंगों की है, जो बहुत ही खतरनाक और असन्तोषजनक है। इस कम्पेरिजन पर ध्यान रखते हुए यदि पुराने राजस्थान के वक्त की परिस्थिति का नकशा रखूँ तो आपको विदित होगा कि वहाँ की हालत केवल असन्तोषपूर्ण ही नहीं बल्कि बहुत खतरनाक हो गई है। उदाहरण के तौर पर, सलूम्बर का आपके सामने उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। उदयपुर डिवीज़न में सलूम्बर एक तहसील है जहाँ एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट कोर्टस, अस्पताल, हाई स्कूल आदि सब हैं, लेकिन इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूँ कि वहाँ पर एक भी सरकारी बिल्डिंग नहीं है। तहसील या मजिस्ट्रेट, कोर्टस, अस्पताल आदि झोपड़ों में पड़े हुए हैं। अस्पताल एक ऐसे झोंपड़े में है जिसके गत वर्ष गिरने की हालत हो चुकी थी। जिसको बड़ी मुश्किल से बचाया गया और जो मकान भी मिला है वह बहुत छोटा सा एक दफा रात को एक मरीज़ बेचारा पेशाब करने निकला तो वापिस आते हुए गिर पड़ा और जिसकी दो-तीन दिन बाद मृत्यु हो गई। वहाँ के लॉक अप की हालत को देखिये तो वहाँ अन्डरट्रायल्स जो कैदी होते हैं उन सब को बेचारों को एक साथ रखा जाता है। जब कभी किसी एक को पेशाब आदि के लिए रात को उठना पड़ता है तो उसके साथ-साथ जितने भी कैदी होते हैं उन सब को उठना पड़ता है। वहाँ की हालत इतनी वीभत्स है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। सब को एक साथ हथकड़ी लगाकर सुलाया जाता है, उन कैदियों को जो अन्डर ट्रायल्स होते हैं। इसलिये निवेदन करने का मेरा मतलब यह है कि इस बजट के अन्दर ऐसे स्थानों पर जहाँ बिल्कुल सरकारी बिल्डिंग नहीं हैं वहाँ के लिए कुछ भी प्रोवीज़न नहीं रखा गया है, और जिनको प्राथमिकता दी जानी चाहिये थी, इस बजट को देखने से पता चलता है कि उनको प्राथमिकता नहीं दी गई।

उदयपुर जिले के तहसील ऑफिसों के लिए ५० हजार रुपये रखे गये हैं, 'बी' क्लास क्वार्टर्स के लिए तीस-तीस हजार रुपये रखे गये हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन चीजों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये थी वह नहीं दी गई।

सलूम्बर में हाई स्कूल की बिल्डिंग के लिए वहाँ की जनता ने साढ़े बारह हजार रुपये खर्च कर दिये हैं और वह अब सरकार से आशा करती है कि सरकार इसे जल्दी से जल्दी पूर्ण कराये,

[श्री सोहनलाल भटनागर]

लेकिन इतनी कोशिश के बावजूद भी वहाँ कार्य करना अभी तक सम्भव नहीं हुआ। मुमकिन है कि वह कार्य जल्दी समाप्त भी नहीं होगा। ऐसी हालत में वहाँ की जनता को यह अन्देशा बना हुआ है कि कहीं युनिवर्सिटी वहाँ हाई स्कूल उठाने का निर्णय न कर दे। इधर जब हम शहर के अन्दर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि दिन-रात बिल्डिंग बना करते हैं। केवल सेक्रेटेरियट के दरवाजे को बदलने के लिए दूसरा फाटक बनाया जाता है। जब हम शहर में आते हैं तो हमें ज्ञात होता है यह सारा बजट शहरी वर्क्स के लिये ही काम आ जाता है, ऐसा प्रतीत होता है। इसलिये इसका नाम डिमान्ड फॉर सिटी वर्क्स कहा जाय तो ज्यादा वाजिब हो सकता है।

दूसरा कट मोशन मैंने जो रखा है (To discuss the reduction in amounts in Budget Estimates of 1954-55 as compared to quota already fixed for the roads under the Five Year Plan) उसका मतलब पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सड़कों के बारे में जो रकम रखी गई है उससे है। जो रकम गत वर्ष अलॉट की गई थी वह इस वर्ष बहुत कम कर दी गई है। सलूम्बर से जो सड़क बनाई गत वर्ष उसके लिए ५० हजार रुपये रखे गये थे और जिस समय ठेका देना चाहते थे उस समय कोई ठेकेदार नहीं आया। इसलिए वे ५० हजार रुपये लेप्स (lapse) हो गये। इस वर्ष १ लाख रुपया रखा गया है, उसको घटा कर ११ हजार रुपये कर दिया है। जयसमन्द से सलूम्बर की सड़क के लिए एक लाख रुपया निश्चित था उसकी जगह अब ५३ हजार कर दिया गया है। यह सड़क गत वर्ष बननी शुरू हुई थी इसमें दो-तीन हजार रुपये व्यय भी हो चुके हैं। इस तरह से रुपये खराब जायेंगे, क्योंकि बजट में देखने से पता चलता है कि इनके लिए कोई रकम नहीं रखी गई है।

इसलिये मेरा निवेदन है कि जिन चीज़ों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये दी जाय, और जहाँ गलती हो गई हो उसको दुरूस्त करने का प्रयत्न किया जायगा।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष, जहाँ तक सिविल वर्क में ठेकेदारों के द्वारा काम लेने न लेने का प्रश्न है माननीय श्री जोशी ने इस पर काफी प्रकाश डाला। लेकिन यह सत्य है कि ठेकेदार लोगों की वास्तव में एक बहुत चतुर कौम है और वे लोग रुपये की आमदनी को प्रमुखता देने के कारण बड़े-बड़े जाल बिछाते हैं। कुछ-कुछ जिम्मेदार अधिकारियों को अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं और इस में कामयाब भी हो जाते हैं। और यह एक ऐसी बड़ी बीमारी है कि जिससे सिविल वर्क्स विभाग का काम सन्तोषजनकरूप से नहीं चल पाता है। अभी कुछ मित्रों ने कहा और यह सही है कि लाखों रुपयों के मकान, सड़कों का काम इस सरकार ने हाथ में लेकर केवल इसलिए छोड़ दिया कि योग्य ठेकेदार नहीं मिले। अगर मिले, और टेन्डर दिये तो वर्क हाथ में लेकर फिर पूरा नहीं किया। बहुत सी सड़कों की मरम्मत करनी थी, खराब थीं वे भी हाथ में लीं, पर अधूरी ही छोड़ दीं। फिर यह भी एक सुझाव दिया गया कि इस ठेकेदारी प्रथा में यह खराबी है तो इसको खत्म करके अमानी में काम शुरू करके देखा जाय। पर मैं सोचता हूँ क्या इसमें भी हम सफल होंगे? इसमें भी मस्टर रोल्स की गड़बड़ियों की सम्भावनाएँ हैं। जिम्मेदारी लेने वाले लोग और नीचे तबके के लोग और पी. डब्लू. डी. के कर्मचारियों के जो तरीकें हैं वे भी असन्तोषपूर्ण हैं और वहाँ भी मूल में वही बीमारी मिलेगी।

[श्री श्रीदास गोयल]

तो ऐसी स्थिति में मैं यह निवेदन करूँगा कि सबसे बड़ी बीमारी तो है भ्रष्टाचार की और इस जड़ को हमें दूर करना चाहिये। अगर यह कर सकें तो हम किसी भी प्रथा से काम ले सकते हैं। हमें कोई खतरा तब नहीं रहेगा। मूल दोष तो भ्रष्टाचार का है। और ठेकेदार लोगों के लिए तो यह प्रमाणित है कि बोल्ड हाउन्ड्स इनके पीछे छोड़े जावें। सरकारी अधिकारी भी रिश्वत लेते हैं और मैं यह मानता हूँ कि अगर हर विभाग के इन्चार्ज, सेक्रेटेरियट का स्टॉफ और माननीय मन्त्री महोदय स्वयं भी उचित ध्यान दें तो यह बीमारी किसी हद तक कम हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ जिस लापरवाही से काम किया जाता है उसके पीछे कुछ सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का भी छुपा हाथ होता है। इनके लिए उनकी महरबानियाँ होती हैं और वही महरबानियाँ कन्सिडरेशन (Consideration) का कारण है। इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। अस्तु।

इसलिए यह निहायत जरूरी है कि इस जन-कल्याणकारी राज्य का निर्माण करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, हम सब इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सरकार के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर काम करने को तैयार हों। पंच-वर्षीय योजना के द्वारा हम प्रगति कर रहे हैं। पी. डब्लू. डी., इर्रिगेशन और सिविल वर्क्स में काम करने वाले अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए यदि जिम्मेदार ठेकेदार को बनाए और अपना लोभ-लालच छोड़ सकें तो बहुत अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष—The cut motions moved by Sarva Shri Hari Krishan Vyas, Abani Kumar, Kapil Deo Agrawal, Lal Bahadur, Bhairon Singh and Chand Mal Mehta are time-barred, and hence they are rejected. I will give them opportunity to speak, but they will confine themselves within the scope of the cut motions which are to be moved.

श्री हरिकृष्ण व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री अबनिकुमार।

(अनुपस्थित)

श्री कपिलदेव अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री लालबहादुर।

(अनुपस्थित)

श्री भैरूसिंह (वि० स० १६)—माननीय अध्यक्ष महोदय, सिविल वर्क्स को लेकर इस सदन में जो भ्रष्टाचार की एक चर्चा चल रही है उसमें शक करने की गुँजाइश तो, मैं समझता हूँ, इस सदन के किसी भी माननीय सदस्य को नहीं होगी। जब कभी भी इस विषय को लेकर इस सदन में चर्चा

[श्री भैरूँसिंह]

चली है तो उसमें जो पहला चार्ज लगाया जाता है वह यह होता है कि इस विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है और इसी में सबसे ज्यादा खर्चा है। राजस्थानी भाषा में एक कहावत है :—

"मियाँ जोड़े तार-तार
और बीबी लेजावे पगड़ी उतार।"

यह रुपया राजस्थान की जनता से एक एक पैसा और एक-एक पाई करके इकट्ठा किया जाता है और इसलिए किया जाता है कि उस धन के सदुपयोग से जनता को सुख-सुविधाएँ प्रदान हों। लेकिन यह इस प्रकार का डिपार्टमेंट है कि जो धन संग्रह किया जाता है उसका सदुपयोग के स्थान पर इस बुरी तरह से दुरुपयोग किया जाता है कि राजस्थानी की यह कहावत हमें मजबूर कर देती है यह बात कहने के लिए कि यह एक सत्य है। अध्यक्ष महोदय, इस विभाग में रोड्स के काम में, बिल्डिंग्स के काम में, आर्चीटेक्ट (architect) के काम में और इस डिपार्टमेंट की जो मशीनरी है उसको और उसके कारनामों को यदि विभक्त तौर पर देखा जावे तो मैं यह विश्वास के साथ बता सकूँगा कि इस विभाग में किस प्रकार से और किस हद तक भ्रष्टाचार व्याप्त है। मैं इस सम्बन्ध में हाल ही की चर्चा का जो विषय बना हुआ है उसका उदाहरण सदन में प्रस्तुत करूँगा। वह है भांडारेज से लालसोट की सड़क का। अध्यक्ष महोदय, आगरा से भांडारेज तक एक सड़क का टुकड़ा है। इस टुकड़े का काम २२० प्रतिशत शिड्यूल रेट (Schedule rate) से एबाऊ (Above) पर चल रहा है। रोड वर्क का और अर्थ वर्क का २७० प्रतिशत एबाऊ शिड्यूल रेट के हिसाब से चल रहा है। इसी भांडारेज से आगे लालसोट की सड़क का काम था। इसके लिए सरकार ने नोटिस दिया २३ तारीख को और इसके बाद में तीन दिन के पश्चात् ही अर्थात् २७ तारीख तक टेंडर इन्वाइट कर लिये गये। २७ तारीख तक २४, २५ और २६ इन तारीखों को क्रिकेट मैच होने के कारण छुट्टियाँ थीं दफतरों में, लेकिन चौथे रोज़ ही सब जितने भी कन्ट्रेक्टर्स थे, उनके लिए यह मानकर कि हमने उनको पूर्व सूचना दे दी है, यह टेन्डर इन्वाइट कर लिया गया।

यह क्यों ऐसा होता है यह भी मैं आपको बताऊँगा। जब कि ऐसा नियम है कि नोटिस के १५ दिन के बाद टेन्डर इन्वाइट किया जावे पर इस मामले में, इस स्टेज में खास तोर से तीन दिन का नोटिस दिया गया। ऐसा भी नियम है कि कन्ट्रेक्टर्स एसोसियेशन (Contractors' Association) के पास भी सूचना भेजी जावे पर सूचना उसको भी नहीं भेजी गई और आखिर में भेजी भी गई तो तीस तारीख को। २७ तारीख को टेन्डर इन्वाइट किये और सूचना देते हैं तीस को। अर्थात् यह सूचना भी केवल नाम मात्र के लिए थी कि कोई इत्तला नहीं देने का इल्जाम नहीं लगा सके कि हमारे पास इत्तला नहीं मिली। तीस तारीख को इत्तला भेजी। इसका नतीजा यह होता है कि किसी ने कोई टेन्डर नहीं भेजा, इत्तला नहीं हो सकने से कोई टेन्डर भेज नहीं सका और एक कम्पनी है मैसर्स जे. मोहन एण्ड को, उसने टेन्डर भेज दिया। दूसरों को न तो किसी को सूचना मिली और न इसी

[श्री भैरूँसिंह]

वास्ते टेन्डर भेज सके । लेट हो गये सब और इस कारण टेन्डर नहीं भेज सके। लेकिन एक मैसर्स जे० मोहन एण्ड कम्पनी थी उसने टेन्डर दे दिया। लेकिन ठेके के अनुसार एक आदमी को ठेका नहीं दिया जा सकता। उस लेने वाले को पार्टी बनानी पड़ती है। इस कारण सरकारी अधिकारियों से मिलकर और दूसरे आदमियों को मिलाकर उसने एक नई पार्टी स्थापित की और उसका नाम रख दिया राजस्थान इन्जीनियर्स।

लेकिन अध्यक्ष महोदय, एक बात और है इसमें। जब तक ठेकेदार का रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता है तब तक वह टेन्डर देने का हकदार नहीं हो सकता, और अगर दे भी तो उसका टेन्डर स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह विचार करने का सवाल है और इसमें एक-एक ठेकेदार को रजिस्ट्रेशन कराने में दो-दो ढाई-ढाई महीने लग जाते हैं, यहाँ तक कि छः-छः महीनों तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाता। लेकिन आश्चर्य तो यह है कि टेन्डर का नोटिस जारी करने के बाद तीन दिन में ही टेन्डर मन्जूर करने से पहले वह पाँच मिनिट में मैसर्स जे० मोहन एण्ड कम्पनी को राजस्थान इन्जीनियर्स के नाम से रजिस्टर्ड कर लिया गया और उसको एक रजिस्टर्ड पार्टी मान लिया गया।

तो इतना सब होने पर इसके आँकड़े अगर आप देखेंगे तो मालूम होगा, माननीय अध्यक्षजी, कि एक तरफ होता है २२० प्रतिशत पर काम, रोड का काम, और दूसरी साइड में उसी सड़क पर एक मोड़ पर एक ठेका दिया जाता है ३४० प्रतिशत के मुनाफे के हिसाब पर, ४०० प्रतिशत के मुनाफे के हिसाब से। इसमें इस विभाग के एक उच्च अधिकारी का पार्टनरशिप में काम कहा जाता है और इसी कारण इस तरह से ३२४ और ४०० प्रतिशत मुनाफे पर काम का टेन्डर चुपचाप दिया गया है। राजस्थान सरकार ने इस काम के लिए दो लाख चालीस हजार खर्च किये और यदि इसी पहले वाली सड़क को देखा जावे, जो आगरा से भंडारेज तक तैयार हो रही है तो उसमें भी प्रतिशत मुनाफा २७० है। इसी टेन्डर के द्वारा अगर देखा जावे तो सरकार का खर्चा ६० हजार का ज्यादा होता है। यह बचत हो सकती थी अच्छी तरह से, पर जिस ढंग से टेन्डर कॉल (call) किये गये, और जिस प्रकार से इसकी सूचना लोगों को दी गई उससे साफ जाहिर है कि सरकारी अधिकारी इसमें रुचि रखते थे। आज मैंने अभी-अभी सुना है कि इस मामले को लेकर माननीय निर्माण मन्त्री ने इस काम को रुकवाने के आदेश दिये हैं। पर अब तक तो इस पर हज़ारों रुपयों का खर्चा हो गया और इसके बिल भी सरकार को सम्बन्धित पार्टी द्वारा सबमिट (submit) कर दिये गये हैं और वे अब अवश्य ही मन्जूर होने वाले हैं।

मेरे निवेदन करने का मतलब यह है कि ठेकेदारों के जो रेट्स कायम किये जाते और जो ठेका उनको दिया जाता है, वह किसी एक नियम पर आधारित नहीं होता है। उनका कुछ काम नहीं देखा जाता, उनकी शक्ल देखी जाती है। उनका कुछ काम नहीं देखा जाता है, उनकी ईमानदारी नहीं देखी जाती है, केवल उनके पीछे का सपोर्ट (support) देखा जाता है। इस कारण से उनका सारा का सारा काम……

श्री अध्यक्ष—आप किस पर बोल रहे हैं ?

श्री भैरूँसिंह—मैं कटमोशन के सम्बन्ध में बोल रहा हूँ। मैं सिविल वर्क्स के बारे में बोल रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष--No general discussion. You should confine yourself to one particular cut motion.

श्री भैरूँसिंह—मैंने जो कटमोशन्स दिये हैं उन पर ही थोड़ा-थोड़ा बोल रहा हूँ। मैं एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, अध्यक्ष महोदय, बोल रहा हूँ।...

श्री अध्यक्ष—They have been time-barred, I have just declared.

The Hon'ble Member can confine himself to any of the cut-motions which have been moved. Those cut motions which were tabled have been rejected, the Hon'ble Member is not allowed to speak on those cutmotions.

कट मोशन्स पर बोलने की इजाजत नहीं है। जनरल डिबेट में इस तरह की बात कह सकते हैं at the time of the general debate·········

(श्री भैरूँसिंह बोलने के लिए खड़े होते हैं)

श्री अध्यक्ष—No, Order please !

श्री भैरूँसिंह—मुझे दो एक बातें और बतलानी हैं...

श्री अध्यक्ष--Order ! Order !!

श्री भैरूँसिंह—मैं समझता हूँ कि कट मोशन पर बोलने की इजाजत नहीं है...

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !! मैं यह स्पष्ट कर दूँ कि बजट की जनरल डिबेट जब होती है उसमें डिपार्टमेंटवाइज़, जैसा कि आपको समय दिया गया उसमें कर देना चाहिए, मगर प्रत्येक कट मोशन पर, किसी कट मोशन के सपोर्ट पर जब आप बोलें या जो कट मोशन लाया गया है उस कटमोशन के सपोट में बोलें तो उनको मूव करते वक्त जो आप क्रिटिसिज्म जिन रोड्स के बारे में, जिन बिल्डिंग्ज़ के बारे में हों उनके बारे में ही क्रिटिसिज्म करें। जनरल डिस्कशन आप अभी नहीं कर सकते।

(विराम)

This is not a Parliamentary way. I have been requesting and pressing the Hon'ble Members to come to Parliamentary methods of criticizing the Government.

श्री संतोषसिंह कछवाहा—माननीय अध्यक्ष, पी. डब्ल्यू. डी. की ग्रान्ट के ऊपर काफी चर्चा हो चुकी है। मैं इस डिपार्टमेंट के मुतआल्लिक ही कुछ बातें कहूँगा। अभी हाउस के अन्दर

[श्री सन्तोषसिंह कछवाहा]

ठेकेदारी पर काफी चर्चा हुई है । उसमें मुझे मालूम हुआ है कि माननीय सदस्यों को ठेकेदारी के मुतअल्लिक कुछ अनुभव नहीं है । पी. डब्ल्यू.डी. में जितना कुछ काम ठेकेदारों के ज़रिए से होता है वह सबसे जल्दी होता है और अच्छा होता है । अमानी पर जो काम किया जाता है, गवर्नमेंट को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है । गवर्नमेंट इस बात को जानती है । अमानी में कुछ महीनों पहले जो कि फैमीन का वर्क किया गया है तो १, १ मील के अन्दर ६०-६० हजार रुपया खर्च कर दिया और वह काम पूरा नहीं हुआ । अमानी तो केवल नाम मात्र की है । दरअसल में बेईमानी की गुंजाइश बहुत ज्यादा है । इसके लिए अगर आप बड़ा भारी प्रमाण चाहें तो मैं वह बता सकता हूँ कि जवाई बांध जो ५ साल से अमानी पर चल रहा है तो वह ५ साल में भी खत्म नहीं हो सका और अभी भी ५ साल तक खत्म नहीं कर सकते हैं । तो गवर्नमेंट को विवश होकर टेन्डर्स काल (call) करने पड़े और वह काम ठेकेदारों को दिया गया । माननीय अध्यक्ष, इसलिए जो कुछ भी माननीय सदस्य ने ठेकेदारी प्रथा के बारे में खयाल ज़ाहिर किया है, उससे महसूस हो सकता है कि उनको जानकारी वहाँ तक नहीं है । ठेकेदारों को ठेका देकर काम कराते हैं तो गवर्नमेंट को यह फायदा होता है कि उनका मज़दूरों पर कमान्ड (command) होता है । ठेकेदार सस्ते मज़दूर लाते हैं और अमानी पर जो काम होता है तो उनके इन्जीनियर्स और दूसरे आदमी होते हैं उनका मज़दूरों पर कोई कमान्ड नहीं होता है । वे मजदूरों से पूरा काम नहीं करा सकते हैं । यह जो व्यवस्था होती है उसकी जानकारी नहीं होने के कारण ही उन्होंने यह बतलाया है ।

दूसरा उन्होंने यह बतलाया कि इस डिपार्टमेंट के अन्दर भ्रष्टाचार बहुत है । इसके लिए मैं यह कहूँगा कि ऐसा कौनसा डिपार्टमेंट है जहाँ कि यह काम नहीं है । यह तो सभी जगह ऐसा होता हैं । सिर्फ यह अधिकारियों की कम देख-भाल के कारण होता है । माननीय सदस्य ने यह फरमाया कि सड़कें बहुत जल्दी टूटती हैं, बड़ी कच्ची बनती हैं । इसके लिए मैं कहूँगा कि सड़कों के ऊपर बड़ा हेवी लोड चलता है तो सड़कें कोलटार की बना दी जाँय तो सड़कें कभी भी नहीं टूटेंगी । इधर तो सड़कें बनती हैं और उधर १०-१० टन की लारियाँ चलती हैं । इसमें न ठेकेदार का कसूर है और न पी. डब्ल्यू. डी. का कसूर । कसूर गवर्नमेंट का है जो कि सड़कों पर डामर की व्यवस्था नहीं करती है या उसके लिए सेन्क्शन (sanction) नहीं करती है ।

माननीय सदस्य ने यह भी बताया कि सड़कों का जो पर्सेन्टेज है वह किसी जगह १२० पर्सेन्ट है और किसी जगह ३०० पर्सेन्ट हैं, तो इसके लिए मैं बताता हूँ कि एक जगह कन्क्रीट पास में मिलती है तो दूसरी जगह कन्क्रीट जब बहुत दूर मिलेगी तो अपने आप ही उस पर पर्सेन्टेज बढ़ जायगा । यह बातें जो ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ कही हैं उसके लिए निवेदन करूँ कि वह ठेकेदारों को ज्यादा जानते नहीं हैं । इसलिए माननीय सदस्य को चाहिए कि वे उनसे सम्पर्क रखें । और बस मैं इतना ही कहूँगा ।

श्री चाँदमल मेहता—इस सम्बन्ध में मेरे जो ४ कट मोशन हैं मैं उम्मीद करूँगा कि मुझे उनके हिसाब से टाइम दिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष—उन कट मोशन्स का कोई नियम नहीं है। जो कट मोशन्स मूव हो चुके हैं, जिनको एलाउ कर दिया गया है, उन पर आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।

श्री चाँदमल मेहता—मैं आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि किशनगढ़ की कुछ सड़कों के लिए रुपया रखा गया है, लेकिन उस रुपये का कितना उपयोग होता है इस ओर निगाह डालें तो यह मानना पड़ेगा कि उतनी रकम का मन्जूर होना या नहीं होना करीब-करीब एकसा ही है। यदि किशनगढ़ तहसील में किशनगढ़ से सिलोरा तक की सड़क को अगर आप देखेंगे तो यह पता चलेगा कि ठेके की शर्तों के मुताबिक बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। जहाँ सड़क के खुर्रे में खड़े पत्थर होने चाहिये थे उसके बजाय आड़े पत्थर लगाये गये हैं। जहाँ ४॥ इंच की गिट्टी होनी चाहिये थी वहाँ १ इंच, २ इंच, २॥ इंच तक ही गिट्टी डाली गई है, और गिट्टी के ऊपर मुरड़ डाली जानी चाहिये थी तो मुरड़ के बजाय गिट्टी डाली गई है। सड़क का अभी तक जितना हिस्सा बन चुका है उसको अगर देखा जायगा तो वह सड़क अभी से टूट गई है। मैं यह मानता हूँ कि एक साल से पहले ही वह सड़क पूरी की पूरी टूट जायगी। इसके सम्बन्ध में वहाँ के गाँव वालों के द्वारा कई प्रार्थनापत्र पहुँचाये गये कि सड़क कमज़ोर बन रही है। अधिकारी जाँच के लिए जाते हैं तो ठेकेदार उन अधिकारियों को किसी तरह से राजी कर लेता है और वह रिपोर्ट दे देता है कि सड़क का काम ठीक हो रहा है। मैं यह निवेदन करूँगा कि पैसे का जो अपव्यय हो रहा है उसकी जाँच की माकूल व्यवस्था की जानी चाहिए। इस तरह की सड़कों के खिलाफ जो शिकायतें हैं तो चीफ इन्जीनियर स्वयं उनकी जाँच करे कि आया किस तरह से सड़कों पर पैसा बरबाद होता है।

दूसरी ओर सड़कों के लिए जो रुपया स्वीकार किया है तो नई सड़कों में एक नई सड़क किशनगढ़ से अराई तक बनने की तजवीज है। यह तजवीज पहले थी किशनगढ़ से सरवाड़, बांया, अराई होते हुए। आज सरवाड़ जाने के लिए रास्ता अजमेर से नसीराबाद होकर है जिससे बड़ी कठिनाई होती है, बड़ा लम्बा रास्ता भी होता है। मैं यह निवेदन करूँगा कि अराई तक प्रोवीज़न रखा है तो उसके बजाय उसको आगे बढ़ाकर सरवाड़ तक कर दिया जायगा।

कुछ सड़कें जो किशनगढ़ सब डिवीज़न टेरिटरी में हैं उनकी मरम्मत नहीं हो रही है। उन सड़कों के मुताल्लिक जो सड़क अजमेर से देवली जाती है उसके अन्दर जितना हिस्सा सरवाड़ के पास आता है......

श्री कानसिंह—On a point of Order, Sir, वह कट मोशन के बारे में बोल रहे हैं या कहाँ-कहाँ सड़कें होनी चाहिये इसके बारे में?

श्री अध्यक्ष—Right. The Hon'ble Member will confine himself to the cut-motions which have been already moved and will not go beside them.

श्री चाँदमल मेहता— इस तरह सड़कों पर रुपया बरबाद होता है वह बरबाद नहीं हो इस तरह की व्यवस्था की जाय और जो रुपया मन्जूर किया जाय वह सही माने में खर्च हो, यही कहना चाहता हूँ।

श्री किशनलाल शाह—माननीय अध्यक्ष, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को दर असल में प्लंडर विदाउट डेन्जर (plunder without denger) कहा जाय तो शायद अनुचित नहीं होगा; क्योंकि इस डिपार्टमेंट का जब मैं कंपेरिजन (comparison) करता हूँ उस चतुर बनिये से, जो लेते समय अपने फायदे की दृष्टि से भाव और तौल अलग रखता है और देते समय भी अपने भाव और तोल अलग रखता है और दोनों ही तरफ से अपना फायदा करता है, उसी तरह से यह डिपार्टमेंट है। पहले इसमें एस्टीमेट्स बनते हैं और उसके बाद जब काम शुरू होता है तब शुरू से आखिर तक इसमें फायदा उठाते हैं। जब एस्टीमेट बनता है तो एस्टीमेट कुछ और होता है और असली खर्चा कुछ और तरह से होता है। और जब एक्चुअल एक्सपेन्डीचर (वास्तविक व्यय) की तरफ देखते हैं तो पता चलता है कि आखिरी बात क्या होती है। इसके बीच में कितने ही पावड़िये (सीढ़ियें) हैं। डिपार्टमेंट इटसेल्फ (स्वयं) और ठेकेदार और बीच के आदमियों का जो हिस्सा बँटता है उसके बाद लेबररर्स को कितने परसेन्ट जाता है इसका परिणाम जब देखते हैं तो मालूम होता है कि उनको बहुत कम मिलता है। यह एक साधारण बात है कि जो खर्चा होने वाला है और वह जिसके पास पहुँचने वाला है उसके बीच में जितनी ज्यादा सीढ़ियें होती हैं उतना ही ज्यादा भ्रष्टाचार होता है और मजदूरों को उतना ही नुकसान होता है। मैं सम टोटल (सारांश) में इतना ही कह कर हरदेवजी के कट मोशन का समर्थन करके आसन ग्रहण करूँगा लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि यदि उनको कुछ नहीं, मिलता है तो वे कहते हैं कि वर्क अकोरडिंग टू स्टेन्डर्ड (work according to standard) नहीं है, मिट्टी ज्यादा है, इतना ग्रेवल लगाना चाहिये, सीलिंग होगा, आदि बातें बताई जाती हैं और दूसरी ओर यह कहा जाता है कि जो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है उनकी जो गाड़ियें चलती हैं वे सड़क को खराब कर देती हैं इसलिए सड़क जल्दी ही खराब हो जाती है। इसका मतलब यह तो नहीं होना चाहिये कि ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट की गाड़ियें आदि उन पर चले ही नहीं। मैं मानता हूँ कि उनकी बात सही है। वे एक दूसरे की शिकायत करते हैं। जब ठेकेदार काम बन्द कर देते हैं तब यदि इन्क्वारी (जाँच) की जाय तो पता चले कि उन्होंने कितना मेटीरियल (material) इसमें लगाया है। दूसरी ओर यदि कोई उनकी शिकायत करने वाला कहीं पर होता है तो वहाँ पर वे काम शुरू ही नहीं करते फिर उनकी शिकायत हो भी तो कैसे? मुझ से, मेरे गाँव में एक पी. डब्ल्यू. डी. के एक जिम्मेदार पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि यदि वे शिकायत करते हैं तो हम उनकी माँग को ठुकरा देंगे। ये एक्च्युअल (वास्तविक) शब्द हैं जो मैं कह रहा हूँ। जहाँ पर इस तरह का पक्षपात होता है वहाँ भ्रष्टाचार का कारण होता ही है। तो मैं निवेदन करूँगा कि भ्रष्टाचार के साथ-साथ दूसरे परिणाम भी हो सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप पर जो होता है उसको भी खराब करते हैं, जनता के दिमाग को खराब करते हैं। इससे तो अमानी पर कार्य किया जाय तो ज्यादा अच्छा हो। हमारे यहाँ एक सड़क का छोटा टुकड़ा बना। ठेकेदार को ठेका दिया गया। ठेकेदार बाहर का था वह मजदूरों को अपने साथ अपने गाँव से लाया उससे लोकल मजदूरों को एक पैसे का भी फायदा हुआ हो ऐसा मैं नहीं मानता। अमानी पर काम चले तो भी खाने वाले तो अपना रास्ता निकाल ही लेते हैं। चाहे जितने कानून बना लें वे अपनी गुंजाइश तो निकाल ही लेते हैं। इसको मजबूती के साथ तय करना चाहिये अन्यथा इसका रिजल्ट प्लन्डर विदाऊट डेन्जर (plunder without danger) होगा और उसकी प्रतिक्रिया होगी।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष जी, मैंने इस डिपार्टमेन्ट के बारे में कुछ कटौती प्रस्ताव दिये थे लेकिन उनको आपने नामंजूर कर दिया है, इसलिये उन पर न बोल कर मैं थोड़े से समय में जो कटौती प्रस्ताव सामने हैं उनके बारे में आपसे निवेदन करूँगा। आज-कल हमारे यहाँ पर कॉन्ट्रेक्ट (Contract) देने की जो प्रणाली है वह बहुत ही गलत है। यह प्रणाली पहले से चली आ रही है और राजस्थान बनने के बाद भी इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ा। फर्क इतना सा जरूर पड़ गया कि कॉन्ट्रेक्टर्स को पहले हम जब जयपुर रियासत के समय में पी. डब्ल्यू. डी. के वर्किङ्ग को क्रिटिसाइज़ किया करते थे तब २० प्रतिशत हिसाब वेशी कॉन्ट्रेक्टर्स को देना पड़ता था; क्योंकि उनको वह रकम हमारे पी. डब्ल्यू. डी. के स्टाफ को देनी पड़ती थी। अध्यक्ष महोदय, जो बात मैं कह रहा हूँ वह सब को मालूम है, मिनिस्टर से लेकर प्रत्येक व्यक्ति को यह मालूम है कि पी. डब्ल्यू. डी. में जो कॉन्ट्रेक्ट सिस्टम है उसमें रकम बंधी हुई है और वह उस विभाग के ऊपर के आदमी से लेकर छोटे छोटे कर्मचारियों तक में बांटी जाती है। यह खुले आम है। वह रकम जो पहले २० प्रतिशत थी अब वह ४० प्रतिशत तक बन गई है। हम उम्मेद करते हैं कि हमारे नये मिनिस्टर साहब के हाथ में यह महकमा अब गया है इसलिये वे अब उसमें सुधार करेंगे। और कुछ नहीं हुआ तो मत्स्य के ४० प्रतिशत से घट कर जयपुर के २० प्रतिशत तो इसमें कमी जरूर होगी। इसकी रफ्तार तो कम जरूर होगी। (हंसी) इसमें हंसने की बात नहीं है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इसके लिये हम लोग आज तक कोई तरीका नहीं निकाल सके। यदि प्राइवेट में जाकर मिनिस्टरों से बातें की जांय तो कहते हैं कि यह बात है तो सच, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं कहा कि यदि ऐसा करते हैं तो उन पर चार्ज शीट (Charge sheet) लगाई जायगी और जांच करा कर सजा दी जायगी। मैं आपके सामने एक मिसाल पेश करता हूँ। हमारे यहाँ के आर्चीटेक्ट श्री परमानन्द हैं। वे प्राइवेट में काम करते हैं। जो गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट प्राइवेट में काम करते हैं उनके लिये यह कायदा है कि उस काम से जो उनको आमदनी होती है, उसका ५० प्रतिशत गवर्नमेंट में जमा कराना पड़ता था, लेकिन वे महाशय ऐसे हैं कि उन्होंने एक पाई भी खजाने में जमा नहीं कराई। यदि वे जमा कराते तो आज तक सरकार को लाखों रुपये का फायदा हुआ होता लेकिन ऐसा नहीं किया गया। लेकिन हमारे यहाँ के चीफ इन्जीनियर वगैरह सब उनसे मिले हुए हैं और उनको वे इसके लिये बाध्य नहीं करते कि वे ऐसा काम नहीं करें। इसके अलावा जब इस प्रकार की धांधलियां चीफ इन्जीनियर के डिपार्टमेंट में होती हैं तो उस चीफ इन्जीनियर को सस्पेन्ड करना चाहिये और उसको सस्पेन्ड करने के बाद जांच करें तो लाखों रुपया ही क्या, बल्कि सिविल वर्क्स के काम में जो पैसा रखा है उसका ४० प्रतिशत ऐसा होगा जो लोगों की जेब में जाता है, २० पर्सेन्ट ऐसा होता है जो कांट्रेक्टर की जेब में जाता है और बचे हुए ४० पर्सेन्ट से हमारी सरकार का काम होता है। जिस विभाग में इस तरह का काम होता है उसकी इन्क्वायरी होनी चाहिये और विभाग के अफसर को सस्पेन्ड करना चाहिये और उनको सस्पेन्ड करके यदि खुली जाँच करवाई जाय तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कई कॉन्ट्रेक्टर्स ऐसे मिलेंगे जो आगे आकर सरकार की मदद करेंगे और यह मालूम हो सकता है कि यह डिपार्टमेंट किधर जा रहा है। अभी हमारे एक दोस्त ने एक मिसाल दी थी और उसमें यह फरमाया कि सामान कुछ दूर होगा, कुछ नज़दीक होगा, लेकिन उनको नहीं मालूम की दोनों जगहें एक समान हैं, फिर भी इतना बड़ा फर्क हुआ। सामान को छोड़ दीजिये। एक रजिस्ट्रेशन का मामला चीफ इन्जीनियर के सामने आता है; छः महीने होने पर भी उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं और दूसरा उनका ही एक आदमी जाता है

[श्री मानसिंह महार]

जिसका रजिस्ट्रेशन ५ मिनिट में हो जाता है। इसमें पक्षपात की बात नहीं है तो क्या है ? एक तो ५ मिनिट में रजिस्ट्रेशन को पूरा करा लेता है और दूसरा छः महीनों में भी नहीं करा पाता। मेरे पास और भी कई मिसालें मौजूद हैं, लेकिन मैं अधिक नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे इजाजत नहीं देंगे। इस डिपार्टमेन्ट में रिश्वतखोरी इतनी बढ़ गई है कि उसकी कोई हद नहीं है। हमारे नये मन्त्रीजी यहाँ मौजूद नहीं हैं फिर भी मैं आशा करूँगा कि वे इसमें सुधार करेंगे और इस बात की ओर जरूर ध्यान देंगे और हम लोगों ने जो छोटे मोटे ओब्जेक्शन्स उठाये हैं उनकी जाँच करेंगे। हम जो कहते हैं उसको यह नहीं समझा जाय कि केवल क्रिटिसिज्म के नाते कहते हैं। इससे सरकार का लाभ होगा और हमारे मन्त्रियों का मान और उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

मैं नहीं मानता कि हमारा एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट किसी गरीब ओवरसियर को २५) रुपया लेते पकड़ लेता है, किसी चपरासी को ५) रुपया लेते पकड़ लेता है। अगर राजस्थान सरकार के मन्त्री महोदय यह बतायें, चीफ इन्जिनियर को पकड़ें, जो ५०, ५०, हजार रुपया रिश्वत लेते हैं, उनको पकड़ कर राजस्थान के समक्ष आदर्श उपस्थित करें, तो हम मानेंगे कि यह सरकार वाकई में पोपुलर गवर्नमेंट है। यह एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें करप्शन बहुत ज्यादा है, इसलिये अवश्य जाँच होनी चाहिये।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—मुझे, माननीय अध्यक्ष, इस पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के मुतल्लिक एक छोटी सी शिकायत है। इस पर अगर माननीय मन्त्री महोदय या पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ध्यान देंगे तो उनको कोई दुविधा भी नहीं होगी। जैसा कि सबको मालूम है बीकानेर का जिला एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आम तौर से बरसात बहुत कम होती है और पीने का पानी भी, ईश्वर ने ऐसी विधि रचा है, खारा है, ज़हरीला भी है और अच्छा भी नहीं है इसलिए बीकानेर के निवासियों ने या बीकानेर की सरकार ने जहाँ कुओं की सुविधा नहीं हो सकती थी वहाँ आदमियों के पीने के लिए और जानवरों के पीने के लिए बड़े-बड़े तालाब खुदवाए थे। क्योंकि ईश्वर की कृपा ऐसी ही रही है, बरसात भी वहाँ कम होती है इसलिए तालाबों में कम बरसात से भी पानी आ जावे, पाँच-पाँच, दस-दस माइल से तालाबों में पानी आ जाय और पाँच छः महीनों तक तालाबों में पानी रह सके इसलिए ड्रेन्स वाटर चेनल्स बनाई हुई हैं। पिछले चार पाँच वर्षों से, जब से कि राजस्थान बना है, राजस्थान सरकार की बीकानेर पर विशेष कृपा रही है और जब से राजस्थान बना है तब से बीकानेर में वर्षा भी कम हुई है। फिर भी पिछले वर्ष में काफी अच्छी वर्षा हुई। गत वर्ष तालाबों में से लोगों ने मिट्टी भी निकाली थी और आशा लगाई थी कि साल दो साल के लिए पानी का अच्छा बन्दोबस्त हो जायगा। किन्तु पिछले दो तीन साल में राजस्थान सरकार की ओर से ऐसी व्यवस्था बना दी गई कि तालाबों में पानी लाने के लिए ड्रेन्स वाटर चैनल्स बनाये हुये थे वे किसी की मिल्कियत नहीं रहीं। बीकानेर में पी. डब्ल्यू. डी. का महकमा है। वहाँ उनसे पूछ ताछ करने पर मालूम हुआ कि चेनल्स का काम उनके नीचे नहीं रहा, शायद इरिगेशन के नीचे चला गया है। नतीजा यह हुआ कि उन चेनल्स की हालत यह हो गई है कि वर्षा कितनी ही क्यों न हो उन तालाबों में एक बूंद भी पानी नहीं पहुँचे। मगरा में पिछली वर्षा

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

के समय तालाब दो तीन दफा भर जाना चाहिये था पर एक बार भी जरा भी नहीं भरा। इसका कारण साक्षात यह है कि जो चेनल्स पाँच-पाँच, दस-दस माइल से पानी लाती थीं वह मिट्टी से भर गई हैं या कंकर ले जानेवाले ऊँट वालों ने खोद कर उन्हें ऐसा निकम्मा बना दिया है कि उन चेनल्स में पानी चल ही नहीं सकता। पिछले वर्ष, यही कारण है कि वर्षा अच्छी हुई फिर भी पानी का अकाल ही रहा। जब हमने एग्जीक्युटिव इन्जीनियर, पी. डब्ल्यू. डी. से इस बात की शिकायत की तो उन्होंने कहा कि हमारे बजट में ऐसी कोई रकम नहीं रखी गई है। उनसे पूछा तो मालूम हुआ कि इर्रिगेशन महकमे के नीचे यह काम चला गया है। बीकानेर में इर्रिगेशन का तो काम हो ही क्या सकता है ?

श्री सोहनलाल भटनागर—On a point of order, Sir, on what cut motions is the Hon'ble leader of the Opposition speaking ?

श्री अध्यक्ष—आप (कुँ० श्री जसवन्तसिंह) कोन से कट मोशन पर बोल रहे हैं ?

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—मैं सिविल वर्क्स पर बोल रहा हूँ। अगर आपको (सोहनलाल की ओर इशारा करते हुए) एतराज हो तो मैं नहीं बोलूँ। चाहे किसी मन्त्री महोदय के अधीन में यह काम हो पर बीकानेर के लिये यह एक बहुत आवश्यक काम है। बीकानेर जैसे पानी की कमी के क्षेत्र में पानी का सवाल आदमियों की जिंदगी की कीमत का सवाल है, मैं तो इसे कुव्यवस्था का ही परिणाम समझता हूँ कि एक ऐसी छोटी सी चीज़ को इतना झगड़े में डाल दिया है। मैं आशा करता हूँ अपनी सरकार से कि इस चीज़ पर विचार करके खयाल करें और जो एक आसान चीज़ थी वह बीकानेर के लिये बड़ी समस्या बन गई है। मुझे आशा है कि सम्बन्धित मन्त्री महोदय इस ओर अवश्य ध्यान देंगे।

श्री अध्यक्ष—Reply.

श्री हरिकृष्ण व्यास—No, Sir, I have to.........

श्री अध्यक्ष—Your name was called and you were absent.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am supporting the cut motion.

श्री अध्यक्ष—No, Order !

श्री हरिकृष्ण व्यास—Is there a procedure to call names of those Members who support cut motions also ?

श्री अध्यक्ष—You were absent and you cannot question the proceedings which took place in your absence.

Page No.47

श्री हरिकृष्ण व्यास—Please listen to me.

श्री अध्यक्ष—Order, please!

श्री हरिकृष्ण व्यास—I want to raise a point of order.

श्री अध्यक्ष—No, Order!

श्री हरिकृष्ण व्यास—I want to raise a point of order.........

श्री अध्यक्ष—Yes.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I want to know when a member wants to support a cut motion already moved, then can his name be called out? If he wants to move the cut motion, I can understand his name being called.

श्री अध्यक्ष—He had a right to move the cut motion but if the cut-motion was time-barred, and if he wanted to support a cut motion which is moved, then his name was called. But since then he was not present he had no right to speak again.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I want to know......

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, मैंने एक कट मोशन २१ तारीख को दिया था। मैं समझता हूँ कि वह टाइम पर था। मैं कभी का इन्तजार कर रहा था कि मुझे इत्तिला कर दी जायगी। अब १० बजकर २५ मिनिट हो गये हैं, तो पूरे दो दिन निकल गये पर; मुझे क्यों टाइम नहीं दिया गया?

श्री अध्यक्ष—I am sorry.

श्री हरिकृष्ण व्यास—What is the ruling on this point?

श्री अध्यक्ष—Order!

श्री हरिकृष्ण व्यास—It is.....

श्री अध्यक्ष—Order!

श्री हरिकृष्ण व्यास—Let me have a say.....

श्री अध्यक्ष—Order! If the Hon'ble Member was so particular about speaking, he ought to have stayed in the House. When his name is called and he was not present, he is deemed to have waived his right.

श्री हरिकृष्ण व्यास—But when a particular member has not moved the cut motion....

श्री अध्यक्ष—It was not a question of moving. It was a question of giving opportunity to speak.....

Page No.48

श्री हरिकृष्ण व्यास—And I waived that opportunity......

श्री श्रीदास गोयल—This is indiscipline. When the Hon'ble Member is being .....

श्री हरिकृष्ण व्यास—You give me a ruling. I want to know clearly.

श्री अध्यक्ष—That is clear. I do not want to repeat.

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of order, Sir.........

श्री अध्यक्ष—Order ! You will come to order in the House.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Speaker, Sir.........

श्री अध्यक्ष—You want to create disturbance and indecency in the House ? If you have any grievance you can come and discuss with me in the Chamber.

श्री हरिकृष्ण व्यास—But what is the ruling, Sir ?

श्री अध्यक्ष—I have given the ruling.

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of order, you have not given your ruling.

श्री अध्यक्ष—I have given the ruling. There is no point of order......

श्री हरिकृष्ण व्यास—But on my point of order no ruling has been given.

(सदन में भारी हलचल)

श्री अध्यक्ष—I call you to order.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am holding the floor.

श्री अध्यक्ष—Order !

(श्री हरिकृष्ण व्यास बैठ गये)

श्री हरिकृष्ण व्यास—(पुनः खड़े होकर) Having obeyed the order......

श्री अध्यक्ष—Order !

श्री हरिकृष्ण व्यास—Have I no right to raise a point of order ?

श्री अध्यक्ष—When the Hon'ble Member has been given order, this is most undesirable.

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of order, Sir......

श्री अध्यक्ष—I have listened to your point of order and given my ruling on it. Order! You have no right to speak now. This is the ruling on this point. When once an Hon'ble Member is called and he is not present, he is deemed to have waived his right and he has no right to speak again.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I want to know the ruling on another point of Order.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—The Hon'ble Member should keep to order.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का सदन के अन्दर वातावरण हो रहा है उसे देखते हुए कोई न कोई स्ट्रोंग कार्यवाही की जानी चाहिये। इस प्रकार की नीति सदन के लिये शोभाजनक नहीं है; इसलिये मैं आपसे निवेदन करूँगा कि चेयर इस सम्बन्ध में अपना निश्चित निर्णय दे।

श्री अध्यक्ष—I want to make it once more clear to the Hon'ble Members that it is none of my intention to curtail the right of discussion, but when the Members have moved their cut motions and a decision has been given that they are time-barred, and if they have to say something when they are called on the floor of the House, and when they are not present, they have no right to speak again on the floor of the House regarding the same demand. This is the ruling which I have given clearly and the Hon'ble Members should......

(राज्यपक्ष की ओर से भारी करतल ध्वनि)

श्री हरिकृष्ण व्यास—But my point of order is different.

श्री अध्यक्ष—Order!

श्री हरिकृष्ण व्यास—My point of order is this......

श्री अध्यक्ष—Then let me hear your point of order.

श्री हरिकृष्ण व्यास—My point of order is this, Sir, that if a Member does not want to exercise his right of moving a cut-motion, of course if he wants to move the cut motion and is called, and if he is absent, then of course he loses that right; or if he does not want to exercise his right of moving the cut motion, that is rejected; but if he wants to make a submission on the cut-motion which is already moved and is under discussion on the floor of the House, whether he is to be called out or it is necessary for him to speak at a particular stage or

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

whether at any stage during the discussion he can avail of this right ? That is my question.

(सदन में पुनः भारी शोर)

(क्रम में) My point is whether any Hon'ble Member of this House can at any stage rise to speak on a cut-motion which is already the subject-matter of discussion ? This is my point, Sir.

श्री अध्यक्ष—I think I need not observe again. My ruling is very clear and I think it must satisfy the Hon'ble Member. The point is very clear. There was no question of the Hon'ble Member being given an opportunity to speak on a cut motion which is already rejected. It was for the particular Member to take opportunity to speak on a cut motion which is already moved. If he had desired to support any cut motion, his name was called and when he is not present it was deemed to have waived his right.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Speaker, Sir......

श्री अध्यक्ष—I do not want any more discussion on this point which is clear. He has no right. As a matter of right, he has no right to speak again, to exercise his right again.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I want a ruling on......

श्री अध्यक्ष—That is the ruling.

श्री हरिकृष्ण व्यास—My point is different......

श्री अध्यक्ष—Order !

(राज्य-पक्ष की ओर से 'Order-Order' की ध्वनियें)

श्री अध्यक्ष (क्रम में)—If you have anything to say, you cannot disturb the proceedings of the House.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I want one point......

श्री अध्यक्ष—Order !

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—(अश्रव्य)

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of order, Sir......

Page No.51

श्री अध्यक्ष—There cannot be any point of order when the proceedings are going on.

श्री भैरूसिंह (वि० सं० १६)—On a point of order, Sir.........

श्री अध्यक्ष—You should keep patience. There cannot be any point of order in a suspense when the proceedings of the House are going. Order !

श्री भैरूसिंह—माननीय अध्यक्ष, यह माननीय सदस्यों के विशेषाधिकारों का प्रश्न है, अतः.........

श्री अध्यक्ष—You will keep patience. I am the saviour of all the privileges of the House.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Am I not entitled to receive any clarification ?

(श्री भोलानाथ, सार्वजनिक निर्माण मन्त्री, से)

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !! Reply.

(श्री भोलानाथ खड़े हुए)

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में...

एक माननीय सदस्य—Mr. Speaker, Sir, the Hon'ble Member wants to create disorder in the House.

(श्री हरिकृष्ण व्यास के खड़े रहने पर)

श्री अध्यक्ष—I have given the possession of the floor of the House to the Hon'ble Member (Shri Bhola Nath). If the Hon'ble Member (Shri Vyas) cannot keep order, he will please withdraw.

श्री हरिकृष्ण व्यास—No.

श्री अध्यक्ष—You will please withdraw if you cannot......

श्री हरिकृष्ण व्यास—Can I not seek clarification ?

श्री अध्यक्ष—If you wish to seek clarification, you can come and discuss with me in the chamber.

श्री हरिकृष्ण व्यास—It concerns the immediate proceedings of the House, Sir.

Page No.52

एक माननीय सदस्य—This is rather.........

श्री अध्यक्ष—You (Shri H. K. Vyas) will come to order. If you cannot, you will please withdraw.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am prepared to withdraw, but I want clarification before I withdraw. I will ask you to......

श्री अध्यक्ष—If you have any point of order, I have given the ruling

श्री हरिकृष्ण व्यास—That is another question.

श्री अध्यक्ष—This is another disgrace of the House that when the Speaker is on his legs the Member dares persistently standing.

श्री हरिकृष्ण व्यास—But then the point if you hear is......

एक माननीय सदस्य—Because he is interrupting each and every moment...

श्री अध्यक्ष—I have given possession of the House to the Hon'ble Member (Shri Bhola Nath). Order !

(राजपक्ष की ओर से पुनः 'Order, Order' की ध्वनियें)

श्री हरिकृष्ण व्यास— Another point of order.

राज्यपक्ष के माननीय सदस्य—Persistently disobeying......

श्री अध्यक्ष—Keep paitence please.

श्री वेदपाल त्यागी—क्या उनका फर्ज है कि वे सदस्य को बैठने के लिये कहें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—Supporting the Chair.

श्री अध्यक्ष—There should be no address to the Members in individual. Everything should be addressed to the Chair.

(विरोधी पक्ष की ओर से करतल-ध्वनि)

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of Order, Sir.

श्री अध्यक्ष—Order !

श्री हरिकृष्ण व्यास—I rise to a point of order Sir.

श्री अध्यक्ष—Order !

श्री हरिकृष्ण व्यास—I rise to a point of order.

श्री अध्यक्ष—Order !

Page No.53

श्री हरिकृष्ण व्यास—My point of order......

श्री अध्यक्ष—Your point of order has been decided. If you are not satisfied......

श्री हरिकृष्ण व्यास—Another point of order.

श्री अध्यक्ष—There cannot be another point of order itself in a vacuum.

श्री हरिकृष्ण व्यास—It is concerning the immediate proceedings of the House.

श्री श्रीदास गोयल—When you have given a ruling . ...

श्री अध्यक्ष—I will have to call the Sergeant-at-Arms if you do not obey the orders of the Chair.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Then do I take it that we cannot.....

श्री अध्यक्ष—Order ! You will either withdraw from the House or I will call my Sergeant-at Arms.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Yes. But do we take it that we cannot......

श्री अध्यक्ष—No more discussions are allowed. I want no discussion on my ruling.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Do we take that the point of order......

श्री अध्यक्ष—No point of order in the vacuum.

(श्री हरिकृष्ण व्यास फिर भी खड़े रहे।)

श्री अध्यक्ष—I hereby order that Mr. Harikrishna Vyas should withdrawe from the House.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Until my point of order is permitted to be raised, I am afraid I will not have to agree to this decision.

श्री अध्यक्ष—I will have to call the Sergeant-at-Arms.

श्री हरिकृष्ण व्यास—You can call. I have a right to raise a point of order.

श्री अध्यक्ष—There cannot be any point of order in a vacuum. I have given a ruling on that. If you are not satisfied you can come and discuss with me in the Chamber. I have repeated so many times that I will not face any discussion in the House.

श्री वेदपाल त्यागी—अध्यक्ष महोदय, जब पोइन्ट ऑफ आर्डर रेज् किया जाता है तो पहले उसको सुन लिया जाय। जब कि श्री हरिकृष्ण व्यास अपना दूसरा पोइन्ट ऑफ आर्डर रेज़ (raise) करना चाहते हैं तो उसको अवश्य सुना जाय।

श्री अध्यक्ष--The Hon'ble Member has seen that I have given a ruling on his point of order. He is watching the proceedings of the House and in a way he is obstructing the House. I think the Hon'ble Members will maintain the dignity and decorum of the House. I, appeal to all the Members of the House to observe decency and decorum of the House If the Hon'ble Member will come to order, I will permit him to say.

श्री हरिकृष्ण व्यास--I want to raise another point of order, unless it is clarified......

श्री अध्यक्ष--Order !

(राज्य पक्ष की ओर से पुनः 'Order Order' की ध्वनियें)

श्री हरिकृष्ण व्यास--It is no use getting excited. I have a right to rise at any stage.

श्री अध्यक्ष--Please state your point of order.

श्री हरिकृष्ण व्यास--My point is this. Whether without a member having givun notice of moving any motion, how his name is called out under the rules ? When he has not given notice of his intention to make any motion how his name can be called and under what rules ? That is my point of order ?

श्री अध्यक्ष--From the cut motions which were moved and time-barred, the Speaker can take notice that if the Members want to speak, apart from these cut motions which have been rejected, he can speak. and when his name is called and he is absent, then he waives his right to speak on any other cut motions which have been rejected. This is my ruling. No Member, unless the Speaker permits him, has any right to speak on the floor of the House other than this.

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, इस डिमान्ड के बारे में ५-६ कट मोशन्स आये हैं उनमें से पहली बात जो बाडमेर के बारे में रखी गई थी वह इस बात की कमी को बताते हुए रखा था कि वहाँ पर सड़कें बिल्कुल नहीं हैं हालाँकि वह बहुत बड़ा एरिया है, उसकी आबादी लगभग ४ लाख के करीब है। इस सम्बन्ध में सदन की जानकारी के लिए यह निवेदन करना चाहता हूँ कि बाडमेर कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं जिसमें कोई काम सिविल वर्क्स का चालू न किया गया हो। अलबत्ता जो काम चल रहे हैं उनमें से कई ऐसे हैं जो बहुत पहले शुरू किये जा चुके थे। लेकिन जो काम आगे करने के तजवीज है मैं उनके इत्मीनान के लिए बताना चाहता हूँ कि—

[श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)]

(१) १ लाख रुपये में एक सड़क बाड़मेर से सिंदड़ी तक।

(२) १ लाख २५ हजार में बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के बोर्डर से जैसलमेर को जोड़ने के लिए सड़क बनाई जायगी।

(३) १ लाख से बाड़मेर से गडरा रोड तक सड़क।

(४) १ लाख से बाड़मेर से चितलवान तक सड़क।

इस प्रकार ४३ वें मील पर और खर्च किया जाने वाला है।

डिस्ट्रिक्ट के महत्त्व को देखते हुए जो रकम खर्च की जा रही है उस रकम से माननीय सदस्य को सन्तोष होगा। हरेक डिस्ट्रिक्ट में कुछ न कुछ कमी आपको अवश्य दिखाई देगी; क्योंकि राजस्थान इतना बड़ा प्रदेश है कि ५ करोड़ रुपयों में कोई बहुत बड़ा काम दिखने वाला नहीं है। कई जगह पर काम शुरू करवाना चाहते है, लेकिन कहीं पर पानी की फेसिलिटी (facility) नहीं होती तो कहीं पर पत्थर नहीं मिलता। हर जगह कुछ न कुछ कमी अवश्य दिखाई देती है। बाडमेर के इलाके में सड़क बनवाते हैं तो वहाँ पर ५०–६० हजार रुपये प्रति मील खर्च आता है। जहाँ पर पहाड़ नजदीक है, पानी भी नजदीक है वहाँ पर बीस हजार फी मील खर्च आता है इसलिये जो भी काम वहाँ होता है वह कम दिखाई देता है।

दूसरे कट मोशन के ऊपर श्री हरिदेव जी ने यह सुझाव दिया है कि ठेकेदारी की प्रथा बिल्कुल समाप्त कर देनी चाहिये। मैं सदन की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि पी. डब्ल्यू. डी. का काम दोनों तरह से होता है लेकिन आज यह हालत नहीं कि डिपार्टमेंटल काम हम इतना बढ़ा दें कि जिससे यह ठेकेदारी प्रथा बिल्कुल समाप्त हो जाय। आज की हालत में यह सम्भव नहीं। दूसरी बात यह है कि ठेकेदारी प्रथा का राजस्थान में ही कटु अनुभव नहीं बल्कि भारत सरकार भी इसका कटु अनुभव कर चुकी है। माननीय सदस्य ने जो मद्रास का हवाला दिया वहाँ यह प्रयोगावस्था में है। जहाँ पर भी प्रोजेक्ट्स आदि पर काम करने का सवाल है वहाँ पर पब्लिक की मदद से काम शुरू किया जाता है, जनता द्वारा काम शुरू करने पर पचास फीसदी लेबर की सहायता हमको मिल सकती है। जहाँ पर पब्लिक का लेबर मिल जाता है वहाँ पर नियन्त्रण भी पब्लिक का हो जाता है तथा वहाँ पर रुपया बरबाद होने की कोई संभावना भी नहीं रहती। जहाँ पर छोटे-मोटे काम करने होते हैं वहाँ पर डिपार्टमेंट ही काम करता है। ठेकेदार जो होते हैं वे अपने साथ लेबर रखते हैं, यह जरूरी बात है। हर जगह काम करना शुरू हो वहाँ पर उनको लेबर मिल जाय तो उनको भी इसमें फायदा रहता है लेकिन टेक्निकल काम के लिए तो उनको अपने लेबर रखने पड़ते हैं। ठेकेदारों को जो काम दिया जाता है वह अपने साथ एक खास प्रकार की लेबर रखते हैं, उस काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वे स्थानीय लेबर की भी मदद लेते हैं। स्थानीय मजदूर केवल सड़क पर पत्थर बिछाने के लिए ही काम में लिए जा सकते हैं, दूसरे टेक्निकल वर्क के लिए ठेकेदारों को अपने लेबर रखने पड़ते हैं। सड़क बनाने में केवल इतना ही काम नहीं कि पत्थर डाल दिए जाय

[श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)]

और सड़क तैयार हो जाय। पत्थर डालने के अलावा कई दूसरी बातें ऐसी होती हैं जिनमें कई प्रकार की तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसलिये ठेकेदार अपने लेबर ले जाते हैं, हालांकि वे स्थानीय लेबर से बहुत महंगे पड़ते हैं; फिर भी टेक्निकल वर्क के लिए उनको रखना पड़ता है।

बिल्डिंग के बारे में कहा गया, जो बहुत ठीक है। राजस्थान में अनेक रियासतें मिलीं; जहाँ बहुत सी जगह ईमारतें नहीं हैं, अच्छी-अच्छी रियासतों में भी इमारतें नहीं हैं। बीकानेर एक बड़ा राज्य था, जहाँ बड़ी रेलवे थी, नहरें थीं; लेकिन उसके चूरू जैसे बड़े शहर में कलेक्टर के दफ्तर के लिये भी जगह नहीं है। उदयपुर डिवीजन में लोकअप तथा तहसील हैडक्वार्टर आदि का कोई प्रबन्ध नहीं था। आज की स्थिति में यह संभव नहीं कि हरेक तहसील में हैडक्वार्टर की बिल्डिंग एक दम इतने सुन्दर ढङ्ग से बना दी जा सके जो कि आज की स्थिति में ठीक समझी जा सकती हो।

पहला ध्यान हम डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स की ओर दे रहे हैं। भीलवाड़ा और डूँगरपुर में मकानात बनवाने की तजवीज की गई है। अगर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स की बिल्डिंग ठीक तौर से बन जाती हैं तो स्वाभाविक तौर से दूसरा प्रोग्राम होगा। तहसील हैडक्वार्टर्स के लिए मकानात बनाने का; जिसमें लोकअप, अदालत, अस्पताल आदि सब हो सकते हैं। जब डिपार्टमेंट के पास कोई माँग आती है कि हमारे यहाँ यह काम होना चाहिये तो उसके लिए प्रायोरिटी डिपार्टमेंट फिक्स करती है। शुरू में उनको तरीके बताने के लिए पी. डब्ल्यू. डी. काम शुरू करता है। श्री भटनागरजी ने जिन कमियों को बतलाया, हॉस्पिटल की हालत के बारे में कहा उसके लिए डिपार्टमेंट के पास किसी तरह की माँग आयगी तो उन तकलीफों को अवश्य दूर किया जायगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग उस कमी को दूर करने की पूरी कोशिश करेगा।

रोड्स के जो प्रोग्राम बनाये गए हैं वे प्रकाशित कर दिये गए हैं, अगर इसमें कुछ कमी मालूम हो या कहीं पैसा कम खर्च हो रहा है; काम शुरू करने के बारे में जितने भी सुझाव आप दे सकते हैं दीजिये। सालाना जितना बजट जरूरी होता है रखा गया है। भारत सरकार की ओर से भी इमदाद दी जाती है, वह भी ध्यान में रखी जाती है और वह रुपया ठीक तरह से मिलता रहेगा और काम भी जल्दी से शुरू किया जा सकता है। जैसा कि अगले साल आपने देखा होगा भारत सरकार से रुपया मिलने वाला था, उसमें बहुत देर हो गई, सितम्बर में जाकर ५० लाख रुपया आया। बहुत सी जगह काम शुरू किया जा चुका था, फिर भी उन रुपयों का सदुपयोग किया गया। जल्दी में काम शुरू किया गया इसलिए कुछ प्रगति नजर नहीं आ सकी। यह जो पाँच करोड़ रुपया है उससे आप क्या यह सोच सकते हैं कि इनसे कोई चमत्कारिक स्थिति राजस्थान की हो जायगी? अभी हम सड़कों का जहाँ भी निर्माण करा रहे हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव शासन की सुविधा को ध्यान में रख कर खर्च किया जा रहा है। इन पाँच करोड़ रुपयों में गाँवों से तहसीलों को जोड़ा जाय, यह कदापि संभव नहीं। अभी तक तो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर को डिवीज़न हैडक्वार्टर से जोड़ा जा रहा है। अगर

[श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)]

पाँच करोड़ में यह काम पूरा हो गया तो दूसरे पंचवर्षीय योजना में दूसरे काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। इससे माननीय सदस्य को संतोष होगा।

इसमें कोई शक नहीं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की जो माँग है वह बहुत कम है, लगभग ५० लाख रुपया सड़कों की मरम्मत के लिए रखा है, उसमें से ६ लाख रुपया शहर की सड़कों के लिए अलग रख दिया गया है; इससे यह जरूर स्वाभाविक है कि सड़कों का काम देहातों में कमी जरूर होगा और उससे मेम्बर साहबान को असन्तोष भी हो सकता है किसी हद तक। किसी-किस इलाके में तो शहरों की हालत भी ऐसी हो गई है कि उसकी भी दुरुस्ती करना जरूरी था। पिछले साल भी शहरों की सड़कों को, जो ज्यादा खराब हो गई थीं, ठीक कराया गया और इस साल भी इनके बारे में सोचा गया है। पिछले दिनों शहरों में सड़कों की हालत बहुत खराब हो गई थी और लोगों ने भी इधर काफी सरकार का ध्यान खींचा और उनकी बिगड़ती हालत को देखते हुये सरकार ने भी उनका कुछ ध्यान रखा है। इसके बाद देहातों में विशेषरूप से ध्यान दिया जा सकता है।

इसी तरह से बिल्डिंग्ज़ के मेन्टेनेन्स (mintemance) के लिए भी रुपया दिया गया है, जो कि ६२ लाख रुपया है जब कि इसके लिए १ करोड़ चाहिये था। इसलिए यह दिक्कत पेश आती है कभी-कभी बहुत से मकानों की तो थोड़ी बहुत व्हाइट वाश (white wash) भी हो जाती है पर कुछ मकान जिनकी अच्छी तरह से मरम्मत होनी चाहिये वह नहीं हो पाती है। यह भी एक महत्वपूर्ण काम है; जिसकी ओर सरकार का ध्यान है, पर यह दिक्कत है जो महसूस की जा रही है।

फिर और भी डेवलपमेंट के काम भी चल रहे हैं। उनको ध्यान में रखते हुए और जो रकम हमारे पास है उसको ध्यान में रखते हुए अभी इस ओर अधिक रुपया लगाना सम्भव मालूम नहीं हो रहा है। जैसे-जैसे पैसा हमारे पास अधिक होता जावेगा और जब सम्भव हो सकेगा तो इस तरफ भी हम पूरा-पूरा ध्यान देंगे चाहे फिर वह रोड का काम हो, चाहे बिल्डिंग का हो।

नई बिल्डिंग बनाने का काम करने के लिए २३ लाख रुपये खर्च करने का सरकार का इरादा है। अगर यह हो जाता है तो निश्चित रूप से बहुत सी जगहों की कमियाँ पूरी हो जावेंगी। खास तौर से कुछ थाने भी बनेंगे, तहसील हैडक्वार्टर्स की बिल्डिंग्ज़ भी बनेंगी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के ऑफिस आदि-आदि भी बनाने का इरादा है और यह प्रोग्राम जल्दी से जल्दी पूरा होने की सम्भावना है और इसको न केवल राजस्थान सरकार बल्कि भारत सरकार भी काफी महत्व दे रही है और वह भी पैसा देने को तैयार है।

डूँगरपुर की एक सड़क के बारे में जिक्र किया गया। इसमें केवल ठेकेदार का ही कुसूर नहीं है। आजकल रिटों (writ) का बड़ा सवाल है। कोई भी मनमानी तरीकों से काम शुरू नहीं कर सकता। जैसे जंगलों का काटना है, पत्थरों को तुड़वाना है, चबूतरों को तोड़ना है; सब काम बाकायदा करने पड़ते हैं। जब ठेका दिया गया और जब सड़क बनने लगी तो कुछ सड़क बनने पर

[श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)]

म्युनीसिपैलिटी ने आगे उसे बनाने पर रोक लगा दी, इसलिए देर हुई पर इस देरी को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। मियाद भी उसे दी गई है पर किसी की भी तरफ से बाधा पड़ती है तो इसको ठीक करने का काम सब का ही हो जाता है, वह चाहे जनता हो, जनता की संस्था हो, सरकार हो या और कोई हो। इसके लिए केवल ठेकेदार ही सजावार नहीं हो सकता है। क्योंकि काम नहीं हो पा रहा है इसलिए उसको ही सजा दी जावे, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हमें यह भी देखना पड़ेगा कि वह काम किये जाने में किसकी ओर से बाधाएँ खड़ी की जा रही हैं और वे बाधाएँ पहले दूर करनी होंगी।

भांडारेज-लालसोट रोड के बारे में भी कहा गया। उसमें कहते हैं कि जल्दबाजी से टेन्डर लिया गया। तो इस बारे में तो पहले ही यह ऑर्डर दे दिया गया है कि इसे रिटेन्डर किया जावे। तो इस तरह कोई शिकायत आती है तो उस पर अवश्य ध्यान दिया जाता है और जिसकी कोई इन्क्वायरी (जाँच) करना बहुत जरूरी हो जाता है तो सरकार उस पर इन्क्वायरी भी कराती है और ऐसी सब शिकायतों पर जरूर ध्यान देती है और फिर यह तो इतना बड़ा डिपार्टमेंट है कि इसकी कई शिकायतें आनी स्वाभाविक ही हैं। पिछले साल भी बहुत शिकायतें आई थीं, सरकार ने उनकी पूरी-पूरी जाँच की हैं; किन्हीं पर केसेज़ भी हुए हैं, बहुत से सस्पेन्ड भी हुए हैं और बहुतों पर आवश्यक कार्यवाही भी की गई है। अगर माननीय सदस्य इस प्रकार की शिकायतों को न केवल भाषणों द्वारा बल्कि व्यक्तिगत रूप में भी रक्खेंगे तो ज़रूर उनको ठीक करने की कोशिश करूँगा।

आगे श्री परमानन्दजी के बारे में कहा गया कि वे प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और उन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस से रुपया मिलता है और वह रुपया चीफ इन्जीनियर के पास जमा कराना चाहिये। पर मैं माननीय सदस्य को निवेदन कर दूँ कि यह टर्म्स अगर उनकी सर्विस की कन्डीशन्स में है तो इसके लिए उनको मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर कन्डीशन करते समय ही उनके साथ में यह शर्त रख दी जाती तो यह कहना सम्भव था। पर जब तक उनकी सर्विस की कन्डीशन्स में यह बात है तब तक यह कहना कि वे प्राइवेट प्रैक्टिस से आने वाला रुपया चीफ इन्जीनियर के पास जमा करा दें, यह ठीक नहीं है और न कोई न्याय की बात है। हां, अगर ऐसा ही है तो आगे सर्विस की कन्डीशन्स किसी के साथ करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखा जा सकता है। मैं आशा करता हूँ कि इन सब बातों से आपको संतोष होगा।

श्री अध्यक्ष—Now we put the cut-motions to vote. Shri Tansingh.

श्री तनसिंह—क्योंकि माननीय मन्त्री महोदय ने बाड़मेर जिले में हमारी सड़क के लिए आश्वासन दिया है इसलिए मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की सदन से प्रार्थना करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री तनसिंह—मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री सोहनलाल भटनागर—I also beg leave of the House to withdraw my cut-motion.

श्री अध्यक्ष—Is it the wish of the House to allow leave ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री सोहनलाल भटनागर—I withdraw.

श्री अध्यक्ष—श्री हरिदेव।

(अनुपस्थित)

So I put his cut motion to vote. The question is that the cut-motion by Shri Harideo be accepted.

(अस्वीकृत)

The cut-motion fails.

(विराम)

The question is, "That a sum not exceeding Rs. 2,17,63,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1955, in respect of Grant No. XXV, Major Head 50—Civil Works etc."

(स्वीकृत)

The Demand is granted.

(विराम)

माँग संख्या १७—चिकित्सा

The motion is "That a sum not exceeding Rs. 1,28,35,000/- be granted to His Highness the Rajapramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1955, in respect of Grant No. XVII, Major Head 38—Medical."

(विराम)

Cut motion by Shri Khet Singh.

श्री खेतसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो अपनी कटौती प्रस्ताव इस जनहितकारी विभाग, स्वास्थ्य, पर रखा है उसका ध्येय यह है :

"To discuss the inadequacy of Ayurvedic out-posts in desert area of Rajasthan"

अध्यक्ष महोदय, सभी सदस्य इस बात को मानते हैं कि स्वास्थ्य मानव जीवन के लिए अत्यन्त आवश्यक है और उसकी हमारे जीवन में सबसे ज्यादा अहमियत है। उसको देखते हुए, जिस इलाके से मैं आया हूँ वहाँ पर सरकार ने इस ओर जो कदम उठाया है उसके मुतल्लिक मैं कुछ निवेदन आपके द्वारा श्रीमन् मन्त्री महोदय से करना चाहता हूँ। यह तीसरा वर्ष है जबकि हम इस सदन में फिर से बैठे हैं, लेकिन इन तीनों वर्षों में उस इलाके में एक भी आयुर्वेदिक अस्पताल अथवा एलोपैथिक डिस्पेन्सरी नहीं खोली गई हैं। रियासतों के जमाने में भी वह इलाका इतना पिछड़ा हुआ था कि वहाँ पर कदम इस ओर नहीं बढ़ाया गया था। राजाओं के वक्त में तो अधिकतर उनकी राजधानियों में ही ऐसे कार्य हुआ करते थे, और अपना यह राज्य, जन-हितकारी राज्य जब स्थापित हुआ तो हम यह उम्मीद करते थे कि अब जो पिछड़े हुए इलाके हैं उनमें कुछ कार्य अवश्य इस ओर अवश्य किया जायगा। लेकिन मुझे अफसोस है कि बार-बार इस सदन में हमारे मन्त्री महोदय से रिक्वेस्ट (प्रार्थना) की, लेकिन फिर भी आज तक कोई डिस्पेन्सरी उस इलाके में नहीं खोली गई है। माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा मैं सदन को यह बतला देना चाहता हूँ कि वह ऐसा इलका है कि जिसमें १०० मील के एरिया में जब एक भी आयुर्वेदिक अस्पताल नहीं है तो एलोपैथिक डिस्पेन्सरी होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस अरसे में अगर एक भी औषधालय वहाँ खोल दिया होता तो हमें कहने को कुछ जगह होती कि कम से कम एक औषधालय तो इस राज्य के स्थापित होने पर हुआ। जनरल डिसकशन में जो बतलाया है और ३५ नई आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरियाँ खोलने का आश्वासन जो दिया गया है उस पर भी मुझे ऐसा मालूम होता है कि उस इलाके में डिस्पेन्सरी खोलने का अभी प्रोवीज़न नहीं रखा गया है। हम तो यह उम्मीद करते थे कि इस विभाग के मन्त्री महोदय जो कि ग्रामीण तबके को रिप्रेज़ेन्ट (प्रतिनिधित्व) करते हैं, कुछ न कुछ वहाँ अवश्य करेंगे लेकिन फिर भी यह सुनकर बड़ा भारी अफसोस हुआ कि उन्होंने भी इस ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया है। मैं बहुत कम कहकर बैठ जाऊँगा और खास तौर से मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाऊँगा कि जहाँ १०० मील के एरिया में एक भी अस्पताल नहीं दिखलाई देता यह राजस्थान सरकार के लिए कोई अच्छी, प्रशंसनीय बात नहीं होगी। मैं इसलिये खड़ा हुआ हूँ कि मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे और ३५ डिस्पेन्सरियाँ जो इस वर्ष खुलने को हैं तो उस लिस्ट में कुछ इधर-उधर करके जहाँ २-३ डिस्पेन्सरियाँ खोली जाती है वहाँ एक ही खोल कर उस १०० मील के एरिया में एक डिस्पेन्सरी खोलने का तो अवश्य प्रयत्न करेंगे।

श्री अध्यक्ष—Next, Shri Abani Kumar.

श्री अवनिकुमार—(To discuss the increased expenditure under this Head) माननीय अध्यक्ष, मैंने जो कटौती प्रस्ताव रखा है वह सिर्फ स्पष्टीकरण के लिए रखा है। जब मैंने मेडिकल के बजट को देखा तो मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट के अन्दर रिज़र्व एस्टेब्लिशमेंट के नाम से एक

[श्री अवनिकुमार मुकर्जी]

प्रोवीज़न रखा है और जब मैंने रिज़र्व (Reserve) एस्टेब्लिशमेंट को देखा तो इसके अन्दर मैंने यह पाया कि ५३-५४ के अन्दर ३० सिविल असिस्टेन्ट सरजन रखे हैं और दूसरी ओर ५४-५५ के अन्दर ४३ सिविल असिस्टेन्ट सरजन का प्रोवीज़न किया गया है तथा ५३-५४ में ४३ कम्पाउन्डर का प्रोवीज़न था और ५४-५५ में ३२ कम्पाउन्डर का प्रोवीज़न किया गया है। मैंने यह जो कट मोशन मूव किया है वह यह जानने के लिए किया है कि यह रिज़र्व मेडिकल एस्टेब्लिशमेंन्ट का प्रोवीज़न क्यों रखा गया है और यह किस काम के लिए रखा है ? इसलिए मैंने सदन के सामने यह कटौती प्रस्ताव रखा है। मैं समझता हूँ कि सम्बन्धित मन्त्री महोदय इसका स्पष्टीकरण करेंगे। बस मैं सदन का ज्यादा वक्त नहीं लेता हूँ और इतना ही कहकर मैं बैठ जाता हूँ।

श्री अध्यक्ष—Next, Shri Jawan Singh.

श्री जवानसिंह—(To discuss unsatisfactory work and disaffection prevailing in the Department) माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा सरकार का ध्यान मैं इस पर आकर्षित करना चाहता हूँ कि सरकार की जो कुछ भी नीति राजस्थान के एकीकरण के पश्चात् रही है वह संतोषप्रद नहीं है और जितना फायदा सर्विसेज का, जनता का, हम करने की आशा लगाये हुए थे या जितना फायदा हम जनता का करना चाहते थे और सरविंसेज़ को संतोष देना चाहते थे वह हम इन ३-४ वर्षों में नहीं दे सके हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि बार-बार इस सदन में प्रश्न के रूप में तथा श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण के अवसर पर इस सरकार का ध्यान इस ओर जरूर आकर्षित किया गया है। इतने अरसे के बाद भी क्या वजह है कि अभी सर्विसेज़ का इन्टिग्रेशन नहीं हो पाया है और अफसोस की बात है कि बार-बार इस सरकार ने इस बात के लिए आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी ही मेडिकल सर्विसेज़ का एकीकरण होने वाला है और यह आश्वासन, यह वायदा इसी सरकार ने जब इस सदन का पहला सत्र हुआ था उस वक्त से और इस मौजूदा सदन में बराबर दिया जा रहा है; लेकिन माननीय अध्यक्षजी, अभी तक उस विषय में कोई कदम, जो कुछ भी लिया गया है मालूम होता है कि वह वापिस रिट्रेन्च (retrench) किया जा रहा है। माननीय मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध के महकमे के बदलते हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि उनके साथ-साथ सरकार की नीति भी बदलती जाती है। इस बात की मुझे जरूर आशा करनी चाहिये और मैं विश्वास रखता हूँ कि जो मौजूदा मन्त्री इस सम्बन्ध के महकमे के हैं वे अवश्य ही इस ओर बहुत जल्दी ध्यान देकर हमारी सर्विसेज़ का एकीकरण करेंगे।

इसके बाद मैं, हमारे बजट में जो प्रोवीज़न रखा है उनके बारे में आपका ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहूँगा। Statement of Demands for Grants and appropriation for the yea 1954-55 के अन्दर जो एक्सपेन्डीचर ओन मेडीकल (चिकित्सा पर व्यय) के तहत १,२८,३५,०००) रु० का प्रोवीज़न दिया गया है और जो डिटेल्स ऑफ एक्सपेन्डीचर दिया हुआ है उसके तहत नेट टोटल १,२४,००,०००) रु० का दिया हुआ है। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि

[श्री जवानसिंह]

४ लाख का अन्तर कैसे और कहाँ होगा जिसके लिए किसी तरह का कोई एक्स्प्लेनेशन नहीं दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि माननीय मन्त्री महोदय इस ओर अवश्य प्रकाश डालेंगे।

जहाँ तक मेडीकल सर्विसेज़ के एकीकरण का सम्बन्ध था मैंने आप से निवेदन किया। उस के साथ में, जहाँ तक कम्पाउन्डर्स का सवाल है उस विषय में भी सरकार की जो पक्षपातपूर्ण नीति होती जा रही है, उस तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करूँगा। ऐसा मालूम होता है कि २-३ महीने पहिले तो परिस्थिति इतनी गम्भीर हो गई थी कि एकाउन्टेन्ट जनरल के वहाँ से तनख्वाह लेने का सवाल था तो वह कुछ अरसे के लिए रोक दी गई थी। यह बात समझ में नहीं आती कि आज तनख्वाह को रोकने के लिए ऐसे ऑर्डर्स हो सकते हैं और जहाँ तक मालूम हुआ है उसकी वजह केवल यह बतलाई गई कि इतना अरसा होने के बाद भी अब तक उनका इन्टिग्रेशन नहीं हो पाया है और यह कहा कि जब तक स्ट्रिक्ट एक्शन (strict action) नहीं लेंगे उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी। इसको दूर करने के लिए जो रास्ता अपनाया गया वह शोभाप्रद नहीं है। वह तरीका यह था कि फिलहाल के लिए कम से कम दो सरकारी अफसर यह सर्टीफाई (certify) कर दें कि उन्होंने जो अपने इन्टिग्रेशन के लिए दरख्वास्तें दी हैं उनका अन्तिम निर्णय नहीं लिया है केवल इतना सर्टीफाइ करने से उनको तनख्वाह लेने का अधिकार दिया गया है। तो यह सरकार के लिए कोई शोभाप्रद चीज नहीं है कि एक डिपार्टमेंट की, पूरे के पूरे की तनख्वाह और खास तौर से उन छोटे-छोटे आदमियों के लिए जिनकी तनख्वाह कम्पाउन्डरों की तनख्वाह के बराबर है, उनकी तनख्वाह कम्पाउन्डरों के बराबर हो और खास तौर से क्लास फोर्थ सरवेन्ट्स की तनख्वाह, जिनकी तनख्वाह गवर्नमेन्ट के क्लास फोर्थ सरवेन्ट्स की तनख्वाह से कम है, उनकी बढ़ानी चाहिये। सरकार अपनी कमी पूरी करने के लिये ऐसा क्यों कर रही है?

अब इन बातों के अलावा कुछ बातें मैं सिरोही जिले के सम्बन्ध में आपके सामने निवेदन करना चाहता हूँ। वहाँ पर एक गम्भीर मसला बनता जा रहा है, इसलिये यह आवश्यक है कि इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करूँ। माननीय अध्यक्षजी, जब जोधपुर अस्पताल में कुछ वर्ष पेश्तर एक हड़ताल हुई थी जिसके कारण कई कंपाउन्डर्स को नोकरी से अलग कर दिया गया था और उसके बाद विस्तार से यह हुक्म जारी हुआ था कि उन विशेष आदमियों को नौकरी में नहीं लिया जाय; उन आदमियों में एक आदमी ऐसा है जो सिरोही में सी. एम. ओ. है उनका खास कृपा-पात्र है या कहिये कि उनका सम्बन्धी होने के नाते किसी तरह से यह हुक्म हुआ है कि वे फिलहाल अस्पताल में ट्रेनिंग लेने का काम करें। यह बहुत ही अजीब चीज है कि जो कंपाउन्डर जोधपुर के अस्पताल में १०-१२ साल तक काम कर चुका है और कंपाउन्डर नियुक्त था, वह आदमी सिरोही में आकर ३ महीनों के लिए ट्रेनिंग ले। यह सी. एम. ओ. का कृपापात्र होने के नाते रखा गया है। दुर्भाग्य इस बात का है कि मुख्य मन्त्री जी का हुक्म यहाँ पर पहुँच गया था कि ऐसा यदि कोई आदमी मौजूद है जो जोधपुर अस्पताल में रहा और जो २ साल नौकर रहा उससे कम भी हो सकता है, लेकिन जो वहां पर सर्विस से अलग कर दिया गया है, वह नहीं रखा जा सकता। बाहर से आकर इस आदमी को, केवल सी. एम. ओ. का कृपा पात्र होने के नाते, मुख्य मन्त्री के हुक्म को ताक पर रखकर, नौकरी दे दी गई, यह दुःख का विषय है।

[श्री जवानसिंह]

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि वहाँ पर एक्सरे काफी समय से बेकार पड़ी है क्योंकि वहाँ कोई डाक्टर यह काम करने वाला नहीं है। भूत पूर्व सिरोही राज्य के जमाने से एक्सरे और लेबोरेटरी ठीक तरह से काम कर रही थी और वहाँ पर स्पेशलिस्ट डाक्टर था, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि वर्षों से अब कोई ऐसा डाक्टर नहीं है जो एक्स रे और लेबोरेटरी का काम कर सके। इनको कोई देखता-भालता तक नहीं है और मौजूदा सी. एम. ओ. ने केवल लेबोरेटरी में अपना आदमी रखने के लिये वहाँ पर एक साहब को अपोइन्ट कर दिया है, लेकिन यह चीज़ इतने गलत तरीके से और सरकार के हुक्म की अदूली करके इस तरह से गलत की गई है कि कोई भी सरकार इस चीज को ठीक नहीं मान सकती और मैं आपको निवेदन करूँगा कि इस पर अच्छी तरह से ध्यान दिया जाय।

अस्पतालों की हालत के बारे में एक-दो शब्द निवेदन करता हूँ। वहाँ पर कालन्द्री में एक अस्पताल है लेकिन वहां कोई डाक्टर नहीं है और केवल कंपाउन्डर है। सरकार को जब डाक्टर भेजने के लिये कहते हैं तो जवाब देते हैं कि वहाँ पर मरीज़ नहीं जाते हैं। वहाँ पर कोई डाक्टर नहीं है और उस पर भी आप कहते हैं कि मरीज नहीं आते। डाक्टर न होने की हालत में मरीज़ कैसे आ सकते हैं? मरीज़ चाहते हैं कि उनका इलाज हो। फिर जनता कैसे आ सकती है। पिन्डवाड़ा में एक कंपाउन्डर को तनख्वाह मिलती है और वह काम करता है बागरा डिस्पेन्सरी में। तनख्वाह एक जगह से मिलती है उससे काम लिया जाता है दूसरी जगह पर, यह कैसी बात है? जिसको जहाँ तनख्वाह मिलती है उसको वहीं काम करना चाहिये। इस तरह की छोटी-छोटी बातें गंभीर विषय बनती जा रही

(श्री द्वारकादास पुरोहित, सभापति, पदासीन)

है। मैं माननीय सम्बन्धित मन्त्री जी से, आपके जरिये निवेदन करूँगा कि वे जल्दी ही इस बारे में उचित कदम उठावें।

श्री तनसिंह—(To discuss the inadequacy of medical relief provided in Barmer District) माननीय सभापतिजी, अभी शेरगढ़ से निर्वाचित होकर आनेवाले मेरे एक पूर्व वक्ता मित्र ने बताया था कि इस रेगिस्तान के इलाके में बहुत कम अस्पातल और बहुत कम औषधालय हैं; मैंने अपना कट मोशन एक स्पेसफिक एरिया के लिये दिया है। उसके बारे में मैं निवेदन करूँगा कि १० हजार वर्ग मील का बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है। उसमें दो अस्पताल बाड़मेर और बालोतरा में है। अभी हाल ही में सिवाना के लोगों ने आपस में चंदा करके डिस्पेन्सरी के लिये भवन का निर्माण कराया है और बाड़मेर की जनता ने भी चंदा करके स्त्रियों के लिये अस्पताल बनाया है। उनको अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिये कोई न कोई साधन ढूँढना पड़ता है और उनको पैसा देना पड़ता है। जितना पैसा देने के लिये सरकार टालमटोल करती है उतनी ही कठिनाई बल्कि उससे भी ज्यादा कठिनाई जनता को करनी पड़ती है, क्योंकि जनता की आमदनी के साधन इतने कम होते हैं कि उससे जीवन-निर्वाह करना कठिन हो जाता है और सरकार की आमदनी का साधन बहुत है और उसको केवल जन-हित के काम करने पड़ते हैं। तो १० हजार

[श्री तनसिंह]

वर्ग मील में केवल दो अस्पताल हैं और २ आयुर्वैदिक एड पोस्ट हैं; एक शिव में और दूसरा जसोल में ।

सरकार ने इस बजट में बहुत थोड़ी मेडिकल ऐड की रकम रखी है । सरकार का विचार इस साल ३५ नये अस्पताल खोलने का है । वह जरूरत को देखते हुए बहुत कम है । इसलिये मैं निवेदन करूँगा कि जो पिछड़े हुए इलाके हैं जहाँ सभी साधनों की कमी है, जैसा कि एक मित्र ने बताया था कि सड़क वहाँ इसलिये नहीं बनाई जा सकती कि वहाँ पर पानी की बहुत कमी है; लेकिन बीमारी के लिये न देश के सीमा की बाधा है और न किसी और चीज की । जयपुर में और बाहर भी लोग बीमार पड़ते हैं । अस्पताल खोलने में अन्य आवश्यक साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । जिन साधनों की यहाँ आवश्यकता है उन्हीं की वहाँ भी आवश्यकता होगी । आपने जो ३५ अस्पताल खोलने का विचार किया है या तो यह संख्या बढ़ावें और यदि नहीं बढ़ा सकें तो जो इलाका अब तक पिछड़ा हुआ है उसमें पर्याप्त मत्रा में अस्पताल खोलने का सरकार आश्वासन देगी, ऐसा मेरा विश्वास है ।

श्री वृजसुन्दर शर्मा—To discuss the inefficiency of the Head of the Department of Ayurvedic aud hampering the progress of the system of medicine) आदरणीय चेयरमेन, इस कट मोशन के ज़रिये मैं इस सदन का ध्यान आयुर्वेद विभाग की ओर ले जाना चाहता हूँ जहाँ इस विभाग में बहुत जबर्दस्त इनएफिशियेन्सी (inefficiency) है । इस शब्द से मेरा अभिप्राय विभागीय अध्यक्ष के लिये यह कहने का नहीं है कि वे अच्छे वैद्य नहीं हैं, अच्छा इलाज नहीं करते हैं; लेकिन मेरा मतलब उस ऐफिशियेन्सी से है जो इस विभाग के अध्यक्ष में होनी चाहिये । अध्यक्ष महोदय, साल भर से इस विभाग में जो गड़बड़ियें हो रही हैं उसकी ओर से मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । कुछ दिन पहले अखबारों में पेम्फलेट (pamphlet) में पढ़ने को मिला कि किस तरह से इस विभाग में दो गुट हैं । एक उन वैद्यों का जो पुरानी परिपाटी के हैं, जो अंग्रेजी नहीं जानते और जो आधुनिक ढङ्ग का इलाज नहीं जानते, दूसरा ग्रूप उन लोगों का है जो आधुनिक ढंग से शिक्षा पाये हुए हैं, आधुनिक ढंग के आयुर्वेदिक कॉलेजेज़ तथा इस तरह की दूसरी शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा पाये हुए हैं और इसमें विश्वास करते हैं कि आयुर्वैदिक आधुनिक ढंग से तरक्की करे । इन दोनों ग्रूपों में इस विभाग में द्वन्द्व मचा हुआ है । ये दोनों ग्रूप एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न करते रहते हैं और यह इस विभाग में एक बड़ी गलती का कारण बना हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय, साल भर से जहाँ डिस्पेन्सरीज़ हैं वहाँ दवाइयाँ नहीं पहुँचती हैं, जहाँ दवाइयाँ हैं वहाँ वैद्य नहीं पहुँचते हैं, व जहाँ वैद्य हैं वहाँ कम्पाउन्डर्स नहीं पहुँचते हैं । विभागीय अध्यक्ष अँग्रेजी का एक शब्द भी नहीं जानते हैं । अँग्रेजी के शब्द उनके सामने पहुँचते हैं तो उनके पी. ए. तर्जुमा करके उन्हें सुना देते हैं और अगर इन पी. ए. साहब की गड़बड़ियों की जाँच की जाय तो राजस्थान के मेडिकल विभाग में एक नया रंग आयेगा ।

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

साल भर हुआ इस विभाग में कोई अध्यक्ष मुकर्रर नहीं हुआ। अभी मौजूदा जो अध्यक्ष काम कर रहे हैं वे विभाग के कानून-कायदों से, सरकारी कानून-कायदों से और जितने रूल्स वगैरह बने हुए हैं उनसे कतई अपरिचित हैं और केवल वे जयपुर मे ही रहते हैं। आज तक उन्होंने शायद ही किसी डिस्पेन्सरी का दौरा किया होगा। दौरा करने भेजा है तो अपने मातहत श्री प्रेमशंकर साहब को भेजा जिन्होंने केवल दौरा करने के लिये वह स्थान चुना जो उनके प्रतिद्वन्द्वी का स्थान था। अभी एक जाँच हुई है, अभी एक स्थान के कागजात को उड़ाने का प्रयत्न किया गया, उस शख्स के कागजात जो उनका प्रतिद्वन्द्वी था। यह बताने की कोशिश की गई कि उन महोदय के जमाने में जब वे किसी एक जगह थे तो इतनी गड़बड़ी की। यह सब चीजें अखबारों में आईं और हमने देखीं।

इस कट मोशन के जरिये सदन का ध्यान और मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूँ कि केवल इलाजी योग्यता ही एक विभागीय अध्यक्ष के लिये काफी नहीं है, विभागीय अध्यक्ष के लिये शासकीय योग्यता भी होना जरूरी है। इस विभाग में जब तक शासकीय योग्यता वाला व्यक्ति इस विभाग का अध्यक्ष नहीं होगा तब तक इस विभाग की तरक्की नहीं हो सकती।

आज नई दवाइयाँ ईजाद हो रही हैं, आयुर्वेद तरक्की कर रहा है: पर यहाँ कोई तरक्की नहीं हुई है। आप नई डिस्पेन्सरियाँ खोलना चाहते हैं लेकिन उन जगहों को तो देखें कि जहाँ पहले से आयुर्वेदिक औषधालय हैं पर उनमें कोई सुधार नहीं हुआ है; उनकी कोई तरक्की नहीं हो रही है।

मैं बूँदी के आयुर्वेदिक अस्पताल के बारे में आपको निवेदन करूँ जो कि इन्डोर पेशंट अस्पताल है। एक वैद्य-मंडल के सदस्य वहाँ आये तो नीचे के हिस्से में इन्डोर पेशंट रखने लग गये और ऊपर के हिस्से में आप खुद रहने लग गये जिससे वह अस्पताल दिन-दिन प्रगति की बजाय अवनति कर रहा है। पुराने राजस्थान में जितनी आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरीज़ थीं उनकी हालत आज गिर रही है बजाय सुधरने के।

मैं माँग करूँगा कि जल्दी से जल्दी इस विभाग के मौजूदा अध्यक्ष को अपदस्थ किया जाय और किसी योग्य से योग्य आदमी को इस विभाग का अध्यक्ष बनाया जाय।

श्री कानसिंह—जो कट मोशन पेश हुए हैं उनमें से "Inadepuancy of Ayurvedic posts" से जो ताल्लुक रखता है उसके बारे में मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ।

नोखा मन्डी डिस्पेन्सरी आज से करीब ३० साल पहले खुली थी। उस वक्त मन्डी की आबादी आठ-दस दूकानों की थी और उसके लिये ५०० रुपयों की दवाइयाँ मुकर्रर हुई थीं। तरक्की करते-करते मन्डी की आबादी अब लगभग ६००० के हो चुकी है और पहले जो एक वैद्य

[श्री कानसिंह]

और एक कम्पाउन्डर रहते थे वहाँ अब एक सब-असिस्टेन्ट सर्जन आ गया है और मन्डी काफी तरक्की पर है; परन्तु दवाइयों के लिये जिस वक्त डिस्पेन्सरी खुली थी और ५०० रुपया मुकर्रर हुआ था वही दिया......

श्री सभापति (श्री द्वारका दास पुरोहित)—The Hon'ble Member has neither moved any cut-motion nor he is supporting the last cut-motion. He may please take his chair, The next cut-motion is by Shri Sohanlal Bhatnagar.

श्री सोहनलाल भटनागर—(To discuss the failure of the Government to provide proper medical facilities to the residents of Sarada Salumber tehsils.

2. To discuss the unjustified step of the Government in shifting the Ayurved Department from Udaipur to Jaipur and closing the Bhisgacharya classes at Udaipur).

चेअरमेन साहब, अभी ऊपर वाले कट मोशन के द्वारा रेगिस्तान में जो मेडिकल की हालत है उस बारे में बताया गया है। मैं इस कट मोशन के जरिये पहाड़ी क्षेत्र में जो मेडिकल की हालत है उसको बताना चाहता हूँ।

सराड़ा और सलूंबर तहसीलें एक-एक लाख की आबादी की तहसीलें हैं। वहाँ एक-एक डिस्पेन्सरी राजस्थान के निर्माण के पहले से चली आ रही हैं। मुझे इस दृष्टिकोण को मानते हुए भी कि राजस्थान निर्माण के बाद राजस्थान में तरक्की हुई है, परन्तु आयुर्वेद के बारे में निवेदन करना पड़ेगा कि कोई उन्नति नहीं हुई है। सराड़ा में करीब चार पाँच वर्ष हुए कोई डाक्टर नहीं हैं; वहाँ के लोगों की हालत खराब है, वहाँ नेहरू और मलेरिया की बीमारी बहुत हैं। मैंने कई बार निवेदन किया, मन्त्री महोदय को लिखा भी परन्तु अभी तक कोई पर्वाह नहीं की गई।

इसी तरह सलूंबर की डिस्पेन्सरी के बारे में, डिस्पेन्सरी की बिल्डिंग के बारे में अर्ज किया कि छोटा सा कमरा है, इन्डोर पेशंट रखने को कोई वार्ड नहीं है। ५०० की दवाइयाँ आती हैं जो जल्दी ही खत्म हो जाती हैं, मेरे क्षेत्र में जो डिस्पेन्सरियाँ हैं उनकी हालत सुधरनी चाहिये

औषधालयों के बारे में जैसा कि बजट में कहा गया कि ३६ औषधालय खोले गये और ३६ और खोले जायेंगे; मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ३६ खुले और ३६ खुलने वाले हैं पर खुलने वाले औषधालय हैं उनके लिये कोई मापदण्ड पोपुलेशन (जन-संख्या) आदि का नहीं रखा गया है।

[श्री सोहनलाल भटनागर]

अब मैं जो दूसरा कट मोशन है उसके बारे में निवेदन करूँगा कि जब राजस्थान का निर्माण हुआ तो पुरानी राजधानियों के महत्व को बनाये रखने के लिये वहाँ कुछ विभाग रखे गये थे। उदयपुर में आयुर्वैदिक कॉलेज रखा और वहाँ भिषाचार्य की क्लासेज़ चलती थीं। अब वह कॉलेज भी वहाँ से हटा दिया गया और भिषाचार्य की क्लासेज़ उठा दी गई हैं। इन्हें इस वर्ष न मालूम वहाँ से क्यों हटा दिया गया है? कहा जाता है कि जिनको आयुर्वेद विभाग का अध्यक्ष बनाया गया है वे यहाँ से नहीं जाना चाहते थे। उनकी शर्त थी कि इस विभाग को वे यहीं रखेंगे। एक व्यक्ति की कन्डीशन के पीछे सरकार चलती है और एक कन्डीशन राजस्थान के निर्माण के समय रखी गई थी पुरानी राजधानियों के महत्व को बनाये रखने के लिये, तो उस कंडीशन को तोड़ कर एक व्यक्ति की सुविधा के लिये वहाँ से एक विभाग को हटाया गया। मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि इस सम्बन्ध में कदम उठाया जावे और इसमें सुधार किया जावे और वापिस इस विभाग को उदयपुर रखा जावे।

श्री श्रीदास गोयल—चेयरमैन महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी सोहनलाल जी भटनागर ने जो कट मोशन.........

श्री हरिकृष्ण व्यास—सोहनलालजी ने कौन-सा कट मोशन पेश किया है? हमारे पास तो उसकी कोई कॉपी नहीं आई है। I want to know which cut-motion has been moved by Shri Sohanlal Bhatnagar because we have not been supplied any copy pertaining to the cut-motion moved by him.

श्री सभापति (श्री द्वारकादास पुरोहित)—Copies have been circulated.

श्री तेजमल बापना—It is in List III, Serial No. 56.

श्री सभापति—Yes. List No. III, serial No 56.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I have received only one paper in List III which ends at serial No. 54.

श्री सभापति—Please try to find out. It must be lying somewhere in your papers.

श्री श्रीदास गोयल—सोहनलालजी ने अभी-अभी फरमाया कि उदयपुर में जड़ी-बूटियों को बहुत अच्छी सुविधा है इसके साथ-साथ पुरानी राजस्थानियों में भी कोई ऑफिसेज रखे जा सकें। राजस्थान सरकार प्रगतिशील है तो ऐसी हालत में आयुर्वैदिक डिपार्टमेंट को भी तरक्की करनी चाहिये और उसके लिए इसे जयपुर में स्थानान्तर कर दिया तो इसके लिए कोई न कोई कारण होगा। मेरा यह निवेदन है कि जहाँ तक पुरानी राजधानियों की उन्नति और समृद्धि का प्रश्न है उसका तो मैं बिल्कुल विरोध नहीं करता और यह कहूँगा कि अधिक से अधिक डिपार्टमेंट जो वहाँ पर रखे जा सकें

[श्री श्रीदास गोयल]

रखे जावें और जितना फायदा पहुँचाया जा सके, पहुँचाया जावे परन्तु इसके साथ-साथ यह भी देखना निहायत जरूरी है कि इस विभाग को जयपुर में रखने की आवश्यकता इसलिए है कि इस महकमे के द्वारा जन-सेवा केवल राजधानी में होने के कारण से नहीं हो सकेगी। मैं कहूँगा कि केवल राजधानी में इस महकमे के होने से कोई रुकावट नहीं आनी चाहिये। यहाँ पर आयुर्वेदिक कॉलेज भी है और उसकी सुविधा भी मिल सकती है। इस बात को देखते हुए जयपुर एक ऐसा स्थान है जहाँ भारत में सबसे बड़ा संस्कृत कॉलेज है और यहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज भी है जहाँ भिषगाचार्य आदि लोग यहाँ से निकलते हैं और वे बड़े सफल विद्यार्थी साबित हुए हैं तथा वे बाहर जगह-जगह हिन्दुस्तान में फैले हुए हैं। इसके यहाँ होने से कॉलेज को बहुत बड़ा लाभ पहुँच सकता है।

अब रहा औषधियों का मामला। औषधियों के मामले में यह कहा जाता है कि उदयपुर में उपलब्ध है, तो मैं यह कहूँगा कि उतनी ही सुन्दर और संतोषजनक सुविधाएँ हमारे यहाँ सवाई माधोपुर के पहाड़ों में मिल सकती हैं, जो रतनपुर में मौजूद हैं। वहाँ पहाड़ी-बूटियें मिलती हैं। सवाई माधोपुर में एक कोनवत का ऐसा स्थान है जो चम्बल के रेतीले मैदान के पास है जहाँ जड़ी-बूटियाँ मिल सकती हैं, जो अनुभव से बहुत मुफीद साबित हुई हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करूँगा कि मेरे मित्र ने जो कट मोशन रखा है उस पर आप विचार करें और सरकार ने जो निर्णय दिया है वह स्वागत करने योग्य है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय सभापति, मैं आपका ध्यान लिस्ट नं० २ के कट मोशन ३४ और List I के कट मोशन की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

पहले इस विभाग में जो इनएफिशिएन्सी फैली हुई है उसके निस्बत जिक्र किया गया है। कट मोशन ....

श्री सभापति—On which cut-motion you are speaking ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—The cut-motion has already been moved.

श्री सभापति—It has been rejected.

श्री हरिकृष्ण व्यास—My cut-motion has of course been rejected but I am speaking in support of the cut-motion which has already been moved. That was moved sometime back.

श्री सभापति—Then you will get some chance after all the cut-motions have been moved by all the Members.

श्री हरिकृष्ण व्यास—All right, Sir.

श्री तेजमल बापना—चेयरमेन साहब, मैं मेडिकल के सम्बन्ध में कट मोशन मूव करना चाहता हूँ। कट मोशन इस प्रकार है :

[श्री तेजमल आपना]

"That the Demand for Grant No. XVII in respect of 38—Medical be reduced by Re 1/-(to discuss the requirements of Doctors, necessary quarters in Gandhi Hospital Bhilwara and Ayurvedic dispensaries in the District.)"

चेयरमेन साहब, इस बात की खुशी है कि मेडिकल का जो बजट हमारे सामने है उसमें हर साल लाखों रुपयों की बढ़ोती की जा रही है। मगर इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ भीलवाड़ा एक बहुत बड़ा जिला है, कस्बा भी बहुत बड़ा है और राजस्थान के इने-गिने कस्बों में है। खुशी की बात यह है कि होस्पिटल की इमारत तो एक सेठ ने २, २। लाख रुपया लगा कर बनवाई और उस होस्पिटल में आजकल इस कदर मरीजों की तादाद बढ़ गई है कि बहुत से इन्डोर पेशेन्ट्स को बरामदे में रखा जाता है। वहाँ पर एक तो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर है जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है और बहुत कम काम मरीजों को देखने का करता है। इसके अलावा दो और डाक्टर हैं जो इन्डोर और आउटडोर पेशेन्ट्स को देखते हैं। बड़ी मुसीबत इस बात की है कि पेशेन्ट्स को बराबर नहीं देखा जाता। बजट में हाँलाकि दो डाक्टर हैं, एक तो फर्स्ट क्लास डाक्टर और दूसरा सेकिन्ड क्लास; मगर उनकी नियुक्ति क्यों नहीं की जाती है और सरकार उनकी नियुक्ति क्यों नहीं करती, यह सरकार से पब्लिक की माँग है। वहाँ पर दो डाक्टरों के लिये बजट में प्रोविजन है तो फिर डाक्टर को नियुक्त क्यों नहीं करते? इसके अलावा बड़ी मुसीबत यह है कि वहाँ डाक्टर और कम्पाउन्डरों के रहने के लिये कोई क्वार्टर्स नहीं है। इतना बड़ा होस्पिटल तो सरकार को एक सेठ ने बना दिया, अब क्वार्टर तो सरकार को बनवाना ही चाहिये। सरकार यह चाहती है कि वही सेठ डाक्टरों के लिये और कम्पाउन्डरों के लिये क्वार्टर भी बना दे। इसके लिये सरकार कोशिश कर रही है। हमें इसकी कोई चिन्ता नहीं कि कौन बनावे, कोई बनवाए। यहाँ पर सब जगहों से आसपास के मरीज आते हैं और वहाँ पर डाक्टरों का होस्पिटल में मौजूद नहीं रहने से उन लोगों को बड़ी कठिनाई होती है। इसलिये वहाँ पर क्वार्टर्स बनने चाहिये, यह हमारा निवेदन है। इसके साथ-साथ मैं चेयर का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि ३ वर्षों का बजट हम देखते हैं। काफी आयुर्वैदिक डिस्पेन्सरीज़ हमारे राजस्थान में बढ़ाई जा रही हैं लेकिन भीलवाड़ा जिले की तरफ कोई निगाह नहीं जा रही हैं। इस विभाग की तरफ से कोई भी डिस्पेन्सरी इस जिले में नहीं बढ़ाई जा रही है। आज तक एक भी आयुर्वैदिक डिस्पेन्सरियाँ वहाँ नहीं बनाई गई।

इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्रीजी से जिनसे अभी-अभी यह डिपार्टमेंट दूसरों के पास चला गया है यह आश्वाशन दिया था कि वहाँ जो बड़े-बड़े ग्राम है जिनकी संख्या तीन हजार है और जिनके आस-पास के गाँवों की आबादी ७ हजार हो जाय तो वहाँ एक आयुर्वैदिक औषधालय खोलेंगे। एक कस्बे में जहाँ आयुर्वैदिक औषधालय चलते हैं उसकी तब्दीली उस तहसील के गाँवों के सिवाय दूसरे तहसील में तबादला नहीं होगा, वहाँ के जब तक बड़े ग्रामों में कोई प्रोवीजन न हो जाय। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि भीलवाड़े में इस समय जो आयुर्वैदिक डिस्पेन्सरी है

[श्री तेजमल बापना]

उसको भीलवाड़े के अन्य ग्रामों में, जहाँ के आसपास की आबादी ७ हजार की है जहाँ पर कई तरह की बीमारियाँ फैलती हैं स्थानान्तरित कर दी जावे। जो मिकदार इस साल के बजट में रखी है ३५ औषधालय खोलने की, यह राजस्थान के लिये बहुत नगण्य है फिर भी भीलवाड़े की बढ़ती हुई अहमियत को देखते हुए वहाँ के जो बड़े-बड़े ग्राम हैं, आस-पास के ग्रामों की जन-संख्या मिलकर ७ हजार हो जाती है वहाँ आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी खोलने का सरकार प्रयत्न करेगी। अब मैं माननीय मन्त्रीजी की जानकारी के लिए बता दूँ कि भीलवाड़ा तहसील में एक पुर नामक कस्बा है, जहाँ एक आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी है। भीलवाड़ा से यदि आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी को स्थानान्तरित किया जाता है तो वह डिस्पेन्सरी ३ हजार की आबादी वाले दूसरे ग्राम में उसी तहसील में उसको स्थानान्तरित किया जाय। तारापुरा और मंगरोट वहाँ अच्छे कस्बे हैं जहाँ के आसपास के गाँवों को मिलाकर आबादी करीब १० हजार की हो जाती है। पहले उस डिस्पेन्सरी को वहाँ स्थानान्तरित किया जाय। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि औषधालय हटाये जायं तो एक तहसील से दूसरे तहसील में न हटाये जायँ।

अब मैं आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में कहूँगा। जो रुपया आयुर्वेदिक औषधियों के लिए हर औषधालय को मिलते हैं वह रकम १००) से लेकर २००) रुपये तक की है। इतने से रुपयों में सारे साल का काम नहीं चलता। हमीरगढ़ में एक औषधालय है वहाँ पर जो पैसा औषधियों के लिए दिया जाता है वह करीब दो-तीन महीने में खत्म हो जाता है। जहाँ पर आयुर्वेदिक औषधालय हैं वहाँ पर औषधियों को बढ़ाने के लिए अधिक रकम दी जाय। एक तहसील में जो डिस्पेन्सरी आयुर्वेदिक है वह यदि स्थानान्तरित की जाती है तो उसी तहसील के किसी गाँव में होनी चाहिये। इन्हीं बातों की ओर तवज्जुह दिलाने के लिए मैंने यह कट मोशन पेश किये हैं।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री गोपीलाल यादव—उपाध्यक्ष महोदय, कट मोशन पेश करने का मेरा अभिप्राय यह है कि देहातों में मेडिकल एड का जो प्रोवीज़न है वह बहुत कम है और जिस रफ्तार से गवर्नमेंट चल रही है उस रफ्तार से तो देहातों में औषधालयों की व्यवस्था पचास वर्षों में भी पूरी नहीं हो सकेगी क्योंकि ३५ औषधालय इस साल रखे गये हैं। इसी रफ्तार से यदि सरकार चलती रही तो पचास वर्ष में भी यह (व्यवस्था) पूरी नहीं हो सकेगी। जिस प्रकार किसी इलाके में चोरियाँ बहुत होती हैं, अगर उस इलाके में पुलिस का इन्तजाम नहीं है तो कोई समझेगा कि कहीं भी अमन चैन नहीं है, उसी प्रकार जहाँ औषधालय नहीं हैं तो देहातों के लोग समझेंगे कि हमारी सरकार बिल्कुल ही हमारी तन्दुरुस्ती पर ध्यान नहीं देती है। इसको दूर करने के लिये मैं एक सजेशन आपके सामने पेश करना चाहता हूं। कुछ दिनों तक एज्युकेशन मिनिस्टर महोदय और स्वास्थ्य मन्त्री महोदय दोनों मिल कर काम करें; क्योंकि जैसी कि हमारी सरकार की योजना है हम प्राइमरी स्कूल्स बहुत तादाद में खोल रहे हैं। तो जो मास्टर उन प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने जायं उनको ६ महीने के लिए आयुर्वेदिक की ट्रेनिंग दी जाय ताकि वे रोजमर्रा की बीमारियों; जैसे खांसी, बुखार, सर्दी आदि को ठीक कर

Page No.71

[श्री गोपीलाल यादव]

सकें। उस काम के लिए उस अध्यापक को कुछ अलॉउन्स दे दिया जाय और उसको दो-तीन घन्टे स्कूल टाइम के अलावा काम करने को कहा जाय। मामूली बीमारियों को ठीक करने के लिए उनके पास दवाइयों का भी कुछ स्टॉक हो, जिससे वहाँ के लोगों का वह इलाज कर सके। जब प्रत्येक एक हजार की आबादी वाले क्षेत्र में आप प्राइमरी स्कूल खोल रहे हैं तो इससे एक औषधालय का भी वहाँ काम हो जायगा और देहाती जनता को इससे कुछ आराम तो अवश्य हो जायगा और उससे आस-पास के छोटे-छोटे गाँव भी फायदा उठा सकेंगे। मेरा माननीय मित्रों से निवेदन है कि वे मेरे इस सजेशन पर जरूर विचार करेंगे।

श्री कस्तूरचन्द—उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी पता चला कि मेरे माननीय मित्र ने अभी कहा कि उनको माननीय मन्त्री जी ने आश्वाशन दिया है कि जिस तहसील में जो डिस्पेन्सरीज़ हैं उनको वहाँ से दूसरी तहसीलों में नहीं हटाया जायगा, ऐसा मुझे पता चला है और उनकी बातों से भी यही बात दिखाई देती है। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि अगर मन्त्रीजी ने इस तरह का आश्वाशन दे दिया है तो मेरे ख्याल से मैं इसको अच्छा नहीं समझ रहा हूँ क्योंकि जिस जगह, जिस डिस्ट्रिक्ट के अन्दर, जिस तहसील में डिस्पेन्सरी नहीं, जहाँ पर बीमारियों से लोग मरते हों, हरेक को अपने इलाज के लिए मदद नहीं मिलती है तो इस तरह से कहीं कहीं तो दो-दो औषधालय हैं और चलते-फिरते अस्पताल भी हैं, मगर डिस्टिक्ट भीलवाड़े के अन्दर जो भी औषधालय हटाये जाँय वे किसी भी हालत में उस तहसील में न रखे जाँय, उनके पास की किसी दूसरी ऐसी तहसील में रखे जायं जहां औषधालय का इन्तजाम न हो। एक तरफ तो मनुष्य बीमारी से मरा करें; हमारे यहां इतनी जन-संख्या होने पर भी, हमारे द्वारा कई बार निवेदन करने पर भी यह कहा जाता है कि आपके गांव का नाम लिस्ट में ले लिया जायगा, न मालूम कब ले लिया जायगा; अभी जो लिस्ट निकली हैं उसमें हमारे यहां का नाम नहीं है तो फिर कब नाम लिख लिया जायगा, समझ में नहीं आता? ३५ औषधालय जो इस साल खोले जाने वाले हैं उनमें न मालूम कौनसी लिस्ट में हमारा नाम है, समझ में नहीं आता? बापना साहब के कहने पर जो मन्त्रीजी ने आश्वासन दिया वह गलत चीज है। इसके लिए मेरा निवेदन है कि जिस जगह औषधालय नहीं है वहाँ औषधालय को बदला जाय और जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ बिल्कुल न रखा जाय।

श्री सन्तोषसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा के सम्बन्ध में जो माँग रखी गई है वह बहुत थोड़ी है। बढ़ती हुई जन-संख्या को देखते हुए और साथ-साथ बढ़ती हुई नयी-नयी किस्मों की बीमारियों को देखते हुए यह डिमान्ड जो रखी गई है वह बहुत कम है। इस चिकित्सा विभाग के लिये जितनी माँग रखी गई है उसका ८० प्रतिशत तो इन्तजाम में ही खर्च हो जाता है और सिर्फ बीस पर्सेन्ट की दवाइयाँ आती हैं जो बिल्कुल काफी नहीं हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस डिमान्ड को बढ़ाया जाय।

दूसरा इस विभाग में देखा गया है कि जितने बेड्स होते हैं वह उन्ही लोगों के लिए ही एक तरह से रखे रहते हैं जो या तो किसी के रिश्तेदार हो या किसी डॉक्टर के मित्र हों, बेचारे गरीब

[श्री गोपीलाल यादव]

जब तड़फते हुए शहर की ओर जाते हैं तो उनको भरती नहीं किया जाता और उनको बराबर दवाइयाँ नहीं मिलतीं।

और दूसरी बात यह कहूँगा कि गाँवों में इस वक्त बाले का जोर इतना बढ़ा है कि उसका इलाज डॉक्टर कतई जानते नहीं और इस विभाग में हमारे जोधपुर शहर में बाले का एक डॉक्टर रखा हुआ है और करीब २५०) रुपया माहवार इस पर खर्च भी सरकार करती है, पर इसके अन्दर शिकायतें इतनी रह गई हैं कि इस डॉक्टर को भी जैसे-तैसे फीस मिल जाती है पर दवाइयाँ और पट्टियाँ वगैरह जरूरी सामान मिलता नहीं है। जब एक बात का इन्तजाम सरकार कर देती है और दूसरी वैसी ही जरूरी बात का इन्तजाम नहीं कर पाती तो पहले का किया-कराया भी बेकार जाता है।- दिन भर वह डॉक्टर ऐसे ही बैठा रहता है और दूसरे शहर में इतने बाले भी नहीं होते। यह बीमारी अधिकतर गाँवों में होती है पर गाँवों में आने-जाने के लिये उस डॉक्टर के पास कोई साधन नहीं। इसलिये मेरा निवेदन है इस सरकार से कि उसे गाँवों में जाने के लिए सवारी दी जावे। उसे गाँव-गाँव में फिराया जावे तो इससे गाँव के लोगों को बहुत लाभ हो सकता है। वह डॉक्टर इस बाले के बारे में बड़ा एक्सपर्ट है। वह एक मिनिट के अन्दर बाले को निकाल कर फेंक देता है। पर इसकी ओर कोई तवज्जोह सरकार नहीं देती है और न उसको प्रोत्साहन ही देती है। इसके लिये मेरा सजेशन है कि उस डॉक्टर को जोधपुर के बड़े शफाखाने में जगह दी जावे। जैसे और डिपार्टमेंट हैं—कान के, दाँत के, गले के, आँख के; ऐसे ही एक अलग विभाग इस बाले का भी खोल दिया जावे। जब कान, नाक, आँख आदि का अलग-अलग विभाग खोला जा सकता है तो क्यों नहीं बाले का भी एक अलग विभाग खोला जावे और साथ ही उसमें दवाई और पट्टी आदि का इन्तजाम भी कर दिया जावे ताकि कोई भी बीमार आवे तो उसका इलाज किया जा सके, दवाई दी जा सके और पट्टी बाँधी जा सके।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—अभी दो-तीन पोइन्ट्स जरूरी-जरूरी हैं।

श्री उपाध्यक्ष—वह कट मोशन्स मूव हो चुके हैं।

श्री सन्तोषसिंह—आपकी इजाजत हो तो एक मिनिट।

श्री उपाध्यक्ष—तो कह दीजिये।

श्री सन्तोषसिंह—तो इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि बाले की जो बीमारी गाँवों में बहुत अधिक फैली हुई है उसको रोकने के लिये भी सरकार इस ओर काफी तवज्जोह दे। डॉक्टर को कभी-कभी तो तनख्वाह भी नहीं मिलती है; चार-चार महीने हो गये, यह भी शिकायत है। काम तो वह बहुत अच्छा जानता है पर सरकार काम लेती नहीं है उससे।

जोधपुर इतना बड़ा शहर है और वहाँ के ह्युसन डिस्पेन्सरी, विंडम हॉस्पिटल भी अच्छे हैं

[श्री सन्तोषसिंह]

और विंडम हॉस्पिटल को तो महात्मा गाँधी के नाम पर रखने के बाद भी आँखों का जो डिपार्टमेंट है वह बन्द कर दिया गया है। आँखों के डाक्टर को वहाँ से निकाल दिया और एक बात और देखने में आई है कि जो आँखों का अच्छा डाक्टर है और एक अच्छा एक्सपर्ट मौजूद है आँखों का। सात सौ, आठ सौ रुपया फीस का जिसे मिलता है उसको आज सिर्फ एक क्लर्क का काम दिया गया है और वह जानता है आँखों के ऑपरेशन का काम। कई सफल ऑपरेशन आँखों के उसने किये हैं और बड़े-बड़े सर्टिफिकेट भी उसे मिले हुए हैं, हजारों आपरेशन भी किये हैं सफलतापूर्वक; पर खेद है कि आज ऐसे एक्सपर्ट आदमी से ऑपरेशन का काम न लेकर क्लर्क का काम लिया जा रहा है और जोधपुर शहर का हयुसन एक बड़ा सफाखाना था वह आज एक मामूली डिस्पेन्सरी बना दी गयी। तो ये सारी गलत बातें हैं।

इसके बाद एक बात है वहाँ के खाने की।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

वहाँ शफाखाने में खाना बड़ा खराब मिलता है और वह भी ढाई रोटी मिलती है कम्पेनियन को, जिसमें वह पूरा धापता भी नहीं है। तो कम्पेनियन को पूरा खाना दिलाना चाहिये।

छिलाड़ा तहसील में भावी और अचलगढ़ पाँच-पाँच हजार के गाँव हैं उनके अन्दर भी शफाखाने की व्यवस्था होनी चाहिये।

और भी बहुत से ऐसे गाँव हैं जहाँ इस तरह की व्यवस्था नहीं है। टाइम खत्म की घंटी दो बार बज चुकी है। अब सरकार से इतनी ही प्रार्थना है कि इसके लिए उचित व्यवस्था करे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष जी, थोड़ी देर पहले यह कहा गया था कि बाद में बोलने का हमें अवसर दिया जावेगा। मैं समझता हूँ कि वह समय आया है या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष—All the cut-motions have been discussed and the Minister has to reply ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—They have not been discussed. As a matter of fact when we got in between, we were told that let the cut-motions be moved, then we will be given an opportunity. Now when the opportunity has come, we are told that they have been discussed. They might have been discussed, but they have not been discussed enough. So I request that permission be granted to make some submission on cut-motions No. 34 in List II and No. 2 of List I.

श्री उपाध्यक्ष—Have two minutes each.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I hope then the Hon'ble Deputy Speaker will look

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

to the material that I am making available to the House and then he would consider the question of relaxing the time also.

(विराम)

माननीय उपाध्यक्षजी, अभी मेरे एक मित्र ने मुबारिकवादी दी थी बड़े एफीशिएन्ट वर्किंग (efficient working) के लिये सरकार के इस महकमे को, यह कह कर कि इसका बजट सालो साल बढ़ रहा है। यह तो अच्छी बात है कि इसका बजट सालों-साल बढ़ रहा है, लेकिन मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ कि यह एक ऐसा विशेष विभाग है कि जिसका बजट प्रोवीजनल्ली (provisunally) तो बढ़ता है पर रिवाइज्ड एस्टीमेट में कम हो जाता है। एस्टीमेट प्रोवीजनल्ली इसमें रकम थी तीन लाख चार हजार और रिवाइज्ड एस्टीमेटस में यह दो लाख हो गयी।

और दूसरे-दूसरे महकमों में सप्लीमेंटरी माँग आई, पर इस कल्याणकारी राज्य में यह एक खास बात है कि मेडिकल महकमे की प्रोवीजनल बजट की रकम भी पूरी नहीं होती।

दवाइयों की निस्बत अभी-अभी कहा गया कि पूरी दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं। उपलब्ध हों तो कैसे, जब कि पैसा ही खर्च नहीं किया जा रहा है।

सन् ५३ की मद में बजट एस्टीमेट था ५,६६,२८०)। पेशेन्टस् की तादाद दो-तीन सालों से निरन्तर बढ़ती जा रही है, पर खासियत है राजस्थान सरकार की और इस विभाग की कि रिवाइज्ड एस्टीमेटस में यह कम कर दिया गया।

माननीय उपाध्यक्षजी, इस महकमे में लगातार यह बात क्यों हो रही है? दवाइयों में हो तो कोई बात। पर अभी देहातों में खोले गए अस्पतालों और औषधालयों का जिक्र हुआ, लेकिन अगर आप बजट को बजट के पेज नं० १४८ पर गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि बजट एस्टीमेट ५३-५४ का इस काम के लिये एक लाख रुपये का रक्खा गया और खर्च किया केवल २८ हजार, जहाँ कि दूसरे विभागों में प्रोवीजन था तीन हजार का एक विभाग में एक काम के लिए और खर्च किया २ लाख; लेकिन इस कल्याणकारी राज्य में आयुर्वेदिक औषधालयों के लिए एक लाख का प्रोवीजन रक्खा गया पर खर्च किये केवल २८ हजार।

मैं पूछना चाहता हूँ माननीय उपाध्यक्षजी, यहाँ और यह कौनसी बीमारी है जिसका इलाज करना आवश्यक है। दूसरी बीमारियों का तो इलाज हो भी सकता है पर हमारे माननीय मन्त्री महोदय को यह कौन सी बीमारी है कि इसमें कटौती ही कटौती हर साल करते जा रहे हैं।

आप डाइट का प्रोवीजन देखिये।

बजट ५३-५४ में ४,३७,७४५) रु० का रक्खा गया और रिवाइज्ड में ३,७५,०००) का रक्खा गया। मैं पूछता हूँ क्या अस्पतालों में मरीजों की तादाद कम हो रही है या कोई एक ऐसा

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इन्जेक्शन ईजाद हुआ है कि कम डाइट देकर भी इलाज किया जा सकता है और अगर नहीं तो फिर यह कटौती क्यों ?

उस दिन एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया हमारी असेम्बली में कि जो साधारण डाइट दी जाती है वह १६०० कैलोरीज़ और २३०० कैलोरीज़ तक दी जाती है और एक न्युट्रिशन एक्सपर्ट (nutriticn expert) की राय के मुताबिक यह उचित है। मैं इस कथन की असत्यता के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं क्वोट करूँगा एक प्रसिद्ध न्युट्रीशन एक्सपर्ट की राय को और वह राय भी और किसी की नहीं ऐसे एक्सपर्ट की जिसे भारत सरकार द्वारा काफी मान्यता मिली हुई है और वह है प्रसिद्ध न्युट्रीशन एक्सपर्ट डॉक्टर एकटारे, जिन्होंने न्युट्रीशन के सिलसिले में एक पुस्तिका भी लिखी है, जो सन् १९४९ में प्रकाशित हुई है और जिसमें उन्होंने यह लिखा है कि मेन्युअल वर्क करने वाले एक भारतीय नागरिक को ३२०० केलोरीज़ खुराक मिलनी चाहिये, इससे कम मेहनत करने वालों को २८०० केलोरीज़ मिलनी चाहिये। इसके मुकाबले में हमारे अस्पताल में १६०० केलोरीज़ और २३०० केलोरीज़ खुराक दी जाती है। यह भी कहा जाता है, दी जाती है या नहीं दी जाती इसमें भी मुझे तो शक है और अगर दी जाती है तो न्युट्रीशन के स्टेन्डर्ड से कम है और इस पर भी देखते हैं कि डाइट के लिए जो रकम दी जाती है ४,३५ हजार के करीब उसको भी कम करके ३,७६ हजार कर लिया गया है।

और भी मुझे आपके सामने अर्ज करना है। इसी राजस्थान के अन्दर इसी विभाग में बचत की जाय तो अलग बातें हैं, लेकिन हालत राजस्थान की यह है माननीय उपाध्यक्षजी, कि सरकार ने जो कुछ किया है, आज हर साल टी० बी० की बीमारी से २१ हजार आदमी मरते हैं और सारे राजस्थान में अभी भी १ लाख व्यक्ति इस बीमारी के शिकार हैं। इसके एवज में हमारे पास बेड्स की तादाद २४३ है। गिनी वर्म (नेहरुआ) की एक बीमारी जो कि मेरे एक मित्र ने 'बाला-बाला' कहा और दूसरे इलाके में नेहरू कहते हैं उस बीमारी के लिए आज तक इस विभाग की ओर से कोई प्रयत्न किया गया हो ऐसा कम से कम हमारे सामने और राजस्थान के रहने वालों के सामने नहीं आया। कोई योजना बन रही हो इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मुमकिन है योजना बन रही है, ऐसा उत्तर दिया जाय।

तो मैं आपसे यह अर्ज कर रहा था कि यहाँ इस बात पर धन्यवाद देने के बजाय इसमें प्रोवीज़न बढ़ाये जाने के इस विभाग को कहा जाय कि कटौती करो। आप लोग, कल्याणकारी राज्य की दुहाई देने वाले लोग जब कि इन सब मदों में ज्यादा खर्चा करते हैं तो मेडीकल में से पैसा बचा-बचाकर रखने की क्यों कोशिश करते हैं, डाइट में से पैसा क्यों बचाते हैं, अस्पताल में बीमारों की दवाइयों में से पैसा क्यों बचाते हैं, देहातों में दवाई क्यों नहीं पहुँचाते हैं ? बजट में से प्रोवीज़न रखकर

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

उसमें से पैसा बचाने और साल के अन्त में यह दिखाने, कि इतनी बचत कर ली, की कोशिश करते हैं। इस विभाग में इस बचत का विरोध करने के लिए ही मैंने यह कट मोशन रखा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक ही प्वाइन्ट और है।

मैं अपने कट मोशन पर ही कन्फाइन रह कर अर्ज कर रहा हूँ। मैंने जिस बारे में कट मोशन दिया है उन्हीं प्वॉइन्ट्स को डील विध कर रहा हूँ, उसके निस्बत ही थोड़ा सा कहने जा रहा हूँ।

दूसरी चीज़ जो मैं कह रह हूँ वह यह है कि इस विभाग में १ करोड़ से ज्यादा का प्रोवीजन किया गया है। उसके अन्दर यह देखना आवश्यक है कि इस बजट में एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा कितना है और हकीकत में कार्य का खर्चा कितना है। मैं इस राय से सहमत नहीं था और न मेरी यह कहने की इच्छा है कि राजस्थान में डॉक्टरों की तादाद बढ़ रही है, कम्पाउन्डरों की तादाद कम है, और दूसरे ट्रेन्ड स्टॉफ की तादाद कम है, लेकिन इस ओर गौर फरमायेंगे, माननीय उपाध्यक्षजी, तो यह देखेंगे कि हमारे पास जो ट्रेन्ड आदमी, इस प्रकार के वैद्य वगैरह हैं उनका जितना उपयोग कर सकते हैं उसके मुकाबले में २५ फी सदी भी प्रोवीज़न अस्पताल में नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं। जितना स्टॉफ हमारे पास में है उस स्टॉफ से राजस्थान की जनता को जितनी मेडीकल फेसिलिटीज़ दे सकते हैं उसके मुकाबले में यह देखेंगे कि हकीकत में औषधालयों के लिए, छोटी-छोटी डिस्पेन्सरीज़ के लिए; दवाइयां, बीमारों के काम के लिए कितना प्रोवीज़न कर रहे हैं, तो हमें यह पता लगेगा कि हमारे पास जो मौजूदा आदमी हैं उनकी ट्रेनिंग का पूरा-पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं। नतीजा यह हो रहा है कि एक करोड़ रुपये का खर्चा करने के बावजूद भी एस्टेब्लिशमेंट पर कितना खर्च कर रहे हैं उस पैसे का उपयोग नहीं होता है, इसलिए उपयोग नहीं होता है कि इस मद की ओर जब ज्यादा पैसा खर्च करने की आवश्यकता है तो वह खर्च करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। इन दोनों कारणों की ओर खास तौर से आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ।

इतना यह कहकर (घंटी) मैं जो छोटी तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी हैं उनकी हालत के बारे में कहूँगा। अलवर के अस्पताल में जो रात की ड्यूटी पर काम करने वाले नर्सेज़ व कम्पाउन्डर्स हैं उन्हें १३-१३ घंटे का काम दिया जाता है। परसों ही इस सिलसिले में मेरे पास सूचना उपलब्ध हुई है। इस सिलसिले में आप कहीं भी जायँ, ८ घन्टे से ज्यादा काम नहीं लिया जाता है, लेकिन इस महकमें के अन्दर, जहाँ कि उन कर्मचारियों को अधिक ध्यान देना पड़ता है, वहाँ काम के घन्टे निर्धारित नहीं।

मेरे एक मित्र ने यह कहा कि जोधपुर में रॉइट (riot) हुआ था। वहाँ कुछ नहीं हुआ था। सरकार की नीति के खिलाफ आम लोगों के असंतोष की भावना बढ़ गई थी। नर्सेज़ और कम्पाउन्डरों को ८ साल पहले ग्रेड देने का वायदा किया था, तो वायदा खिलाफी करने पर और फिर यह कि केवल मैट्रिक पास को रखा जायगा तो ऐसे अन्याय के कारण जो असंतोष था उस असन्तोष के

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

परिणामस्वरूप यह हुआ। भूख-हड़ताल हुई और हड़ताल के बाद में सरकार ने आश्वासन दिया था कि कोई दमनकारी कदम नहीं उठायेंगे... (घंटी) लेकिन ६ लोगों पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया, गैर कानूनी तरीके से लिया गया था, उस पर विचार नहीं किया जा रहा है।

ऐसी हालत में मैं यह कहूँगा कि यह महकमा जो कि दरअसल में ह्यु मेनिटेरियन (humanitarian) महकमा है वह ह्यु मेनिटेरियन ढंग से नहीं, लेकिन एक बहुत ही गलत ढंग से, पैसा बचत करने, अन्याय करने और गैरवाजिब काम करने की दृष्टि से चल रहा है। इसलिए मैं इस कट मोशन का समर्थन कर रहा हूँ।

श्री मानसिंह मद्दार—माननीय अध्यक्ष.....

श्री जसवन्तसिंह—माननीय उपाध्यक्ष मैं २ मिनट बोलूँ, यदि आज्ञा हो तो।

श्री उपाध्यक्ष—श्री जसवन्तसिंह।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—माननीय उपाध्यक्षजी, मुझे मेडिकल डिपार्टमेंट के मुताल्लिक २-४ शब्द कहने हैं, और खास तौर से मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि बड़ी प्रसन्नता है कि जो मेडिकल डिपार्टमेंट के इन्चार्ज मिनिस्टर हैं, वह हमारे बीकानेर के प्रतिनिधि हैं। वैसे तो बीकानेर के लिए मैं अक्सर बहुत कुछ कह चुका हूँ, लेकिन आज खास तौर से इस आशा से कहना चाहता हूं कि जो कुछ कहूँ उस पर मेरे मित्र ठीक सुनवाई करेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वह हकीकतन बीकानेर के रिप्रेजेन्टेटिव हैं?

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—हाँ, जरूर हैं, बीकानेर से चुने जा कर आये हैं। जरूर हैं।

तो मुझे आपसे यह निवेदन करना है कि बीकानेर का अस्पताल जो आज से १०-१५ वर्ष पहले हिन्दुस्तान में ही क्या, लेकिन दुनियाँ के अस्पतालों में एक नामी अस्पताल समझा जाता था। मेरे एक बीकानेर के दूसरे प्रतिनिधि, 'दुनियाँ में एक नामी अस्पताल था" उसका नाम सुनकर हँस रहे हैं; खैर, वे हँसें। बीकानेर की शायद पहले की तरक्की उन्हें पसन्द न हो, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूँ कि लॉर्ड माउन्टबेटन जब हिन्दुस्तान के वाइसराय होकर नहीं आये थे, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया के सुप्रीम कमान्डर थे; तो लड़ाई के मौके में उनको बीकानेर में आने का अवसर मिला। तो बीकानेर के अस्पताल के बारे में उन्होंने जो रिमार्क दिये हैं वह वहाँ कि रिमार्क्स बुक में हैं। वे रिमार्क्स देखेंगे तो उनके यह शब्द हैं, 'The Pride of Assia (एशिया का गर्व)'; यह माउन्टबेटन के रिमार्क्स हैं। जो हमारे साथी हँसने लगते हैं उनके लिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि माउन्टबेटन का रिमार्क है, "दी प्राइड ऑफ एशिया"। इसके बाद जनरल मिरजकर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के डाइरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज़ थे उन्होंने बीकानेर के अस्पताल का इनसपैक्शन किया तो उन्होंने कहा "The best hospital of Northern India"; उसको आप जाकर देख सकते हैं, उस रिमार्क बुक में। और उसी बुनियाद पर बीकानेर अस्पताल को एक

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

आर. सी. एस. के, प्रिलीमिनरी एक्ज़ामिनेशन के लिए किया गया था। वह केवल एक ही इन्स्टीट्यूशन राजस्थान में था, जो कि इसके लिए रिकॉग्नाइज़ (recognise) किया गया था और हमारा अस्पताल राजस्थान में ही केवल रिकॉगनाइज्ड़ नहीं था बल्कि सिवाय बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के और कोई अस्पताल हिन्दुस्तान भर में ऐसा नहीं था जो कि एफ० आर० सी० एस० के प्रिलीमिनेरी एक्जामिनेशन के लिए रिकगनाइज्ड़ था; लेकिन बीकानेर का अस्पताल इस बात के लिए रिकॉगनाइज्ड़ था, लेकिन आज उस अस्पताल में यह हो रहा है कि जहाँ-जहाँ ४-४, ५-५ एफ० आर० सी० एस० बीकानेर के अस्पताल थे वहाँ ३-३, ४-४ हजार रुपया तनख्वाह दी जाती थी, जिनसे इलाज करवाने के लिए हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान के बाहर से लोग वहाँ आते थे, आज वहाँ एक ही एफ० आर० सी० एस० मौजूद है मेन्स हास्पिटल में। विमन्स हॉस्पिटल में एक लेडी एफ० आर० सी० एस, एक लेडी एम० डी०, एक लेडी डॉक्टर एम० एस० जहाँ मौजूद हुआ करते थे उस हास्पिटल में आज एक भी लेडी डॉक्टर एम० एस० मौजूद नहीं हैं, न एम० डी० लेडी डॉक्टर मौजूद है और न एफ० आर० सी० एस० लेडी डॉक्टर है। ऊँची से ऊँची जो लेडी डाक्टर हैं वह एम० बी० बी० एस० है। तो मेरे माननीय मित्र से यह निवेदन करूँगा कि आज हम लोगों के लिए यह देखना है कि हमारे बीकानेर के लिए, हमारे बीकानेर के प्रतिनिधि कुछ करने को तैयार हैं या नहीं ? मैं निवेदन करूँगा कि बीकानेर का अस्पताल जो हमारे लिए कभी गौरव की चीज़ थी, आज उस अस्पताल का पतन हो रहा है मैं आशा करता हूँ कि माननीय मन्त्री उसको वापिस उसी स्थान पर लाकर बतायेंगे।

इसके अलावा बीकानेर के अस्पताल में जितना स्पेश्यलाइज्ड स्टॉफ (Spcialised staff) था उतना राजस्थान के किसी दूसरे अस्पताल में नहीं था। वे एक-एक करके बीकानेर से ट्रान्सफर करके बाहर भेज दिये गये हैं और बहुत से नाउम्मीद होकर बीकानेर से बाहर नौकरी छोड़कर चले गये हैं। रेडियम का ट्रीटमेन्ट बीकानेर के अलावा और कहीं नहीं था। वहाँ पर इसका भी आज इलाज करने वाला डॉक्टर नहीं है। टी० बी० का राजस्थान में सबसे बड़ा अस्पताल बीकानेर में है और वहाँ के डॉक्टर इनचार्ज आज एम० बी० बी० एस० छोटे ग्रेड के हैं और जयपुर का अपस्ताल छोटा है लेकिन वहाँ का इन्चार्ज कई डिग्रियों वाला बड़ी तनख्वाह वाला डॉक्टर है। (घंटी) ये छोटी-बड़ी बातें हैं जिनके कारण मुझे बहुत रंज है। और भी कई बातें मुझे कहनी थीं लेकिन क्योंकि घंटी बज गई है इसलिये मैं ज्यादा नहीं कहूँगा। देखना है कि माननीय मन्त्रीजी बीकानेर के लिये क्या करते हैं।

श्री मानसिंह महार—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कटौती प्रस्ताव नम्बर ३५ का विरोध करना है और २, ३ और ३४ का सपोर्ट करना है। मैं कटोती प्रस्ताव नम्बर ३५ पहले ले लेता हूँ। जो ३५ नम्बर पर कटौती प्रस्ताव रखा गया है वह इस प्रकार है।

"That the demand for Grant No. XVII be reduced by Re. 1/- (to discuss the inefficiency of the Head of the Department of Ayurvedic which is hampering the progress of the system of medicine") माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह मानकर चलता हूँ कि आयुर्वेदिक विभाग में...

श्री उपाध्यक्ष —आप पाँच मिनिट तक बोलें।

श्री मानसिंह महार—जिन कट मोशन्स को सपोर्ट करूँगा उनके लिये अलग-समय चाहिये।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—इनको १० मिनिट का समय दीजिये साहब।

श्री मानसिंह महार—(भाषण जारी रखते हुए) आयुर्वेद विभाग को जिस प्रकार की प्रगति करनी चाहिये वह नहीं की। यह मानकर चलते हुए भी बड़ा दुःख हुआ जब यह सुना कि इस सदन के एक सदस्य ने राजस्थान के बड़े उच्चकोटि के वैद्य के लिये, जिनकी ख्याति राजस्थान में ही नहीं है बल्कि कलकत्ता बम्बई में भी है और जिन्होंने नाम कमा रखा है, जिस प्रकार राजस्थान में इलाज के लिये हम डाक्टरों के पास पहुँचते हैं उसी प्रकार कलकत्ता और बम्बई के लोग उनके पास पहूँचते हैं, हिन्दुस्तान के कोने-कोने में इस आदमी को पहचानते हैं। जो इतना काबिल आदमी है, उसको ५००) रू० की तनख्वा पर हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट रखा जाता है, उनको भी इन-एफिसियेन्ट (inefficient) बताया और यह कहा जाता है कि क्योंकि वे अंग्रेजी नहीं जानते इसलिए उनको हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट नहीं बनाया जाना चाहिये था। यह मेडिकल विभाग का दुर्भाग्य है। मेडिकल विभाग के हैड भी अंग्रेजी नहीं जानते, तो क्या इसका मतलब यह है कि वे अपना काम पी. ए. आदि से पूछ कर करते हैं? यह गलत बात है। वे इतने योग्य हैं कि उनकी योग्यता को देखते हुए अंग्रेजी की क्वालिफिकेशन नहीं होने से यह कह दिया गया कि उनको आयुर्वेद विभाग का हैड नहीं बनाया जाय, यह बहुत बुरी बात है। जो बातें ३५ नम्बर के कटौती प्रस्ताव में बताई गई हैं उनका मैं विरोध करता हूँ और उन सज्जन से प्रार्थना करूँगा कि इन सारी बातों को मद्दे नजर रखते हुए यदि वे इस प्रकार का कटौती प्रस्ताव पूरे मेडिकल विभाग के खिलाफ रखते, हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट को इनएफिशियेन्ट मानकर लाते तो मैं मान सकता था, लेकिन इस प्रकार की पक्षपातपूर्ण नीति नहीं होनी चाहिये। ये जो टेक्निकल डिपार्टमेन्ट्स् होते हैं उनके हैडस् की योग्यता को देखना चाहिये। यह कह देना कि फलां बात नहीं जानते हैं, मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान के जितने डिपार्टमेन्ट्स् हैं उनके हैड्स् वाकई काबिल होंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर कम ध्यान देंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनको हटा दिया जाय। सरकार ने इसी काम को करने के लिए हमारे सवाई मानसिंह अस्पताल में एक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेन्ट दिया था और वे कितने काबिल हुए हैं यह जनता के सामने आ चुका है। हमारा आयुर्वेदिक विभाग मेडिकल विभाग से ज्यादा काबिल है। हमारे इतने योग्य आदमी को, जिनको हिन्दुस्तान का रत्न कहना चाहिये, ऐसा कहना शोभा नहीं देता।

श्री कपिलदेव—मालूम होता है, ये उनके जेर-इलाज हैं।

श्री मानसिंह—मैं तो जेर-इलाज उपाध्यक्ष महोदय, इस समय आपका हूँ।

यह भी मुझे मालूम हुआ है कि डिप्टी डाइरेक्टर इस विभाग के जो हैं उनके जेर-इलाज हमारे नेता महोदय हैं और तरक्की के उम्मीदवार हैं। इसलिए योग्य आदमी को दुनियाँ की नजर से गिराकर सारी बातें कही गई हैं। इसलिए मैं इस कटौती प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूँ और

[श्री मानसिंह महार]

अपील करता हूँ कि इस कटौती प्रस्ताव को टुकरा दें और उनसे भी अपील करता हूँ कि इस तरह के प्रस्ताव लाकर सदन का समय ज्यादा खराब न करें और इसको विद्ड्रा कर लें।

इसके बाद मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्ताव नं. २,३ और ३४ का सपोर्ट करता हुआ सदन के सामने चन्द बातें रखूँगा, ज्यादा समय नहीं लूँगा। आजकल जो राजस्थान के मैडिकल विभाग की हालत है वह बहुत ही खराब है। मैंने बजट के ऊपर जनरल बहस के समय कहा था कि सवाई मानसिंह अस्पताल की हालत बहुत ही खराब हो गई है। हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि बीकानेर में यह कमी है, वह कमी है, किसी ने कहा कि भीलवाड़ा में यह कमी है और सब यह समझते हैं कि जयपुर एक ऊँचे शिखर पर है; लेकिन मैं बताऊंगा कि जयपुर का अस्पताल आज नरक के समान हो रहा है और यहाँ भले आदमी पैर नहीं रखना चाहते हैं। आज सौभाग्य की बात है कि हमारे मन्त्रीजी सदन में पधार आये हैं इसलिये उनसे भी अर्ज करूंगा कि जयपुर के अस्पताल के लिये जिस प्रकार की पक्षपातपूर्ण नीति अपनाई जा रही है उसका बहादुरी के साथ सामना करें। दमन करें और कुछ लोग जयपुर के अस्पताल को बिगाड़ रहे हैं उनको रोकें।

उधर चलिये जयपुर के जनाने अस्पताल की ओर। जयपुर के जनाने अस्पताल के बारे में मैंने पहले ही कहा था कि डिलीवरी के समय वहाँ पर मेडिकल कॉलेज के लड़के जाया करते थे और अब इस बात की और भी ज्यादा छूट उनको दे दी गई है। यह कहा जाता है कि जयपुर के मेडिकल कॉलेज के लड़के जयपुर के जनाने अस्पताल में डिलीवरी के समय यदि न जावें तो वे सीखेंगे कैसे? मैं कहता हूँ कि लड़कों को इस बारे में आप सिखाते ही क्यों हैं। लड़कियें या औरतें इतनी हैं कि उनको काम सिखावें। हमारी स्त्रियें इतनी निर्लज्ज नहीं हैं कि मरदों के सामने जाकर जापा करवावें। यह जयपुर की जनता के लिये असन्तोष की बात हो रही है। इसलिये माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके जरिये स्वास्थ्य मंत्रीजी से अपील करूँगा कि वे जो खुद राजस्थान के देहात के बाहरी इलाके से आये हुए हैं, जहाँ की स्त्रियाँ शहर की स्त्रियों से ज्यादा लज्जाशील हैं, वे इस ओर ध्यान देंगे।

मुझे मालूम है कि इस तरह की शिकायतें, इस तरह की परेशानी स्वयं मन्त्रियों ने भी उठाई है और उन्हें बड़ी शिफारिशों और कोशिश के बाद इस प्रयत्न में सफलता मिली है कि उनकी स्त्रियों के डिलीवरी के समय लड़के न आयें। तो ऐसी सूरत में, मैं आशा करूँगा कि उन्हें आम जनता के लिये भी सोचना चाहिये। तो दूसरी अपील यह है, इस ओर राजस्थान सरकार को ध्यान जरूर देना चाहिये।

(घन्टी)

एक मिनट और दीजिये। तीसरी बात यह है कि हमारे देहातों के जो अस्पताल हैं उनकी हालत बहुत ही चिन्ताजनक है। देहातों में जो अस्पताल हैं उनमें डाक्टरों पर अंकुश न होने के

[श्री मानसिंह महार]

कारण उनकी हालत बड़ी खराब हो गई है। वे लोग आँखों में आइ ड्रोप्स डालने के २, २ आने चार्ज करते हैं और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि माननीय मन्त्री जांच कराना चाहें तो जयपुर डिस्ट्रिक्ट में सामोद का अस्पताल है; वहाँ चार आने फी आदमी आई ड्रोप्स डालने के चार्ज किये जाते हैं, गांव का गांव इसका सबूत देने के लिए तैयार है।

एक माननीय सदस्य—टी. बी. सील्स होंगी।

(हँसी)

जी नहीं, टी. बी. सील्स-वील्स कुछ नहीं है: बात टालने की कोशिश न कीजिए। सीधा कहते हैं चार पैसे दो तो आँख में दवा डालेंगे, नहीं तो ऐसी दवाइयाँ डाली जाती हैं कि आँखें फूल कर कुप्पा हो जाती हैं। (हँसी)। हमारे यहाँ राजस्थान में कोई मेडिकल एक्ट नहीं है, इस वजह से "ऐरे-गेरे नत्थू खैर" कोई भी पैसे की दवाई ले जाते हैं और गाँवों में पाँच-पाँच रुपये चार्ज करते हैं। सामोद के अस्पताल की यही हालत है। सामोद मेरे नजदीक है इसलिए वहाँ के इन्टर्नल वर्किंग (internal working) का मुझे ज्यादा तजुर्बा है।

तीसरी बात यह है कि गाँवों में डाक्टर इतनी एग्जोबिटेन्ट (अत्यधिक) फीस लेते हैं कि गरीब आदमी तो दे ही नहीं सकता। एक मील जाने की गाँव में डाक्टर १०) रुपया फीस लेते हैं। दुर्भाग्य से आज डाक्टरों का मोरेल इतना गिर गया है कि एक मील पर डाक्टर को बुलाते हैं और आगे मुर्दा पड़ा मिलता है तो भी वह कहता है कि मेरी फीस १०) रुपया तो दे दो और फीस के रुपये दिये बिना मुर्दा पड़ा रहता है। आदमी अपनी मुर्दा औरत को छोड़कर थाली-ठीकरे ले जाकर बनिये के यहाँ गिरवे रखता हैं, डॉक्टर को १०) रुपये उसकी फीस के देता है और तब वह उसका दाह-संस्कार कर पाता है। हमारे गाँवों में डिस्पेन्सरियों में दवाइयाँ तो हैं ही नहीं, सब दवाइयाँ मोल लाकर काम चलाना पड़ता है। मेरी जमुवा रामगढ़ कॉन्स्टीट्युएन्सी है, उसमें मानपुरा, अचरोल और मानपुर अच्छे बड़े बड़े कस्बे हैं, पर वहाँ कोई डिस्पेन्सरी नहीं है। मानपुरा तो एक बड़ा तरक्की करता हुआ कस्बा है। वहाँ भी डिस्पेन्सरी नहीं है। इसके लिए मन्त्री महोदय ध्यान रखेंगे तो बड़ी कृपा होगी।

श्री चाँदमल मेहता—उपाध्यक्ष महोदय, दवाइयों की कमी के बारे में कई कॉस्टीट्युएन्सीज़ से आये हुए सदस्यों ने सदन के सामने बातें रखीं......

श्री उपाध्यक्ष—एक मिनट।

श्री चाँदमल मेहता—मैं खास तौर से निवेदन करना चाहता हूँ कि कहीं तो दवाइयों की कमी रही, परन्तु किशनगढ़ में सन् ५३-५४ में किशनगढ़ की डिस्पेन्सरी को एक पैसे की भी दवाई नहीं दी गई। पिछले तीन वर्षों में अराई की डिस्पेन्सरी को कुल मिला कर ३००) रुपयों की दवाइयाँ दी गई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये मन्त्री महोदय से अपील करूँगा कि इतने

[श्री चाँदमल मेहता]

औषधालय खोले गये हैं उनका कोई उपयोग नहीं होगा जब तक कि उनको दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में नहीं दी जायेंगी। परबतसर के इलाके में जावले में एक औषधालय था, उसको हटा लिया गया है, उस निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक औषधालय है; जावले के औषधालय को अकारण हटा लिया गया है ।

मैं माननीय मन्त्रीजी से अपील करूँगा कि अगर आपको औषधालय खोलने हैं तो यह देखना होगा कि राजस्थान की जितनी जनसंख्या है, उसी जनसंख्या के अनुपात से औषधालय खोले जाकर दवाइयों की माकूल व्यवस्था की जावे। तभी उनका कुछ उपयोग हो सकता है, नहीं तो बिना दवाइयों के उनका कोई उपयोग नहीं होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—श्री कुम्भाराम आर्य, सरकार की तरफ से उत्तर देंगे ।

श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, जिस वक्त कटौती के प्रस्ताव रखे गये थे तो अध्यक्ष महोदय ने जिन सदस्यों के कटौती के प्रस्तावों को रद्द कर दिया था तब फरमाया था कि उन सदस्यों को, जिनके कि कटौती के प्रस्ताव रद्द करार दिये गए हैं उनको कटौती के प्रस्तावों पर बहस हो जाने के बाद में बोलने का मौका दिया जायगा, उन सदस्यों में से मैं भी एक सदस्य हूँ जिनके कि कटौती के प्रस्ताव रद्द कर दिये गए थे, परन्तु मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया है । इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि मुझे बोलने का अवसर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—इस डिमान्ड पर आज वोट ले लेने हैं ।

कु ँ श्री जसवन्तसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या हम शाम को भी मिल रहे हैं या नहीं? अगर शाम को मीटिंग हो तो जरूर उन्हें मौका देना चाहिए, जो बोलना चाहते हैं। जवाब शाम को दे सकते हैं। अब तो टाइम होने में १२ मिनट बाकी हैं, मन्त्री महोदय का भी भाषण समाप्त नहीं होगा, अगर सब पोइन्ट्स का जवाब देना है। अगर संक्षेप में सबका एक ही जवाब देना चाहेंगे तो २ मिनिट में ही खत्म हो जायगा। इस बहस में बड़े-बड़े महत्त्वपूर्ण सवाल उठाये गए हैं, आयुर्वेदिक के बारे में और एलोपेथिक के बारे में, हामियोपेथिक के बारे में भी सवाल उठाये हैं या नहीं, मैं नहीं कह सकता क्योंकि थोड़ी देर के लिए मैं बाहर चला गया था। तो बड़े महत्त्वपूर्ण सवाल सदन के सामने हैं। ऐसे मौकों पर ही ऐसे-ऐसे महत्त्वपूर्ण सवालों पर लम्बा विचार हो सकता है। वैसे भी १२ मिनट में जवाब दिया जाना मुश्किल है, तो ऐसी सूरत १०–१२ मिनिट के लिए दूसरे सदस्यों को बोलने का मौका दिया जाना चाहिये। शाम के सेशन में मन्त्री महोदय घण्टे डेढ़ घण्टे में इसका उत्तर दे देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—आज संध्या को फिर सेशन होगा, पर इस वक्त अगर एक डिमान्ड पर ज्यादा समय लगेगा तो फिर दूसरी डिमान्ड्स पर ज्यादा बहस नहीं हो सकेगी। इसी खयाल से

[श्री उपाध्यक्ष]

डिबेट कर्टेल की जा रही है। अगर हाउस की सेंस हो कि और सदस्य बोलें, तो और समय बढ़ाया जा सकता है।

कुँ० श्री **जसवन्तसिंह**—अब तो १० मिनिट का ही तो काम है।

श्री उपाध्यक्ष—क्योंकि ज्यादा-ज्यादा टाइम जनरल डिबेट की तरह तो नहीं मिल सकेगा, इसलिए जो सदस्य बोलना चाहें, खास-खास चुनी हुई बातों पर दो-दो, तीन-तीन और ज्यादा से ज्यादा पाँच मिनट में बोल लें।

श्री भैरूँसिंह (दांताराम गढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय खेतसिंहजी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा और उसके जरिये राजस्थान के रुरल एरियाज़ में आयुर्वैदिक औषधालयों के द्वारा वहाँ की जनता की सेवा न करने की जो नीति राजस्थान सरकार ने अपनाई है उसके ऊपर जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उस पर मैं अपने विचार सदन के सामने प्रस्तुत करूँगा।

राजस्थान में और सारे भारतवर्ष में हम यह मान कर चलते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यदि हमें आर्थिक संचय को ज्यादा बढ़ाना है तो उन लोगों की मदद करनी पड़ेगी जिनके जरिये आर्थिक लाभ हमें ज्यादा होता है। किसी प्रकार कोरे कागज पर लिख लेने मात्र से, या योजनाएँ बनाकर कागजों पर रख लेने मात्र से मदद नहीं हो सकेगी। उनके कार्य रूप में परिणत करने का भार जिस दल विशेष पर है उनका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वे उनको सुखी और समृद्धशाली बनाएँ और ऐसे कार्य करें जिनसे आर्थिक स्थिति जल्दी से जल्दी ठीक हो। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश होने के कारण ज्यादा लोग देहातों में ही रहते हैं इसलिए देहातों में मेडिकल रिलीफ पहुँचाने के लिये यदि कोई योजना सरकार बनाएगी तो उससे किसानों और देहात के रहने वालों को ज्यादा सहायता मिल सकेगी और यह कार्य तभी हो सकता है जब सस्ते मेडिकल रीलिफ के ज़रिये निकाले जावें। इसका एक ही मार्ग हो सकता है; वह है आयुर्वैदिक डिस्पेन्सरीज़ को प्रोत्साहन देना। लेकिन मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान के बजट को जब हम देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि आयुर्वेद में प्रगति नहीं हो रही है, इस वर्ष उतने ही वैद्यों की और उतनी ही दवाइयों की योजना जितनी पहले साल थी, है। एक तरफ तो सरकार यह कहती है और चाहती है कि देहातों के रहने वालों को सुखी बनाया जावे और दूसरी तरफ उनकी मुसीबतों को दूर करने के लिये कोई ध्यान नहीं दिया जाता, जो बजट को देखने से आपको साफ मालूम होगा। इतनी सी रकम में देहातों के रहनेवालों को मेडिकल रिलीफ नहीं मिल सकती। मगर सरकार की तरफ से यही कहा जाता है कि देहातों को बहुत कुछ रिलीफ दिया जाता है। आँकड़ों को देखने से मालूम होता है कि जहाँ पर मेडिकल फेसिलीटिज़ (medical facilities) का जिक्र है वह सिर्फ जुबान पर ही है और वह भी इसलिए कि लोगों को विश्वास दिला कर कहा जाता है कि उनके दुःखों को दूर करने की झूठी योजनाएँ उनके सामने रखी हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ। कि यदि कोई इस काम में प्रोत्साहन देने में कोई बात आती है तो महज यह कहकर कि डाइरेक्टर ऑफ आयुर्वैदिक हिन्दी में ही काम करते हैं और अंग्रेजी पढ़े-लिखे नहीं हैं। अँग्रेजी पढ़ा-लिखा नहीं होने से आयुर्वैदिक का काम बिल्कुल

[श्री भैरूँ सिंह]

ढीला-ढाला है, चुप्पी साधी जाती है । उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो इस बात का घमण्ड है कि हमारी हिन्दी जो हमारी राष्ट्र भाषा है उसके वे पक्ष में हैं । इसलिए हमें तो गर्व होना चाहिये कि डाइरेक्टर अपना सारा काम हिन्दी में ही करवाते हैं, परन्तु बजाय उनको प्रोत्साहन देने के यह कहा जाता है कि वे हिन्दी जानते हैं, अंग्रेजी नहीं जानते ।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी चीज़ मुझे यह निवेदन करनी है कि आज-कल होस्पिटलों में जो करप्शन फैल रहा है उसको कोई रोक नहीं सकता और जो कार्यवाही हो रही है उसको कोई पकड़ नहीं सकता । यहाँ के होस्पिटलों में दवाइयाँ भी कम मिलती हैं और जो बजट दवाइयों के लिये रखा जाता है वह दवाइयों में खर्च नहीं होता । इस बात का तो पता जब रिवाइज्ड ऐस्टीमेट देखेंगे तब लगेगा । होस्पिटल में कोई रोगी जाता है तो उसको यही कहा जाता है कि फलाँ दवाइ यहाँ नहीं है, और तुम्हारा रोग इस प्रकार का है कि यदि जल्दी से जल्दी इसका इलाज नहीं किया गया तो रोग बढ़ता ही जावेगा, इसलिये आप चले जावें अर्जुन मेडिकल स्टोर्स या भीम मेडिकल स्टोर्स पर । इस प्रकार कई स्टोर्स के नाम बता दिये जाते हैं, जहाँ पर कि खास तौर से वे दवाइयें उपलब्ध होती हैं । इससे मालूम होता है कि या तो उस स्टोर में डाक्टर साहब का साजा होता है या किसी प्रकार का उनको उस दुकान से कमीशन मिलता है और इसी आधार पर उस व्यक्ति को दवाइ लेने के लिये भेज दिया जाता है ।

यही हाल आजकल सवाई मानसिंह होस्पिटल में हो रहा है । आप देखेंगे कि होस्पिटल के आगे, निकलते ही सामने ही एक मेडिकल स्टोर है । डाक्टर पर्ची लिख देता है । मरीज यह समझता है कि डॉक्टरों ने जिस जगह से दवाई लाने का लिखा है वहीं से लानी चाहिये क्योंकि उनको वहाँ से कुछ न कुछ कमीशन के रूप में अवश्य मिलेगा और इसलिये डाक्टर साहब कुछ इलाज में दिलचस्पी लेंगे ही । उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं यह आपके ज़रिये सदन से अर्ज करूँगा कि जिस स्टोर के साथ डाक्टर का हिस्सा हो या कमीशन मिलने का जरिया हो उसको बन्द करा दिया जावे और इस सम्बन्ध में इन्क्वायरी की जावे । (घण्टी) तहसील दाँतारामगढ़ के कस्बा लोसल के अन्दर होस्पिटल आज से चार साल पहले बन चुका है । इसके बाद सारे मिनिस्टरों ने वहाँ के दौरे किये । किसी ने नींव का पत्थर रखा और किसी ने कुछ किया, लेकिन जब आज उसका ताला खोलने का समय आया तो कोई भी उसका ताला खोलने के लिये तैयार नहीं होता है । सारे मिनिस्टर दूर बैठे हैं और आप देखेंगे कि वहाँ पर दो लाख की इमारत बनी तैयार खड़ी है । यदि सरकार इस पर खर्च नहीं कर सकती थी तो उसका कर्त्तव्य था कि वह पहले ही कह देती, दो साल पहले या ५ साल पहले कि जिस वक्त हमारी शक्ति होगी होस्पिटल का निर्माण कर लेंगे, मगर सरकार दोनों चीजें नहीं कह सकती (घण्टी) इसी तरह दाँतारामगढ़ तहसील में ५२ हजार के लगभग की पब्लिक होते हुए भी कोई होस्पिटल नहीं है । कहा यह जाता है कि शेखावाटी, फतहपुर आदि में सेठ बहुत रहते हैं, वह धनियों का मुल्क है, वहाँ पर सरकार को होस्पिटल की कोई जरूरत नहीं; वे लोग बम्बई, कलकत्ता आदि जगहों प रहते हैं और बहुत पैसे वाले हैं लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि दाँता रामगढ़ शेखावाटी में नहीं आता न इस तहसील में सेठ लोग हैं; मगर फिर भी उसको इसी कारण छोड़ दिया

[श्री भैरूँसिंह]

गया है और वहाँ पर कोई होस्पिटल नहीं है। समयाभाव के कारण में इतना ही कह कर निवेदन करूँगा कि आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरीज़ बढ़ाई जावें।

आर. एस. श्री दलीपसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मैं इस मेडिकल डिपार्टमेंट में जो कुशासन चल रहा है उसके मुताल्लिक, अपने कोटा होस्पिटल के सम्बन्ध में कुछ अर्ज करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। वहाँ देखा जा रहा है कि कोई फिज़ीशियन नहीं है। इसके अलावा वहाँ होस्पिटल में एक ही लेडी डाक्टर रहती है। वह बीमार भी रहती है, कहीं बीमारों को देखने के लिये भी जाती है या छुट्टी भी जाती है। उसकी गैर मौजूदगी में भी कई लोग दवाई लेने के लिये जाते हैं। अगर वह नहीं होती है तो मेलहोस्पिटल से मेल डॉक्टर उसकी जगह काम करने के लिये भेज दिया जाता है जिससे लेडी पेशेन्ट्स को परेशानी होती है। दूसरी बात यह कि बड़े होस्पिटल में पी. एम. ओ. जो हैं वे बहुत शरीफ आदमी हैं, लेकिन उनके कर्मचारी उनकी लीनिएन्सी का नाजायज़ फायदा उठाते हैं। पुराने डाक्टर अपना व्यक्तिगत फायदा उठाते हैं और नये डाक्टर भी जो पास करके आये हैं ५, ६ सालों से कोटा होस्पिटल में ही काम कर रहे हैं। इन सब लोगों ने दुकानदारों से साँठ-गाँठ कर रखी हैं और जो कोई पेशेन्ट वहाँ पर होस्पिटल में आते हैं उनको गाँठ लेते हैं। अगर वे उनसे इलाज करा लेते हैं तो ठीक, वरना वे उनके खिलाफ बड़े डाक्टर से कह कर उनको तकलीफ देते हैं, उनको डिस्चार्ज करा देते हैं। जो स्पेशल वार्ड के काबिल पेशेन्ट हों उनको स्पेशल वार्ड न देकर जनरल वार्ड में ही रख देते हैं; इस तरह से तंग करते हैं।

इसके अलावा सरकार से मुझे यह शिकायत है कि वहाँ कोटा के होस्पिटल में जितना ध्यान सरकार को देना चाहिये उसकी उन्नति के लिये नहीं दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कोटा में नया होस्पिटल बनाया जा रहा है। मैं यह कहूँगा कि ७ लाख रुपया कोटा के दरबार ने अपने प्राइवेट पर्स से दिया और आज ५, ६ साल के बाद उसका व्याज १ लाख रुपया हो गया है। इस सम्बन्ध में सुना है कि फाइनेन्स सेक्रेट्री साहब यह एतराज कर रहे हैं कि व्याज का एक लाख रुपया इस होस्पिटल के लिये नहीं दिया जावे। इसके अलावा मुझे यह भी मालूम हुआ है कि इस होस्पिटल का एस्टीमेट पहले ३५ लाख का किया गया था, उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि यह ३५ लाख ज्यादा है। इसके बाद १५ लाख का एस्टीमेट हुआ और इस पर भी माननीय मन्त्रियों में विचार हुआ और कहा गया कि यह भी बहुत ज्यादा है।

एक ग्राम कहावत के अनुसार- "जिसकी चूल्हे में जड़ होती है उसको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती"; जो सात लाख रुपये तक कर दिये गये हमारे कोटा अस्पताल को बनाने के लिए तो उससे जो हमारा मौजूदा अस्पताल है उससे ज्यादा इम्प्रूवमेन्ट होने की आशा नहीं। इसका कारण यह है कि कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं और न कोई इस ओर ध्यान देने वाला ही है। हमारी आवाज उठाने वाला कहीं किसी प्रकार का है ही नहीं।

दूसरी अर्ज यह है कि मेडिकल डिपार्टमेंट का इन्टीग्रेशन ही नहीं हो रहा है। इतने अरसे से टलाया जा रहा है, कारण कि कई डाक्टर जूनियर हैं और जो बड़े-बड़े ओहदों पर लगाये हुए हैं

[आर. एस. श्री दलीपसिंह]

उनको छोड़ना पड़ता है इन्टीग्रेशन हो जावे तो । यह सब चीजें सामने आ जावें जिनको जूनीयर से सीनीयर बना दिया गया और जो योग्यता में जूनीयर हैं, फिर भी वे बड़े-बड़े ओहदों पर कार्य कर रहे हैं । उनका यदि इन्टीग्रेशन किया जायगा तो उनको नीचा ओहदा देना पड़ेगा । मिसाल की तौर पर डा. तनेजा जो केवल एम. बी. बी एस. हैं, जो किसी मामूली अस्पताल में डाक्टर थे वहाँ अस्पताल में, असिस्टेण्ट डाइरेक्टर बना दिये गये । उनका किसी एक विशेष आदमी से ताल्लुक था इसलिये उनको असिस्टेन्ट डाइरेक्टर ऑफ मेडिकल एण्ड पब्लिक हेल्थ लगाया गया है। उनके पास एम. बी. बी. एस. से किसी विशेष प्रकार की डिग्री नहीं, फिर भी उनको ए. डी. एम. एस. बना दिया गया । यह हालत है हमारे यहाँ की ।

श्री उपाध्यक्ष—अब सभा की कार्यवाही सायंकाल ४ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

[सदन की कार्यवाही १२ बज कर ३५ मिनट (मध्यान्होत्तर) पर संध्या के ४ बजे तक के लिये स्थगित हुई ।]

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक—२३ मार्च, १९५४

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा ।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ४०३ का उत्तर देखिये)

खनिजों से उपलब्ध राजकीय आय और उसका शतप्रतिशत क्रमशः वर्षों के लिए

१९५०-५१, १९५१-५२, १९५२-५३

क्रम संख्या	खनिज के नाम	आय व उसका शतप्रतिशत					
		१९५२-५३		१९५१-५२		१९५०-५१	
		सम्पूर्ण आय रुपयों में	शतप्रतिशत	सम्पूर्ण आय रुपयों में	शतप्रतिशत	सम्पूर्ण आय रुपयों में	शतप्रतिशत
१	चूना तथा इमारतों के लिए उपयोगी पत्थर	२०,१९,३७०/-	४५.६३	२४,१७,२३२/-	५०.४६	२२,१६,९७१/-	५६.७५
२	अभ्रक	९,९३,५६२/-	२२.५०	११,६६,९४६/-	२४.३७	९,७८,४०५/-	२५.००
३	भुरा कोयला	५,०१,७६१/-	११.३३	४,४५,६४२/-	९.३०	१,२७,०८०/-	३.२५
४	जिप्सम	२,८२,३८५/-	६.३७	६०,४६०/-	१.२६	१,२५,६५१/-	३.२५
५	संगमरमर	१,११,४२१/-	२.५१	१,२८,६७९/-	२.६८	१,७८,८८०/-	४.६०
६	मुलतानी मिट्टी	१,००,६८०/-	२.२७	९८,४४९/-	२.०७	९९,८६०/-	२.५७
७	घीया भाटा	९५,७३६/-	२.१६	९०,०८७/-	१.९०	७९,४३७/-	२.०३
८	शीशा, जस्त व चाँदी	६५,८६३/-	१.४८	७१,७८०/-	१.४९	७०१/-	.०१
९	पन्ना	५३,५७०/-	१.२१	६,८२३/-	.१४	५,२००/-	.१३
१०	बेरुज	२६,२३९/-	.५९	६,९८३/-	.१४	८०९/-	.०२
११	मेग्नीज़	२३,६२०/-	.५३	१९,५९९/-	.४०	४,६११/-	.११
१२	कांच की बालू	१६,६६७/-	.३७	८,०१४/-	.१६	११,२४४/-	.२८
१३	कलमी शोरा	१५,६००/-	.३५	११,०२९/-	.२३	३२०/-	.००८
१४	सुतिया पत्थर	२,०४०/-	०.०४	२,७८३/-	.०५	२०६/-	.००५
१५	सेलेनाइट	२९०/-	०.००६	१८५/-	.००३	२३५/-	.००६

क्रम संख्या	खनिज के नाम	आय व उसका शतप्रतिशत					
		१९५२-५३		१९५१-५२		१९५०-५१	
		सम्पूर्ण आय	शतप्रतिशत	सम्पूर्ण आय	शतप्रतिशत	सम्पूर्ण आय	शतप्रतिशत
		रुपयों में		रुपयों में		रुपयों में	
१६	बेन्टोनाईट	१८०/-	०·००४	—	—	—	—
१७	स्लेट	—	—	२,०८८/-	·०४	—	—
१८	घाटा भाटा	—	—	१,९२१/-	·०४	—	—
१९	फलेस्पाट व क्वार्टज़	—	—	५४७/-	·०१	१७५/-	·००४
२०	टंगस्टन ओर	—	—	१३३४७३/-	२·७८	—	—
२१	काईं नाईट	—	—	—	—	१,८००/-	·०२
२२	विविध	८,६७४/-	०·१९	५९,९२९/-	१·२५	६,०२५/-	·१७
२३	विविध	१,०९,३३१/-	२·४६	५९,१८०/-	१·२३	७१,८६४/-	१·८५
		सम्पूर्ण आय १९५२-५३ Total Revenue रु० ४४,२६,९८९/-		सम्पूर्ण आय १९५१-५२ रु० ४७,९१,७९९/-		सम्पूर्ण आय १९५०-५१ रु० ३९,०८,४७४/-	

Page No.89

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ४०५ का उत्तर देखिये)

नगरपालिकाओं की सूची जिनकी अवधि सन् १९५३-५४ में समाप्त हुई और उनके कार्यकाल बढ़ाने का कारण—

क्र०सं०	नगरपालिका का नाम	अवधि बढ़ाने का कारण
१	टोंक	बोर्ड के चुनाव संपन्न हो गये हैं, चैयरमेन का चुनाव होना है।
२	निम्बाहेड़ा	बोर्ड के चैयरमेन के चुनाव में कुछ समय लगा, अब नये बोर्ड ने फरवरी १९५४ को चार्ज ले लिया है।
३	कपासन	बोर्ड की अवधि १५-१०-५३ को समाप्त हुई। चुनाव के पश्चात् नये-चेयरमेन का नाम प्रकाशित करा दिया गया है।
४	झालावाड़	इस नगरपालिका की अवधि १-१२-५३ को समाप्त हुई। निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्यों के नाम प्रकाशित करा दिये गये हैं। चेयरमेन का चुनाव होना है।
५	अलवर	इसकी अवधि ४-१-५४ को पूर्ण हो गई। चेयरमेन का चुनाव होना है।
६	लछमनगढ़	इसकी अवधि २५-१०-५३ को पूरी हो गई परन्तु चेयरमेन के चुनाव न होने के कारण अवधि बढ़ाई गई। नये चेयरमेन का नाम फरवरी में विज्ञापित कर दिया गया है।
७	निवाई	चेयरमेन के चुनाव के अभाव के कारण
८	उनियारा	ऐजन
९	भीनासर	चुनाव संपन्न हो गये हैं और नया बोर्ड कार्य कर रहा है।
१०	बिदासर	यहाँ चुनाव संपन्न हो गये हैं और नया बोर्ड कार्य कर रहा है।
११	बालोतरा	इस नगरपालिका के कार्यकाल की अवधि २८-२-५४ को समाप्त हुई है। चुनाव हो चुके हैं। इस नगरपालिका की अवधि नये-चेयरमेन द्वारा चार्ज लेने तक बढ़ाने का प्रश्न विचाराधीन है।
१२	नागोर	इस नगरपालिका के क्षेत्रवृद्धि का प्रश्न विचाराधीन है, अतः इसके कार्यकाल की वृद्धि ३०-६-५४ तक कर दी गई है।

परिशिष्ट ३

(सदन की मेज पर रखे गये अतारांकित प्रश्नोत्तर)

प्रश्न

१. (८०। सी. एम.) श्री गुरुदयालसिंह सन्धु, एम. एल. ए., विभाजन संख्या ४६—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) बीकानेर रेन्ज से कितने उम्मीदवार पुलिस ट्रेनिंग स्कूल किशनगढ़ के लिये चुने गये थे ?

(ख) उन उम्मीदवारों में कितने ऐसे उम्मीदवार थे जिनका बीकानेर रेन्ज में इन्टरव्यू हुआ था और जयपुर रेन्ज से चुने गये ?

(ग) जो उम्मीदवार किशनगढ़ स्कूल के लिये चुने गये उनमें से कितने उम्मीदवार शिक्षा व शारीरिक स्वास्थ्य में अच्छे थे ?

(घ) क्या सरकार प्रत्येक उम्मीदवार की शिक्षा व स्वास्थ्य की रिपोर्ट हाउस के सामने रखेगी ?

(ङ) क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि पुलिस ट्रेनिंग स्कूल किशनगढ़ के लिये जो उम्मीदवार चुने गये हैं, उसमें कोई करप्शन हुई है या नहीं ? यदि हुई है, तो क्या सरकार उस किशनगढ़ स्कूल को बन्द करने, हकदार उम्मीदवारों को भेजने के लिये तैयार हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(क) बीकानेर रेन्ज से ८१ व्यक्तियों ने आवेदन पत्र भेजे थे, जिनमें से ६ चुने गये।

(ख) सिर्फ २.

(ग) सब.

(घ) नहीं। यह प्रशासन का विषय है ।

(ङ) नहीं। ऐसी कोई घटना सरकार के सामने नहीं आई, अतः यह प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान विधान सभा

चौदहवीं बैठक, मंगलवार, दिनांक—२३ मार्च, सन् १९५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-भवन, जयपुर, में (मध्यान्होत्तर) पर ४ बज कर ५ मिनट पर प्रारम्भ हुई

(सायंकालीन बैठक)

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

माँगों पर मतदान

चिकित्सा—१७ (क्रम में)

श्री अध्यक्ष (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री की ओर संकेत करके)—Yes, reply

श्री कुम्भाराम आर्य (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, सर्व प्रथम बोलने वाले के भावों के सम्बन्ध में, जो उन्होंने सबसे पहले इस बात पर आपत्ति की है कि राजस्थान के लिए हैल्थ और मैडिकल की पूरी तौर से व्यवस्था नहीं है और इसके साथ सबसे बड़ी जो उन्होंने बात कही है वह यह कि बाडमेर के अन्दर औषधालय तक नहीं है, डिस्पेन्सरी की तो बात ही क्या कहने की; इसके सम्बन्ध में मैं थोड़ा सा बतला देना चाहता हूँ कि बाडमेर की स्थिति ऐसी नहीं है जैसी कि मेरे एक माननीय सदस्य ने हाउस के सामने रक्खी है। बाडमेर डिस्ट्रिक्ट में सात आयुर्वेदिक औषधालय हैं और वे इस प्रकार से हैं :

(१) जसोल

(२) बालोतरा

(३) पचभदरा

(४) पाटोदी

(५) सिवाना

(६) समदड़ी, और

(७) शिव ।

[श्री कुम्भाराम आर्य]

इन सात आयुर्वेदिक औषधालयों के अलावा डिस्पेन्सरियें भी हैं जो इस प्रकार हैं :—

(१) सिवाना

(२) बाडमेर

(३) बालोतरा, और

(४) शिव ।

इन सारे आँकड़ों को देखने से यह स्पष्ट होगा कि जिस तरह से बातें कही गई हैं, वैसी बातें नहीं हैं।

इन सारी बातों के अलावा भी इतना मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान का एरिया जिसमें जन-संख्या कम है और गाँव बहुत छोटे और वे भी काफी दूर-दूर हैं वहाँ भी स्वास्थ्य की जितनी व्यवस्था अधिक की जावे उतना ही अच्छा है। पर इसके लिए बजट में जो भी रकम रक्खी गई है या रक्खी जाती है वह इतनी कम है कि सब की माँग एक साथ पूरी नहीं की जा सकती, पर इसमें इन एरियाज़ का भी वैसा ही ध्यान रक्खा जाता है जैसा कि अन्य एरियाज़ के सम्बन्ध में ध्यान रक्खा जाता है।

पिछले साल जितने भी औषधालय खोले गये थे उनके सम्बन्ध में भी इस बात का ध्यान रक्खा गया और अनुपात के हिसाब से करीब-करीब वैसे ही उन इलाकों में भी औषधालय खोले गये, जिस तरह से कि दूसरे इलाकों में खोले गये। इतना कुछ होते हुए भी उन्होंने अपने उस क्षेत्र के लिए, जिस शेरगढ़ क्षेत्र से वे चुनकर आये हैं एक बात कही है कि शेरगढ़ के आस-पास के १०० मील के क्षेत्र में कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसमें भी यह बतला देना चाहता हूँ कि शेरगढ़ खास में एलोपैथिक डिस्पेन्सरी है और उसमें एक कस्बा है बालोतरा, वहाँ एक औषधालय है। इस तरह से जहाँ तक हो सका है इस तरफ पूरा-पूरा ध्यान रक्खा गया है कि कोई ऐसा क्षेत्र बिल्कुल ही औषधि और स्वास्थ्य की दृष्टि से ओझल नहीं रह जावे और इस बात को ध्यान में रखकर ही सारा काम किया गया है।

इसके साथ-साथ दूसरे एक सदस्य ने रिज़र्व स्टाफ के सम्बन्ध में आपत्ति उठाते हुए कहा है कि यह स्टाफ क्यों रखा जाता है, यह समझ में नहीं आता। इसके बारे में मैं निवेदन कर दूं कि यह इसलिए रक्खे जाते हैं कि यह महकमा हैल्थ का है। इसी तरह से दूसरे भी महकमे जो जन-सेवा के हैं; जैसे शिक्षा, पुलिस आदि और क्योंकि इन विभागों के लोगों को खास तौर से जनता की सेवाओं की जो अपनी जिम्मेवारियाँ अदा करनी पड़ती हैं उनको सामने रखते हुए उनकी सुख-सुविधा और आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है। जो इस काम में लगे हुए हैं उनके लिए यह भी देखना पड़ता है कि इनमें से कोई आदमी बीमार न पड़ जावे या बीमार पड़ गया है तो उसे छुट्टी दी जा सके और इस छुट्टी के कारण उसकी अनुपस्थिति से जन-सेवा में विघ्न न पड़ सके, इसलिए यह रिज़र्व स्टाफ भी हमें रखना पड़ता है। जो बीमार पड़ जावें या और कोई जरूरी काम से छुट्टी

[श्री कुम्भाराम आर्य]

चला जावे तो उनकी जगह की पूर्ति किस तरह से की जावे, अगर यह रिज़र्व स्टाफ हम न रक्खें तो ? उनके स्थान की पूर्ति करने के लिए ही इस तरह का स्टाफ रखा जाता है और इसका भी एक पर्सेंटेज होता है। १० पर्सेंट के हिसाब से राजस्थान में ऐसे लोग रक्खे जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो राजस्थान में लोग हैं इस रिज़र्व स्टाफ में तीन पर्सेंट कम हैं। हम १० पर्सेंट को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इतना करने के बाद भी हाउस में यह प्रश्न किया गया है कि सब जगह वैद्य और डाक्टर लोग पूरी तौर से नहीं रहते हैं। इसी कमी को पूरा करने के लिए इन लोगों को रिज़र्व में रखना पड़ता है, लेकिन यह लोग जो रिज़र्व में रखे हैं इनमें से कोई ऐसा नहीं है कि यह बिना ड्युटी के रहता हो। यह किसी लीव वाले की जगह जाते हैं, छुट्टी वाले के स्थान पर काम करते हैं और छुट्टी वालों से फुरसत होती है तो हैडक्वार्टर जहाँ उनकी नियुक्ति होती है रह कर किसी बड़े अस्पताल में उनको तैनात कर दिया जाता है। इन लोगों की उपयोगिता राजकीय हिसाब से और जनता के हिसाब से दोनों के लिए आवश्यक है और दोनों हिसाब को सामने रखकर ये रक्खे जाते हैं।

दूसरे मित्र ने यह प्रश्न किया है कि राजस्थान के अन्दर डाक्टरों की बड़ी कमी रहती है, सब जगह डाक्टर नहीं पहुँच पाये और एकीकरण नहीं हो पाया है, और उस एकीकरण के सम्बन्ध में छोटी-छोटी सर्विस के लोगों के बारे में कहा गया है और उनमें कम्पाउन्डरों को लिया गया है। मैं यह बतला देना चाहता हूँ कि कम्पाउन्डरों का जो एकीकरण है वह एकीकरण करीब-करीब आधे से ज्यादा पूरा हो चुका है। एक क्लास की लिस्ट निकल चुकी है, दूसरी क्लास की निकल चुकी है और तीसरी क्लास के २४५ आदमियों की निकल चुकी है, और शेष २५२ ऐसे आदमी हैं जिनके केसेज़ पेन्डिंग हैं और उनकी लिस्ट भी जल्दी ही निकल जायगी और वह आखिरी लिस्ट रहेगी और उस लिस्ट के निकल जाने के बाद राजस्थान में इस वर्ग का एकीकरण जो है वह सम्पूर्ण हो जायगा। जो केसेज़ सी. ए. एस. क्लास वन के हैं वे पेन्डिंग हैं। वह लिस्ट भी जल्दी ही प्रकाशित होने वाली है और इसके बाद एकीकरण का कोई प्रश्न शेष नहीं रहेगा और राजस्थान के एकीकरण का मसला सदा के लिए हल हो जायगा।

कम्पाउन्डर्स की तनख्वाह के बारे में एक प्रश्न जो किया गया था, वह भी इसी प्रकार का था क्योंकि एकीकरण के संबन्ध में उनकी सब लिस्टें प्रकाशित नहीं हुई थीं, इसलिए १–१॥ महीना तनख्वाह के लिए इन्तजार करना पड़ा लेकिन इसके वास्ते आइन्दा ऐसा न होने का तय कर दिया गया है और भविष्य के अन्दर इस प्रकार की समस्या सामने नहीं आ सकेगी और न ऐसी कोई शिकायत सामने आयेगी।

जोधपुर के कम्पाउन्डरों की बदली कर देने के संबन्ध में जो प्रश्न था और उसके संबन्ध में यह कहा गया था कि उनको अलग किया हुआ है और हुक्म जारी होने के बाद भी किसी बहाने से सिरोही में उनको लगा दिया गया है। यह बात छोटी नौकरी के सम्बन्ध में है, वह हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट से सम्बन्ध नहीं रखती और सेक्रेटेरिएट से भी सम्बन्ध नहीं है। इसका छोटी भरती से सम्बन्ध होते हुए भी इसकी शिकायत हमारे पास पहुँच जाती तो इस हाउस में यह प्रश्न आने से पहले

[श्री कुम्भाराम आर्य]

ही देख लिया जाता। अब भी यह देख लिया जायगा कि हुक्म के अनुसार काम किया हुआ है या नहीं। अगर हुक्म के खिलाफ कोई भी काम पाया गया तो इसकी रोक थाम की जायगी और उस अफसर का जवाब तलब किया जायगा जिसने कि हुक्म-उदूली की है।

कालन्द्री हॉस्पिटल के बारे में डाक्टर की शिकायत है कि डाक्टरों की कमी है। इस कमी का कारण यह था कि कई मेडीकल स्कूल्स जो थे वे बन्द कर दिये गये थे और दूसरे डाक्टर सी. एस. क्लास २ के वेतन की कमी की वजह से भी कुछ लोग नहीं आ रहे थे। अभी उस वेतन की जो समस्या थी उसका हल किया गया है और इसकी प्रारम्भिक कार्यवाही हो चुकी है और उनका वेतन वगैरह कुछ बढ़ा दिया गया है, और पब्लिक सर्विस कमीशन से ६० आदमियों (डॉक्टर्स) की माँग की हुई है और वह एनकरीब ही हमको मिलने वाले हैं। जब ६० आदमी (डाक्टर) हमें मिल जावेंगे तो राजस्थान के सभी हॉस्पिटल्स में जो डाक्टरों की कमी है वह करीबन पूरी हो जायगी और आगे के लिए समस्या इस प्रकार की नहीं रहेगी कि जिसके लिए सदस्यों को इस काम के लिए कष्ट उठाना पड़े और चिन्ता करनी पड़े।

एक मित्र ने आयुर्वेद विभाग के सम्बन्ध में प्रश्न किया था। वह इस तरह से किया था कि आयुर्वेद विभाग में दो तरह के लोगों की विचारधारा चल रही है। एक वे लोग हैं जो पुरानी विचारधारा के हैं और दूसरे वे लोग हैं जो नई विचारधारा के हैं और वे लोग अपनी विचारधारा की बात चलाने के लिए सदा एक दूसरे पर हावी रहते हैं और इसमें एक दूसरे के खिलाफ कार्यवाही करते रहते हैं। इसके सम्बन्ध में कुछ कागजात गुम किये गये जो जाँच से बरामद किये गये और वह जाँच के कागज दबा दिये गये। इस सम्बन्ध में मैं इतना बतला देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के सामने ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि आयुर्वेद विभाग में २ दल चल रहे हैं, दो पार्टियां चल रही हैं, दोनों की राइवलरी (rivalry) वहाँ काम करती है या शिकायतें आपस में एक दूसरे के होती रहती हैं, तो डिपार्टमेंट का कोई एक आदमी किसी की शिकायत कर सकता है। इस तरह की एक शिकायत जो बतलाई गई उसकी एन्क्वायरी हुई थी तो एन्क्वायरी से वह शिकायत बिल्कुल झूँठी पाई गई और वह झूठी पाये जाने के कारण आगे किसी कार्यवाही की गुन्जाइश नहीं समझी गई। मैं हाउस को यह बतला देना चाहता हूँ और माननीय सदस्य को यह बात बता देना चाहता हूँ कि अगर उनको कोई विश्वास हो, अपने आप पर इस बात का विश्वास रखते हों कि इन्क्वायरी जो हुई है वह गलत हुई है तो वे इसके लिए कोई प्रमाण दें तो हम दुबारा भी एन्क्वायरी कराने का साहस रखते हैं और जो बात सही पाई जायगी और उसको बरामद करने की कोशिश करेंगे तो उचित कार्यवाही की जावेगी। लेकिन इस तरह से सदस्य महोदय की ओर से ऐसी बिना प्रमाण की बात कह देने से कोई काम नहीं बन पायेगा।

दूसरी बात उन्होंने कही कि आयुर्वेद के इन्चार्ज जो हैं वे इस तरह के आदमी हैं कि अँग्रेजी नहीं जानते हैं और अँग्रेजी नहीं जानने की वजह से काम-काज ठीक ढंग से नहीं कर सकते हैं। मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी देना उचित समझता हूँ कि आयुर्वेद की जितनी भी शिक्षा-दीक्षा

[श्री कुम्भाराम आर्य]

होती है वह दो तरह की होती है; एक हिन्दी में और दूसरी संस्कृत के अन्दर, लेकिन अँग्रेजी के अन्दर नहीं। ऐसी हालत में अगर डाइरेक्टर अँग्रेजी नहीं जानता है तो इतनी आपत्ति की बात नहीं है जितनी कि वह समझते हैं कि आयुर्वेद के जो इन्चार्ज हैं वे अँग्रेजी जानें तभी काम चले और अगर अँग्रेजी नहीं जानते तो काम नहीं चलता है। डाइरेक्टर हिन्दी और संस्कृत नहीं जानते हैं तो उसके प्रति आपत्ति की जा सकती है। आयुर्वेद का जो साहित्य और जितनी भी उसकी शिक्षा-दीक्षा की प्रणाली है वह सारी की सारी हिन्दी में है या संस्कृत में। अँग्रेजी जानने वाला आदमी उसकी सीमा में नहीं आ सकता। अँग्रेजी जानने वाला आदमी उतना काम नहीं कर सकता। वर्त्तमान डाइरेक्टर, उस विषय के लिये जो प्रणाली है-उसके ज्ञाता हैं; जो अपने विषय के ज्ञाता हैं। उसके अन्दर अँग्रेजी का नाम उस विषय के लेकर कि वह अपना काम करने में सफल नहीं, यह कहना कोई तर्कसंगत नहीं लगा।

इसी तरह से एक दूसरे मित्र ने इस आयुर्वेद विभाग के सम्बन्ध में कहा था कि आयुर्वेद विभाग तरक्की नहीं कर रहा है। इसके विषय में ऐसा नहीं है कि राजस्थान सरकार सचेष्ट नहीं है राजस्थान सरकार भी यह चाहती है कि राजस्थान के अन्दर आयुर्वेद विभाग फले-फूले और इसके लिए एक बड़े पैमाने पर कोई योजना बनकर अभी तक अपने लोगों के सामने आई हो, ऐसा दिखाई नहीं देता है। लेकिन सरकार फिर भी इस पर विचार करेगी और जल्दी से जल्दी कोई ऐसी योजना बनायेगी जिससे हमारे सभी गाँवों में और ऐसे गाँवों में जिनकी ५ हजार के आस पास आबादी हो उन सब में तो कम से कम आयुर्वेद का प्रसार तो हो ही और यह स्थिति, मैं समझता हूँ सरकार जल्दी से जल्दी ला सकेगी और इस स्थिति के आ जाने के बाद राजस्थान के इस रेगिस्तानी इलाके में जिसके लिए आज यह चिन्ता करते हैं कि वहाँ पर आयुर्वेद की कोई व्यवस्था नहीं है, यह कमी हमारी पूरी होगी और इस काम के पूरा हो जाने के बाद यह शिकायत दूर हो जायगी कि इस इलाके को तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और दूसरे इलाकों की ओर ध्यान सरकार का जा रहा है।

मेरे एक मित्र ने सराड़ा और सालूम्बर की बात कह कर प्रश्न किया था कि डाक्टर नहीं जाता है, यह उनकी शिकायत थी। सालूम्बर के अन्दर इस वक्त डॉक्टर मौजूद है और सराड़ा के अन्दर डॉक्टर नहीं है। उसकी वजह अभी बताई गई है कि हमारे यहाँ डाक्टरों की कमी रही है, वह हमें मिल नहीं पाये हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए हमने वेतन अधिक देने की बात तय की है और पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ६० डॉक्टरों की माँग की गई, जिसके लिए अभी हाल में इन्टरव्यू होने वाला है और इन्टरव्यू हो जाने के बाद इस काम को बढ़ा देने से वह कमी भी पूरी हो जायगी।

दूसरा यह कहा गया है कि आयुर्वेद विभाग को उदयपुर से हटाया जाकर जयपुर लाया जायगा। मैं माननीय सदस्य को इतनी जानकारी देना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है कि उदयपुर से वह विभाग हटाया जाकर जयपुर चला आयेगा। इस विभाग के जो इन्चार्ज हैं वह यहाँ के आयुर्वेद कॉलेज के प्रिन्सिपल हैं और उनकी योग्यता का लाभ दोनों जगह उठाने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि वे जयपुर ही रहें और इस विभाग का काम

[श्री कुम्भाराम आर्य]

करते रहें। इस हिसाब से उदयपुर के अन्दर हैड ऑफिस होते हुए भी उसका केम्प ऑफिस जयपुर के अन्दर है और इस तरह से आयुर्वेद का काम पहले से कहीं अच्छा चल रहा है, ऐसा हमको मान-कर चलना चाहिये और अभी भी ऐसा कोई आदेश राजस्थान सरकार जारी करने की इच्छा नहीं रखती है कि इस विभाग को कतई तौर पर उदयपुर से हटाया जाकर जयपुर लाया जाय।

अस्पताल के मकानों के बारे में भी प्रश्न था कि सरकार ने वहाँ अस्पताल तो खोल दिया है, लेकिन मकान नहीं बना है। मैं माननीय सदस्य को बतलाना चहता हूँ कि यह अस्पताल जागीर के गाँव में जागीरदार की ओर से खुला हुआ था, वह राजस्थान सरकार को जागीर की ओर से मिला और इस मकान को बनाने के लिए सरकार उस वक्त तक सचेष्ट रहेगी जब तक कि इसकी एक-एक कमी को पूरा नहीं कर दिया जाय,लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे हॉस्पिटल हैं जो कि बड़े-बड़े स्थानों पर हैं, लेकिन उनके मकानात की कमी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। जब तक उनकी कमी को पूरा नहीं कर दिया जाय तब तक इस छोटी जगह का नम्बर आना कठिन होगा। भिषगाचार्य के विद्यार्थियों को उदयपुर में पढ़ने की जो आज्ञा मिली हुई थी उसको बन्द कर दिया गया; इस बारे में मैं इतना निवेदन करना उचित समझता हूँ कि उदयपुर में भिषगाचार्य में जो विद्यार्थी पढ़ते थे उनके पढ़ने के लिए राजस्थान सरकार ने कोई आज्ञा नहीं निकाली थी। पिछली बार वहाँ के प्रिन्सिपल ने कुछ विद्यार्थियों को जिनकी संख्या दो थी जो बहुत ही कम कही जानी चाहिए भरती कर लिया। उसमें कुल लड़कों की तादाद १८ है। इतने कम लड़कों के होते हुए इतनी बड़ी कॉलेज चल सके यह कठिन दिखाई देता है। इस तरह के कॉलेज और ऐसे विद्यार्थियों के लिए इतना बड़ा अस्पताल चाहिये कि जिसमें कम से कम ५० बेड्स हों। जब इस प्रकार का अस्पताल हो जायगा तब इस विषय में कुछ कहा या सोचा जा सकता है। जब तक ऐसी स्थिति नहीं हो जाय इस काम को पूरा करना कठिन हो जाता है।

एक सदस्य महोदय ने भीलवाड़ा के अन्दर होस्पिटल बन जाने के बाद डॉक्टर के लिए मकान और बनाने के लिए विशेषरूप से आग्रह किया और यह भी कह दिया कि जब तक मकान नहीं बनाये जायंगे बड़ी कठिनाई होगी। मैं हाउस को बताना चाहता हूँ कि पुराना होस्पिटल था उससे काम चल रहा था और नया हॉस्पिटल बन जाने के बाद पुराना हॉस्पिटल खाली हो गया; वह सारा का सारा स्टाफ के काम आ रहा है। उसमें डी. एम. एच. ओ., कम्पाउन्डर्स, सरवेन्ट्स आदि रहते हैं और बहुत कुछ मकानों की समस्या पूरी हो रही है।

श्री तेजमल बापना—On a point of order, sir, क्या पुराने हॉस्पिटल में मेटर्निटी का काम नहीं हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष—This is no point of Order.

श्री कुम्भाराम आर्य—(भाषण जारी रखते हुए) डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में मकानों की समस्या कम करने का सरकार ध्यान रखती है।

[श्री कुम्भाराम आर्य]

पुर के आयुर्वेद औषधालय के बारे में कहा गया कि तहसील के बाहर नहीं जाना चाहिये और दूसरे सज्जन ने कहा था कि यह बाहर जाना चाहिये। मैं दोनों के सुझावों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह पुर से उठ कर रायला जा रहा है। पुर में पहले से ही डिस्पेन्सरी है इसलिए वहाँ आयुर्वेद एड पोस्ट रखना जरूरी नहीं है। इसके साथ-साथ कुछ और मित्रों ने प्रश्न किये हैं, कई बातें कहीं हैं उनको ब्यौरेवार कहने के बजाय छोटे रूप में कह दूँ तो ठीक रहेगा। रायला के हॉस्पिटल के बारे में कहा गया है कि यह हॉस्पिटल तैयार हो गया तो इसका ताला खोलने को कोई तैयार नहीं; इसलिए कि ताला खोला जाय तो इसे चालू भी रखना पड़ेगा। मैं, माननीय अध्यक्ष, बताना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार ने इस हॉस्पिटल के लिए आदेश दिया है कि वह हॉस्पिटल खुले और यह कार्य जल्दी से जल्दी होने वाला है और सब तैयारी राज्य की ओर से हो चुकी है। (हियर-हियर)

यह भी कहा गया कि डॉक्टर लोग जो होते हैं वे दूकानदारों से मिले हुए होते हैं और दवाइयाँ बेचने में अपना हिस्सा रखते हैं तथा जो दवाइयें हॉस्पिटल के लिए होती हैं उनको वहाँ नहीं रखा जाता, इसलिये इलाज की व्यवस्था ठीक नहीं है और काम ठीक नहीं होता है। सरकार के सामने आज से पहले किसी माननीय सदस्य ने इस प्रकार की शिक़ायत पेश नहीं की और न प्रमाण ही दिये।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—यह बात हर साल कही जाती है।

श्री कुम्भाराम आर्य—(भाषण जारी रखते हुए) मैं अपील करता हूँ और आशा करता हूँ कि उनके पास इस प्रकार के प्रमाण हों तो वे दें, उस पर अवश्य कार्यवाही की जायगी। सब प्रकार की व्यवस्था करने के लिए सरकार तैयार है ताकि जनता की सेवा ज्याद से ज्यादा की जा सके।

एक मित्र ने कोटा के हॉस्पिटल की बात कही। उन्होंने कहा कि उसके लिए ३५ लाख रुपये मन्जूर हुए थे और वह रकम घटते-घटते अब ७॥ लाख रही। (हियर : हियर) यह जो बात उन्होंने कही उससे मैं सहमत नहीं हूँ क्योंकि सरकार के आँकड़ों में कहीं भी इस प्रकार की रकम नहीं मिलती है कि पहले ३५ लाख रुपये सेंकशन हुए और फिर घटते-घटते ७॥ लाख रुपये रखे गये। सरकार के पास जो आँकड़े हैं उनसे पता चलता है कि पी. डब्ल्यू. डी. ने तखमीना दिया है वह यह है कि ७॥ लाख रुपयों में १५० बेडस वाला हॉस्पिटल बन जायगा। जब यह विभाग इतनी रकम वाजिब समझता है तो फिर इससे अधिक की सरकार से माँग करना और मन्जूर करवाना मैं उचित नहीं समझता।

एक सदस्य महोदय ने अजीब बात कही कि स्कूल के मास्टरों को आयुर्वेद और एलोपेथिक की शिक्षा दी जाय और वे गाँवों में बच्चों को पढ़ावें और लोगों के पट्टी भी बांधते फिरें। इस व्यवस्था के साथ-साथ जो लोग इन विभागों के इन्चार्ज हैं उनको व इन दोनों विभागों के मिनिस्टरों

[कु॰ श्री जसवन्तसिंह]

को मिलकर काम करना चाहिये। मैं इस सम्बन्ध में इतना कहना चाहता हूँ कि पढ़ानेवाले मास्टरों को इस काम में लगाया गया तो वे लोग बच्चों को नहीं पढ़ा सकेंगे। जिस शिक्षा में वे निपुण हैं उसके प्रतिकूल दूसरी तरह की शिक्षा में निपुण होने में उनको समय लगेगा। यदि समय का सवाल है तो दूसरे लोगों को ही तैयार क्यों न किया जाय जिससे कि बेकारी की समस्या हल हो। एक ही को दो काम देना वाजिब नहीं होगा। इसके अलावा सरकार इस बात के लिये सचेष्ट है कि अधिक से अधिक दाइयें, नर्सें, कंपाउन्डर्स, वैद्य आदि रखे जावें और इसके लिए व्यवस्था करें। जहाँ तक हो सकेगा इस तरफ अधिक से अधिक ख्याल रखा जायगा।

एक सदस्य महोदय ने यह आपत्ति की कि मेडिकल विभाग का जो बजट पास हुआ था उसमें से बहुत सी रकम बच गई थी जो बचनी नहीं चाहिये थी। इस बारे में, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि मेडिकल डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ रकम खेंच-तान कर नहीं रखी जा सकती। खाने-पीने की बात ही को लीजिये। इसमें इतनी कमी नहीं की जा सकती या इतना नहीं रखा जा सकता कि बीच ही में खत्म हो जाय और मरीजों को रोटी देने के लिए ही कुछ न बच पावे। रकम अन्त में बच जाय तो इसमें हर्ज नहीं है। इसलिए स्वाभाविक है कि जब बजट बनाया जाता है तब पूरा ध्यान रखा जाता है कि वह कम न हो जाय। इसका मतलब यह नहीं समझना चाहिये कि कुछ खर्च नहीं किया जाता है। इसमें किसी तरह की कंजूसी नहीं की जाती है।

दवाइयों के बारे में भी यह कहा गया था कि इस बार दवाइयाँ कम खरीदी गईं। मैं हाउस को बताना चाहता हूँ कि दवाइयाँ कम खरीदीं इसका कारण यह था कि इस बारे में नये नियम बन रहे हैं। जब तक नियम नहीं बनें तब तक दवाइयां नहीं खरीदी गईं और जो पुराना स्टोक जमा था उससे काम चलाया।

अब वह रूल्स बन चुके हैं और आगे के लिए ऐसे प्रश्न कभी पैदा नहीं होंगे कि दवाइयाँ नहीं खरीदी गईं और होस्पिटल्स में समय पर नहीं पहुँचीं।

मेरे एक माननीय सदस्य ने बीकानेर के बारे में खास तौर से काफी तवज्जोह दिलाई और साथ-साथ इस तरह का स्लोगन (slogan) भी दिया जो अपने क्षेत्र के नाम से था। मैं हाउस को बता देना चाहता हूँ कि इस तरह के स्लोगन से तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है। फिर भी मैं माननीय सदस्य को बता दूँ कि बीकानेर की तरफ हमारा ध्यान कम नहीं है और हमें पूरी तरह उसका खयाल है।

रेडियोलोजिस्ट के बारे में उन्होंने कहा था, इसके लिये मैं यह बता देना चाहता हूँ कि श्री विष्णुदत्त शर्मा जो बाहर ट्रेनिंग के लिये भेजा गया था, वे अगस्त तक लोटने वाले हैं और उनके आते ही यह कमी पूर्ति हो जायगी। वहाँ लेडी डॉक्टर भी ऐसी है जो प्रसूति शास्त्र की पूर्ण ज्ञाता हैं।

बाले की बीमारी का प्रश्न इस तरीके का आया था कि जिसके सम्बन्ध में मैं कह देना चाहता हूँ। बाले की बीमारी के सम्बन्ध में सरकार सचेष्ट है और इस बीमारी की रोक-थाम के बिना हम बहुत

[कु॰ श्री जसवन्तसिंह]

ज्यादा लाभ अपनी जनता का नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे बड़ी रोक जो आ रही है वह यह है कि बाले की बीमारी पानी से चलती है। जब तक हम गन्दा पानी, जो शुद्ध नहीं है, ऐसे पानी का उपयोग पीने में करते रहेंगे तब तक इस बीमारी की रोक-थाम नहीं हो सकती। इसलिये पानी को जल्दी से जल्दी शुद्ध किया जाय। इसके लिए सरकार सचेष्ट है और पंचायतों के जरिये लाखों रुपया हर साल इस तरह के काम की तरक्की के लिए खर्च किये जा रहे हैं। इस काम की ज्यों-ज्यों तरक्की होती जायगी, यह काम लाभदायक सिद्ध होता जायगा और नेहरुवा की बीमारी कम होती जायगी। जहाँ तालाबों का पानी पीने के काम में लाया जाता है वहाँ यह बीमारी होती है, इसलिए कूओं का इन्तजाम किया जा रहा है। इस साल भी २,५०,०००) रुपया राजस्थान सरकार इस काम के लिए खर्च करेगी; जो खास तौर से ऐसे कामों में खर्च करेगी कि कूए ज्यादा से ज्यादा बनाये जाँय जिससे इस बीमारी खत्म किया जा सके।

एक डॉक्टर के बारे में बात कही गई जो हाथ से बाले निकालता है। मैं कहता हूँ कि इस तरह के उपचार राजस्थान के हर गाँव में चलते हैं। राजस्थान में कोई गाँव शायद ऐसा नहीं होगा जहाँ एक न एक आदमी हाथ से बाले को निकालने की बात नहीं जानता हो। हाँ, यह बात हो सकती है कि वह व्यक्ति जिसका सदस्य महोदय ने नाम लिया है सबसे अधिक निपुण हो सकता है, परन्तु यह बात नहीं कि उसके सिवाय राजस्थान में इस तरह का काम और कोई नहीं जानता हो। राजस्थान में सब गाँवों में लोग इस तरह बाले निकालते हैं, पर इसके साथ एक डर रहता है कि वह बाला अगर बीच में रुक जाता है तो ज्यादा नुकसान पहुँचाता है। इस डॉक्टर में ऐसी विशेषता बताई जाती है कि जिस बाले के हाथ लगाता है उसको बीच में नहीं रुकने देता। इसमें हाथ की विशेषता है, दवाइयों से निकालता हो, ऐसी बात नहीं है। पूरे राजस्थान में गाँव-गाँव में कोई न कोई आदमी ऐसा मिल ही जायगा जो बाले को निकालता है। हरिजनों में खास तौर से इस कला को जानने वाले बहुत हैं। ऐसी सूरत में इसका अलग हॉस्पिटल खोल दें और उस डॉक्टर को उस अस्पताल का इन्चार्ज बना दें, यह ठीक नहीं है। बाले की बीमारी के बारे में राजस्थान सरकार इसकी रोक-थाम करने के लिए सचेष्ट है।

मेरे एक माननीय सदस्य ने एक डॉक्टर के बारे में शिकायत की कि वह चार पैसे लिए बिना किसी की आँख में दवाई भी नहीं डालता। इसके बारे में इन्क्वायरी हुई है और इन्क्वायरी होने पर यह बात बिल्कुल झूठ पाई गई है, इतनी झूंठ पाई गई है कि हम डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सके।

श्री मानसिंह (महार)—On a point of information, Sir.

श्री कुम्भाराम आर्य—(न रुक कर भाषण जारी रखते हुए) तो मैं कह देना चाहता हूँ कि वे अपने प्रमाण दें। मैं यह हाउस में ऐलान के साथ कह देना चाहता हूँ कि कोई भी उनके पास इस प्रकार के यदि प्रमाण हों तो हमें दें, हम दुबारा इसकी इन्क्वायरी कराने को तैयार हैं, जिस तरह

[श्री कुम्भाराम आर्य]

से भी कराने को तैयार हों—करने के लिए तैयार हैं। इस पर भी झूठ साबित हो तो माननीय सदस्य ऐलान करें कि वे क्या करेंगे ?

कुँवर श्री जसवन्तसिंह—वे विद्ड्रा कर लेंगे।

श्री मानसिंह (महार)—नहीं मैं विद्ड्रा नहीं करूँगा। On a point of information, Sir.

श्री कुम्भाराम आर्य—मेरे उन्हीं माननीय सदस्य की यह भी एक शिकायत थी कि...

श्री मानसिंह (महार)—On a point of information. Sir...

श्री अध्यक्ष—He dose not want to yield, I do not allow.

(श्री कुम्भाराम बैठ जाते हैं)

श्री मानसिंह (महार)—He has yielded.

श्री कुम्भाराम आर्य—(पुनः खड़े होकर अपना भाषण जारी करते हुए) यह शिकायत थी कि......

(हँसी)

डॉक्टर फीस अधिक लेते हैं। इस तरह की शिकायत हमारे पास नहीं है। इस तरह की शिकायत हो तो माननीय सदस्य को हमें देना चाहिए। हमें, यह बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा। इसलिए हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि इस तरह की डाक्टरों की शिकायतें यदि हों तो हमारे पास पहुँचाने की कोशिश करें, हम उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

एक सदस्य ने कहा कि सिरोही के अन्दर डॉक्टर नहीं है और वहाँ बहुत दिनों से यह जगह खाली पड़ी है। डॉक्टर के बारे में मैं पहले ही इतना कह चुका हूँ कि डॉक्टरों की कमी रही है और उसको पूरा करने की व्यवस्था हमने कर ली है और यह कमी अब नहीं रहने वाली है।

इन थोड़े से शब्दों के साथ में हाउस को जानकारी देते हुए निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—Yes, now the Cut motions,

श्री जवानसिंह—मुझे सदन इजाजत दे कि मैं अपने कट मोशन वापिस लूँ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन श्री जवानसिंह को अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान करता है ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान हुई ।

श्री जवानसिंह—मैं अपना कट मोशन वापस लेता हूँ ।

श्री तेजमल बापना—I also want to withdraw my cut motion.

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House to allow Shri Bapna to withdraw his cut motion.

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री तेजमल बापना—I withdraw my cut motion.

श्री सोहनलाल भटनागर—I beg leave to withdraw my Cut motion.

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House to allow Shri Bhatnagar to withdraw his Cut motion.

(स्वीकृत)

आज्ञा दी गई ।

श्री भटनागर—I withdraw my Cut motion.

श्री खेतसिंह—माननीय अध्यक्ष, मुझे कोई खास आश्वासन तो मन्त्री महोदय द्वारा नहीं दिया गया है, फिर भी मैं अपना कट मोशन वापिस लेने की सदन से आज्ञा चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House to allow withdrawal.

(स्वीकृत)

आज्ञा दी गई ।

श्री खेतसिंह—मैं अपना कट मोशन वापिस लेता हूँ ।

श्री तनसिंह—मेरी बातों को तोड़-मरोड़ कर सत्य को बिल्कुल बेढंग कर दिया गया है, फिर भी मैं अपना कट मोशन वापिस लेता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House to allow withdrawal,

(स्वीकृत)

आज्ञा दी गई ।

(विराम)

Cut motion by Shri Brij Sunder Sharma.

श्री तनसिंह—I withdraw my Cut motion.

श्री मथुरादास माथुर—(श्री बृज सुन्दर के कटौती प्रस्ताव के लिए) If you permit me I can withdraw.

श्री अध्यक्ष—No. The question is that cut motion moved by Shri Brij Sunder Sharma be accepted.

(अस्वीकृत)

The cut motion is dropped.

(विराम)

The question is that the cut motion by Shri Abani Kumar be accepted.

(अस्वीकृत)

The Cut motion fails.

(विराम)

The question is, "That a sum not exceeding Rs. 1,28,35,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1955 in respect of Grant No. XVII, Major Head 38 - Medical."

(स्वीकृत)

The demand is passed.

जन स्वास्थ्य-१८

The motion is "That a sum not exceeding Rs. 66,29,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1955 in respect of Grant No. XVIII. Major Head 39—Public Health."

(विराम)

Cut motion by Shri Tej Mal Bapna.

श्री तेजमल बापना—('To discuss the water requirements of Gandhi Hospital Bhilwara and rural areas of the district.) अध्यक्ष महोदय, मेरा तो साधारण सा कट मोशन जो है वह यह कि भीलवाड़े में जो हॉस्पिटल है उसमें पानी की बहुत कमी है। ऐसे तो वहाँ पर कोई वाटर-वर्क्स नहीं हैं। कूए हैं, इसलिए एक इन्जिन और एक पम्पिग सेट की माँग की है। बस यही मेरे कट मोशन का मतलब है।

श्री अध्यक्ष—I have received some 11 cut-motions tabled by six members. They ere ruled out of order being time-barved.

श्री चाँदमल महता—मैंने मेरा कट-मोशन ता: १६ को भेज दिया था और वह १७ को ही मिलना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष—It was received on 18th.

(विराम)

I can allow the Members only if they catch my eye and if they confine themselves to the cut-motion moved by Shri Bapna.

श्री माधोसिह (भैंसवाडा)—अध्यक्ष महोदय, हैल्थ डिपार्टमेंट के बारे में जो अभी कहा गया है उसके बारे में दो-तीन शब्द मैं भी कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, यह बात कहनी तो बड़ी आसान हो जाती है कि फलाँ-फलाँ विभागों में रुपया बढ़ाया जावे और फलाँ-फलाँ जगह खर्च किया जावे। जहाँ तक इस बिल (माँग) में विरोधी पक्ष का सवाल है मैं यह अर्ज करता हूँ कि वे कहते हैं कि फलाँ जगह होस्पिटल खोले जावें, स्कूलें खोली जावें, सड़क के बनाने पर (हियर, हियर) और नये टेक्स नहीं लगाये जावें तथा कर्मचारियों की भी तनख्वाह बढ़ा दी जावे। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार को चलाने के लिये वे पैसों का दूसरा जरिया कौनसा जानते हैं? वे यह कहते हैं कि बजट पर इतना खर्चा करें, टैक्स नहीं लगावें मगर इसके साथ-साथ, मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि सरकार का यह फर्ज होता है कि वह अपने बजट को बेलेन्स्ड करे, परन्तु किसी पर टैक्स नहीं लगावें। इस जमाने में टैक्स लगाने की जो जन-तन्त्र प्रणाली है उसके अनुसार भी टैक्स नहीं लगावें। जब सरकार टैक्स नहीं लगाती है तो फिर आप जो माँगे पेश करते हैं उनकी पूर्ति कैसे हो सकती है। अभी आपने हैल्थ पर माँग पेश की उसमें सरकार को खर्च करने के लिये की है कि सरकार उस पर खर्च करे और सरकार पब्लिक के लिये करती है। मैं आप लोगों से और खास तौर से विरोधी पक्ष के लोगों को (करतल-ध्वनि) यह कहूँगा कि उनको यह ध्यान देना चाहिये कि पैसा कहाँ से आवेगा, पैसा पब्लिक से ही आवेगा और वह उनके लिये ही खर्च कर दिया जावेगा...

श्री तनसिंह—On a point of order, Sir......

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !!

श्री तनसिंह—ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, आपने फरमाया था कि तेजमल बापना ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उस पर ही......

श्री माधोसिह—मैं उसी पर बोल रहा हूँ—

श्री अध्यक्ष—The House can treat it as a maiden speech.

(हँसी)

श्री माधोसिंह—मैं खास कर अपने विरोधी पक्ष के लोगों से जिन्होंने सरकारी बजट पर अपनी माँगें पेश की हैं (घंटी) इसके लिए अर्ज कर देना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष, अगर आप इजाजत दें तो इस पर कहूँ।

श्री अध्यक्ष—No.

श्री माधोसिंह—तो, मैं हैल्थ डिपार्टमेंट के बारे में कहूँगा कि श्री बापना ने एक ही जरिये को दृष्टिकोण में रख कर कहा है और मैं यह कहना चाहता हूँ कि ऐसी तो बहुत सी जगहें हैं जहाँ सरकार को होस्पिटल खोलने की माँग है; मगर सरकार को यह ध्यान रखना पड़ता है कि जो पैसा खर्च किया जावे उसको ढंग से किया जावे और व्यवस्था से किया जावे।

("हियर-हियर" तथा श्री अध्यक्ष द्वारा घंटी बजाना)

श्री जवानसिंह— × × × ×

श्री माधोसिंह—XXXXमाननीय सदस्य से ये शब्द वापिस लिवाये जावें। मैं इन शब्दों को हाइली ओब्जेक्शनेब्ल (highly objectionable) समझता हूँ। माननीय सदस्य को विद्ड्रा करना चाहिये।

श्री भैंरूँसिंह—आपने तरक्की की है।

श्री माधोसिंह—I rise to object to the Hon'ble Member.

श्री अध्यक्ष—It is no use wasting jokes on people who do not like them.

श्री शम्भूसिंह—अध्यक्ष महोदय, श्री तेजमल बापना ने भीलवाड़ा के मुत्तल्लिक पानी न मिलने के सम्बन्ध में जो कट मोशन उपस्थित किया है उस विषय पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा में पहले पुराना होस्पिटल था लेकिन कुछ अर्से पहले उसको महात्मा गाँधी होस्पिटल के नाम से अंकित कर दिया गया है। वह बीमारों के रहने के लिये काफी गुंजायश का है और सब तरह के सामान से करीब-करीब संपन्न है, लेकिन इतना होते हुए भी वहाँ पर पानी का अभाव ही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को यह महसूस कराना चाहता हूँ कि वहाँ जब पानी का अभाव है तो दूसरे सभी साधन किसी तरह से सक्सेसफुल (successful) नहीं हो सकते। अध्यक्ष महोदय, पानी की कमी से सफाई का प्रबन्ध नहीं होता और न बीमारों को पानी मिलता है और न उसकी वजह से दूसरी जरूरतें पूरी हो सकती हैं; जैसे सफाई। मेरा यह मतलब है कि जितने साधन होस्पिटल के बनने से प्राप्त हो सकते हैं वे एक तरह से बगैर पानी के बेकार से लगते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये आयुर्वेद विभाग के मिनिस्टर महोदय का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि जनता के इस अभाव को शीघ्र से शीघ्र दूर करें। भीलवाड़ा

XXXX श्री अध्यक्ष की आज्ञा से कार्य-विवरण में से हटाये गये।

[श्री शम्भूसिंह]

एक बहुत बड़ा जिला है जिसमें बहुत से गाँव ऐसे हैं जहाँ पीने के पानी का सन्तोषजनक प्रबन्ध नहीं है। आम तौर पर पानी के वास्ते लोग कूओं पर जाते हैं, कूओं के वास्ते भारत सरकार ने एड दी थी, राजस्थान के लिए काँट्रीब्युशन (Contribution) हुआ था मगर, भीलवाड़ा का दुर्भाग्य है कि उसको उस काँट्रीब्युशन से बिल्कुल लाभ नहीं मिला। न वहाँ के कुओं की जाँच-पड़ताल होती है और न उनमें दवाइयाँ ही डाली जाती हैं। इससे वहाँ कोलेरा और अन्य एपेडेमिक बीमारियों के फैलने का सदा भय बना रहता है। नेहरू की जो बीमारी उधर बहुत मात्रा में फैलती है वह पानी की अशुद्धता के कारण ही फैलती है; दूषित पानी पीने से ही फैलती है। वहाँ पर कई बावड़ियाँ हैं जिनमें सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, लोग उन सीढ़ियों के जरिये अन्दर जाकर पानी लेते हैं। इस प्रकार बावड़ियों में छूआछूत के न रहने की वजह से वहाँ स्वच्छता नहीं रह सकती और यह स्वच्छता की दृष्टि से उचित नहीं कि लोग सीढ़ियों के जरिये कूओं में उतरें और पानी को गन्दा करें। आम तौर पर जो लोग बावड़ियों का पानी पीते हैं उनमें अधिकाँश में नेहरू की बीमारी होती है, कम से कम बावड़ियों की मरम्मत और उनमें दवाई डालने का प्रबन्ध तो अवश्य सरकार की ओर से होना चाहिये। इस तरफ न तो ग्राम-पंचायतें ही ध्यान देती है और न जहाँ म्युनिसिपैलिटी है वहाँ के म्युनिसिपल अधिकारी ही ध्यान देते हैं।

स्वास्थ्य विभाग की जो हालत है वह और भी अफसोसजनक है। वहाँ कभी कोई स्वास्थ्य विभाग का अफसर दौरे में नहीं जाता है, इस जिले में वे दौरा करते ही नहीं। माननीय अध्यक्ष, मैं आपके जरिये हाउस को बतला देना चाहता हूँ कि जिस इलाके पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का ध्यान न हो उस इलाके के स्वास्थ्य की क्या दशा हो सकती है, यह आपही के सोचने का विषय है। अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा जिले की जो हालत मैंने आपके समक्ष रखी कि वहाँ के अस्पताल में पानी की कमी रहती है, गाँवों में पानी की ठीक व्यवस्था नहीं है, इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि आप वहाँ के कष्ट शीघ्र ही निवारण करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री चाँदमल मेहता—माननीय अध्यक्ष, मैं भी अपने कट मोशन पर कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। मेरा अपना कट मोशन नोटिस ऑफिस में १२ बजे पहले आ चुका था, लेकिन वह लिस्ट में नहीं लिया गया।

श्री अध्यक्ष—(श्री मेहता को पत्र दिखाते हुए)

You can come and see the papers. It was received on the 18th.

श्री कुम्भाराम आर्य—माननीय अध्यक्ष, सदस्य महोदय ने भीलवाड़ा के सम्बन्ध में, पानी की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में विशेषरूप से ध्यान देने की बात कही है। मैं इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य को जानकारी दिला देना चाहता हूँ कि सरकार के सामने ऐसी दिक्कतें या प्रोपोज़ल्स (proposals) बनकर न तो जनता की तरफ से आये हैं, न कोई वहाँ के पब्लिक की डिमान्ड ही आयी है इसलिये मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूँगा कि वे इस सम्बन्ध में सरकार से लिखा-पढ़ी

[श्री शम्भूसिंह]

करें । सरकार इस सम्बन्ध में विचार करके जितना हो सकेगा, मदद करेगी। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूँ कि माननीय सदस्य अपनो कटौती प्रस्ताव वापिस लेंगे।

श्री तेजमल बाफना--माननीय मन्त्री महोदय ने जो फरमाया है, माननीय अध्यक्ष, मैं आपके जरिये माननीय मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि भीलवाड़ा में वाटर पंप के लिये काफी अर्से से लिखा जा चुका है। ऐसा मालूम होता है कि यह शायद डिपार्टमेंट तक पहुँच चुका है। उस ओर मन्त्री महोदय ने जैसा फरमाया कि ध्यान देंगे, इसलिये इस आश्वासन पर मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष--क्या सदन की यह आज्ञा है कि श्री तेजमल बापना अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस लें।

(आज्ञा प्रदान की गई)

श्री तेजमल बाफना—I withdraw it.

श्री अध्यक्ष—The question is,"That a sum not exceeding Rs. 66,29,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1955, in respect of Grant No. XVIII, Major Head 39--Public Health."

(स्वीकृत)

The demand is granted.

माँग संख्या १९–कृषि

The motion is,"That a sum not exceeding Rs. 37,70,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1955, in respect of Grant No. XIX, Major Head 40-- Agriculture."

(विराम)

Cut motion by Shri Jawan Singh.

श्री जवानसिंह—[To discuss failure for providing better facilities to agriculturests.] माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा हमारी सरकार का ध्यान मैं खासतौर से काश्तकारों को जिस कदर सहायता की जा सकती है उस ओर दिलाना चाहता हूँ। जहाँ तक राजस्थान और हिन्दुस्तान के दूसरे भागों में इरिगेशन फेसीलिटीज़ (सिंचाई–सुविधायें) ज्यादा से ज्यादा दिये जाने के लिए पंच–वर्षीय योजना में स्थान दिया गया है और जैसा स्थान राजस्थान को दिया गया है उसका जरूर मैं अभिनन्दन करता हूँ लेकिन इसके साथ साथ मैं, माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमारे राजस्थान में,जहाँ चम्बल और भाखरा

[श्री शम्भूसिंह]

जैसी योजनायें नहीं पहुँच सकती, ऐसे बहुत से हिस्से हैं, जैसे जैसलमेर का कुछ हिस्सा, बीकानेर का और काफी हिस्सा जोधपुर का है अब जहाँ पर ऐसी योजनायें, जैसा कि मैंने जिक्र किया, चम्बल और भाखरा नांगल जैसी योजनायें, जवाई बान्ध बना है, ऐसी योजनायें नहीं बन सकती उन इलाकों में जहाँ पर पानी इतनी ज्यादा तादाद में नहीं मिलता है। इस कारण वहाँ पर योजनायें नहीं बन पा रही है तो वहाँ पर कृषि के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मुझे ऐसी सूचना प्राप्त है कि अब तक पूरे राजस्थान का इस दृष्टिकोण से कोई सरवे या जांच नहीं हो पाई है, यह वाकई में दुख की बात है। जहाँ पर पानी के साधन उपलब्ध हैं वहाँ पर अवश्य ज्यादा ध्यान दिया जाता है लेकिन प्रश्न तो यह है कि उन स्थानों पर जहाँ पर आज तक सिंचाई के लिये योजनायें नहीं वहाँ पर सिंचाई के साधन उपलब्ध करने के लिए सरकार क्या कर रही है? जहाँ तक सरकार का सम्बन्ध है उन लोगों को सहायता उतनी ही आवश्यक है जितनी कि और स्थानों की जनता के लिए। इसलिए इस ओर मैं खास तोर से सरकार को नये कूए खुदवाने के लिए और जो कूए हैं उनको ज्यादा गहरे करने के लिए निवेदन करूँगा। जहाँ पर केवल कुओं द्वारा ही सिंचाई हो सकती है वहाँ पर यह आवश्यक है कि सरकार उचित ध्यान दे। वहाँ के किसानों को अपनी जमीन में कूए खुदवाने के लिये धन से भी सहायता दे, ताकि मामूली किसान भी अपनी जमीन में कूआ खुदवा सकें, उसका सारा खर्चा सरकार को बर्दाश्त करना चाहिये। जिन कूओं में पानी नहीं उनके लिए भी सरकारी मदद से कूए गहरे करवाये जांय और इस तरह से उनका पानी भी ज्यादा गहरा करना आवश्यक है। खासतौर से राजस्थान में जो अकाल की परिस्थितियाँ हर साल सिर पर मंडराया करतीं है उसमें कुछ हद तक कमी हो सकेगी। खासतौर से उन स्थानों पर, जोधपुर के उन स्थानो पर जहाँ पर सिंचाई की योजनायें नहीं, जहाँ पर ये साधन नहीं हैं, उस ओर सरकार द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिये।

अब मैं इस महकमे में आये कुछ ऐसे औजारों की ओर, जिनकी खरीद में सरकार ने काफी पैसा व्यय किया है और जिनकी आज कहीं भी, जिनकी कीमत दी गई है, उतनी सरकार को नहीं मिल रही है, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करूँगा और माननीय अध्यक्षजी, इस सदन में बार बार प्रश्न पूछने के बाद भी यह प्रश्न अब भी सरकार के सामने रह जावेगा कि जो मशीनरी सरकार ने काफी अरसे पहले खरीदी थी, जिसकी कीमत ८० हजार थीं उसका कोई भी लाभ राजस्थान की जनता को नहीं हुआ, राजस्थान की सरकार को भी नहीं हुआ। उसका खर्चा, उसका डेप्रिसियेशन चार्ज (depriciation charge) ही केवल प्रति दिन १०) रुपये के हिसाब से आता है और यह सारा का सारा पैसा, ऐसा खयाल किया जाता है कि शायद उसकी टैकनिकल डेप्रिसियेशन के हिसाब की आँकी जावे तो मलूम होगा कि उस एग्रीकल्चर की मशीन का आज पूरा का पूरा खात्मा हो चुका है और वह राजस्थान की जनता के लिए किसी प्रकार भी उपयोगी सिद्ध नहीं हो पायी है। सिर्फ इसके अलावा और कुछ न हुआ कि एक-दो बार एग्जीबिशन्स में वह उठाकर रख दी गई थी और लोगों को दिखा जरूर दी गई थी। बाकी काम के लिहाज से ये ८० हजार रुपये पानी की तरह से बेकार बहा दिये गये हैं।

इसके अलावा केन्द्रीय सरकार की मदद से हमारे राजस्थान के अलवर जिले में कुछ पम्पिंग सैट्स भी लगाये गये हैं। मुझे जहाँ तक सूचना प्राप्त हुई है उसके आधार पर, अध्यक्ष

Page No.108

[श्री शम्भूसिंह]

महोदय, आपकी मार्फत मैं इस सदन से निवेदन करूँगा कि उन पम्पिंग सैट्स में से काफी तादाद में बिल्कुल बेकार गये। इनके द्वारा जिनकी सहायता राजस्थान सरकार करना चाहती थी उनकी सहायता करने के बजाय उन पम्पिंग सैट्स में से काफी सैट बेकार पड़े रहे जिनमें से काफी लोग चुराकर ले गये और मालूम पड़ता है तीन-चार महीनों की सरकारी जाँच के बाद पता लगा कि लाखों रुपयों का खर्चा ऐसा हुआ कि जिसका हिसाब मिलना भी मुश्किल हो गया। तीन-चार महीनों तक आपने अफसर मुकर्रर करके जाँच करवाई और फिर मालूम हुआ कि लाखों रुपयों का जो खर्चा हुआ था उसका लाभ जनता को नहीं मिला।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान में एक और विशेष चीज़ की ओर दिलाना चाहूँगा और वह यह है कि इस वर्ष केन्द्रीय सरकार से हमको मशीनरी के सम्बन्ध में तकावी देने के लिए करीब ६ लाख रुपया मुकर्रर हुआ था और इसी सिलसिले में मैंने एक प्रश्न भी सदन में पूछा था, जिसके उत्तर में कतई सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। मैं माननीय अध्यक्षजी, आपके जरिये इस सदन से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर सरकार ने इसमें थोड़ी सी भी बुद्धमानी से काम लिया होता तो दस लाख रुपये की तकावी, जो मशीनरी के लिए मन्जूर की गई थी वह मिल जाती और इससे लोगों को फायदा होता और जो लोग मशीनरी चलाना चाहते थे या खरीदना चाहते थे वे खरीद सकते थे पर, अब जब कि वर्ष खत्म होने होने वाला है इस बारे में अगर लोग चाहें भी तो क्या हो सकता है। सरकार ने गैर जिम्मेवाराना तरीके से ऐसा रास्ता अपनाया जिसकी वजह से यह दस लाख रुपये की रकम सरकार को वापिस केन्द्रीय सरकार को देनी पड़ी। वह रकम यों ही खत्म हो गई और इससे जनता को जो फायदा होने वाला था और जनता के काम जो रकम आ सकती थी वह नहीं आई और यह भी तब हुआ जब कि इसमें जनता की तरफ से काफी शिकायतें आईं। ऐसा मालूम हुआ कि इसमें भी सौदे बाजियाँ हुईं और हो रही हैं, पर वे सन्तोषप्रद रूप से नहीं हुईं; इस कारण यह ऐसा हुआ ऐसा सुना जाता है। अब इसमें कितना सत्य है इसके बारे में में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, पर इतना सही है कि वह रकम जिस काम के लिए खर्च की जा रही थी वह खर्च नहीं हो पाई। पर मैं इतना कह देना चाहता हूँ कि यह रकम जो मशीनरी के सम्बन्ध में खर्च की जा सकती थी और जिससे जनता को फायदा हो सकता था, जनता उस फायदे को पाने से महरूम रही और इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की है।

माननीय अध्यक्ष, इस कारण जिन तरीकों से हमारी जनता को जो काफी मदद मिलने वाली थी वे सही तरीके अपना कर अगर हम नहीं करना चाहते, तो यह सरकार की अकर्मण्यता है। ऐसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से हमें काम नहीं करना है, इस ओर मैं खास तौर से आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा।

सिंचाई के सम्बन्ध में कुओं के अलावा एक चीज़ की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ और वह है ट्यूब वैल के सम्बन्ध में। खास तौर से पाली जिले में ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पर ट्यूब वैल खोदे जा सकते हैं और जनता को उससे फायदा हो सकता है, लेकिन इसके लिए खर्चा

[श्री शम्भूसिंह]

इतना ज्यादा पड़ता है कि मालूली आदमी व्यक्तिगत रूप से इतना खर्चा करने को शायद तैयार न हो और इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि सरकार इस ओर कदम बढ़ावे और वहाँ पर ट्यूब वैल खोदे; खास तौर पर यह देखने के लिए कि सफलतापूर्वक वहाँ पर खोदे जा सकते हैं या नहीं ? सरकार को इस ओर कदम उठाना चाहिये, ताकि वहाँ पर सिंचाई की मात्रा बढ़ सके।

अन्त में मैं इस महकमे के अफसरों के सम्बन्ध में भी एक-दो शब्द अवश्य निवेदन करना चाहूँगा और वह यह है कि इनके बारे में जनता को ऐसा खयाल होने लगा है कि शायद जिले के जो कृषि अधिकारी या ऐसा ही अन्य अधिकारी हैं वे बिल्कुल सुस्त बैठे रहते हैं। उनके पास में कोई खास काम नहीं है कि जिससे वे अपने उस पद पर बने रहने को जस्टिफाई (justify) कर सकते हों। अपने दफ्तर में केवल सीज़न के ऊपर बीज वितरण करने से ही उनका काम समाप्त नहीं हो जाता। हमारी कृषि-उत्पादन की इस इन्डस्ट्री में हमें किस तरह से प्रगति का काम करना है, इसे पब्लिसिटी विभाग की तरह से हमें लोगों को समझाना होगा, इसकी पब्लिसिटी करनी होगी। इसमें खास तौर से मशीनरी वगैरह का काम समझाया जावे तो अच्छा होगा।

इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर को चाहिये कि ज्यादा से ज्यादा वह अपने एरिया में घूम-घूम कर ऐसे मामलों में लोगों को जानकारी दें और उनकी सहायता करें कि किस तरह से किस चीज का ज्यादा से ज्यादा अच्छा उत्पादन किया जा सकता है व किस तरह से कैसे बीज को बोया जावे जिससे उसका अच्छे से अच्छा फायदा उठाया जा सके। इन सब बातों की ओर खास तौर से उनको रुचि रखना बहुत जरूरी है। इसलिये मैं निवेदन करूँगा, माननीय अध्यक्षजी, आपकी मार्फत इस सदन से और सरकार के इन मन्त्रियों से कि वे इस ओर विशेष ध्यान दें और सरकारी अधिकारियों को इस ओर आग्रह करें और सख्त आदेश दें। वे अफसर जो खाली बैठे रहते हैं और केवल बीज का वितरण करके ही अपना काम समाप्त हुआ समझते हैं, गलत चीज़ है। उनका यह समझना गलत है कि उनका इतना ही काम है। उनको अपनी इस मनोवृत्ति को थोड़ा बहुत तब्दील करना है। इसके लिए सरकार को भी निवेदन करूँगा कि इसके लिए वह विशेष कदम उठावे।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—माननीय अध्यक्ष, मैं एग्रीकल्चर के मुतल्लिक कुछ कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—कौन से कट मोशन पर आप बोलेंगे ?

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—जवानसिंहजी वाले......

श्री अध्यक्ष—Looking to the nature of the discussion I feel inclined to allow all the members, provided the Members of the House co-operate because there are some nine cut-motions and I feel induced to accord my sanction to all of these. But the Members of tha House should co-operate with me in keeping the time factor in view.

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—एक मेरा भी है। एग्रीकल्चर तकावी दी जाती है उसके सम्बन्ध में मैंने पहले भी कहा था कि यह......

श्री अध्यक्ष—कौन से कट मोशन पर आप बोलना चाहते हैं?

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—जवानसिंहजी के कट मोशन पर......

श्री अध्यक्ष—If you keep patience you will have better opportunity later on to put your criticism.

(विराम)

Then, Mr. Yadav.

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, चूँकि इस डिपार्टमेंट का सम्बन्ध उदयपुर से आने वाले एक मंत्री महोदय से है और वह नाराज हो जाते हैं हमारे क्रिटिसिज्म को सुनकर.....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—नहीं, बिल्कुल नहीं होता हूँ, जवाब जरूर देता हूँ।

श्री गोपीलाल यादव—इसलिए मैं यह सोचता था कि कुछ नहीं कहूँ, लेकिन वह कहते रहे हैं कि नाराज़ नहीं होंगे.....

श्री अध्यक्ष—Order please!

I just read out your cut motion because the Members mostly have not got copies of those. "That the Demand for Grant No. XIX—Agriculture be reduced by Rs. 500/- (to discuss the wrong policy of the Government which has stood in the way of making the Department a success)."

श्री गोपीलाल यादव—मैं इस सम्बन्ध में इतना सख्त निवेदन करना चाहता हूँ कि एग्रिकलचर डिपार्टमेंट जिस तरीके से चलना चाहिए और पब्लिक का जो काम एग्रिकल्चर के सम्बन्ध में होना चाहिए वह इस वक्त नहीं हो रहा है और डिपार्टमेंट के लोग इन आंकड़ों को इस तरह से बताते हैं कि हमने इतने फार्म्स खोले हैं, बजट में खर्च ज्यादा नहीं हो जाता है, खर्च कुछ ज्यादा हो जाता है, इस डिपार्टमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसी बातें लोग सोचते रहते हैं। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि सबसे पहली चीज़ जो है वह यह कि किसी डिपार्टमेंट को इस हिसाब से जज नहीं करना चाहिए कि इस पर खर्च कितना होना चाहिये, आमदनी से ज्यादा है। यह एक ऐसा काम है कि जिसमें खर्चा बजट से ज्यादा होगा और आमदनी नहीं होगी। कुछ फार्म्स में आमदनी हो सकती है और इन फार्मों पर आपके द्वारा पहले से ही डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की केडर का मेनेजर दिया हुआ है। उसको २००), ३००) रु० माहवार देना पड़ेगा तो फार्म में बचत नहीं दिखला सकेंगे। जिसमें आप कुछ बचत दिखला सकें उसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हरेक फार्म में इस हिसाब से

[श्री गोपीलाल यादव]

बचत दिखती है कि वहाँ के बड़े अफसर हैं उनकी तनख्वाह को शामिल नहीं करें, फिर देखें कि वे कितना काम करते हैं।

इसके बाद डिस्ट्रिक्ट के अन्दर काम लिया जाय स्टेटिस्टिक्स (statistics) तैयार करने के लिए कि कितने लोगों को कितने इलाकों में अच्छे बीज दिये जायं, अच्छा खाद दिया जाय, खेती के तरीके बताये जायं, कहाँ गेहूँ पैदा होता है, कहाँ मामूली कपास पैदा होती है, वहां कितने एरिया के अन्दर यह चीज पैदा होने लगी है। इसके स्टेटिस्टिक्स लगातार आपके पास आने चाहिये। बाद में यह जाँच करें कि आपके डिपार्टमेंट का स्टेन्डर्ड कितना बढ़ रहा है।

इसके सम्बन्ध में मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम गलत रास्ते की ओर जा रहे हैं। वह गलत रास्ता ऐसा है कि आज कल एग्रिकलचर डेवलपमेंट हम इसी में समझ लेते है कि ट्रेक्टर, पम्पिंग सेट्स और बड़ी-बड़ी मशीनें हैं: इससे हम एग्रिकलचर की उन्नति करेंगे। एग्रिकलचर डिपार्टमेंट से जो तकावी दी जा रही है वह लोगों को दी जा रही है ज्यादातर १०-१० हजार रुपये ट्रेक्टर खरीदने के लिए, पम्पिंग सेट लगाने के लिए और जो बड़े-बड़े फार्म रखेंगे। मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बहुत बड़ी गलती है। यह पोलिसी उन विदेशों में मिलेगी जहाँ मेन पावर (men power) कम है। आस्ट्रेलिया और अमेरिका में आबादी ज्यादा नहीं है, जमीन बहुत पड़ी हुई है और एक आदमी अपनी इतनी बड़ी ज़मीन को मैनेज नहीं कर सकता इसलिए ट्रेक्टर खरीद लेता है और ट्रेक्टर की मदद से वह अकेला काम करता है, पम्पिंग सेट की मदद से यह अकेला अपने सारे फार्म को पानी दे देता है लेकिन यहाँ पीपिंग सेट, ट्रेक्टर और दूसरी मशीनें जो विदेशों में इस्तेमाल होती हैं उनके इस्तेमाल का एक ही नतीजा होता जा रहा है और वह यह है कि हमारे मुल्क में जहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है वह वहाँ बेरोजगारी और भी ज्यादा बढ़ा देता है। जिस कुएं पर ४ आदमी काम करते हैं वह कुआ ४ आदमियों का रोजगार है और वे उसकी पैदावार आपस में बाँट लेते हैं। इससे तीन आदमी बेकार हो जाते हैं। अब यह होगा कि अकेला आदमी हल चलायेगा कुछ सीखकर, या अकेला ही पानी दे देगा और उसको दूसरे आदमी रखने की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह से एक ट्रेक्टर हजारों बीघा जमीन जोत देता है, अकेला आदमी ही अपने खेत में पम्पिंग सेट से पानी दे देता है तो उसका नतीजा यह हुआ कि हजारों आदमी जो अपने हल से खुद खेती करते थे और बाकी बचे हुए टाइम में दूसरे आदमियों के खेत जोता करते थे वह सब बेरोजगार होते जा रहे हैं। इसलिए हमारे देहात की समस्या इन चीजों से हल होने वाली नहीं है, मैं यह आपको बतला दूँ। इसलिए ज्यादा जोर इन चीजों की तरफ नहीं दें। जो रुपया इसमें लगाते हैं वह उनको कुएं बनवाने में लगायें। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस साल जितनी तकावी ज्यादा दे सकते हैं, सेन्ट्रल गवर्नमेंट से ले सकते हैं, वह ज्यादा से ज्यादा कुओं के ऊपर दें, और उनके तीन हिस्से करें। $\frac{1}{3}$ तो वह आदमी खुद लगायेगा, $\frac{1}{3}$ गवर्नमेंट की तरफ से ग्रान्ट मिले और $\frac{1}{3}$ गवर्नमेंट उसको लोन दे, जो कि १० इन्स्टालमेंट में वापिस ले लिया जाय। गवर्नमेंट जो अपनी तरफ से ग्रान्ट देगी वह चाही के लगान के रूप में उसको मिल जायगा और जो लोन पर देगी वह उसको वापिस मिल जायगा तथा कुछ किसान जो देंगे वह उनको ज्यादा पैदावार के रूप में मिलेगा। इस तरह

Page No.112

[श्री गोपीलाल यादव]

से बहुत बड़ी तादाद में कूए बनाये जायेंगे और हर एक किसान के पास में एक-एक कूआ हो जाना चाहिए। आज अभी जो ट्रेक्टर वगैरह के लिए लोन दे रहे हैं तो बड़े-बड़े जागीरदार यह कर रहे हैं कि जो लोग पहले अपनी जमीन किसानों को उठा देते थे, वह समझते हैं कि किसानों को बेदखल नहीं कर सकेंगे और चूँकि हल उठाने की जरूरत नहीं इसलिये एक ट्रेक्टर लेकर अपनी हजार बीघा जमीन को वे खुद जोतें, १ या २ हजार बीघा जमीन खुद ट्रेक्टर से जोतने लगे हैं। कुछ नये लेन्डलॉर्ड्स भी बनाये गये हैं जिन्होंने अपनी नई जमीन ले ली है। मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ जयपुर के नजदीक ही एक मि० रामजी काक हैं उनको २० एकड़ का फार्म मिल गया है, कहीं किसी को कोटा की तरफ १ हजार बीघे जमीन का फार्म मिला है और किसी को और किसी जगह मिला है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि बड़े फार्म क्यों मिलते हैं? डिपार्टमेंट जितना रुपया इन्वेस्ट करती है ट्रेक्टर और पम्पिंग सेट पर हरेक आदमी नहीं ले सकता है। वह मिलता है उन लोगों को जिनके पास में पैसा है। इस तरह से लोगों को इतनी जमीन मिलेगी तो वह थोड़े से लोगों के हाथ में चली जायगी। इसलिए इसके टुकड़े कर दिये जायं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ १००-१०० फेमिलाज़, ५०-५० फेमिलीज़ की बनाई जाय। कुछ रुपया वे खुद लगायेंगे और कुछ रुपया आप उनको देदें। इस तरह से फार्म आप करेंगे और बड़ी तादाद में जमीन दूसरों को न दी जाय। जो तकावी देते हैं वह ठीक ठीक काम के लिए दी जाय। (घंटी) इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष—Shri Kapildeo.

(विराम)

I read out his cut-motions.

1. "That the Demand No. XIX Major Head 40—Agriculture for Rs. 37,70,000/- be reduced by Rs. 10/- (to discuss the inefficiency in regard to the working of the Compressor unit)"

2. "That the Demand No. XIX Major Head 40—Agriculture for Rs. 37,70,000/- be reduced by Rs. 10/-(to discuss the policy followed in respect of purchases)"

Yes, Shri Kapildeo Agrawal.

श्री कपिलदेव—अध्यक्ष महोदय, एग्रिकलचर डिपार्टमेंट में कम्प्रेसर्स 'नो प्राफिट एन्ड लोस' बेसिस (no profit, no loss basis) पर काम में लाये जाते हैं। 'नो प्राफिट एन्ड नो लोस' ऐसा है कि एक तो उनके लिये पर्मानेन्ट स्टाफ (permanent staff) है जोकि हमेशा उस कम्प्रेसर पर वर्क करता है। इसके अलावा जब वह काम करता है तो कुछ और आदमियों को टेम्पोरेरी नौकर रखते हैं और एक जगह आकर कूए पर काम करता है या दूसरी जगह वह वर्क करता है और एक महीने भी वह ठाला रह जाता है तो वह सारा खर्चा भी उसी कूए की खुदाई के ऊपर लगता है। 'नो प्रोफिट, नो लोस' का यह वर्क इस वक्त मंहगा पड़ता है। इसके काम का ५५) रु० प्रति घन फुट तक इसकी खुदाई का खर्चा आता है। किसी भी प्रोविन्स में यह इतना मंहगा नहीं है। प्राइवेट

[श्री कपिलदेव]

कम्पनी से इतनी ही खुदाई किसी कम्प्रेसर के द्वारा करायें तो १५) या १६) रुपये की घन फुट से ज्यादा नहीं आता है। पब्लिक एकाउन्टस् कमेटी के एक्ज़ामिनेशन के दौरान में इस बात पर काफी चर्चा हुई है। उस वक्त डिपार्टमेंट के हैड ने यह वायदा किया था कि इस विषय में काफी सुधार किया जायगा, लेकिन उन बातों को कई दिन हो गए। फिर दुबारा इन कम्प्रेसर्स के लिए लिखा गया कि यह किस तरह, किस बेसिस पर काम करते हैं, कम से कम किस कीमत पर वह खुदाई करते हैं, बतलाया जावे। लेकिन अब तक उसका सेटिसफेक्ट्री जवाब नहीं मिला है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। इसलिए मैं यह सुझाव देना चहता हूँ कि कम्प्रेसर का काम इस तरह से किया जाय जिस तरह से कि प्राइवेट कम्पनियों में होता है। उस लिहाज से, बिज़नेस प्वाइन्ट ऑफ व्यू (business point of view) से इसका वर्क हो ताकि जनता और खास तौर पर काश्तकारों को फायदा मिल सके। आज सरकार का कितना ही रुपया लग जाता है लेकिन आम पब्लिक को फायदा नहीं मिलता है। १२ में से १० खुद डिपार्टमेंट के सब लोग जानते हैं कि कम्प्रेसर्स की गोलियाँ वर्क नहीं करती हैं। जहाँ कहीं भी गये हैं बिल्कुल रिडीक्यूलस पोज़ीशन (ridiculous position) में वापिस आते हैं और जनता के सामने वह वापिस गये हैं। एक दफा तो ऐसा मौका हुआ, हम लोगों ने बड़ी तादाद में काश्तकारों को इकट्ठा किया था, लेकिन जब कूए के खोदने की व्यवस्था की गई थी तो यह देखा कि कम्प्रेसर में १२ गोलियाँ डाली गई तो १२ में से ६–१० बेकार गई और ३ ने वर्क किया और ६ ने बिल्कुल काम नहीं दिया; इससे उन लोगों पर बुरा असर पड़ा। इस तरह 'नो प्रोफिट नो लोस' के ऊपर यह कम्प्रेसर वर्क करते हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह आश्वासन चाहूँगा कि भविष्य में कम्प्रेसर वर्क की ओर ज्यादा ध्यान दें और इस बात को देखेंगे कि जिस प्रयोजन के लिए वे खरीद किये गये हैं उनसे काश्तकारों और मजदूरों को फायदा हो।

दूसरी बात परचेज़ ऑफ स्टोर्स (purchase of stores) के विषय में अर्ज करना चाहता था? जो भी परचेजेज़ अब तक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में की गई, अगर आप उनको देखेंगे (कुछ बातें इस हाउस के सामने आई है), अगर आप उनकी जाँच करने के लिए जाँच कमेटी बिठायेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन परचेजेज़ में एक बहुत बड़ा स्कैन्डल हुआ है। पब्लिक एकाउन्टस कमेटी के एग्ज़ामिनेशन के सिलसिले में एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने इसमें बताया कि इस विषय में जाँच कर रहे हैं। उसके लिए जाँच कमेटी बिठाई गई है, पर्टिक्युलर परचेजेज़ के बाबत जाँच की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी एक कमेटी इसकी बनाई गई थी कि जो परचेजेज़ कमेटी के नाम से हैं और जिसमें कुछ ट्रेक्टर्स वगैरह कई चीजों के ऑर्डर्स भी दिये थे और एक क्वेश्चन के जवाब में माननीय मन्त्री महोदय ने यह बताया था कि अब तक के जो टेन्डर्स कॉल किये गये थे या जो भी खरीदने के बारे में, सोचा गया था उनके लिये अभी कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया है। इस विषय में तो मैं इस समय कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन इतनी बात जरूर कहना चाहता हूँ कि अब तक की स्थिति को देखते हुए जो खर्च हुआ है इसमें ज्यादा खामियें हैं और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में दृढ़ता से निश्चय किया जायगा ताकि कोई नहीं कह सके कि खर्च में कोई घपला हुआ है।

श्री अध्यक्ष—Should I read out the cut-motion which I have allowed ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्षजी, सबसे पहले एस्टाब्लिशमेन्ट में २ लाख रुपयों की कमी करने की गुंजायश है।

श्री अध्यक्ष—I may just inform that those cut-motions which have been covered by other cut-motions are rejected. The first cut-motion moved by Shri H. K. Vyas reads as follows:—"That the Demand for grant No. XIX Major head 40—Agriculture, be reduced by the Rs. 100/- (to discuss the failure in respect of granting loans to cultivators for mechanized farming)."

II. "That the Demand for Agriculture be reduced by Rs. 1000/- (to discuss the failure on the part of the Government to root out corruption in the Department)."

III. "That the Demand for Agriculture be reduced by Rs. 20,000/- (Economy-reduction in the expenditure on motor vehicles).

IV. That the Demand for Agriculture be reduced by Rs. 2,00,000/- (Economy-drastic reduction of Establishment expenditure).

You are not entitled to more time because of the these four cut-motions.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am going to be very economical as far as time is concerned. २ लाख रुपयों की कमी करने की जो गुंजायश है, जिस पर मैंने कटौती का प्रस्ताव रखा है वह क्यों और कैसे हो सकती है इसके कारण में सदन के सामने रखूँगा। बजट के पेज १६४ पर आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस विभाग के कुल बजट में एस्टाब्लिशमेन्ट का खर्चा रखा गया है १ लाख ५१ हजार ८ सौ, सुपरिन्टेन्डेन्स के करीब ५० हजार और सबोर्डिनेट स्टॉफ आदि के ३ लाख ७३ हजार; कुल मिलाकर पौने छः लाख रुपये एसटाब्लिशमेन्ट के लिये मुकर्रर रखे गये हैं और यह कुल बजट की ३० प्रतिशत रकम इसमें आती है और जो डेवेलपमेन्ट की स्कीम्स हैं जिनमें भारत सरकार की पूँजी लगती है या सरकार को भारत सरकार से मदद के रूप में पैसा मिलता है और जो वितरण होता है इस डिपार्टमेन्ट में वह अगर गिन लें तो यह २० पर्सेन्ट तक पड़ता है। अभी जो आँकड़े मैंने प्रस्तुत किये हैं उनके बारे में आपसे अर्ज करूँगा। बजट के पेज १६४ पर डाइरेक्टर, डिप्टी डाइरेक्टर्स आदि की तनख्वाह रखी गई है २४ हजार रुपये। फिर पेज १७५ पर एक्सपैरिमेन्ट्स और रिसर्च के निस्बत जो रकम रखी गई है उसके निस्बत माननीय मन्त्रीजी ने तीन-चार दिन पहले एक प्रश्न के उत्तर में फरमाया था कि केवल ३ एक्सपर्ट्स इस विभाग में रखे गये हैं और मैं नये साल से उसकी जानकारी के लिये बजट में जो नाम प्रस्तुत हैं वे पढ़कर सुनादूँ तो आपको मालूम होगा कि वे कितने हैं। उनके नाम हैं एग्रीकल्चरल केमिस्ट, एन्टोमोलोजिस्ट, माइकोलोजिस्ट, हाइड्रोलोजिस्ट, स्टेटिस्टीशियन, बोटेनिस्ट, एग्रीकल्चरल इन्जीनियर, रिसर्च असिस्टेन्ट इन्जीनियर्स, ट्रैक्टर फोरमेन, जिनकी तादाद माननीय अध्यक्ष, तीन नहीं १५ है, तो यह तो स्टाफ है। उनकी तनख्वाह यदि और जोड़ लें तो और इसके अलावा फूड ओफिसर्स हैं और जो दूसरे ओफिसर हैं उनकी सबकी मिलाकर १ लाख २५ हजार रुपये तो तनख्वाहों में बजट के आँकड़ों के मुताबिक टोटल

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

खर्च होता है। फिर भत्ता भी होगा, किराया भी होगा। इस प्रकार एस्टाब्लिशमेंट पर २० पर्सेन्ट से ३० पर्सेन्ट तक खर्चा होता है। मैंने जो आँकड़े प्रस्तुत किये वे डिटेल्स के मुताबिक सही उतरते हैं। अब यह खर्चा किस प्रकार होता है उसकी एक तफसील अर्ज करूँगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रिसर्च और एक्सपर्ट के लिए जहाँ तनख्वाह आदि में १५ हजार रुपये खर्च कर रहा है वहाँ पर लेबोरेटरी के चार्जेज़ हैं ६५००) रुपये। १००० रुपयों की तनख्वाह का पायन्दार रिसर्च करता है और लेबोरेटरी के लिये केवल ६००० का प्रोवीजन है। यदि दूसरी ओर देखेंगे तो एस्टाब्लिशमेंट का खर्चा ५० परसेन्ट हो जाता है और लेबोरेटरी पर केवल ६ हजार ५ सौ रुपये रखे गये हैं। मेरे पास और भी बहुत तफसील हैं, पर मैं समय का खयाल रखता हुआ इन तफसीलों में नहीं जाऊँगा लेकिन केवल इतना ही कहूँगा कि इस तरह का खर्च स्टॉफ पर किया जाता है और काबिल से काबिल लोग रखे हैं तो उनके काम करने के लिए सरकार को प्रोवीज़न रखना चाहिये, पर एक्युचल रखा है आपने ६५०० रुपये लेबोरेटरी के खर्च के लिए और एक्सपर्ट्स की तादाद है १५; तो इसका मतलब यह हुआ कि यह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नहीं, यह तो रिहेबिलिटेशन विभाग होगा जो अफसरों को रिहेबिलिटेट करता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आज तक एक भी रिपोर्ट रिसर्च वर्क की डिपार्टमेंट के सामने सबमिट नहीं की गई कि आपने कौनसी वेराइटी गेहूँ की निकाली है और रिसर्च किया हुआ कौनसा बीज हमारे यहाँ के किसानों के पास पहुँचा है, एग्रीकल्चर फार्मस में जो अलग-अलग प्रकार के बीज हैं उनमें से आपने किसका सिलेक्शन किया और वह कौनसा बीज है जो किसानों के पास पहुँचा और उसके फलस्वरूप पैदावार में बढ़ोतरी हुई। इसकी रिपोर्ट डिपार्टमेंट के पास नहीं है। यह एस्टाब्लिशमेंट का खर्चा कम किया जा सकता है। या तो सारा स्टाफ न रहे और यदि स्टाफ रखने की आवश्यकता है तो उनके लिये काम प्रोवाइड करने के लिए ज्यादा खर्चा किया जाना चाहिये।

दूसरा प्रस्ताव मेरा है मोटरों के खर्चे के बारे में। इस बारे में मैं दो बार अर्ज कर चुका था। यहाँ प्रोपर मेन्टेनेन्स ऑफ वेहिकल्स (proper maintenance of vehicles) नहीं होता है। जो जीपें खरीदीं गई थीं उनकी आज तक सफाई नहीं हुई। जो हॉलेज (haulage) के लिये खरीदी गई थी आज उस काम के लिए ट्रेक्टर खरीदे जा रहे हैं और शायद ऑर्डर हो चुका है। तो उन जीपों का क्या होगा? वे घूमती-फिरती हैं शहर के बाजार में। वे सरकारी काम के लिए घूमती हैं या किस काम के लिए घूमती है, इसकी कहीं रूप रेखा नहीं है और जाँच करने से पता नहीं चल सकता। दुर्भाग्य तो यह है कि ट्रेक्टर्स के लिए भी प्रोवीजन रखा है। फार्म्स कम कर दिए गए हैं पहले १६,१८ या ५० थे पर अब काफी कम कर दिए गए हैं।

(विराम)

कितने मिनट और देंगे?

श्री अध्यक्ष—One minute more.

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो कुल कितने मिनट मेरे लिए हुए?

श्री अध्यक्ष—Don't discuss. You are wasting your own time. You were to be given 5 minutes in all but you have taken 7 minutes.

श्री हरिकृष्ण व्यास—अब मुझे कितना समय और देंगे ?

श्री अध्यक्ष—One minute more.

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो फिर जाने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—Any other Member ?

श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष, कट मोशन मैंने भी भेजे थे, मैंने १८ तारीख को ही ऑफिस में भेज दिये थे इसलिए मुझे भी उन पर बोलने की इजाजत दी जाय ।

श्री अध्यक्ष—I am sorry I have not received. You can confine yourself to any of the cut-motion which have been moved.

श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष, श्री जवानसिंहजी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा उसके समर्थन में मैं अपने विचार इस सदन के समक्ष रखूँगा ।

राजस्थान में काश्तकारों को, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा किस तरह से विशेष सुविधा दी जाय और वैसी विशेष सुविधा न दी जाने के फलस्वरूप जो कटौती का प्रस्ताव श्री जवानसिंहजी ने रखा था उसके कुछ सुझावों का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ ।

एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक्सपेरीमेंटल फार्म्स के लिए जो प्रोवीज़न है उसके पहले के आँकड़े यदि देखे जायं तो मालूम होगा कि पहले जो एक्सपेरिमेंटल फार्म्स बनाये गये थे उनकी संख्या कम करदी गई है। वह इसलिए कम करदी गई है कि वे एक्सपेरिमेंटल फार्म्स सेल्फ सपोर्टिंग नहीं बनाये जा सके। एक्सपेरिमेंटल फार्म्स के ज़रिये से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा एग्रीकल्चरिस्ट्स की विशेष सेवा नहीं की जा सकी।

अध्यक्ष महोदय, एक्सपेरिमेंटल फार्म्स में सिवाय गेहूँ के, सी. ५६१ के सिवाय किसी प्रकार का रिसर्च नहीं किया जा सका। अगर इस तीन साल के अर्से में सिर्फ गेहूँ का ही रिसर्च किया जाय तो इस प्रकार का खर्चा सरकार के लिए बिल्कुल ही अनावश्यक होगा। एक्सपेरिमेंटल फार्म्स को अगर सेल्फ सपोर्टिंग बनाना है तो सरकार को चाहिये कि वह एक्सपेरिमेंटल फार्म्स को, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को डिस्ट्रिक्ट्स में, तहसीलों में ले जायं तो यह स्कीम कामयाब हो सकती है, इसमें बहुत तरक्की हो सकती है। राजस्थान का जलवायु भिन्न-भिन्न प्रकार का है, जमीन भी भिन्न-भिन्न प्रकार की है। एक तहसील की जमीन और जलवायु दूसरी तहसील से भिन्न है, एक तहसील में गेंहूँ की पैदावार अच्छी हो सकती है तो दूसरी में अच्छी नहीं। एक जिले में किसी एक खास किस्म के गेंहूँ के बीज से अच्छी प्रोडक्शन की जा सकती है तो दूसरे जिले में उस बीज से प्रोडक्शन में नुकसान हो सकता है। एक्सपेरीमेंट के लिए तहसीलवाइज़, डिस्ट्रिक्टवाइज़ और डिविजनवाइज़ एक्सपेरिमेंटल फार्म्स किये

[श्री भैरूँसिंह]

जाय तो एक्सपेरीमेंट सही हो सकता है और काश्तकार भी खुद काफी बता सकते हैं, बहुत कुछ बता सकते हैं।

एक तहसील में बाजरे का एक्सपेरीमेंट सफल व लाभदायक सिद्ध हो सकता है तो दूसरी तहसील में गेहूँ का एक्सपेरीमेंट सफल व लाभदायक सिद्ध हो सकता है। अगर गेहूँ और चने का बीकानेर में एक्सपेरिमेंट करें और मक्का का सीकर में एक्सपेरीमेंट किया जाय तो कभी कामयाबी नहीं मिलेगी क्योंकि इनके लिए जहाँ उपयोगी जलवायु और जमीन नहीं है इससे कामयाबी हासिल नहीं हो सकती है। सीकर में और बीकानेर में भी एक्सपेरीमेंट किया जा सकता है कि किस प्रकार से मोटे कण की जमीन में मक्का और चने की पैदावार बढ़ाई जा सकती है; बारां (कोटा डिविज़न) में जहाँ बाजरे की पैदावार अधिक नहीं हो सकती वहाँ किस प्रकार से बाजरे की पैदावार बढ़ाई जा सकती है।

तो इस तरह तहसीलों में, डिस्ट्रिक्ट्स में और अलग-अलग डिविजन्स में एक्सपेरीमेंटल फार्म्स खोले जायें तो मैं समझता हूँ कि इन एक्सपेरिमेंटल फार्म्स के ज़रिये सरकार का जो Establishment पर खर्चा होगा वह निकाला जा सकता है।

प्रोपोगेन्डा (propoganda) के ज़रिये भी इसकी तरक्की की जा सकती है, इम्प्लीमेंटस जो नये-नये निकले हैं उनके जरिये इसको कामयाब बनाया जा सकता है। राजस्थान में कई तरह के हल हैं। किशनगढ़ में जिस प्रकार के हल चलाये जाते हैं उनका उपयोग शेखावाटी के जिले में किया जाय तो उस जमीन में ज्यादा पैदावार हो सकती है, पर सीकर वालों को मालूम ही नहीं है कि किशनगढ़ में किस तरह के हल चलते हैं जिनसे उनके यहाँ भी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। शेखावाटी में बीज बोने का जो तरीका है उस तरीके को अगर कोटा वालों को सिखाया जाय तो पैदावार बढ़ाई जा सकती है।

केवल जयपुर में एक्सपेरीमेंटल फार्म बना लिया जाय और आम, नीबू और नारंगी के पौधे लगाकर एक्सपेरीमेंट किये जाँय तो इससे राजस्थान की कृषि पर कोई फरक नहीं पड़ने वाला है। अगर राजस्थान में पैदावार बढ़ानी है तो राजस्थान में जो चीजें पैदा होती हैं उनकी तरक्की करने से ही राजस्थान की पैदावार बढ़ सकती है।

अतः तहसीलों में, डिविज़न्स में और डिस्ट्रिक्ट्स में अलग-अलग तरह के एक्सपेरिमेंटल फार्म्स वहाँ की जलवायु और जमीन दोनों को ध्यान में रखते हुए खोले जाँय और वहाँ की जलवायु और जमीन के अनुकूल अनाज की पैदावार बढ़ाने के एक्सपेरीमेंट किये जाँय तो इससे राजस्थान की पैदावार बढ़ सकती है और यह स्कीम भी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। बाजरे का झुंझुनू, सीकर, नागौर और बीकानेर में व जौ गेहूँ का जयपुर के ज्यादा हिस्सों में एक्सपेरिमेंट हो सकता है, न कि बीकानेर और जोधपुर में।

[श्री भैरूँ सिंह]

बीज का प्रोवीज़न रखा जाय, इम्प्लीमेंट्स का प्रोवीज़न रखा जाय, अच्छे खाद का प्रोवीजन रखा जाय। काश्त के ऊपर भी बीमारियाँ होती हैं, उन बीमारियों को कैसे दूर किया जाय, इस तरह के एक्सपेरिमेंट किये जायँ, प्रोग्राम रखे जायँ। जैसे आज जयपुर के पश्चिमी भाग में रबी की फसल में रोली की शिकायत आ रही है, इसका उपचार कैसे किया जा सकता है; इसको सीखने के लिए सीकर के काश्तकार यहाँ जयपुर में नहीं आयेंगे। अगर इस काम के एक्सपेरीमेंट के विभाग की शाखाएँ डिवीजन्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में, तहसीलों में रहती हों तो वे लोग काश्तकारों को बता सकते हैं कि किस प्रकार की मेडिकल फेसिलिटीज़ से फसल को रोगों से बचाया जा सकता है परन्तु एक्सपेरिमेंटल फार्म जयपुर में होने से डिस्ट्रिक्ट्स के लोग इससे कोई फायदा नहीं उठा सकते।

जो District एग्रीकल्चरल ऑफीसर हैं वे नाम-मात्र के हैं। एक qualified District Agricultural officers से मैंने पूछा था कि एक बीघे में रिजके का बीज कितना बोया जाना चाहिये, तो वह यह भी नहीं बता सके। वह योग्य समझे जाते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। यही उनकी योग्यता है कि वे यह भी नहीं जानते कि किस जमीन में किस आधार पर कितनी मात्रा में बीज बोया जाय। यह नमूना है एग्रीकल्चर ऑफीसर्स की योग्यता का, एक्सपर्ट्स की योग्यता का। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक-एक काम के स्थानीय एक्सपर्ट रखे जायँ; यह नहीं कि अमेरिका से बुलाये जाँय। इस डिपार्टमेंट में अनपढ़ आदमी भी ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। यदि किसी डिस्ट्रिक्ट का किसान, एक तजुर्बेकार किसान इस डिपार्टमेंट का अध्यक्ष का काम करेगा तो वह ज्यादा अच्छा काम कर सकता है। खेती में किस तरह से तरक्की की जाय, बीज में किस तरीके से तरक्की की जाय, किस तरह के इम्प्लीमेंट्स बढ़ाये जाँय, किस तरह से अच्छी खाद दी जाय, किस तरह से आमदनी बढ़ाई जाय, वह ज्यादा विचार सकेगा। पढ़े-लिखे लोग यह कह सकते हैं कि हमने एग्रीकल्चरल इन्स्टीट्यूट में शिक्षा पाई है या एग्रीकल्चरल कॉलेज में शिक्षा पाई है, लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि उनका सारा का सारा ज्ञान बुक्स में है। उनका किताबी ज्ञान है, प्रेक्टिकल एक्सपीरिएन्स कुछ नहीं है, हम उनके ज्ञान को practical ज्ञान नहीं कह सकते हैं, उनका ज्ञान बराए नाम हैं। उन्होंने घमलों में बीज बोये हैं। अगर उन्होंने हल भी चलाए तो घमलों में ही, एक बाजरी के दाने को घमले में डालकर उस एक दाने के ५० पौधे एक घमले में पैदा करने की चेष्टा की है। यदि उन्होंने कभी हल भी चलाया या पेड़-पौधे बोये होंगे तो एक-आध बीघा जमीन में नीम्बू, नारंगी या आम के पेड़ लगाये होंगे, लेकिन प्रेक्टिकल एक्सपीरिएन्स इससे नहीं मिलता। वास्तविक अनुभव तो उन लोगों को है जो रात-दिन इसी धन्धे में लगे हुए हैं। वे कह सकते हैं कि गेहूँ कितनी मात्रा में बोया जा सकता है और उसकी कितनी प्रोडयूस होगी। इन सारी चीजों का अनुभव तो आपको नहीं है। भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश के कृषक खास जीव हैं और यही लोग देश की ज्यादा से ज्यादा से और अच्छी से अच्छी सेवा कर सकते हैं। पढ़ा-लिखा कितना ही कोई आदमी क्यों न हो उसको उस व्यक्ति के मुकाबले में कुछ भी अनुभव नहीं है जो रात दिन खेत में काम करते हैं। अब मैं बीजों के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जिसके लिए एग्रीकल्चरल Department बहुत कहता है कि यह हमारा Research है। तहसील दांता रामगढ़ में उसी बीज (५६१) को काम में लिया गया। वह ऐसा बीज नहीं कहा जा सकता

[श्री भैंरूँसिंह]

जिससे राजस्थान में एक्सटेन्सिव कल्टीवेशन (Extensive cultivation) को फायदा हो। वह बीज ऐसा है कि एक साल में फायदा होगा, दूसरे साल भी उसको बोने से फायदा होगा और तीसरे साल तक फायदा होता रहेगा। मगर चौथे साल से उसी, प्रॉपोर्शन से उसकी आमदनी घटती जावेगी जिस प्रकार कि बढ़ी थी। अगर एग्रीकल्चर वाले इस बात को ठीक नहीं मानें तो मेरे खुद के गाँव में, खाचरियावास में ठाकुर साहब का एग्रीकल्चरल फार्म है वहाँ पर इसका प्रयोग किया गया और १० साल से बराबर प्रयोग किया जा रहा है। मगर तीन साल के बाद उसकी रिटर्न उसी प्रोपोर्शन से घटती जाती है, जिस तरह बढ़ी थी। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—अध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग के बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा है और मैं भी इस पर कुछ कहने के लिये खड़ा हुआ हूँ। कृषि विभाग की तरफ से तकाबी लोन मिलता है मगर वह इस तरह से देते हैं कि जब कोई किसान या व्यक्ति तकाबी के लिये लोन माँगता है और अपना बिल बना कर ५ या ६ हजार का देता है तो उसका आधा सरकार किसानों को दे देती है, मगर इससे किसान अपना कार्य पूरा नहीं कर सकते और इसका नतीजा यह होता है कि किसानों को वह काम या मशीनरी किसी से कर्ज लेकर खरीदनी पड़ती है और इससे वे कर्जदार हो जाते हैं। इसलिये मैं माननीय मन्त्रीजी से प्रार्थना करूँगा कि तकाबी जितनी वे मांगें और जितनी उनको जरूरत हो, उनको पूरी तकाबी दी जावे।

दूसरी बात यह है कि किसानों को कुछ खाद भी दी गई है। यदि देखा जाए तो आपको मालूम होगा कि यह खाद किसी तरह से काम देती है या नहीं। इस खाद का प्रयोग कई जगह किया गया। कुछ जगह पर तो यह कामयाब हुई और बहुत सी जगह बिल्कुल छोटे-छोटे गेहूँ रह गये और यह खाद काम नहीं दे सकी। यह खाद किस प्रकार की ज़मीन के लिये मुफीद होगी, इसका एक्सपेरिमेंट (experiment) होना चाहिये था। एक्सप्रीमेंट से यह सिद्ध हुआ कि यह खाद अच्छी नहीं, इसलिये इस खाद को लोगों को लोगों को देने से पहले इसका परीक्षण किया जाता तो ज्यादा अच्छा था और बहुत जरूरी था।

अभी मालूम हुआ है कि सरकार बोरिंग के लिये लाखों रुपया खर्च कर रही है। सरकार जो खर्च कर रही है वह इस बेसिस पर है 'नो प्रोफिट, नो लोस'। इस प्रकार की शर्त किसान बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि इससे किसानों के हजारों रुपये इसमें खर्च हो जाते हैं। इससे तो ज्यादा अच्छा यह होता कि हजारों मील में जहाँ ऊसर जमीन है, सरकार बोरिंग करा कर पता लगा ले कि कहाँ पानी प्राप्त हो सकता है। कहीं ५० फीट नीचे पानी निकलता है तो कहीं १०० या १५० या २०० फीट के नीचे पानी निकलता है। जब तक यह पता नहीं लगा ले कि कितने फीट नीचे पानी निकलेगा इससे पहले यदि किसानों के कहने से मशीन लगाली जावे और अगर पानी नहीं निकले तो किसानों को फालतू नुक्सान होगा।

[श्री भैरूँसिंह]

इसके अलावा किसानों के लिये रास्तों का इन्तजाम होना है। रास्ते में मिट्टी बहुत होती है और गाड़ियें मिट्टी में बहुत मुश्किल से चल सकती हैं। इसलिये गवर्नमेंट को उसकी सड़कों और रास्तों को ठीक करना चाहिये क्योंकि उनका ट्रान्सपोर्ट का जरिया गाड़ियें ही तो हैं।

सिंचाई के लिये मैं मानता हूँ कि काफी किया गया है। लेकिन खिलाड़ा में जहाँ ५००० कूए हैं अगर वहाँ पर पॉवर हाउस बना कर बिजली से पानी देवें तो मैं समझता हूँ कि करीब ५ लाख मन धान एक साल में पैदा हो सकता है।

दूसरी बात यह कहनी है, कि फसल तैयार खड़ी है (घंटी) लाटे हो रहे हैं लेकिन जो लोग किसानों में रुपया मांगते हैं वे डिकरी लाकर खड़े हैं जिससे वे सब धान आदि ले जावेंगे। सरकार को चाहिये कि किसानों को उन कर्जदारों से छुड़ाए जो बहुत ज्यादा व्याज लेते हैं। इसके लिये किसानों को एक कर्जा-निवारक सोसाइटी बनाई जानी चाहिये। मैं यह कहूँगा कि पहले जमाने में सरकार की तरफ से यह हुक्म था कि किसानों के बैल, खाने-पीने का सामान, बीज के लिये धान आदि नीलाम नहीं होते थे। आज की सरकार के जमाने में सब कुछ नीलाम हो जाता है। इसलिये किसानों के कर्जे की अदायगी में उनके बैल आदि नीलाम नहीं होने चाहिये, इस प्रकार का इन्तजाम करें। बस मैं इतना ही कहूँगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, कृषि विभाग के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही गई हैं। मैं ज्यादा विस्तार में तो नहीं जाना चाहूँगा लेकिन कुछ मुद्दों की बात पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। सबसे पहले एक माननीय मित्र ने यह कहा कि बहुत से हिस्सों में जहाँ पर बड़े-बड़े बाँध नहीं बनाये जा सकते हैं वहाँ पर कूओं के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को यह सूचित करना चाहूँगा कि हमने पिछले दो वर्षों में इस ओर खास तौर से प्रयत्न किया है और इस वर्ष २५ लाख रुपया किसानों को कूओं की मरम्मत के लिये या नये कूए खुदवाने के लिये तकावी के रूप में दिये। अगले वर्ष में इसके लिए ३० लाख रुपयों का प्रोवीजन और किया गया है कि किसानों को कूओं को खोदने के लिये दिये जावें। हम स्वयं इस बात को मानते हैं कि कूओं के द्वारा किसान ज्यादा फायदा उठा सकता है और इसी बात का सरकार ने अनुभव करके इस रकम को बढ़ाया है।

मेरे कई मित्रों ने कहा है कि कृषि विभाग में बहुत से एक्सपर्ट रखे जा रहे हैं, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं सदन की जानकारी के लिए यह अर्ज करना चाहता हूँ कि कृषि विभाग में एक्सपर्ट रखे गये और उनके द्वारा जहाँ तक राजस्थान में उपयोगी बीज हो सकता है उसका अनुसंधान किया गया और उसका भी परिणाम आज हमारे सामने है। उसमें ५६१ ही केवल नहीं है, राजस्थान में एक आर. जे. एस. ३१.१ व्हीट की वैराइटी को तैयार किया है और मैं अर्ज करूँगा कि इसको प्रयोग में लाये हैं। जोधपुर में सरदार समन्द में इसका प्रयोग किया गया और यह ५६१ और दूसरों से काफी अच्छा साबित हुआ। वह वहाँ के परिणामों से देखा जा सकता है।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि इसके परिणाम इस वक्त सरकार के सामने मौजूद हैं सी. एस. ६१ दूसरी वेराइटीज़ के मुकाबले काफी अच्छा परिणाम देता है, इसके मुकाबले में रखा जा सकता है। इसका दूसरी जगह उपयोग किया गया। इसमें रस्ट रेज़िस्ट करने की शक्ति होती है तथा draught कन्डीशन के लिये भी ठीक है। इसलिये रिसर्च (Research) के मामले में एक प्लान के अनुसार काम करना पड़ता है।

बारली के अन्दर भी अनुसन्धान किया गया। आर.जे.एस. १७ एक ऐसी वेराइटी निकाली गई जिससे एक एकड़ में चार मन ज्यादा पैदावार होती है। इसमें भी रस्ट रेज़िस्ट करने की शक्ति है। यह इसका एक खास गुण है।

आर. जे. एस. १० जो निकला गया, इसका भी एक्स्पेरीमेन्ट किया गया और इसके परिणाम भी अच्छे आये हैं।

मूँग की वेराइटी आर. जे. ४ को भी इवोल्व (evolve) किया गया। बाजरे की भी एक नई किस्म का अनुसन्धान किया गया, जिसका रिज़ल्ट (परिणाम) भी अच्छा आया है।

आर. आर. ४५ लिन्सीड वेराइटी है। इसका भी एक्सपेरिमेन्ट किया गया। इसके भी अलग अलग जगह अच्छे परिणाम जाहिर हुए हैं। कोटन में भी I. C A. R. की स्कीम के मुताबिक काम किया गया। उसमें भी हमने काफी सफलता प्राप्त की है।

मक्का में एक अमेरिकन वेराइटी का अनुसन्धान किया गया जिसके परिणाम भी ज्यादा अच्छे नजर आये हैं। इन सारी बातों के लिए जो साधन हमें उपलब्ध हैं उनसे स्पष्ट होगा कि एक्सपेरिमेन्ट का काम कोई साल भर में छः महिने में दिखाई देता है। इस प्रकार के कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होते जिनके परिणाम आपको रोज ही मालूम हो जाँय। इसके लिए पहले जितना स्टाफ दिया गया वह भी पूरा नहीं रखा गया है। इसके बावजूद भी जो प्रयत्न किए गए उसके परिणाम निराशाजनक नहीं कहे जा सकते। आगे हम इन परिणामों को ज्यादा फैलाना चाहते हैं, इन चीजों का ज्यादा प्रयोग करना चाहते हैं जिससे हमारी खेती को लाभ हो। करीब ३० प्रतिशत खर्चा एक्सपेरिमेंटल स्टाफ पर होता है। मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चरल विभाग इस प्रकार का विभाग है जिसमें ३० प्रतिशत खर्चा एक्स्पेरिमेंट्स पर किया जाय और उसके परिणाम जो आज तक निकले हैं उसको देखते हुए मैं मानता हूँ कि इस प्रकार का जो खर्चा हम कर रहे हैं वह गलत नहीं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा भारतवर्ष के अन्दर अगर किसी के परिणाम निकले हैं एक्स्पेरिमेंटस के, तो वह सिर्फ I. C. A. R. के निकले हैं। इसके द्वारा जो कुछ भी चीज पैदा की जाती है दूसरी जगह फैलाने के अन्दर जो स्टॉफ काम करता है उस पर खर्च ज्यादा होना अनिवार्य है। एक्सपेरिमेंट्स किए जायें और उसके परिणामों को लोगों तक पहुँचायें, यह हमारा प्रयत्न होना चाहिये। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूँ कि हमने एक प्रोग्राम, कृषि विकास का प्रोग्राम सारे राजस्थान में चालू करने का तय किया है। आम तौर पर किसानों में यह भावना होती है कि अगर हम उनसे कहें कि

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

तुम अमुक फर्टिलाइज़र्स को काम में लावो तो एकाएक मामूली काश्तकार को जँचता नहीं, जब तक कि वह अपनी आँखों से उसके परिणामों को देख न ले। किसान अपनी आँखों से देखी हुई चीज़ पर ही अधिक विश्वास करता है, बजाय हमारे विश्वास दिलाने के। इसलिए हमने राजस्थान में अलग-अलग तहसीलों के अन्दर कुछ किसानों के खेतों को डिमॉन्स्ट्रेशन फार्म्स की तौर पर प्रयोग करने का सोचा है। उनको एग्रीकल्चर विभाग की ओर से बताया जायगा कि किस प्रकार बीजों को बोया जाता है, किस प्रकार खाद दिया जाता है, कौन से तरीके अपनाये जाँय जिनसे ज्यादा पैदावार बढ़ सकती है। जिस खेत को एग्रीकल्चर विभाग लेगा उसमें से आधा हिस्सा उस किसान को अपने तरीके से बोने के लिए उसके पास रखा जायगा ताकि वह दोनों की तुलना कर सके। अगर कृषि विभाग की तरफ से की जाने वाली खेती में कुछ लोस (loss) रहेगा तो सरकार उसका लोस पूरा करेगी। अगर कृषि विभाग के तरीकों से खेती में उन्नति हो सकी तो उन किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे भी उन तरीकों को अपनाने लग जायेंगे। जैसा कि पिछले वर्ष जापानी पद्धति से जो चावल की खेती की गई उससे काफी फायदा हुआ और आज हमारे पास कई किसान आते हैं उन मेथड्स को अपनाने के लिए। पहले हमारे राजस्थान में अमोनियम सल्फेट का प्रयोग बहुत कम होता था, उसके मुकाबले आठ गुना प्रयोग अब ज्यादा बढ़ गया है और हम आशा करते हैं कि इसका प्रयोग अगले वर्ष कई गुना और ज्यादा हो जायगा।

राजस्थान में वैज्ञानिक ढंग से कृषि की तरक्की के लिए प्रयोग की शुरूआत है इसके परिणाम आने में समय लगना जरूरी है। लेकिन मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह चीजें गति पकड़ रही हैं। हमारे यहाँ फर्टिलाइजर का प्रयोग आठ गुना बढ़ा है।

कृषि विभाग के लिए कहा गया कि इसमें टिड्डियें मारने के लिए डस्ट-स्प्रेडिंग मशीन जो खरीद की गई उसके ज्यादा दाम दिए गए हैं, लेकिन आप सोचिए कि पिछले वर्ष इतना भयंकर टिड्डियों का आक्रमण हुआ जितना पिछले इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। ऐसे समय में भी कृषि विभाग के प्रयत्नों से फसलों को नुकसान नहीं हो सका केवल 'न' के समान नुकसान हुआ। सही तौर पर प्रयत्न किये गये, इसी का परिणाम था कि हमें इसमें कामयाबी हासिल हुई। लेकिन इस कामयाबी के लिए किसी ने सोचा नहीं। यह स्पष्ट तौर पर ज़ाहिर है कि इस चीज़ में हमने पूर्णतया कामयाबी हासिल की। जो कुछ गड़बड़ इसमें हुई है उसकी जाँच की जा रही है। अगर इसमें तथ्य होगा तो उसको स्वीकार किया जायगा। लेकिन इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि इनके ज़रिये खड़ी फसलों को बचाया गया और अधिकाधिक इनसे उपयोगी कार्य हुआ।

मशीनों के बारे में एक बार नहीं अनेकों बार प्रश्न उठाए गए। जिन लोगों ने प्रश्न को उठाया उनकी भावनायें क्या हैं, इस बात को वे अच्छी तरह जानते हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि कृषि विभाग के अन्दर जो खरीद की जाती है उस पर किसी को सन्देह करने की गुँजाइश ही नहीं होनी चाहिये। कृषि विभाग द्वारा जो सामान लिया जाता है—ट्रैक्टर्स, कम्प्रेसर्स आदि; भारत सरकार के डाइरेक्टर ऑफ परचेजेज् (Director of Purchases) का जो डिपार्टमेंट है उनके द्वारा खरीदे जाते

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

तो शायद सस्ते मिल सकते थे। निश्चित तौर से नहीं कह सकते कि सस्ते मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, केवल सस्ते मिलने की सम्भावना है। हमने यह रेडिली (readily) मन्जूर किया है, अगर इसमें कोई सन्देह होता और अगर कोई बात होती तो हम स्वीकार करने के बजाय टेढ़े-मेढ़े रास्ते अपनाने का प्रयत्न करते। लेकिन हमने उस प्रोसीजर को अडोप्ट करना मन्जूर किया है। अगर उसके ज़रिये से ठीक चीजें ठीक दामों में मिलती हैं तो उसकी कोशिश की जाय। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप ठीक रूप में किसी को रखेंगे तो हमें स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। बजाय इसके कि आप ऐसा चश्मा लगाना चाहें जो ठीक न हो तो उसके परिणाम ज्यादा लाभप्रद नहीं होंगे। इस प्रकार कई सही चीजें समझने में भूल हो सकती है।

मैं यह भी साफ अर्ज करना चाहता हूँ कि कृषि विभाग द्वारा जो भी कार्य किए गए वे काफी उपयोगी कार्य थे तथा और भी काफी उपयोगी कार्य हम करना चाहते हैं।

कम्प्रेसर्स के ज़रिये हम चाहते हैं कि इस पर किसानों को जो खर्चा करना पड़ता है वह कम से कम पड़े।

अगर कोई भी माननीय सदस्य उचित सुझाव देंगे कि इस प्रकार से खर्च में कमी की जा सकती है तो हम उसका सदैव स्वागत करेंगे।

इसी प्रकार हमारे एक माननीय मित्र ने कहा कि ट्रैक्टर्स और पम्पिंग सेट्स देकर बड़ी-बड़ी जमीनों को बोने के लिए हम प्रोत्साहन दे रहे हैं, ताकि बड़ी-बड़ी ज़मीनों की बढ़ोतरी हो। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि हम आम तौर पर इस बात को नहीं चाहते कि हम ट्रैक्टर्स उन लोगों को दें, जो नए तरीकों से ज़मीन को बोवें। न हम यह चाहते हैं कि जो जमीन पहले से काश्त हो रही है उस जमीन के लिए ट्रैक्टर्स देकर उन्हें बेदखल करने का अवसर दें।

इसलिए माननीय अध्यक्षजी, हमने निश्चित तौर से इन्सट्रक्शन्स जारी किए हैं कि जब कलेक्टर्स और डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफीसर रिपोर्ट करें तो इस बात की भी रिपोर्ट करें कि इस जमीन पर पहले से काश्त है या नहीं, जिससे स्पष्ट मालूम हो सके कि पहले खेती करने वाला उस पर है और वह बेदखल न किया जा सके। वह यह भी रिपोर्ट करते हैं कि वह जमीन ऐसे ही पड़ी है या किसी के पास है। पर पहले से ही बन्जर है और वह उसको उठाना चाहता है तो उसके लिए ट्रैक्टर लोन अवश्य दिया जाता है।

इसी तरह पम्पिंग सेट का लोन १५००) रु० दिया जाता है। इसलिए बड़े-बड़े फार्मों के लिए यह नहीं होता है। मामूली काश्तकार के लिए भी वह उपयोगी होता है और इसके द्वारा अधिक से अधिक काम कर सकता है।

श्री सन्तोषसिंह—पन्द्रह सौ रुपयों में पम्पिंग सेट नहीं आवेगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—तीन हजार में आ जावेगा। १५००) रु. सरकार देती है और इतना ही लेने वाले को देना होता है। तो इस तरह से ३०००) रुपये हो जाते हैं और इसमें पम्पिंग सेट आ सकता है।

श्री सन्तोषसिंह—इतने में तो केवल एक डीजल एन्जिन आता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—मैं समझता हूँ कि दूसरों ने लिए हैं, आप केवल कल्पना करते हैं। पन्द्रह सौ सरकार दे और पन्द्रह सौ खुद की अपनी रकम हो जाती है, जिससे वह पम्पिंग सेट खरीद सकता है।

दूसरी बात ट्यूब वेल के बारे में कही गई। एक सदस्य ने कहा कि कुछ जिलों में ट्यूब वेल खोदे जा सकते हैं। मैं माननीय अध्यक्ष, आपकी मार्फत सदन को सूचना देना चाहता हूँ कि कुछ इलाकों के अन्दर इसकी जानकारी की गई पर परिणाम जितना अच्छा होना चाहिये वह नहीं आया। इसके बाद हमने भारत सरकार के कृषि विभाग से बातचीत की और इस वर्ष जो ट्यूब वेल के लिए रकम 'ग्रो मोर फूड' (grow more food) की स्कीम के मातहत आनी चाहिये थी उसके लिए हमने केन्द्र को कहा कि वह रकम हम नहीं चाहते बल्कि इसके बदले सबसे पहले हमने भारत सरकार से कहा कि भारत सरकार के द्वारा ७ एक्सप्लौरेटरी ट्यूब वैल खोदे जाने चाहिये, इसका एक्सपेरिमेन्ट स्वयं केन्द्रीय सरकार करे और अगर यह सफल हो तो हम आगे इस स्कीम को बढ़ाने के लिए सोच सकते हैं। क्योंकि हमारे पास प्रोपर जिओलोजिकल सर्वे, जो इस काम के लिए निहायत जरूरी है, यहाँ नहीं है और इसके अभाव में कई जगह ठीक परीक्षण नहीं हो पाता और रुपया बेकार हो जाता है, मेहनत भी बेकार जाती है और इससे डरकर काश्तकार भी अपनी आधी रकम इसके लिए लगाने के लिए तैयार नहीं होता, जो कि बिल्कुल स्वाभाविक है। तो इसलिए हमने भारत सरकार को एक्सपेरिमेन्ट के तौर पर पहले-पहले सात जगह ऐसे ट्यूब वैल खोदने के लिए लिखा है। इसमें अगर चार-पाँच जगह भी हम सफल हो जावें तो आगे हमारा उत्साह बढ़ सकता है। इसलिए सबसे पहले भारत सरकार से हमने कहा कि कम से कम सात ट्यूब वैल एक्सपेरिमेन्ट के तौर पर आप अपने खर्च पर यहाँ एस्टेब्लिश कर दीजिये, कि यह परीक्षण कहाँ तक सफल होगा ? इसके बाद तो हम लोन लेकर भी आगे खोदना चाहेंगे। तो इस तरह के अनुभव से जो-जो बातें हमारे सामने आती गईं उनसे हम सीखते गए हैं और भिन्न-भिन्न बातों में इसके आधार पर आवश्यक परिवर्तन करने के बाद हमने जो भी हो सकता था वह किया है।

अभी एक मित्र ने कहा कि सिरोही जिले में इसका एक्सपेरिमेन्ट किया जावे। भारत सरकार के एक्सपर्टस् ने इसकी जाँच की थी और उस जाँच के आधार पर भारत सरकार के इन एक्सपर्टस् ने कहा कि बीकानेर के आस-पास इसकी सफलता की सम्भावना है, बाकी दूसरे स्थानों पर यह सफल नहीं हो सकता। यह प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट पर पहुँचने से ठीक कहा जा सकता है।

बकाया लोन अब देने के लिए जो कहा गया वह इस वर्ष न देकर एग्रीकल्चर अंडर ग्राऊन्ड वाटरबोर्ड के द्वारा ही यह रकम खर्च करने का सरकार का इरादा है। एग्रीकल्चर अन्डर आउन्ड वाटर

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

बोर्ड जो आम तौर पर पीने के पानी के लिए काम करता है उसकी अलग-अलग दो ब्रान्चेंज़ जो काम कर रही थीं, उनके एवज में अब एक ही काम करे, ऐसा तय किया गया है। दो का अलग-अलग खर्चा भी अधिक होता था और काम भी जैसा चाहिये वैसा नहीं हो रहा था और ट्यूब वैल के काम को अब हमने एक तरह से स्थगित करके अपने काम को गहरे कुए खोदने पर कन्सेन्ट्रेट करके और नये कुए तैयार करने के काम पर सीमित किया है। इसमें यह सोचा गया है कि इसमें हमें अधिक सफलता मिल सकेगी और जिसमें अधिक सफलता मिल सके उसको करना चाहिये। यह सोचकर हमनें अपने काम को मर्यादित कर लिया है।

इस तरह से एग्रीकल्चर विभाग हमेशा इस प्रयत्न में रहा है कि किस प्रकार अधिक से अधिक पैदावार राजस्थान की बढ़े और मैं समझता हूँ कि पिछले अरसे में हमारे प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप यह पैदावार बढ़ी है और अब उदाहरण के तौर पर एग्रीकल्चर विभाग ने एक योजना बनाई है, जो भारत सरकार से भी स्वीकार करवाई है। वह योजना यह है कि जयपुर का सेवेज का गन्दा पानी काफी फालतू ही चला जाता है उसको उपयोग में लेकर फल, साग-सब्जी पैदा करने के काम में लाया जाय। इस योजना के फर्स्ट स्टेज में ५ लाख रुपया खर्च करेंगे कि किस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत वेजीटेबिल पैदा हो सकती है और किस तरह से ज्यादा से ज्यादा लाभ इससे हमको हो सकता है: इसके लिए एक योजना स्वीकार की गई है।

इसके बाद सेकिण्ड स्टेज की एक और योजना है। यह पहली योजना अगर सफल रही तो इसको और और शहरों में आगे बढ़ाना चाहते हैं जहाँ के लिए कई और और सुझाव हैं। तो इस तरह से कृषि विभाग दिन प्रति दिन आगे बढ़ना चाहता है। यह (विभाग) अनुभव के आधार पर तथा कुछ फण्डस् की अवेलेबिलिटी (availiability) के आधार पर हर सम्भव प्रयत्न करना चाहता है जिससे यह विभाग ज्यादा से ज्यादा राजस्थान की सेवा कर सके।

ऐसा विभाग जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुँचाने वाला कार्य करता हो, जब हम इसे क्रिटिसाइज़ करें तो कन्सट्रक्टिव क्रिटिसिज्म (constructive criticism) किया जाए, उसे स्वीकार करने को हम हमेशा तैयार हैं। कुछ (सदस्यों) ने कन्सट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी किया है। ऐसा क्रिटिसिज्म लाभप्रद हो सकता है। कुछ ऐसा नहीं कर सकते उनके लिए तो मैं कह ही क्या सकता हूँ कि वे इस बात का प्रयत्न करें। फिर भी जो ऐसा कन्सट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकते हैं उनके लिए कह सकता हूँ कि वे हर समय हमें सलाह दें। उनकी ठीक सलाहों का हम हर समय स्वागत करेंगे।

मैं इतना ही कह कर सदन से और माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूँगा कि वे अपने कट मोशन विद्ड्रा कर लें और इस डिमान्ड को स्वीकार कर लें तो अच्छा हो।

श्री जवानसिंह—मैं सदन से चाहता हूँ कि मेरा कट मोशन वापस लेने की मुझे स्वीकृति दी जाय।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं रिप्लाई में कुछ बोलने की इजाजत चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—बोलिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, मैंने एक कट मोशन मूव किया उसके निस्बत माननीय मन्त्री महोदय ने जो सफाई दी उसमें कुछ गैप्स (gaps) रह गये और बड़ा गैप तो यह रह गया कि जो एक्सपर्ट हैं उनसे हमको तरक्की हो, उन्नति हो तो सबको खुशी होगी, लेकिन उनके काम करने के लिए अगर प्रोवीज़न केवल ६,५००) रु० का है तो फिर काम करवाने के लिए उनको रक्खा गया है या वे ओरनामेन्टल (Ornamental) वजह से रक्खे गये हैं। इस प्रश्न का उत्तर माननीय मन्त्रीजी ने अपनी सफाई में नहीं दिया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं इसका उत्तर पहले ही दे चुका था जब कि माननीय सदस्य सदन में नहीं थे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—दूसरा जिक्र कन्स्ट्रक्टिव और अनकन्स्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का था। पाँच-सात दिन से कैसा भी विषय क्यों न हो, कैसा भी क्रिटिसिज्म क्यों न हो, करना पड़ा है। इसमें भी मैंने कई जगह क्रिटिसिज्म किया है और एक यह है कि पहले, दो साल पहले एक पर्पज़ (प्रयोजन) के लिए एक चीज खरीदी गई, अब दो साल के बाद उसी पर्पज़ के लिए और दूसरी चीज खरीदी जा रही है यहाँ। अगर हम ऐसा क्रिटिसाइज़ करें तो यह क्या कन्स्ट्रक्टिव है या अनकन्स्ट्रक्टिव है, इसको क्या कहें? इसको अनकन्स्ट्रक्टिव तो आप नहीं कह सकते, अनकम्फर्टेब्ल (uncomfortable) हो तो बात दूसरी है। पर उसकी सफाई होनी चाहिये, जो नहीं होती। इसकी भी सफाई हुई नहीं।

तीसरी बात यह कही गई कि इण्डियन कौंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जैसी संस्था ने तरक्की के रास्ते पर ला रक्खा है देश को। लेकिन माननीय मन्त्रीजी यह कहना न मालूम क्यों भूल गये कि राजस्थान के जो इतने उच्चतम एक्सपर्ट्स हैं उनका एक भी ऐसे या पेपर (eassay or paper) इस इण्डियन कौंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बुलेटीन में आज तक शाया नहीं हुआ। आज तक एक भी शाया नहीं हुआ और अगर ऐसी परिस्थिति है तो फिर उस एक संस्था का नाम लेकर यह क्यों कोशिश की जावे समझाने की और कहने की कि हमारे यहाँ के काम-काज का ताल्लुक कैसा भी उस संस्था के साथ है, पाँचवें सवार हम भी हैं। वाकया तो यह है कि रिसर्च का प्लान भी अभी तक ले आउट (lay out) नहीं किया गया है और ऐसी सूचना हमें दिसम्बर के महीने तक निर्माण विभाग द्वारा मिली है। नवम्बर-दिसम्बर तक रिसर्च का प्लान भी ले आउट नहीं हुआ है। और जो रिपोर्ट्स आई हैं उनमें एक रिपोर्ट में विशेषज्ञ साहब ने यही कहा था कि हमारे पास फन्ड्स नहीं हैं, हमारे पास स्टाफ नहीं है, हमारे पास कोई इक्विपमेंट (equipment) नहीं है कि कोई रिसर्च करके आज किसानों के पास ले जाई जाय। इसका भी कोई उत्तर मन्त्री महोदय ने नहीं दिया।

अन्त में मशीन तकावी के सम्बन्ध में प्रश्न उठा था, जिसमें भी एतराज इस बात पर था कि आज तक रूल्स नहीं बनाये गये हैं। अभी कुछ महीने पहले रूल्स बनाये गये हैं तो अब तक की

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

जो मशीन तकावी दी गई है लाखों रुपये की वह और रूल्स के कैसे दे दी गई, और पिछले डेढ़ साल से इस विभाग के पास यह सूचना भेजी थी कि अमुक-अमुक व्यक्तियों ने कर्जा लिया है, लेकिन मशीनें नहीं खरीदी हैं। तो डेढ़ साल तक उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई है। जोधपुर में एक उपचुनाव हुआ। एक सज्जन ने, जिन्होंने आज तक खेती नहीं की और आज भी नहीं करते, उन सज्जन को मशीन तकावी दे दी गई। ३१ अक्टूबर, ५२ को सदन के अधिवेशन के सामने यह प्रस्तुत किया गया था और यह आश्वासन दिया गया था कि जाँच की जायगी, जिसमें कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कर्जा लेकर कपड़े की दूकान खोल ली। क्या कार्यवाही की गई उसके बारे में, इसका भी उत्तर अभी तक नहीं मिला है। यह बात ठीक है कि अब मुकद्दमात बन चुके हैं; यह बात ठीक है कि २ महीने का नोटिस भी दे दिया गया है, मेरी इसमें दिलचस्पी नहीं है। मेरी दिलचस्पी तो इसमें है कि २ महीने गुजर जाने के बाद क्या जवाब दिया गया, सरकार क्या कार्यवाही करेगी, इसका पता बाद में चलेगा; लेकिन आखिर यह २ महीने का नोटिस दे दिया गया, सवाल यह नहीं है; सवाल तो यह है कि १॥ साल तक क्या किया गया, अगर नहीं किया गया तो विभाग के द्वारा क्या कार्यवाही की गई, विभाग के मन्त्री की ओर से क्या कार्यवाही की गई, इन प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर नहीं आने की वजह से मुझे अफसोस है कि मैं इस कटौती प्रस्ताव को वापिस नहीं ले सकता हूँ। बस इतना ही मुझे अर्ज करना है।

श्री अध्यक्ष—और कोई जवाब देना चाहते हैं?

(श्री जवानसिंह को संकेत करके)

You like to withdraw your Cut motion?

श्री जवानसिंह—Yes, Sir, Is it the leave of the House to allow Shri Jawan Singh to withdraw his Cut-motion.

(स्वीकृत)

श्री जवानसिंह—I withdraw my Cut-motion.

श्री अध्यक्ष—The question is that the Cut-motion moved by Shri Gopi Lal Yadav be accepted.

(अस्वीकृत)

The cut motion fails.

(विराम)

The question is that two cut-motions by Shri Kapil Deo Agrawal be accepted.

[श्री अध्यक्ष]

(अस्वीकृत)

The cut-motions fail.

(विराम)

The question is that the four cut-motions moved by Shri H. K. Vyas be accepted.

श्री हरिकृष्ण व्यास—All together, Sir ? Two are economy motions and should be voted separately.

श्री अध्यक्ष—Then they would be voted unanimously.

श्री हरिकृष्ण व्यास—All of them cannot be.

श्री अध्यक्ष—The question is that the cut motions by Shri H. K. Vyas be accepted.

(अस्वीकृत)

The cut motions fail.

(विराम)

The question is, "That a sum not exceeding Rs. 37,70,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1955 in respect of Grant No. XIX, Major Head 40—Agriculture."

(स्वीकृत)

The demand is granted.

माँग संख्या १६–शिक्षा

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Sir, it is a very important subject.

श्री अध्यक्ष—We will discuss.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—We will discuss, but since when ?

श्री अध्यक्ष—The motion is, That a sum not exceeding Rs, 3,35,20,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1955 in respect of Grant No. XVI, Major Head 37—Education."

Page No.129

[श्री अध्यक्ष]

(श्री जसवन्तसिंह को संकेत करके)

You do not want to take the first chance ?

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Certainly I do.

(To discuss the growing spirit of indiscipline amongst students) माननीय अध्यक्षजी, मैंने शिक्षा के विषय पर दो कटमोशन दिये हैं, एक तो जो आजकल के विद्यार्थी हैं उनमें दिन पर दिन इन्डिसिप्लिन का स्तर बढ़ता जा रहा है उस पर। मैं नहीं समझता कि मेरे मित्र माननीय शिक्षा मन्त्री जी या एजुकेशन डिपार्टमेंट उसको अच्छा समझता है या बुरा समझता है, लेकिन यह बात तो जरूर है कि वह इसको बर्दाश्त किये जा रहे हैं और दिन पर दिन विद्यार्थियों की ऐसी हालत हो रही है कि एक दिन वह आयेगा, अगर गवर्नमेंट कोई कदम आगे नहीं उठायेगी, तो हमारे मित्र जो एच. के. व्यास हमारी तरफ बैठे हैं, उनकी रैंक इस सभा भवन में अगले १० साल में इतनी ज्यादा तादाद में आ जायगी कि मुमकिन है कि हमारी जो ट्रेज़री बेन्चेज़ हैं उन पर भी कब्जा करलें।......

एक आवाज़—इन्डिसीप्लिन से।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जायगा तो यह नामुमकिन नहीं रहेगा।

इसलिए मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि दूसरे डिवीज़नों में जो बातें हो रही हैं वह हो रही हैं; लेकिन आजकल बीकानेर इन बातों में सबसे आगे चल रहा है, और पथप्रदर्शन हो रहा है.....

एक आवाज—आप ही नेता हैं।

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !!

कुँ० श्री जसवन्तसिह—मैं, भूतपूर्व शिक्षा मन्त्रीजी, जो कि यहाँ इस समय नहीं हैं, उनके वक्त पढ़ाई का यह नमूना है वह मैं बताना चाहता हूँ। उन्हें आज से २ वर्ष पहले बीकानेर पधारने का अवसर प्राप्त हुआ था। उनका जो स्वागत किया गया डूँगर कॉलेज के विद्यार्थियों ने वह देखने लायक अवसर था। पुलिस का भी बड़ा अच्छा बन्दोबस्त था। बड़े-बड़े राजस्थान के अफसरान; कमिश्नर, कलेक्टर, डी. आई. जी. पी. वगैरह वहाँ पर मौजूद थे, और वहाँ हर तरह से उनके स्वागत के लिए प्रबन्ध किया गया था। मगर इस प्रकार के प्रबन्ध के बावजूद विद्यार्थियों द्वारा जबरन ट्रेन में से हमारे शिक्षा मन्त्रीजी को पकड़ कर बाहर लाया गया और जहाँ कि उनके स्वागत के लिए राजकीय मोटर पोर्च में खड़ी हुई थी उसको उन्होंने पहले से ही पन्चर करके तैयार रख दिया था। ज्योंही वह बैठने लगे तो मोटर नहीं चल सकी और उसके बाद मैं जितनी मोटरें अफसरों की वहाँ पर मौजूद थीं उन सब को पन्चर कर दिया। बाद में एक तांगा जो बिल्कुल

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

काले भन्डों से सुसज्जित था उसमें मन्त्रीजी को पकड़कर जबरदस्ती बिठा दिया। अगर यह गलत है तो इसको कन्ट्राडिक्ट करें और अगर सही है तो इसकी ताईद करें। फिर हमारे मन्त्रीजी के हाथ में काला भन्डा दे दिया और उनसे कहा कि आप इसको हाथ में रखें। मुझे मानना पड़ेगा माननीय मन्त्रीजी का धीरज, वह सराहनीय रहा; क्योंकि उन विद्यार्थियों ने उन्हें जिस तरह का नाच नचाया उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से नाच नाचा। शहर में जहाँ डूँगर कॉलेज स्थित है वहाँ पर उनको सवारी के साथ काला भन्डा उनके हाथ में देकर, पुलिस के सिपाही और स्थानीय अफसर, कमिश्नर, कलेक्टर वगैरह सब वहाँ पर मौजूद थे, उनको बड़ी अच्छी तरह से डूँगर कॉलेज में ले जाया गया और वहाँ जो बरताव हुआ उनके साथ, उसका उल्लेख नहीं किया जा सकता? उसके लिए न सरकार की तरफ से कुछ विद्यार्थियों का कुछ हुआ और न कॉलेज के पदाधिकारी जो थे वह कुछ कर सके। तो मैं आपको यह बतलाता हूँ कि जब ऐसी हालत विद्यार्थी एक माननीय मन्त्री की कर सकते हैं वगैर किसी डर के तो देश का भविष्य अँधेरे में है।

अभी श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण के जवाब में मैंने बतलाया था कि श्री जगजीवन रामजी अभी बीकानेर आये थे, उनके साथ भी इसी प्रकार का बर्ताव किया गया। बच्चों के दिमाग में मालूम नहीं, बैठे-बैठे कभी-कभी क्या सनक आ जाती है कि उन्हीं लोगों ने कहा कि हम जगजीवन रामजी को स्टेशन के मेन दरवाजे से नहीं जाने देंगे तथा चाहे कुछ भी हो उनको गार्ड ऑफ आनर नहीं लेने देंगे। फिर झगड़ा फिसाद वगैरह करके पिछले थर्ड क्लास के दरवाजे से श्री जगजीवन राम जी को किसी तरह गाड़ी पर बिठाकर ले जाया गया। यह चीजें हमारे भविष्य के लिए, जो बच्चे हैं जिन पर कि देश के चलाने का बोझ पड़ने वाला है- हमारी रियासत, हमारे राज्य के संचालन का बोझा पड़ने वाला है और हमारी सरकार ठीक बात समझती है तो मैं कहना चाहता हूँ कि वह बहुत गैर-जिम्मेवरी की बात वह कर रही है।

मैं आपको बतलाऊँ कि हरेक प्रान्त या डिवीजन का अपना-अपना समय हुआ है। हमारे राजस्थान के बनने के बाद कम्पीटिशन जयपुर और जोधपुर के बीच में रहा है। कभी जयपुर ऊपर आ जाता है और कभी जोधपुर ऊपर आ जाता है। दूसरे डिवीज़न्स में तो कम्पीटिशन का कोई सवाल अभी तक पैदा नहीं हुआ है। मैं आपसे अर्ज करूँ कि हमारे यहाँ राजस्थान भर में जो बड़े-बड़े कॉलेजेज़ हैं उनके जितने भी प्रिन्सिपल्स हैं उनमें से लगभग ८० पर्सेन्ट प्रिन्सिपल्स जोधपुर से आये हुए हैं। बहुत अच्छी बात है जोधपुर से आये हैं तो, जोधपुर के हों या कहीं के हों; जिस किसी को भी फायदा पहुँचे तो अच्छी बात है। मैं यह कहने में संकोच नहीं करूँगा कि एजुकेशन मिनिस्टर साहब मेरी बात को ध्यान से सुनें तो अच्छा हो। मैं यह कह रहा था कि ८० प्रतिशत प्रिन्सिपल्स जोधपुर से आये हैं। बीकानेर की डूँगर कॉलेज़, एक फर्स्ट ग्रेड कॉलेज़ हैं। उस कालेज के प्रिन्सिपल जोधपुर से आये हैं और उनका नाम 'बहादुर' है। वे कितने बहादुर हैं, यह मैं सदन में बयान करना चाहता हूँ। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मन्त्रीजी मेरे साथ चल कर देख सकते हैं कि वे क्लासेज़ में राउन्ड तक नहीं लगा सकते। लड़कों ने उनको कह दिया है कि आप क्लासेज़ में नहीं आ सकते। वे अपने रूम में जाकर बैठ जाते हैं। प्रिन्सिपल के नाते उनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि उनके कॉलेज के

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

जो साथी हैं उनके साथ बैठकर बराबरी में बात कर सकें क्योंकि जो स्थिति उन लड़कों ने उनकी कर दी है वे भी उनके साथ उसी तरह का व्यवहार करते हैं। मैं आपको एक वाक्या बताना चाहता हूँ। स्टूडेन्ट्स यूनियन के लिए झगड़ा हुआ। उसके मुतल्लिक लड़कों ने यह कहा कि आज अगर प्रिन्सिपल क्लासेज़ से बाहर निकलेंगे तो उसे ठीक कर दिया जायगा। यह बात लड़कों ने उन बहादुर साहब से कह दी। अब वे बहादुर साहब अपने कमरे का दरवाजा बन्द करके बैठ गये। सुबह से लेकर शाम को ७ बजे तक वे उसमें बैठे रहे, लेकिन चार-पाँच विद्यार्थी वहाँ बैठे रहे कि देखें किस कदर, क्या हालत उनकी होती है। ७ बजे के बाद उनका ब्लेडर बर्स्ट होने लगा क्योंकि वे भी मनुष्य हैं; उनको भी पेशाब-टट्टी की हाजत हो सकती है। सुबह से बैठे हुए को शाम हो गई, ७ बज गये तब उन्होंने सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस और कलेक्टर को फोन किया कि आप जल्दी आइये मेरा ब्लेडर बर्स्ट हो रहा है, विद्यार्थी कहते हैं कि हम तुमको पीटेंगे। यह वाकया बिल्कुल सच्चा है। मिस्टर झाला उस समय कलेक्टर थे, उनको फोन किया। एस. पी. और कलेक्टर ने आकर उनको कमरे से निकाला और कमरे से बाहर निकलते ही उन्होंने पहली बात यह कही कि आप यहाँ खड़े रहें मैं अपना ब्लेडर खाली करलूँ, फिर दूसरी बात करूँगा। यह हालत है एक फर्स्ट ग्रेड कॉलेज के प्रिन्सिपल की, जिनकी ऐसी हालत ५–७ विद्यार्थी कर सकते हैं; वे विद्यार्थी जिनके कन्धों पर देश का भार पड़ने वाला है। यदि सरकार इसको छोटी चीज़ समझती है तो एक दिन वह देखना पड़ेगा जब हमें बड़ा अफसोस करना पड़ेगा।

इसी तरह सादूंल हाई स्कूल है बीकानेर में, जिसमें २०००–३००० लड़के पढ़ते हैं। वहाँ के हैड मास्टर भी जोधपुर से पधारे हुए हैं। उनकी भी यही हालत करदी गई, वे भी लड़कों के क्लासेज़ में राउन्ड नहीं ले सकते। कभी हिम्मत करके क्लासेज़ में चले भी जाते हैं तो यह देखने में आया है कि लड़के और छोटे-छोटे बच्चे अपनी जेबों में कंकर भर लेते हैं और उन पर फेंकते हैं। यह वाक़या सच्चा है। यदि शिक्षा मन्त्री महोदय न मानें तो वहाँ जावें और आँखों से देखें कि विद्यार्थियों की जेबों में कंकर हैं या नहीं। हैड मास्टर जब घूमते हुए आते हैं तो, मैंने सुना है कि उनके केस नहीं हैं वे बाल्ड (bald) हैं, उन पर पत्थर फैंकने लगते हैं। मैं आपसे यह प्रार्थना करूँगा कि यह बड़ी जबर्दस्त समस्या है। माननीय शिक्षा मन्त्री इसे भले ही मामूली समस्या समझते हों तो उनको मुबारिक हो। मैं तो २५ वर्ष तक एडमिनिस्ट्रेटर रह चुका हूँ और वह भी उस समय में जब डिसिप्लिन खास चीज़ समझी जाती थी। मैं मानता हूँ कि स्वराज्य होने के बाद डिसिप्लिन मजाक बन गया है, मैंने ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी। मैं शिक्षा मन्त्रीजी से प्रार्थना करूँगा कि वे इस ओर पूरा ध्यान दें और यदि नहीं देंगे तो उसका प्रभाव बहुत बुरा पड़ने वाला है।

मेरा एक और कट मोशन है जो दूसरे विषय पर है और यह बहुत गम्भीर विषय है। मैं चाहूँगा कि यदि माननीय शिक्षा मन्त्रीजी इस पर ध्यान देंगे तो अच्छा होगा। वह है संस्कृत शिक्षा के बारे में। यह बीमारी समझिये या शौक समझिये कुछ समय से मुझे संस्कृत के लिए शौक पैदा हुआ है और मैंने काफी संपर्क इसमें स्थापित किया है। ज्यों ही राजनीति से मुझे समय मिलता है त्यों ही मैं इसमें समय देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस ओर ध्यान दिया जाय तो सुन्दर बात होगी। भारत

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

के जितने प्रान्त हैं सब में संस्कृत की तरक्की करने की कोशिश की जाती है। यहाँ तक कि बिहार, मध्य प्रदेश आदि स्थानों पर तो सरकार की तरफ से संस्कृत प्रचार के लिए प्रचारक मुकर्रर किये गये हैं; लेकिन राजस्थान में यदि हम संस्कृत शिक्षा की ओर देखें तो असंतोष होता है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मैं खास कर इस बात को इसलिए कहना चाहता हूँ कि माननीय अध्यक्ष जी को इस विषय से प्रेम है और आपकी अध्यक्षता में जब मैं यह बात कहता हूँ तो मैं ख्याल करता हूँ कि सरकार इस पर अवश्य ध्यान देगी।

श्री अध्यक्ष—I can give you time.

कु० श्री जसवन्तसिंह—That is sufficient for the time being.

यह राजनीति का सवाल नहीं है, लेकिन दुःख के साथ यह कहता हूँ कि ५–६ वर्ष में जो संस्कृत पाठशालाएँ थीं और जो अच्छी तरह से चल रहीं थीं उनमें से आधी से ज्यादा बन्द हो गई हैं। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों हुआ? हमारी सरकार इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। हमको खुद को प्रचार करना है। यह देव-भाषा है और परम्परा से रही है। हमारी जो राष्ट्र भाषा है उसको प्रोत्साहन देने के लिये भी संस्कृत की तरफ तवज्जोह देना बहुत आवश्यक हो जाता है। अभी वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेन्स (World Sankrit Conference) काशी में हुई थी जिसकी अध्यक्षता हमारे पूजनीय नेता डॉक्टर राजेन्द्रप्रसाद ने की थी। उन्होंने भी इसके लिए बहुत जोर दिया और उन्होंने हिन्दुस्तान में ज्यादा संस्कृत की तरक्की का कारण यह बताया कि जो छात्रवृत्तियें पहले संस्कृत के विद्यार्थियों को दी जाती थीं उनके कारण बहुत उन्नति हुई। संस्कृत सीखने का काम गरीब आदमी ही ज्यादा करते हैं। अँग्रेजी के लिए लाखों-करोड़ों रुपये खर्च किये जाते हैं, लेकिन संस्कृत के छात्रों को जो छात्रवृत्तियें दी जाती थीं वे भी अब बन्द कर दी गई हैं। अँग्रेजी लोग इसलिए अधिक सीखते हैं कि लोग ज्यादातर गवर्नमेंट की सर्विसेज़ में आना चाहते हैं। उसे पढ़कर प्रोफेसर, वकील आदि बनना चाहते हैं। उनके पास कई तरह के साधन हैं। लेकिन संस्कृत पढ़ने वाले गरीब आदमी ही होते हैं। उनको जो छात्रवृत्तियें पहले मिला करती थीं वे अब दिन पर दिन कम होती जा रही है। जो सेठ-साहूकार संस्कृत पाठशालाएँ चलाया करते थे उनकी इकोनोमिक कंडीशन खराब हो जाने के कारण वे भी बन्द होती जा रही हैं। जो पाठ-पूजा की जाती थी वह भी बन्द होती जा रही है। हमारे राजस्थान में नौकरियों की तरफ देखें तो पता चलेगा कि संस्कृत पढ़े हुए ५ पर्सेन्ट आदमियों को भी यदि नौकरी मिल जाय तो मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा नौकरियाँ मिल गई हैं।

जो हमारे यहाँ कम्पीटिटीव एग्जामिनेशन्स (competitive examinations) होते हैं उनमें भी ऐसा देखने में आया है कि जो लोग मेट्रिक पास हैं और उन्होंने संस्कृत का सब्जेक्ट ले कर मेट्रिक पास किया है तो उनको कम्पीटीटिव एग्ज़ामीनेशन में बैठने की इजाजत दी जाती है परन्तु उनसे ४ गुना, ६ गुना ज्यादा अच्छी काबलियत की संस्कृत परीक्षाएँ जो पास हैं उनको कम्पीटीटिव एग्ज़ामीनेशन्स में बैठने की इजाजत नहीं दी जाती। यह भी एक बात है जो कि हमारी संस्कृत की अवनति का कारण है। जयपुर की संस्कृत परीक्षा का रेकर्ड देखेंगे तो मालूम होगा कि संस्कृत को

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

शिक्षा बजाय बढ़ने के दिन प्रतिदिन अवनति की ओर जा रही है। इस सब को देखेंगे तो मालूम होगा कि हमें इसमें बहुत कुछ करने की गुँजायश है। अतः माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा शिक्षा मन्त्री जी से अनुरोध है कि राजस्थान में संस्कृत शिक्षा के लिए आदर्श राज्य बनना जरूरी है। हमारे यहाँ की परम्परा ऐसी है कि उसे बनाये रखना हमारा कर्तव्य हो जाता है।

इन्डिसिप्लिन के बारे में मैंने अभी बहुत कुछ कहा था। जहाँ अंग्रेजी शिक्षा है वहाँ इन्डिसिप्लिन देखा जाता है। जहाँ संस्कृत की शिक्षा है वहाँ इन्डिसिप्लिन नहीं देखने को मिलेगा, वहाँ गुरू-शिष्य का बरताव रीयल सेंस (real sense) में जैसा होना चाहिये वही होता है। लेकिन कॉलेजेज़ में गुरू-शिष्य का बिल्कुल उससे भिन्न बर्ताव हो गया है जिससे बहुत ज्यादा तादाद में इन्डिसिप्लिन फैल गया है।

हमारे राजस्थान में जो गर्ल्स कॉलेजेज़ हैं उन पर ध्यान दें तो मेरा खयाल है कि बीकानेर के गर्ल्स कॉलेज के अलावा दूसरी कॉलेजेज़ में संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती है। इसका नतीजा यह होगा कि एक दिन वह आयेगा कि राजस्थान में स्त्रियाँ और लड़कियाँ सती सीता और सावित्री का नाम तक भूल जायंगी, हाँ जूलियस और मेरिन्डा के नाम तो उन्हें जरूर याद रहेंगे। परन्तु अगर गर्ल्स कॉलेजेज़ से संस्कृत की शिक्षा उठा दी जायगी तो वे सीता और सावित्री का नाम भूल जायंगी। उन्हें अगर जूलियस और मेरिंडा के नाम पूछेंगे तो उनकी सात पीढ़ियों के नाम बताने को वे तैयार हो जायंगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा शिक्षा मन्त्रीजी से प्रार्थना करूँगा कि यदि गर्ल्स कॉलेजेज़ में संस्कृत शिक्षा बंद हो गई हो तो वहाँ शुरू करा दें, यह अच्छा होगा।

जो अंग्रेजी पर कॉलेजेज़ में और हाई स्कूल्स में खर्चा होता है, जो-जो सामग्री-साधनों और फर्नीचर आदि पर खर्चा होता है संस्कृत शिक्षा पर उसके मुकाबले में ज़ीरो पर्सेंट भी खर्चा नहीं होता है।

इसलिए मेरे सुझाव यह हैं, कि उनको यदि माना जाय तो आप संस्कृत शिक्षा के लिए बड़ा हित कर सकेंगे।

पहला सुझाव यह है कि संस्कृत की जो डिपार्टमेंटल परीक्षायें होती हैं उनको हटा दिया जाय, इनको व्यापक करने के लिए युनिवर्सिटी के आधीन दे दिया जाना चाहिये। इससे बहुत हित होगा। डिपार्टमेंटल जो परिक्षाएँ ली जाती हैं वे नौकरी के भी नाकाबिल बना देती हैं।

जहाँ तक हो सके कॉलेजों में संस्कृत पढ़ाने वाले शास्त्री और आचार्य की डिग्री शुदा जो हों उन्हीं को रखा जाय, वह ज्यादा हितकर होगा। क्योंकि कोई भी आदमी एम. ए. संस्कृत पास हो परन्तु वह आचार्य और शास्त्री का मुकाबला नहीं कर सकता।

मेरा एक यह सुझाव और है कि देवस्थान में पुजारी जो हों उनके लिए संस्कृत शिक्षा अनिवार्य कर दें तो अच्छा रहेगा।

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

संस्कृत के छात्रों की जो छात्र-वृत्तियाँ बन्द कर दी गई हैं उनको फिर से चालू किया जाय।

कम्पीटीटिव एग्ज़ामिनेशन्स में संस्कृत परीक्षा पास शुदाओं को भी मान्यता दी जाय।

अन्त में संस्कृत की उन्नति के लिए जो कट मोशन प्रस्तुत किया है वह मैं पेश करता हूँ।

श्री तनसिंह—[(1) To discuss the slow progess of adult education in Rajasthan.

(2) To discuss the inadequate number of schools in Barmer District]

माननीय अध्यक्ष मैंने दो कटौती प्रस्ताव रखे हैं, एक तो है प्रौढ़ शिक्षा के विषय में और दूसरा है बाड़मेर में काफी स्कूलें न होने के विषय में। प्रौढ़ शिक्षा के विषय में मुझे निवेदन करना है कि हमारे देश में जन-तन्त्रीय शासन और जनतन्त्र को पनपाने के लिए और हमारे देश के लोगों का सामाजिक स्तर उठाने के लिए यह आवश्यक है कि हमें सब लोगों को शिक्षित करना है; और विशेष कर उन लोगों को जो आज कल हमारे देश में प्रौढ़ हैं।

मैं निवेदन करूँगा कि कुछ वर्ष पहले प्रौढ़ शिक्षा का जो आन्दोलन चला था वह बहुत ही द्रुतगति से आम लोगों को प्रौढ़ शिक्षा की ओर आकर्षित कर सका, उन लोगों ने समाज के शिक्षण का बहुत अच्छा कार्य किया। परन्तु न मालूम क्यों सरकार उस ओर ढीली नीति अपना रही है। प्रौढ़ शिक्षा की चलती हुई स्कूलें भी बन्द हो गई हैं; तो फिर नई स्कूलों के तो खुलने का प्रश्न ही नहीं रहता।

पिछली बार मैंने सदन में प्रश्न किया था कि बाढ़मेर में प्रौढ़ शिक्षा के लिए कितने रुपये इकट्ठे किये गए, तो कहा गया था कि बाढ़मेर जिले में प्रौढ़ शिक्षा के लिए डेढ़ हजार रुपये इकट्ठे किये गए थे और २५ रुपये खर्च किए गए। इस उत्तर से ही स्पष्ट हो जाता है कि प्रौढ़ शिक्षा में राजस्थान का शिक्षा विभाग कितनी तरक्की कर रहा है।

दूसरा कट मोशन मेरा बाढ़मेर डिस्ट्रिक्ट की प्राथमिक शिक्षा के विषय में है।

यहाँ की बात बाहर की बात से बिल्कुल भिन्न होती है। इसलिये यहाँ की सच्चाई बाहर की झूट हो जाती है और बाहर की सच्चाई यहाँ की झूठ हो जाती है। वह बात सरकारी प्रमाण के आधार पर है और उसी आधार पर कहूँगा कि बाढ़मेर डिस्ट्रिक्ट में ३३ स्कूलें हैं। पिछली बार २०-३-५३ को मेरे प्रश्न सं० ५७३ के उत्तर में, सम्बन्धित मन्त्री महोदय ने जो कहा था उसके आधार पर मैंने बताया था कि बाढ़मेर में ३ डिस्पेन्सरियाँ और दो मेडिकल आउट पोस्ट्स हैं। अब ६ बताई हैं वह मानना पड़ेगा।

तारीख १६-२-५३ को प्राइमरी स्कूलों की संख्या के सम्बन्ध में मेरे प्रश्न सं० १७८ के उत्तर में सम्बन्धित मन्त्री महोदय ने बताया कि बाढ़मेर डिस्ट्रिक्ट में ३३ स्कूलें हैं और ४, ४१, ३६८

[श्री तनसिंह]

की आबादी बाढ़मेर की बताई । तो इस हिसाब से १३,५०० आत्माओं के लिए एक स्कूल का औसत पड़ता है। १०,००० स्क्वायर मील का एरिया बाढ़मेर डिस्ट्रिक्ट का है तो इस हिसाब से ३०० स्क्वायर मील के एरिया में एक प्राइमरी स्कूल है बाढ़मेर डिस्ट्रिक्ट में। यह मैंने बाढ़मेर नगर के आसपास के गाँवों में खुले हुए स्कूलों को देख कर, औसत निकाल कर आपके सामने रखा है कि ३०० वर्ग मील व १३,५००० आबादी पड़ती है । इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करूँगा कि प्राइमरी स्कूल खोलते समय हमको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जिन इलाकों में बहुत दूर तक कोई स्कूल नहीं है वहाँ पर स्कूल खोले जावें । इसलिए मैं आपसे इस बात का स्पष्टिकरण चाहता हूँ कि स्कूल खोलने के आपके आधार भूत सिद्धान्त क्या हैं । कितने एरिया के पीछे, कितनी पोपुलेशन के पीछे या अन्य कोई बात हो जिसको जनता कर सकती हो और जो स्कूल खोलने की राजकीय कसौटी है, वह बताई जावे ।

इसके अलावा एडल्ट एज्युकेशन के बारे में जो बात कहनी रह गई, वह यह है कि हमारे यहाँ १०वीं कक्षा तो कोई भी व्यक्ति प्राइवेट पास कर सकता है। मगर जो एडल्ट शिक्षा प्राप्त करते हैं उनके लिये स्कूलों में एग्ज़ामिनेशन देकर सार्टिफिकेट हासिल करने का कोई तरीका कोई नहीं है। उनके लिए एक ही रास्ता है और वह यह कि वह मेट्रिक पास कर सकता है और फर्स्ट, सेकिन्ड, थर्ड या फोर्थ आदि कक्षाएँ पास नहीं कर सकता । वह पढ़-लिख कर किसी स्कूल में जाता है और कहता है कि मैंने प्राइवेट पढ़ाई की है, आप मेरी परीक्षा लेकर मुझे सर्टिफिकेट दीजिये तो स्कूल के अधिकारी कहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि प्राइवेट आदमी एग्ज़ामिनेशन दे सकता है । पिछली बार मैंने इसी प्रकार का कट मोशन पेश किया था और माननीय मन्त्री ने कहा था कि सरकार इस पर शीघ्र ही निर्णय करेगी। मगर एक वर्ष हुआ है, अभी तक वह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है । इस पर मैं इस लिए जोर दे रहा हूँ कि जब कोई व्यक्ति पटवारी के लिए जाता है और कहता है कि मैंने प्राइवेट प्रौढ़ शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन उनकी कोई मानता ही नहीं । अमीन के लिये जावें तो शिक्षा के प्रश्न पर उसको यही कहना पड़ता है कि उन्होंने घर पर पढ़ाई की है और अपना ज्ञान हासिल किया है मगर चूँकि उनके पास कोई प्रमाणपत्र नहीं, इसलिए उसको नौकरी नहीं मिल सकती है । इसलिए ऐसी सूरत में दूसरे जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए स्कूलों में इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए कि उन्हें प्रमाण-पत्र प्राप्त हो सकें, ताकि उनको आगे बढ़ने के लिए कोई कठिनाई न हो और उत्साह भी बढे । बस इतना कह कर मैं बैठ जाता हूँ ।

श्री खेतसिंह—(To discuss the inadequate schools in Tehsil Shergarh and Phalodi.) अध्यक्ष महोदय, मुझे शिक्षा विभाग के मुतल्लिक कोई खास शिकायत नहीं है लेकिन फिर भी मैंने जो कट मोशन पेश किया है उसके द्वारा माननीय मन्त्रीजी का ध्यान दो-चार मोटी-मोटी बातों पर दिलाना चाहता हूँ ।

यह मैं मानता हूँ कि गत दो वर्षों में शिक्षा विभाग ने काफी तरक्की की है तथा नयी-नयी प्राइमरी स्कूलें खोली हैं, मगर जो स्कूलें खोली गई हैं यदि वे ठीक ढङ्ग से चलती रहतीं तो मुझे

[श्री खेतसिंह]

कोई आपत्ति नहीं होती लेकिन वास्तव में यह चीज़ नहीं है। मुझे मालूम है और मैंने खास तौर से रेगिस्तानी इलाके का दौरा किया और वहाँ की स्कूलों को देखा तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि जहाँ पर स्कूलें खोली जानी चाहिये थीं वहाँ पर स्कूलें नहीं खोली गई और जहाँ पर नहीं खोली जानी चाहिये थीं वहाँ खोली गई। इसलिये उनका खुलना न खुलना बराबर है। आप स्कूलों में मास्टरों को भेजते हैं, वे शहर के रहने वाले होते हैं और वे डेज़र्ट में रहना पसन्द नहीं करते और वहाँ पर वे फिट इन (fit in) नहीं होते। यदि किसी व्यक्ति को जो बूट-सूट (boot-suit) में रहता हो उसको किसी रेगिस्तानी इलाके में भेज दिया जावे तो मैं इस बात को नहीं मानता कि वह वहाँ पर अच्छी तरह से काम कर सकता है और बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकता है।

श्री मानसिंह महार—ऑन ए पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर, आप उस इलाके को किस तरह से रिप्रेजेन्ट कर रहे हैं।

श्री खेतसिंह—मैं शहर में रहता हूँ और देहात के लोगों को रिप्रेज़ेन्ट करता हूँ।

मैं यह कह रहा था कि शहर के रहने वाले मास्टर वहाँ पर स्कूलों को न तो ठीक तरह से चला सकेंगे और न वे वहाँ पर कामयाब होंगे। क्या आप शहर वाले मास्टर से यह आशा करते हैं कि वह वहाँ जा कर गाँव वालों को समझावेगा और बच्चों को अच्छी तरह से संभालेगा और अपना काम ठीक तरह से शुरू करेगा? मैं यह नहीं मानता।

मेरा यह अनुभव है कि काफी स्कूलें हमारे उधर खोली गई हैं लेकिन वहाँ पर अध्यापक लोग न तो लड़कों को ला सके हैं और न वे खुद सुचारु रूप से काम शुरू कर सके हैं। इस सम्बन्ध में मैंने पहले भी अर्ज किया था कि जहाँ पर स्कूलें खोली गई हैं वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा तादाद में मास्टरों को भेजा जावे, वे देहाती मास्टर हों। इसके अलावा मैं एक और भी बात अर्ज करूँगा और वह यह कि वह इलाका इतना रेगिस्तानी है, जहाँ राजाओं के जमाने से लगा कर आज तक पहले कोई स्कूल नहीं खुला था। इस बात को मैं मानता हूँ कि पहले दो वर्षों में काफी स्कूल खोले गये हैं फिर भी काफी मात्रा में नहीं। मैं खास तौर से शिक्षा मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि जो जगह स्कूलें खोलने के लिये वे नियुक्त करें, वहाँ के रहने वालों से इस बात की दरियाफत करें कि यहाँ कितने गाँव हैं जो पास-पास हैं और जहाँ से लड़के पढ़ने के लिये आ सकते हैं। ऐसे कई गाँव हैं जहाँ २० गाँवों में भी एक स्कूल नहीं है। इसलिये मैं शिक्षा मन्त्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इस बात को ध्यान में रख कर वे स्कूलें खोलें। इतना कह कर मैं अपना आसन ग्रहण करता हूँ।

श्री तेजमल बापना—[To discuss the requirements of science classes in Intermediate College Bhilwara; giving of necessary aid to Panchayat schools and improving of the old school buildings in Bhilwara District] अध्यक्ष महोदय, मैंने भी अपना एक कटौती का प्रस्ताव इस विषय में प्रस्तुत किया है। सबसे पहले तो मैं शिक्षा

[श्री तेजमल बापना]

मन्त्रीजी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि जो पद्धति वे अपना रहे हैं वह सराहनीय है। जैसा कि उन्होंने गत वर्ष किया कि हर एक क्षेत्र के लिये उन्होंने वहाँ के एम. एल. ए. से दरियाफत किया इस बात के लिये कि कहाँ-कहाँ पर प्राइमरी स्कूलें खुलवाना वे चाहते हैं। उनके इस कार्य की तो मैं सराहना करता हूँ। मगर इसके साथ-साथ कुछ सुझाव जो हैं वे भी मैं प्रस्तुत करता हूँ।

सबसे पहले मेरा मतलब उन पाठशालाओं से है जो पंचायतों के आधीन खोली गई हैं। इस वर्ष अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा जिले में भी कई स्कूलें पंचायत के अन्तर्गत खोली गई हैं जो जुलाई और अगस्त से चालू हो रही हैं। जुलाई और अगस्त से वे स्कूलें चालू हुई हैं किन्तु जो एड (सहायता) शिक्षा विभाग से दी जानी चाहिये वह पंचायतों को नहीं मिल पा रही है।

पीपली ग्राम के लिए जहाँ पर अध्यापक करीब अगस्त से काम कर रहा है उसको कई महिनों की तनख्वाह नहीं मिली है। चूंकि पंचायतों के आर्थिक साधन बड़े सीमित हैं, वे पैसा नहीं चुका सकते हैं इसलिये अध्यापकों को बड़ी कठिनाई अनुभव होती है। इस सम्बन्ध में या तो जो भी एड दी जाय वह समय पर पंचायतों को दे दी जाय तभी वे अध्यापकों को बराबर पैसा दे सकती हैं; नहीं तो जो स्कूल्स खुले हैं गत वर्ष तथा इस वर्ष जो खोले जाँय वे पंचायतों के अधीन न रखे जाँय, सीधे शिक्षा विभाग के अन्तर्गत रखे जाँय। इसका बच्चों पर भी असर पड़ेगा, अध्यापकों को भी बराबर वेतन मिलता रहेगा और अध्यापक वर्ग भी अपने आपको ठीक तरीके से महसूस कर सकेंगे। क्योंकि बहुत से अध्यापक स्कूल छोड़कर चले जाते हैं इसलिये कि उनको समय पर तनख्वाह नहीं मिलती है, इसका भी उन पर बड़ा भारी असर पड़ता है। प्रारम्भिक पाठशालायें जो भी खोली जायंगी उनको जो एड दी जाय वह उचित समय में उनके पास पहुँच जाय या शिक्षा विभाग उनको अपने अन्तर्गत ले-ले। लेकिन इसके साथ-साथ मेरा मतलब है भीलवाड़ा कॉलेज में साइन्स और विज्ञान की कक्षायें प्रारम्भ करने का। मन्त्रीजी ने अभी-अभी एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि केवल आर्थिक साधनों की कमी के कारण साइन्स की क्लासेज़ नहीं खोली जा सकतीं; यह किसी प्रकार ठीक हो सकता है, किन्तु आज इस युग में विज्ञान की शिक्षा कितनी महत्त्वपूर्ण है वह आपसे या माननीय मन्त्री से किसी प्रकार छिपी हुई नहीं है। आज किसी भी जगह आर्ट्स की कक्षायें न हों तो वह बरदाश्त की जा सकती हैं लेकिन एक ओर जब बेकारी बहुत बढ़ रही है, पढ़े-लिखे लोग जो हैं वे काफी तादाद में बेकार हैं तो फिर उनको अगर विज्ञान की शिक्षा शुरू में दी जावे तो वे टेकनिकल लाइन ले सकते हैं। अगर उनको मैट्रिक या इन्टर में कोई विज्ञान की शिक्षा मिल जाती हैं तो वे इन्जीनियरिंग और मेडिकल में जा सकते हैं, बहुत से विद्यार्थी इसके अभाव में बड़ी कठिनाई का अनुभव करते हैं। बहुत से विद्यार्थी जो साधन-सम्पन्न होते हैं वे बाहर भी जा सकते हैं लेकिन गरीब विद्यार्थियों को इसके लिए काफी कठिनाई सहन करनी पड़ती है।

तीसरे कटौती प्रस्ताव का मतलब यह है कि बहुत सी जगह जहाँ पुरानी पाठशालायें चली आ रही हैं, मसलन पुर में एक पाठशाला है जहाँ करीब ४०० विद्यार्थी पढ़ते हैं, किन्तु उनके बैठने के लिए तीन कमरे ही हैं। आज की वह स्कूल मिडिल स्कूल नहीं है, उसको काफी अरसा हो चुका

[श्री तेजमल बापना]

है। एक-दो कमरों की कमी के कारण विद्यार्थियों को सर्दी व बरसात में बैठने की तकलीफ होती है। अगर सरकार उस जगह एक-दो कमरे और बनवा दें, ग्रामवासियों ने भी इस सम्बन्ध में करीब दो हजार रुपये एकत्रित कर लिये हैं; इतनी ही मदद यदि सरकार द्वारा दी जाय तो वे कमरे बन सकते हैं। वहाँ विद्यार्थियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। गत वर्ष वहाँ ३०० विद्यार्थी थे। इस वर्ष और विद्यार्थी बढ़ गये हैं। सर्दी व वर्षा में कितनी तकलीफ होती है यह तो वहाँ जाकर देखा जा सकता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस ओर प्रोवीज़न रखा जाय और जहाँ-जहाँ भवन की कमी हो पुरानी स्कूलों में वह कमी पूरी कर दी जाय। मैं शिक्षा मन्त्रीजी से साफ कहना चाहता हूँ कि जब आप प्रारम्भिक पाठशालायें खोल रहे हैं, मिडिल स्कूलें बना रहे हैं और हाई स्कूलें भी बनवा रहे हैं तो जहाँ पुरानी स्कूलें हैं, किन्तु कुछ कमी के कारण पूरी तरह से विद्यार्थियों को सहूलियतें प्राप्त नहीं हो रही हैं तो उस ओर सरकार को अवश्य गौर करना चाहिये, जब कि ग्रामवासियों ने मिलकर दो हजार रुपये एकत्रित भी कर लिये हैं तो उनको एड (aid) देना आवश्यक हो जाता है।

श्री हरिदेव जोशी—(To discuss sterio-type system of primary education and administration of the Department.) अध्यक्ष महोदय, मैंने इस शिक्षा विभाग की डिमान्ड पर एक कटौती का प्रस्ताव रखा है। उस कटौती प्रस्ताव का मकसद है मौजूदा शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करवाना और जो व्यवस्था चल रही है आज शिक्षा विभाग की, उसके बारे में शिक्षा विभाग के अधिकारियों का और माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करवाना।

माननीय अध्यक्ष, यह निर्विवाद बात है कि आज की शिक्षा प्रणाली उतने बेहतर नागरिक पैदा नहीं करती जितने बेहतर क्लर्क व अफसर पैदा करती है और इसीलिये शायद यह स्थिति पैदा हो गई है। स्कूल्स और कॉलेजों से जितने विद्यार्थी निकलते हैं वे अक्सर नौकरियों के लिए इधर-उधर भटकते हुए दिखाई देते हैं। स्थिति यह है कि नौकरियों की कमी है और पढ़ने वाले ज्यादा हैं। जो भी विद्यार्थी कॉलेजों से निकलते हैं अपने आपको असहाय सा अनुभव करते हैं।

शिक्षा विशेषज्ञों के सामने यह समस्या वर्षों से रही है, उन्होंने इसमें आमूल चूल परिवर्तन करने की ओर प्रयास भी किया है और एक नयी प्रणाली को जन्म भी दिया है जिसको हम वर्धा प्रणाली या बेसिक शिक्षा प्रणाली कहते हैं। अभी इस बेसिक शिक्षा प्रणाली के बारे में पहले कई प्रकार की सम्मतियें प्रकट की गई और कई उच्च शिक्षा विशारद इस बारे में कई प्रकार की बातें करते थे और वैसे आज भी करते हैं। पिछली मर्तबा जब सर मिर्जा इस्माइल यहाँ आये थे तो उन्होंने भी इस बेसिक-शिक्षा प्रणाली के बारे में ऐसी ही कुछ बातें कही थीं, लेकिन देश के माने हुए शिक्षा विशारदों ने इस बेसिक शिक्षा प्रणाली को मान्यता दी है। न केवल किसी एक प्रान्त में बल्कि कई प्रान्तों में इसका सफल परीक्षण हुआ है। बिहार जो हमारे प्रान्त से ज्यादा दूर नहीं उस प्रान्त में बेसिक शिक्षा प्रणाली में बहुत ज्यादा प्रगति हुई हैं, आसाम में भी इस बारे में प्रगति हुई है और अभी कुछ इससे मिलती जुलती प्रणाली का मद्रास के अन्दर भी परीक्षण किया जा रहा है क्योंकि श्री राजगोपालाचारी द्वारा

[श्री हरिदेव जोशी]

जो शिक्षा-प्रणाली वहाँ चालू की गई उसके बारे में भी कई लोगों ने कई प्रकार की रायें प्रगट की हैं। लेकिन मेरी यह मान्यता है कि यही तरीका है कम से कम आगे बढ़ने का। वे लोग जो महसूस करते हैं, परिवर्तन करते हैं हमारी शिक्षा प्रणाली में कोई न कोई ऐसा मार्ग हो जिससे फेर-बदल हो। मगर जब हम अपने प्रान्त को इस दृष्टि से देखते हैं तो हम यह महसूस करते हैं कि शायद हमें इस बारे में लम्बे दिनों के लिए इन्तजार करना होगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जितनी देर आप इस बारे में कर रहे हैं इससे उतना ही अधिक नुकसान हो रहा है। आज यह पहला ही मौका नहीं, हम कोई पहले-पहल नहीं कर रहे हैं, कई लोगों के, कई प्रान्तों के उदाहरण हमारे सामने हैं। अब अधिक से अधिक जल्दी इस विषय में ठोस कदम उठाया जाना चाहिये। कहा यह जाता है कि भारत सरकार द्वारा निर्मित कमीशन ने कुछ निर्णय कर लिये हैं, उसके अनुसार ही हम कार्यवाही करना चाहते हैं; लेकिन आप आखिर करेंगे कब? क्या तब जब कि हमारे हजारों नवयुवक कालेजों से निकल कर चले आयेंगे, जो अपने आपको इसके लिए फिज़िकली फिट नहीं कर पायेंगे; तब आपके पास इनके लिए कोई इलाज नहीं। इसलिये मेरा यह मानना है कि इस शिक्षा-प्रणाली में आज ही नहीं, अभी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अगर हम न करेंगे तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस ओर हमें जल्दी से जल्दी ऐसे प्रयत्न करने चाहिये जिससे हमारी पीढ़ी के अन्दर जो शक्ति है, जो नवयुवक वर्ग है उनको काम मिल सके, उनको रोजगार मिल सके और वे आत्म-भरित हो सकें, पेट भर सकें और राजस्थान के अन्दर जितने भी लोग-बाग हैं वे अपने इस प्रान्त को ऊँचा उठाने में मदद दे सकें। आज हालत यह है कि पढ़े-लिखे लोग बाजार से सामान नहीं लाते, वे थैला पकड़कर बाजार में जाना अपने लिए कठिन अनुभव करते हैं, वे मामूली सा बोझ उठाने में अपने आपको शर्मिन्दा अनुभव करते हैं, वे शारीरिक श्रम को करने योग्य नहीं समझते। अगर हमारी शिक्षा का माध्यम ही श्रम होगा तो ऐसी चीज नहीं रहेगी।

इसलिए आज इस सारी प्रणाली में परिवर्तन करने की नितान्त आवश्यकता है।

मैं यह जानता हूँ कि हमारे मन्त्री यह महसूस करते हैं कि इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिये, पर कुछ ऐसे कारण हैं कि हम नहीं कर पाते हैं और वह कारण है हमारी कई बार की ढिलाई और सोचने के दृष्टिकोण का अन्तर। मैं आशा करता हूँ कि वह सोचने का अन्तर अब मिटेगा और जल्दी से जल्दी हम इस बात की आवश्यकता को महसूस करेंगे।

दूसरी चीज़ जो मैं महसूस करता हूँ शिक्षा विभाग के बारे में, वह यह है कि शिक्षा विभाग पर हम जितना खर्च करते हैं उतना लाभ नहीं मिलता। इसमें कोई शक नहीं कि हम प्रतिवर्ष काफी खर्च करते जा रहे हैं इस विभाग पर, जितना लाभ इसका हमें मिलना चाहिये वह नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण यह है कि हम किसी योजना के अनुसार नहीं चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि शायद राजस्थान सरकार के पास में शिक्षा के सम्बन्ध में कोई योजना ही नहीं है। कितनी आबादी पर किन-किन गाँवों में कहाँ-कहाँ किस हिसाब से हर साल कितनी-कितनी स्कूलें सरकार खोलना चाहती है अथवा हाई स्कूल या मिडिल स्कूल खोलना चाहती है या कितने कॉलेज आदि खोलना चाहती है, इस सम्बन्धी प्रायोरिटीवाइज़ कोई योजना नहीं है। हमारे पास इसका एक पूरा-पूरा नकशा

[श्री हरिदेव जोशी]

होना चाहिये कि इस साल एक कॉलेज खोलना है तो वह कहाँ खोलना है, अगर दस हजार स्कूल खोलने हैं तो वे कहाँ किस हिसाब से खोलने हैं, अगर २५ मिडिल स्कूल खोलने हैं तो कहाँ खोलेंगे, इतनी प्राइमरी स्कूलें खोलनी हैं तो वे कहाँ खोलेंगे। इसके बगैर हम अन्धकार में भटकते हुए से मालूम होते हैं।

दूसरी चीज़, जो कमजोरी हमारी मालूम पड़ती है वह है कोर्स के बाबत में, शिक्षा सम्बन्धी केरीकुलम के बारे में। काफी लम्बे अर्से तक इन्तजार करने के बाद जुलाई, अगस्त और सितम्बर का महीना निकल जाता है तब भी कोर्स की किताबों की लिस्ट लोगों के पास नहीं पहुँच पाती कि बच्चों को कौन सी किताबें पढ़नी हैं और कौनसी किताबें खरीदनी हैं। जब ये ही नहीं पहुँचेगी खबर, तब वे पढ़ेंगे क्या और स्कूलों का रिजल्ट कैसे ठीक निकल सकेगा और दूसरी चीज़ यह होती है कि इन स्कूलों में जितना पर्याप्त स्टाफ होना चाहिये उतना पर्याप्त स्टाफ इनमेंनहीं होता। एक हाई स्कूल में एक साइन्स की क्लास शुरू कर देते हैं पर साइन्स का टीचर नहीं भेजा जाता समय तक। इसी तरह मैथेमेटिक्स के टीचर की आवश्यकता होती है पर वह भी समय पर नहीं भेजा जाता। इन सबका परिणाम यह होता है कि वे लड़के कमजोर रह जाते हैं और अन्त में परीक्षा में फेल भी हो जाते हैं और कभी-कभी तो यहाँ तक होता है कि हाफ इयरली (half yearly) परीक्षा आ जाती है पर टीचर नहीं पहुँच पाते और जब आवाज़ होती है तब जाकर एक स्कूल से अथवा दूसरी, तीसरी स्कूल से हटाकर उसे वहाँ भेजा जाता है। इससे लड़के पढ़ाई में कमजोर रह जाते हैं और तब वे अपने भाग्य को कोसते नज़र आते हैं जब वे फेल हो जाते हैं। तो बेहतर तो यह होगा कि अगर आप कहीं हाई स्कूल खोलना चाहते हैं और दस खोलना चाहते है तो आठ खोलें, लेकिन इन आठों ही स्कूलों में आवश्यक स्टाफ जल्दी भेजें, योग्य स्टाफ भेजें और उनके जरिये समुचित शिक्षा की व्यवस्था करें। इस बात की जरूरत नहीं कि जितनी माँग है उतनी हम सप्लाई कर दें, पर जरूरत इस बात की है कि जो वास्तव में जितनी शिक्षा दी जानी चाहिये उतनी अवश्य दी जाय। इसलिए आज इस बात की आवश्यकता है कि अप्रेल में अथवा मई में जब कि स्कूलें बन्द होने को होती हैं तभी हम यह तय कर लें कि अगले वर्ष के लिए कोर्स क्या होगा, क्या किताबें पढ़ाई जावेंगी? इसका एलान हो जाना चाहिए, लड़कों को सूचना हो जानी चाहिये कि इतनी पुस्तकें खरीदनी हैं।

दूसरी चीज़ स्टॉफ के बारे में भी तय हो जानी चाहिये कि कौन-कौन कहाँ-कहाँ जावेगा और यह एप्रिल तक अनाउन्स हो जाना चाहिये ताकि वे अपने-अपने बच्चों और परिवार को वहाँ ले जाने की व्यवस्था कर लें। वर्ना कई बार ऐसा होता है कि एक अध्यापक का तबादला अगस्त में एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है पर बरसात के कारण न तो वे स्वयं वहाँ जा पाते हैं और न अपने परिवार वालों और बाल-बच्चों को ले जा सकता है। वह बड़ी परेशानी महसूस करता है और इस कारण उसका दिल अपने काम में नहीं लगता है।

दूसरी चीज, जो कमजोरी मुझे दिखाई देती है वह यह है कि प्रोपर सुपरविजन (proper supervision) भी नहीं है हमारी स्कूलों का। कई बार ऐसा होता है कि कोई अधिकारी किसी जगह

[श्री हरिदेव जोशी]

जाता है मगर वह ऊपर ही ऊपर की चीजों को देख कर लौट आता है, कई बार साधारण सी चर्चा के बाद लौट आते है। देखने की चीज यह है कि जो केरिकुलम उन्होंने बनाया है उसके अनुसार उस स्कूल में पढ़ाई होती है या नहीं, देखनी की जरूरत यह है अधिकारियों के लिए कि वहाँ पर पर्याप्त स्टाफ है या नहीं और उच्चाधिकारियों के देखने की जरूरत यह है कि इन्सपेक्टर, सब इन्सपेक्टर आदि अपने अपने हल्कों में बराबर दौरा करते हैं या नहीं या वे जो अपनी रिपोर्ट की डाइरियाँ भेजते हैं वे सही भेजते हैं या गलत भेजते हैं।

कई बार ऐसा सुनने में आता है कि गाँव का अध्यापक शुक्रवार के दिन अपने स्कूल से छुट्टी पर चला जाता है और जाते समय एक दरख्वास्त स्कूल का जो मॉनीटर होता है उसको दे जाता हैं कि कभी कोई इन्सपेक्टर आदि आ जावे तो उसको बतादे कि मास्टर साहब अमुक गाँव अमुक काम से गये हुये हैं और यह दरख्वास्त रखकर चले गये हैं। वे शनिवार को एबसेन्ट रहते हैं, रविवार की छुट्टी होती ही है और सोमवार को भी एक दो या तीन बजे तक लोटते हैं और इसके बाद अगर एक-दो दिन छोड़कर एक दो या तीन बाद में छुट्टियाँ आती हों तो बीच के एक दो दिन की छुट्टियाँ और ले लेता है और इस प्रकार इन दो छुट्टियों को चाहे राजस्थान सरकार छुट्टी करार दे या नहीं वे मास्टर साहब तो अपने लिए छुट्टी मना ही लेते हैं। तो इस प्रकार की जो बुराइयाँ हैं उनको दूर करने की आवश्यकता है। कई बार ऐसा होता है कि कई अध्यापकों को, जिनको कि हम नियुक्त करते हैं उनके अन्दर इतनी काबलियत नहीं होती जितनी होनी चाहिए और वे अपने अन्दर एक प्रकार की इस कारण इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्शन (inferiority complexion) अनुभव करते हैं। वे विद्यार्थियों को फेस नहीं कर पाते हैं। कई बार गलत मायने, गलत अर्थ और गलत बातें बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चा आकर अपने-अपने माँ-बाप से, अगर वे पढ़े लिखे हैं तो कहता है कि इस तरह से हमें गलत बात पढ़ाई जाती है और वे बच्चे तब उस मास्टर का मज़ाक उड़ाते हैं। अभी का एक किस्सा है। डूँगरपुर में एक कन्या पाठशाला है, उसमें मेरे एक मित्र की कन्या पढ़ती है। उसको कुछ शब्दार्थ लिखाये गये थे। वह मेरे पास आ गई। मैंने पूछा क्या पढ़ती हो ? तो उसने अपने शब्दार्थों की कॉपी बताई। तो मैंने देखा कि उसके अन्दर २५ प्रतिशत शब्दार्थ गलत थे। जब मैंने उससे यह बात कही तो वह कहने लगी कि मुझको तो हमारी बहनजी यही पढ़ाती हैं। मैंने दुरुस्ती करदी तो वह दूसरे दिन जब स्कूल गई तो यह सब अपनी बहनजी को बताया, तो वह सकपकाई। तो हम सोच सकते हैं कि उन मास्टरनीजी साहिबा की प्रतिष्ठा उन बालिकाओं के दिमाग में क्या रह सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम अच्छे पढ़े-लिखे लोगों को इस काम के लिए चुनें। साथ ही उनको अच्छे स्थान पर रक्खें, उनकी सुख-सविधाओं का भी पूरा-पूरा ध्यान रक्खें, ताकि वे मन पूरी तरह से अपने काम में लगा सकें। कई बार ऐसा भी होता है कि अमुक आदमी का, जो बीकानेर का है हम डूँगरपुर या बांसवाड़ा में तबादला कर देते है। परिणाम यह होता है कि तनख्वाह इतनी नहीं मिलने से वह अपने बाल-बच्चों को वहाँ लेजाकर रख नहीं सकता, वहाँ के खर्चे को बर्दाश्त नहीं कर सकता और वर्ष भर या जब तक कि उसका कहीं आस-पास में ही उसके निवासस्थान के समीप तबादला न हो जाय तब तक यही सोचता रहता है कि मेरे तो बाल-बच्चे वहाँ पर हैं और मैं इतना दूर हूँ, जब कभी क्लास में पढ़ाने भी जावेगा तब भी यह

[श्री हरिदेव जोशी]

सोचेगा कि मैं क्या करूँ मेरा तो बच्चा बीमार है, चाचा-ताऊ बीमार है, वहाँ कैसे जाऊँ, क्या करूँ आदि। तो जरूरत इस बात की है कि हम उनकी तकलीफों को भी देखें, उनकी सुख-सुविधाओं का भी ख्याल रक्खें और इसके अनुसार कुछ ऐसा रास्ता बिठाएँ कि जिससे वे निश्चिन्त होकर बच्चों को शिक्षा दान दे सकें। ये ही बच्चे हमारी भावी होनहार पीढ़ी हैं, उन्हीं पर इस देश का भविष्य निर्भर है। उनके लिए कुछ हम ऐसी सूरत पैदा करें कि हम उनको ऊँचे उठा सकें। हम ऐसा कुछ महसूस करने लगें कि हाँ, हमारी इस व्यवस्था से ये शिक्षक भी कुछ ऊँचे उठ रहे हैं और देश के ये भावी भाग्य-विधाता भी ऊँचे उठ रहे हैं। हमारे देश के ये कर्णाधार हैं, उनसे हमें कई आशाएँ हैं। मगर देखना हमें यह है कि हमारी आशाएँ कितनी और किस हद तक सफल होती हैं।

मैं अपने पहले बोलने वाले मित्रों से सहमत हूँ कि राजस्थान सरकार ने इस वर्ष के बजट में और पिछले वर्ष के बजट में भी इसके लिए काफी पैसा रक्खा है, मगर उसका सदुपयोग होना चाहिये। पिछले दिनों प्रौढ़ शिक्षण के लिए और समाज शिक्षण के लिए राजस्थान सरकार ने रकम रक्खी मगर उसका उपयोग किया नहीं और इसका लाभ जितना जनता को मिलना चाहिये था वह नहीं मिला। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें ऐसे प्रयत्न करने चाहिये कि सदुपयोग हो सके, हमारे इस पैसे का। यही मुझे कहना है।

(समय समाप्त सूचक घण्टी)

अब टाइम भी हो गया।

श्री अध्यक्ष—There are some 22 cut-motions which have been received but they are time-barred. I accord my sanction to them to be moved. Out of these 6 are to be moved by Shri H K. Vyas. I read all of them so that the Members may know.

एक माननीय सदस्य—(७ बजने पर) टाइम हो गया है, साहब।

श्री गोपीलाल यादव—७ बजे तक का ही समय है।

एक अन्य माननीय सदस्य—आज समय ७ तक का ही निश्चित हुआ था।

श्री अध्यक्ष—4 to 8, I decided.

श्री श्रीदास गोयल—हाउस की पोपुलेशन बड़ी थिन है।

श्री अध्यक्ष—Wait up to 7-30. Let him have his (Shri Vyas's) say.

The first cut-motion is "that the Demand for Grant No. XVI, Major Head 37— Education be reduced by Rs. 1000/— (to discuss the high expenditure on travelling allowance).

[श्री अध्यक्ष]

II. That the Demand for Education be reduced by Rs. 1000/— (to discuss the inadequate pay of teachers).

III. That Demand for Education be reduced by Rs. 1000/— (to discuss the failure on the part of the Government to check the activities of the missionary institutions).

IV. That the Demand for Education be reduced by Rs 1000/— (to discuss the failure on the part of the Government to reduce fees of the private institutions to the level of public institutions in Jodhpur).

V. That the Demand for Education be reduced by Rs. 1000/— (to discuss the low level of educational facilities in Rajasthan).

VI That the Demand for Education be reduced by Rs 1000— (to discuss the irregularities in respect of the appointment of staff)."

श्री हरिकृष्ण व्यास—टाइम तो नहीं रहा है।

श्री अध्यक्ष—You go no.

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, कुछ समय पहले मेरे एक मित्र ने शिक्षा मन्त्रीजी को बताया, उनको बधाई दी कि उन्होंने विभिन्न लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों से सलाह माँग कर स्कूलें खोलने की पद्धति अपनाई है। मुझे अफसोस है कि इस बधाई के कट मोशन पर मैं उनका साथ नहीं दे सकता इसलिए कि यदि जो सर्क्युलर शाया हुआ है उसके नीचे प्रतिलिपि सूचनार्थ वाले अंग को वह पढ़ लेते तो मालूम होता उन्हें कि उसमें जितने एम० एल० ए० हैं उनके अलावा एक शब्द और है और वह है, "सेक्रेटरी समस्त जिला कॉंग्रेस कमेटी।" तो मुझे यह समझ में नहीं आया कि शिक्षा मन्त्रीजी एम० एल० एज़० को एप्रोच करें तो अच्छी बात है; ठीक है, एक तरीका है। जन-संस्थाओं को यदि वे एप्रोच करें तो क्या शिक्षा में दिलचस्पी रखने वाले कॉंग्रेस के सिवाय और कोई दूसरी संस्था राजस्थान में हो ही नहीं सकती या उनकी नज़र में नहीं आई है। साफ बात है कि यह सर्क्युलर बधाई का पात्र बनने के बजाय शिक्षा जैसे मामले में पार्टी बन्दी, दलबन्दी की शुरूआत करने की बात है। यह एक खतरनाक क़दम है, इसलिए मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि मैं इस धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता हूँ।

परसों मेरे एक मन्त्री महोदय कल्पना की उड़ान में विदेशों की यात्रा करते हुए बहक गये थे और ऐसी कुछ उन्होंने राय यहाँ व्यक्त की थी या जो सदन में किसी प्रकार व्यक्त हुई है कि हम एक सही किस्म का प्रजातन्त्रात्मक राष्ट्र बना रहे हैं। वह किस तरह से हो रहा है कि जो पढ़ने वाले नव-शिशु हैं, जो कल जाकर इस राष्ट्र के कर्ता-धर्ता बनेंगे, उनको सही किस्म की ट्रेनिंग देते हैं,

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

उसकी व्यवस्था करते हैं, माननीय अध्यक्ष, उसके लिए मैं एक छोटा सा पेम्फलेट और उसके कुछ कोटेशन्स सदन के सामने प्रस्तुत करूँगा और यह सब हो रहा है अपने जयपुर शहर में ही एक एजुकेशनल इन्स्टीट्यूशन में। यह मैं आपको बताऊँगा। उस पेम्फलेट का शीर्षक है, "Backa winner"; घुड़दौड़ वाले घोड़े की लाटरी का ऐसा लगता है। उसका हिन्दी में तात्पर्य यह है और उस पेम्फलेट के आखरी पेज में लिखा हुआ है कि—

"Every one of us is aware of the world-wide struggle between communism and the free world. George Fathers, Mothers etc. offer you a very real opportunity to take part in the struggle with them. Ask for your part to build the St. Xavier's School in Jaipur, India."

यह पेम्फलेट सेन्ट जैवियर स्कूल, जयपुर, में इन्डिया के निस्बत किसी इन्स्टीट्यूशन द्वारा शाया हुआ मालुम होता है, जिसमें यह लिखा है कि दुनिया के कॉम्युनिज्म के खिलाफ जंग और लड़ाई में मदद करने के लिए इस स्कूल के निर्माण में मदद कीजिये और यह केवल यह हैडिंग ही हो ऐसी बात नहीं है। उसके कन्टेन्ट्स में लिखा हुआ है :—

"This School St. Xaviers is right in the front of defence against communism."

यह इस शहर में हो रहा है, इस जयपुर में हो रहा है। और नव-शिशुओं का बहुत ही सही किस्म का दिमाग बनाने का प्रयत्न शिक्षा विभाग द्वारा लगातार करने का दावा करने वाले मन्त्री महोदय से मैं पूछना चाहूँगा कि दिये तले अन्धेरा कैसे ? यह मिशनरी एक विदेशी हुकूमत के इशारे पर चलने वाले, यह मिशनरी साम्राज्यवाद के टुक्कड़खोर, यह मिशनरी न सिर्फ यहाँ आकर ज़हर फैलाये हमारे देश में, लेकिन छाती ठोक-ठोक कर पर्चे निकाले और कहे कि हमने स्कूल खोला है इसलिए कि दुनियाँ के अन्दर कॉम्युनिज्म के खिलाफ लड़ाई करें। उनके लिए तो कोई शर्म की बात नहीं है। वह तो टुक्कड़खोर हैं, इस बात के लिए, लेकिन दूसरी ओर शिक्षा विभाग के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि क्या जवाब है उनके पास इसका, क्या किया है उन्होंने कि इस तरह का ज़हर हमारी इस धरती की छाती पर नहीं जमे, उसको रोकने के लिए। इस इन्स्टीट्युशन में रेशियल डिस्क्रीमिनेशन (racial discrimination) वर्ता जाता है, एक विदेशी राष्ट्र के आधार पर डिस्क्रीमिनेशन वर्ता जाता है, वहाँ कॉम्युनल फीलिंग (communal feeling) बरता जाता है। तो अगर यह चीज़ अपने इस जयपुर शहर के अन्दर मन्त्री-मंडल के नीचे हो रही है तो कम से कम वे इसका जवाब दें और उनको जवाब देना चाहिए। इसी आशय से मैंने यह कटौती का प्रस्ताव रखा है।

दूसरा, जिस बात का जिक्र करना चाहूँगा उसका सम्बन्ध है खर्चे की मद से और वह है मैथड्स ऑफ टी० ए० (methods of T. A.). इसकी तफसील तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही हकीकत का जिक्र करके कि इस मद में होने वाले व्यय के ऊपर कोई नियन्त्रण नहीं है,

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इसका सबूत पेश करूँगा। एक शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी थे जो इस किस्म के दौरे किया करते थे और आज भी कुछ-कुछ उनके छोटे काबिल शिष्य हैं, इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ। वह इस किस्म से दौरा किया करते थे कि आज शाम को जयपुर से बीकानेर गये, दूसरे दिन बीकानेर से जोधपुर, तीसरे दिन वापिस जयपुर तो चौथे दिन फिर बीकानेर। यानी आप यह समझ लीजिये की कभी-कभी तो वह यहाँ से एक स्थान पर जाते थे, एक दिन इन्स्पेक्शन करते थे, रात वहाँ रहते थे, दूसरे दिन वापिस यहाँ आते थे और फिर तीसरे दिन वहाँ ही पहुँच जाते थे। कहीं एडवान्स टूर प्रोग्राम पेश किया था नहीं, इसकी जानकारी अभी तक हम लोगों के सामने नहीं आई, लेकिन यह जो चीज़ है यह चीज़ कुछ हद तक घर कर गई है, इस विभाग में। इसलिए यह कटौती का प्रस्ताव मैंने इस आशय से रखा है कि ट्रेवलिंग के सिलसिले में जो बहुत ज्यादा और फिजूल खर्च होता है इसमें कमी की जाय और कमी इस ढंग से की जाय कि जो टूर करने वाले होते हैं वे इसकी आगामी सूचना अपने उच्चाधिकारी को दें। इस प्रथा को चालू कीजिये ताकि पता चले कि वह टूर यथार्थ में सरकारी काम-काज के सिलसिले में है या सरकार के पैसे का बगैर ध्यान किये किया गया है।

चौथा मेरा कटौती प्रस्ताव, माननीय अध्यक्ष, टैक्स्ट बुक्स के सिलसिले में सरकारी नीति से ताल्लुक रखने वाला है और यह कायदा कोई नया शुरू नहीं हुआ, २ साल पहले जो शिक्षा मंत्रीजी थे उस जमाने में यह शुरू हुआ समझ लीजिये, और छठी और सातवीं क्लास की टैक्स्ट बुक्स, एक साल का अरसा भी नहीं हुआ कि इस बीच में बदल दी गई। उसके बाद कुछ और परिवर्तन किया गया और तब जाकर टैक्स्ट बुक्स कमेटी की योजना बनाई गई। उस कमेटी की योजना में भी परिवर्तन होते-होते उसको पर्फेक्ट किया गया, इस आधार पर कि पब्लिश करने वाले लोगों का नाम भी किसी को पता नहीं चलेगा, लिखने वाले लेखक के नाम का भी किसी को पता नहीं चलेगा और जाँच करने वाले अध्यापक के नाम का भी किसी को पता नहीं चलेगा और उन अध्यापकों के के ऊपर जो अधिकारी होते थे उनको भी किसी के नाम का पता नहीं चलेगा। इस तरह से इन्तजाम हो गया जिसमें कहीं इसमें गड़बड़ घोटाले की गुँजाइश नहीं। यह तो कहना पड़ेगा कि स्कीम बड़ी इन्जीनियस थी और यदि पार लग जाती तो वाकई भ्रष्टाचार न हो सके, ऐसी गुंजायश इसमें जरूर थी। लेकिन वह इतनी बुरी कामयाब हुई और इतनी जरूरत से ज्यादा पार लगी कि पहले ही सबको मालूम हो गया केवल मालूम ही नहीं हुई, बल्कि एक मुलाजिम शिक्षा विभाग का तो इसमें पकड़ा भी गया और उसका मामला जेर तजवीज है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कितनी सीक्रेसी रखी गई और जब फौज दिख गई तो घबराने लगे कि हमारा क्या हो जायगा। तो एक जासूस पकड़ा गया लेकिन उसके द्वारा पूरा पता नहीं चला कि फौज का कमाण्डर कौन है। इसका क्या सुबूत है कि जब एक जासूस पकड़ा गया है तो सारा मामला लोगों को मालूम नहीं हो गया और उसको डीनोवे स्टार्ट करने की हालत हो गई। टेक्टस्ट बुक्स के कारण आज विद्यार्थियों को बड़ी भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। छोटी-छोटी क्लासेज़ में ८, १० और १५ तक टेक्स्ट बुक्स हैं। किसी ने कुछ लालच दे दिया तो उसकी किताब मन्जूर करली गई, किसी बुकसेलर ने ५ हजार रुपये दे दिये तो उसकी भी किताब रखली गई और इस तरह से किताबों की तादाद बढ़ गई और अब उसके लिए कमेटी ने काम करते करते २ साल बिता दिये लेकिन कोई चीज़

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

फाइनेलाइज़ नहीं हो सकी। इस बारे में मैं ज्यादा क्या कहूँ, वे खुद समझ लें। मैं इस बारे में और कुछ शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मेरा यह एक कटौती प्रस्ताव था टेक्स्ट बुक्स के बारे में।

मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव है शिक्षकों की तनख्वाह के बारे में। यह आम तौर से सारे राजस्थान की समस्या है, लेकिन इससे भी ज्यादा गम्भीर चीज है उन स्कूलों के निस्बत और उनके अन्दर भी खासकर के बीकानेर रियासत की उन स्कूलों के बारे में जिनको कम्पलसरी स्कूल्स कहते हैं। इन स्कूलों के दो तिहाई खर्चे की जिम्मेदार हमारी सरकार है और ⅓ खर्च स्थानीय शिक्षण संस्थाएँ देती हैं। उनका बिल पहले स्थानीय संस्थाएँ पास करती हैं और बाद में वह इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल के पास भेजा जाता है और फिर डाइरेक्टर के पास जाता है और उसमें इतना समय लगता है कि कुछ कहने की बात नहीं है। राजगढ़ स्कूल के शिक्षकों का एक डेपुटेशन शिक्षा मंत्रीजी के पास आया। उसने बताया कि सन् ५२ से लगाकर आज तक १८ महीनों का बिल पास नहीं हुआ और उनकी तनख्वाह पास नहीं हुई है। ६, ६ महीनों तक उनको तनख्वाह नहीं मिली है, यह केवल कम्पलसरी स्कूलों के शिक्षकों का हाल है और जहाँ की ज्यादा जिम्मेदारी सरकार पर इसलिये है कि ⅔ खर्चा उसको देना पड़ता है। शिक्षकों की ओर देखें तो किसी को उनकी हालत से सन्तोष नहीं हो सकता। २५), ३०) रुपये का वेतन और १५), २०) रुपये माहवार की मंहगाई भत्ता आप उस मनुष्य को देते हैं जो भविष्य के नागरिकों का निर्माण करते हैं। हमारे पड़ोसी अजमेर में शिक्षकों को शुरूआत में १३०) रु० दिये जाते हैं, दिल्ली जैसे छोटे से राज्य में शिक्षकों की शुरूआत १३०) रु० से की जाती है, लेकिन इस राजस्थान के सेक्रेटेरियट और दूसरे विभागों में अच्छी आला तनख्वाह पाने वाले अफसर रखे जांय और मास्टरों को भर पेट रोटी भी नहीं दी जाती। यह आवश्यक है कि उनको भर पेट रोटी दी जाय और ऐसे शिक्षक रखे जायं जो हमारे बच्चों का भविष्य निर्माण करने वाले हों। उनको २५), ३०) रुपये देना न केवल अन्यायपूर्ण ही है बल्कि शिक्षा के साथ खिलवाड़ करना भी है, इसलिये मैंने एक कटोती प्रस्ताव शिक्षकों के लिये रखा है। उनको न केवल तनख्वाह ही कम दी जाती हैं बल्कि ८-१० साल से जिन्होंने मेट्रिक ग्रेड में बिता दिये, उनको महनत करके बी. ए., इन्टर या एम. ए. पास करने के बाद भी आगे का ग्रेड नहीं दिया जाता है और नये-नये लोग जिनका वसीला है, वे ऊँचे ग्रेड में शुरू में ही भरती किये जाते है। जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सालों बिता दिये हैं उनको उनकी काबलियत के मुताबिक भी ग्रेड नहीं दिया जाता है। जो मनुष्य शिक्षा में ईमानदारी से दिलचस्पी रखने वाला है, उस शिक्षक में असन्तोष रहे तो भविष्य की पीढ़ी पर, जैसा कि कुँवर जसवन्तसिंहजी डिसिप्लिन के निस्बत अक्सर कहा करते हैं, डिसिप्लिन नाम मात्र का नहीं रह जायगा। इससे न शिक्षकों की हालत सुधरेगी और न शिक्षा के क्षेत्र में ही प्रगति होगी।

इसके अलावा मुझे विद्यार्थियों की फीस के बारे में भी दो शब्द कहने हैं। दो-तीन साल से यह फीस का प्रश्न राजस्थान में चल रहा है। मुझे मालूम है कि शिक्षा मन्त्रीजी खड़े होकर उत्तर देंगे कि हमने कोई फीस नहीं बढ़ाई है और न ऐसा ऐलान ही किया है किन्तु यह जानते हुए कि

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इस प्रकार का उत्तर होगा, मैं क्लेरिफिकेशन पहले से ही कर दूँ कि आपने सीधी तौर से फीस नहीं बढ़ाई है, लेकिन आपने गेम्स फीस, एग्जामिनेशन फीस, कोमन रूम फीस, लाइब्रेरी फीस आदि इस प्रकार की ११ फीसें हैं जिनमें किसी में २) रु०, किसी में १) रु० या किसी में ३) रु० बढ़ा दिये हैं। इसके साथ ही एक चीज और है वह यह है कि फीस कम करने के सिलसिले में आपने वादा किया था। उन्होंने उसको भुलाने का फैसला कर दिया, मालूम होता है। इस समय के मुख्य मन्त्री महोदय उस समय मुख्य मन्त्री नहीं थे, वे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। सन् ५० में जोधपुर में फीस के सिलसिले में विद्यार्थियों की एक हड़ताल हुई थी तब उन्होंने लिखित आश्वासन दिया था कि मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ कि जल्दी से जल्दी प्राइवेट स्कूलों की फीस सरकारी स्कूलों के बराबर करदी जायगी, सन् ५१ में आप मुख्य मन्त्री बने और उनके साथ आने वाले एक साथी शिक्षा मन्त्री बने, लेकिन वह वादा अब तक पूरा नहीं हुआ और प्राइवेट स्कूलों में सरकारी स्कूलों से अधिक फीस ली जा रही है और शिक्षा को मंहगा किया जा रहा है।

(समय–समाप्ति–सूचक घन्टी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—Half a minute more, Sir.

श्री श्रीदास गोयल—It is already 7.30.

श्री अध्यक्ष—Shall we sit for half an hour more ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—(जारी) और इस शिक्षा के अन्दर जो आम नागरिकों के ऊपर और विद्यार्थियों के ऊपर बोझा लाद-लाद कर शिक्षा को मँहगी करने का, कि कहीं आगे जाकर ये शिक्षित बेरोजगार सरकार के आगे नई नई मांगें न पेश करें, रोजगार के लिये मांगे पेश न करें, इसलिये शिक्षण संस्थाओं को प्रोत्साहन न देने का, जो तरीका सरकार ने अख्त्यार किया है उस तरीके को बदलना चाहिये। इसलिये मैंने यह कट मोशन प्रस्तुत किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कट मोशन को प्रस्तुत करता हूँ।

श्री किस्तूरचन्द—अध्यक्ष महोदय, मैं भी भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो स्कूलों की हालत है उसके सम्बन्ध में बोलने के लिये इस कट मोशन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से पेश करता हूँ कि भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में बनेड़ा हाई स्कूल के लिये वहाँ की जनता ने २५०००) रुपये लगा कर इमारत तैयार करवाया है, उसमें कुछ अधूरापन रहा, उसको पूरा करवाने के लिये कोशिश करते हुए माननीय शिक्षा मन्त्रीजी से प्रस्ताव करके, अनुरोध करके ले जाया गया और आपको इस इमारत को दिखाया गया। शिक्षा मन्त्रीजी ने वास्तव में उस कमी को महसूस किया और शीघ्रता से उसे पूरा करवाने के लिये आश्वासन दिया, परन्तु इसके लिये कोई ज़रिया मालूम नहीं हो रहा है। ऐसा सुनने में आया था कि इसके लिये

[श्री किस्तूरचन्द]

५३-५४ के बजट में ५०००) रुपया मन्जूर किया है पर ५३-५४ का बजट गया और अब ५४-५५ का बजट भी जाने वाला है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सरकार के मन्त्री महोदय को अर्ज करना चाहता हूँ कि इस इमारत को पूरा करवाया जाय।

शाहपुरा, जो कि राजस्थान बनने से पहले अच्छी स्टेट थी वहाँ की जनता ने, वहाँ के राजाधिराज ने, सब ने मिल कर एक इमारत इन्टरमीजियेट कॉलेज के लिये बनाना तय किया और वह बना भी दी गई और ५०,०००) रुपया नकद और भी देने को तैयार हैं, और मैं आपके जरिये अर्ज करना चाहता हूँ कि शिक्षा मन्त्रीजी जरा इस बात पर ध्यान देकर वहाँ एग्रीकल्चर इन्टर कॉलेज खोलने का काम पूरा कराने की कृपा करें तो अच्छा है। शाहपुरा जो एक स्टेट थी उसकी अहमियत बनाये रखने के लिये इस माँग पर ध्यान दें।

रावत श्री शम्भुसिंह—अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा के सम्बन्ध का कटौती प्रस्ताव श्री तेजमल बापना ने पेश किया उसके सम्बन्ध में मैं भी दो शब्द अर्ज करना चाहता हूँ। बापना साहब ने पुरानी स्कूलों के इम्प्रूवमेंट के बारे में जो कटौती प्रस्ताव रखा, उसके बारे में मेरा कथन इस प्रकार है कि भीलवाड़ा जिले की सराड़ा तहसील में सरकारी स्कूलों की इमारतें हैं, उनमें एक मिडिल स्कूल गंगापुर में और दूसरी पोटला गाँव में है। इन स्कूलों की इमारत की मरम्मत जब मेवाड़ स्टेट थी और गंगापुर में ग्वालियर स्टेट थी तब हुई थी। विद्यार्थियों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। इस सम्बन्ध में काफी शिकायतें हुई, परन्तु आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है।

पोटला स्कूल की इमारत की यह हालत है कि वहाँ की स्कूल का बरामदा बिल्कुल गिर चुका है और इसके अभाव में विद्यार्थियों को धूप, सर्दी और बरसात में यों ही बैठना पड़ता है। कमरे नाकाफी हैं, जिससे वे लोग बरामदे में बैठते थे पर अब वह भी मरम्मत न होने के कारण गिर चुका है। इसलिये वहाँ लड़कों को बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है।

गंगापुर में मिडिल स्कूल है, वहाँ विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गई हैं और स्कूल के मकान में एक्सटेन्शन नहीं होने से धर्मशाला में क्लासें लगाई जाती हैं और वहाँ पढ़ने में लड़कों को जो कष्ट होता है वह एक कल्पना का विषय है। इस तरह मेवाड़ स्टेट के समय में जो दो-चार स्कूलें बनीं थीं वे भी मरम्मत की मोहताज हैं, और अब तो सरकार ने एक नीति अपना ली है कि मेवाड़ में स्कूलें बनवानी हों तो पहले गाँव वाले इमारतें बनवा लें, फिर स्कूलें बनेंगी।

मेरा यह निवेदन है कि जहाँ मेवाड़ गवर्नमेंट की बनाई हुई जो स्कूलें हैं वहाँ तो मरम्मत करवाई जावे।

श्री अध्यक्ष—(श्री भैरूँसिंह खाचरियावास को संकेत करके) If you want to speak on these cut-motions I will give you enough time up to 8.

Page No.149

श्री भैरूँसिंह (दाता रामगढ़)—अध्यक्ष महोदय, कल के लिये रखा जाय। कल ७ बजे के लिये लालसिंहजी साहब ने फरमाया था। आपने इसे बढ़ा कर साढ़े सात बजे तक कर दिया। अब कल के लिये रखा जाय।

श्री अध्यक्ष—Tomorrow you will have time cut.

श्री भैरूँसिंह—आज से मुझे कल आधा समय ही दे दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष—No. I wanted to accommodate you.

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, मुझे अब १५ मिनट तो मिलेंगे।

श्री भैरूँसिंह—हाउस तो अब एक मिनट के लिये भी सुनना नहीं चाहता।

श्री अध्यक्ष—As the House likes.

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, शिक्षा विभाग के बारे में बहुत सी बातें कहीं गई हैं। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूँगा, फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनके कहने से उनमें शायद थोड़ा-बहुत सुधार हो सकेगा। ऐसी उम्मीद करके मैं दो-चार पोइन्ट्स हमारे मन्त्री महोदय के सामने रखूँगा। पहली चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि जिस प्रकार मेरे साम्यवादी मित्र ने फरमाया था कि हमारे शिक्षा मन्त्रीजी ने जो पत्र लिखा था कि एम. एल. एज़. अपने विचार प्रकट करें वह एक ढकोसला-मात्र था इसलिए इसके बारे में कहना कि शिक्षा मन्त्री जी धन्यवाद के पात्र हैं, यह सरासर गलत है।

दूसरी बात मैं यह कहूँगा कि मेरे साम्यवादी मित्र ने सेंट जेवियर स्कूल के खिलाफ कुछ बातें कही हैं। उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि एक तरफ तो हमारे दोस्त यह चाहते हैं कि स्कूलों के अन्दर अनुशासन हो, हम इन्डिसिप्लिन को खत्म करें और दूसरी ओर ऐसी स्कूलों पर छींटा-कशी करते हैं जिनमें वाकई अनुशासन हैं, जिनमें बच्चे पढ़ते हैं तो जानते हैं कि अपने से बड़ों से किस प्रकार का व्यवहार किया जाय। अगर उन स्कूलों के बारे में छींटा-कशी की जाती है तो यह सरासर उस स्कूल के साथ और सरकार के साथ अन्याय होगा।

जो सरकार सेंट जेवियर जैसी स्कूलों को प्रोत्साहन देती है वह बधाई की पात्र है। सेन्ट जेवियर स्कूल एक ऐसी स्कूल है जिसके अन्दर बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है। हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ने के लिए जाते थे उस कमी को पूरी करके जयपुर की जयपुर में ऐसी शिक्षा संस्था खुली है जो इसकी पूर्ति करती है। यह कह कर मैं सेन्ट जेवियर स्कूल के खिलाफ कोई आक्षेप नहीं करते हुए, यही अर्ज करूँगा कि यह आलीशान बिल्डिंग बनी है, उसमें स्कूल बनी हुई है, जिसमें पढ़ाई का पूरा इन्तजाम हो जावेगा और वह एक ऐसी चीज़ होगी जो जयपुर है अच्छी चीजों में एक मानी जावेगी। मैं कोम्युनिजम का विरोध करता हूँ। मैं सही कहता हूँ कि जहाँ स्कूलों और कॉलेजेज़ में आजकल इन्डिसिप्लिन होता है उसमें सबसे बड़ा हाथ इन साम्यवादियों का होता है।

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—कोई सुनने वाला ही नहीं है।

श्री मानसिंह महार—आप सुन लीजिये।

अगर इसी प्रकार की शिक्षा स्कूलों में दी जावेगी तो वह हानिकारक (अकल्याणकारी) होगी और जैसा कि हमारे लीडर ऑफ दी ऑपोजीशन ने बीकानेर में हैडमास्टर और लड़कों के बारे में कहा था कि ब्लेडर फटने लगा। अगर आप अपने शिक्षकों को अच्छी शिक्षा की बात कहेंगे तो यह नौबत नहीं अवेगी।

दूसरी बात अब मैं अर्ज करना चाहता है मेरी कॉस्टीट्युएन्सी के बारे में। माननीय अध्यक्ष, दुर्भाग्यवश मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी जयपुर की तलहटी में होते हुए और अच्छे-अच्छे कस्बे भी वहाँ होते हुए, क्योंकि मेरी मन्त्रियों तक पहुँच नहीं है इसलिए मेरी पूरी कॉन्स्टीट्युएन्सी में एक भी हाई स्कूल नहीं है। यह कहा जाता है कि शिक्षा में यह उन्नति की जा रही है, यह हो रहा है, वह हो रहा है; लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अचरोल, भांडारेज, मांडल आदि अच्छे-अच्छे कस्बे होते हुए भी वहाँ पर आज कोई हाई स्कूल नहीं। यह कोई सरकार के लिए शोभा की बात नहीं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करूँगा कि अगली जुलाई से शुरू होने वाले सेशन से पहले, उम्मीद तो दो हाई स्कूलों की करता हूँ लेकिन अगर सरकार के पास पैसों की कमी हो और उस वजह से दो नहीं खुल सकती हैं तो कम से कम एक हाई स्कूल तो अवश्य खोली जावेगी। यदि एक हाई स्कूल खुल जावेगी तो हम जानेंगे कि आप लोगों का हमारे साथ कोऑपरेशन है और हमारी ओर भी ध्यान दिया जाता है। अगर नहीं खुलेगी तो हमें दुख से कहना होगा कि हाई स्कूल और इन्टर कॉलेज तो दौसा या किसी दूसरी जगह, जहाँ प्रभावशाली व्यक्ति हों, खुल सकती हैं। हो सकता है कि सरदार शहर जैसे स्थान में भी यह खुल सकती है। जहाँ से हम चुन कर आये हैं वहाँ के क्षेत्र के लोगों की माँग है। अगर उसकी पूर्ति होगी तो सरकार हम सब की धन्यवाद की पात्र होगी।

इसके बाद सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारी सरकार हमारे यहाँ के शिक्षकों को ऐसे गलत रास्ते पर ले जा रही है कि जो देश के डेमोक्रेटीक सुधारों को बहुत नीचे गिरा देगा। इसलिये सरकार से प्रार्थना है कि हमारे शिक्षक वर्ग को पोलिटिक्स में भाग लेने के लिए बाध्य न करे और इसी कारण उनकी ट्रान्सफर आदि पक्षपात करने के लिये ही न की जावे। इस नीति का सरकार को कड़ाई के साथ विरोध करना चाहिये। उन लोगों को चाहिये कि कोई भी सरकार हो उनके लिए सब बराबर हैं। अगर यह बात रही तो हमारे शिक्षा का स्तर ऊँचा उठेगा और हमारी उन्नति होगी और हमारे शिक्षक पोलिटिक्स के दलदल में जो अभी फँस रहे हैं, न फसेंगे और न वे किसी पार्टी का प्रचार करेंगे। इस बात पर शिक्षा मन्त्रीजी को गौर फरमाना चाहिये। अगर आप दो-चार आदमियों को इस प्रकार पोलिटिक्स में भाग लेने पर एक्जेम्पलरी पनिशमेंट देंगे तो बहुत कुछ सुधार हो सकेगा।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ मास्टरों को बहुत कम वेतन दिया जाता है और उससे वे अपने बच्चों का पालन-पोषण भी पूरी तरह से नहीं कर सकते। इसके अलावा उनका तबादला उनके घरों से इतनी दूरी पर कर दिये जाते हैं कि वे बहुत परेशान हो जाते हैं और हर वक्त

[श्री मानसिंह महार]

यही सोचते रहते हैं कि किस प्रकार से वे असनी ट्रान्सफर वहीं करवा सकें जहाँ पर वे रहते हैं। इसके लिए वे किसी की खुशामद करना शुरू करते हैं और किसी न किसी प्रकार किसी का फेवर गेन (favour gain) करके या प्रार्थना करके अपना तबादला करवाते हैं। इससे उनका ध्यान लड़कों को पढ़ाने में नहीं लगता। इसलिए इस तरफ भी शिक्षा विभाग को जल्दी से जल्दी ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये जिससे कि वे लोग अपने डिस्ट्रिक्ट में ही रह सकें तो यह बहुत अच्छी बात होगी और हमारे शिक्षक स्टूडेन्ट्स की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करूँगा कि अगर कोई शिक्षक अपने गाँव में या अपने गाँव के आस-पास ही शिक्षा देता है तो उसको हमेशा यह भय रहेगा कि अच्छा काम नहीं किया तो कोई मेरी शिकायत कर देगा और मेरा तबदला कर दिया जावेगा और तबादला हो जाने से वह घर से बहुत दूर जावेगा और उसको तकलीफ होगी। इसके अलावा जिनका ट्रान्सफर कर दिया गया है और वे अपने घरों से १०० मील की दूरी पर हैं वे यह सोचते हैं कि हमको परवाह क्या है, अगर अधिकारी नाराज हो जावेंगे तो, कहीं दूसरी जगह बदल देंगे, हम तो पहले ही १०० मील की दूरी पर घर से बैठे हैं, यहाँ नहीं तो और वहीं चले जावेंगे। अगर इस ओर हमारी सरकार ध्यान देगी तो मैं यह अवश्य कहता हूँ कि हमारे यहाँ के शिक्षक लोग बच्चों को पढ़ाने में पूरा ध्यान देंगे और इससे शिक्षा में काफी तरक्की होगी।

इसके बाद में चन्द बातें अनुशासनहीनता के बारे में कहना चाहता हूँ। यह दुर्भाग्य की बात है कि अनुशासन हीनता विद्यार्थियों में बढ़ती ही जा रही है और जैसा कि हमारे लीडर ऑफ ऑपोजीशन ने फरमाया था कि अनुशासन हीनता चरम सीमा पर पहुँच गई है; उनका मतलब यह था कि जिस हैड मास्टर के पीछे लड़के कंकड़ लेकर फिरते हैं उस हैडमास्टर को वहाँ से बदल देना चाहिये जिससे अनुशासन-हीनता कम हो जावेगी, मैं इस बात का समर्थन करने के लिये तैयार नहीं हूँ कि उस हैडमास्टर को बदल दिया जाए। मैं यह कहूँगा कि जिस स्कूल या कॉलेज में लड़कों का इस प्रकार का बर्ताव हो और उस जगह के हैड मास्टर या प्रोफेसर को लड़कों के इस प्रकार के बर्ताव से बदल दिया जायगा तो लड़कों का हौसला बढ़ जावेगा और उनकी अनुशासन-हीनता और भी बढ़ जावेगी। आज उनके कहने से किसी को बदल दिया तो कल जो व्यक्ति उसके स्थान पर जाएगा उसके साथ भी उसी प्रकार का बर्ताव होगा। ऐसी हालत में लड़कों के साथ सख्ती से काम लिया जाना चाहिये और उसके बाद यदि आप वहाँ के हैडमास्टर या प्रोफेसर को काबिल न समझें तो उसका वहाँ से तबादला कर दिया जावे। अगर बच्चों के विरोध पर ही आप उनका ट्रान्सफर करते हैं तो इससे तो बच्चों को और प्रोत्साहन मिलेगा।

एक चीज़ जो राजस्थान की स्कूलों में पाई जाती है वह यह है कि यहाँ स्कूलों में व्यायाम की ओर कतई ध्यान नहीं दिया जाता है। यह चीज़ मैंने अच्छी तरह से देखी है। मैंने अपना शिक्षण काल इन्दौर में बिताया। वहाँ मैंने देखा कि स्पोर्ट्स में बहुत दिलचस्पी ली जाती है। यदि वहाँ पर किसी छोटी से छोटी स्कूल में आप चले जावेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ के बच्चे खेल-कूद में शिक्षा के बराबर भाग लेते हैं। किन्तु हमारे यहाँ दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ राजस्थान के बच्चे स्पोर्ट्स को

[श्री मानसिंह महार]

एक बेगार समझते हैं और इसके लिये भी कई कारण हो, जिनको मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। इसका खास कारण यह है कि वहाँ का हैडमास्टर या दूसरे मास्टर लोग खेल-कूद में दिलचस्पी नहीं लेते। यदि वहाँ का हैडमास्टर या दूसरे मास्टर खेल-कूदों में दिलचस्पी लेंगे तो यह कठिनाई नहीं होगी। हमारे यहाँ जब मास्टर लिये जाते हैं तो उनकी दूसरी क्वालीफीकेशन के साथ-साथ जैसे मैट्रिक या मिडिल, स्पोर्टस की भी एक क्वालीफीकेशन रखी जावे और यह रख दिया जावे कि जो खेल से दिलचस्पी रखता होगा या खेल की ए. बी. सी. डी जानता है या नहीं; अगर वह जानता है तो सरकार उसको प्रोत्साहन देगी।

सरकार स्कूलों को प्रोत्साहन दे। इन्टर स्कूल्स टूर्नामेंट करके और जो बच्चे वाकई में अच्छे खेलते हों उनको पारितोषिक वगैरह देकर उनको सरकार तरक्की दे; इस तरह से राजस्थान की स्कूलों के अन्दर जो खेल-कूद की कमी है वह पूरी हो सकती है। अगर यह कमी पूरी होगी तो हमारे बच्चों की तन्दरुस्ती सुधरेगी। इसलिए माननीय शिक्षा मन्त्री से मैं यह प्रार्थना करूँगा कि वे इस पर पूरा ध्यान दें। मेरे पूर्व वक्ताओं में से किसी ने भी इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिलाया है। राजस्थान के अन्दर शिक्षा के साथ-साथ खेल-कूद की व्यवस्था की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये तभी हमारे बच्चों की तन्दरुस्ती सुधर सकेगी।

श्री भैंरूँसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष, शिक्षा मन्त्रीजी को एक दल की ओर से धन्यवाद का प्रस्ताव देने की बात सुनने में आ रही है। आज शिक्षा विभाग के एक विषय को लेकर अगर धन्यवाद के स्थान पर दूसरी चीज़ दी जाय तो उस प्रस्ताव का प्रस्ताव करने वाला मैं होऊँगा, वह विषय है संस्कृत के अध्ययन के बारे में।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के १९५३–५४ के बजट में एस्टीमेटेड बजट में जो रकम रखी गई थी वह १ लाख ४० हजार ८०० रुपया थी और रिवाइज्ड बजट में उस रकम को १ लाख २७ हजार कर दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि १३ हजार रुपये की रकम राजस्थान सरकार ने बजट एस्टीमेट में संस्कृत के अध्ययन के सम्बन्ध में रखी थी लेकिन संस्कृत के विषय में कोई दिलचस्पी न होने के कारण १३ हजार रुपया भी खर्च न किया जा सका। यह १३ हजार रुपये खर्च न करने की बात यहीं तक न रही सन् ५४–५५ के बजट में इसको कम करके १ लाख २२ हजार रुपये कर दिये गये। इसका मतलब यह हुआ कि इस तरह से बजट एस्टीमेट्स में १८ हजार रुपये की कमी करदी गई। अध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष के हर प्रान्त से आवाज आ रही है कि राष्ट्र-भाषा के प्रचार हेतु संस्कृत को व्यापक रूप से समाज में लाया जाय लेकिन राजस्थान सरकार दिन प्रतिदिन इसमें कमी करती जा रही है। राष्ट्र-भाषा की जननी संस्कृत भाषा का प्रचार व प्रबन्ध करने के लिए राजस्थान में संस्कृत का अध्ययन जिन पाठशालाओं में हो रहा है और उनका वास्तविक दृश्य देखना हो कि उनकी क्या दयनीय हालत है तो आप जयपुर के संस्कृत कॉलेज को देखें। आपको वहाँ जाने पर सब कुछ पता चल सकता है कि हमारी सरकार संस्कृत के लिए क्या-क्या कर रही है। आज संस्कृत कॉलेज में कोई भी प्रिन्सिपल नहीं। प्रिन्सिपल के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला

[श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)]

गया, कुछ दरख्वास्तें आईं, किन्तु उन पर ६ महिने तक कोई विचार नहीं किया गया। बाद में ऐसा पता चला कि राजस्थान सरकार, संस्कृत कॉलेज़ के पहले जो प्रिन्सिपल थे उनको वापिस बुला रही है, ऐसी कोई सरकार की योजना है। उन्होंने कोई वापिस आने की दरख्वास्त नहीं दी, फिर भी न मालूम सरकार उनको वापिस लाने के लिए इतनी उत्सुक क्यों है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे यहाँ आने को कतई तैयार नहीं और दूसरे की नियुक्ति के लिए सरकार तयार नहीं। अध्यक्ष महोदय संस्कृत के सम्बन्ध में जब हम विचार करते है तो हमें अनायास उन संस्कृत के अध्यापकों और स्नातकों का भी विचार करना होगा जो आज राजस्थान की सर्विसेज़ में नहीं लिये जाते। राजस्थान की सर्विस में स्कूल से पढ़े-लिखे मैट्रिक, इन्टर, बी. ए., को राजस्थान की सेवाओं के अन्दर भाग मिलता है किन्तु संस्कृत की प्रवेशिका, उपाध्यक्ष, शास्त्री और आचार्य जो इस प्रकार की क्लासेज़ हैं जिनमें उसी प्रकार का कोर्स है जैसा कि इन्टर, मैट्रिक और बी. ए. में होता है तथा दोनों की योग्यता बराबर है, लेकिन जब सर्विसेज़ का सवाल आता है, जब संस्कृत या राष्ट्र-भाषा के अध्यापक की नियुक्ति का सवाल आता है तो उस नियुक्ति के अन्दर ग्रेजुएट्स, इन्टर और एम. ए. जो होते हैं उनको ज्यादा तनख्वाह मिलती है और प्रवेशिका, उपाध्यक्ष, आचार्य क्लासेज़ जिन्होंने पास की हों उनको कम वेतन दिया जाता है। अगर शिक्षा की दृष्टि से देखा जाय तो इन चारों संस्कृत की क्लासों में उसी प्रकार के विषय होते हैं जो एक ग्रेजुएट के लिए हिन्दी पढ़ाने के लिए आवश्यक माने गये हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भारत की पंचवर्षीय योजना के अन्दर ८० हजार लोगों को शिक्षा विभाग में नियुक्त करने का सवाल है; वहाँ हमारे राजस्थान में ५०० व्यक्तियों की नियुक्ति शिक्षा विभाग में हुई है। उन नियुक्तियों के लिए जो प्रचार हुआ, जो शहरों में ढूँडी पिटवाई गई उसमें कहा गया कि जो व्यक्ति मिडिल पास हों, मैट्रिक पास हों वे प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, किन्तु कहीं भी यह नहीं कहा गया कि जो संस्कृत के स्नातक हों वे भी दरख्वास्त दे सकते हैं। यह संस्कृत के स्नातकों के प्रति अन्याय नहीं है तो क्या है? आज इस योजना के अन्तर्गत एक भी संस्कृत के स्नातक को स्थान नहीं मिला। अगर हमें राष्ट्र-भाषा का व्यापक रूप में प्रचार करना है तो हमें संस्कृत अध्ययन अनिवार्य करना होगा और इसके प्रचार को व्यापक रूप देना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँगा कि हमारी राष्ट्र-भाषा के प्रति कोई अच्छी भावना नहीं है।

दूसरा, अभी एक मित्र ने सेन्ट जेवियर स्कूल की बात को लेकर यह बताया कि यह संस्था साम्यवाद के प्रचार में बाधक है, इसलिये इसको एड नहीं दी जानी चाहिये। अगर वास्तव में ही यह संस्था साम्यवाद को रोकने के लिए अग्रसर हो रही हो तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं, किन्तु यह संस्था साम्यवाद की आड़ में साम्राज्यवाद और क्रिश्चियनवाद का प्रचार कर रही है। जयपुर के वेटरनरी हॉस्पीटल में कल मैंने देखा कि वहाँ इन मिशनरियों ने कुछ दूध के डिब्बे मंगाये और उनमें गरम पानी मिलाकर हरिजन बच्चों को दूध बाँटा। उनको बातें बाइबल की बतायी गयीं, क्राइस्ट के गुणगान कराये गये। यह सिर्फ एक जयपुर में ही नहीं हो रहा है, माननीय अध्यक्ष, इन मिशनरियों ने सीकर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर भी इसी तरह का प्रचार आरम्भ कर रखा है। ये लोग वहाँ गरीबों को कपड़े बांटते हैं, किताबें बांटते हैं और उनको बताते हैं क्राइस्ट की बातें। तो मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि यह तरीका नहीं है साम्यवाद के रोकने का, इसकी आड़ में वे क्रिश्चियनवाद और साम्राज्य वाद

[श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)]

को फैलाना चाहते हैं। हमने अभी देखा है कि आसाम के नागा लोगों ने किस प्रकार पंडित नेहरू के सामने यह माँग रखी कि आप हमारे लिए नागा प्रान्त बना दें। यह सब इन्हीं मिशनरियों का प्रपंच था, जो यह चाहते थे कि इस तरह से इस नये प्रान्त में उनका बहुमत हो जायगा और वे अपना सम्बन्ध ट्रावनकोर-कोचीन से कर लेंगे ताकि उनकी क्रिश्चियनिटी का ठीक ढङ्ग से प्रचार हो सके। लेकिन उनकी यह योजना आसाम में सफल नहीं हो सकी। आप इन सारी बातों को देखते हुए केवल उस स्कूल के अनुशासन को ही न देखें, बल्कि उनके कमरों में खुदी हुई बाइबिल की नसीहतें देखें, उन कमरों में लगे हुए चित्र जो आपको ईसाइयत की ओर ले जाते हैं, आपके बच्चों को क्रिशिचयनिटी की ओर आकर्षित करते हैं और देखिये उनकी प्रार्थना जो वे बच्चों को स्कूल प्रारम्भ होने से पहले कराते हैं; जिसमें सिर्फ बाइबिल का जिक्र है। बाइबिल जो पढ़ाई जाती है उनकी चीजों की ओर आप अपना ध्यान आकृष्ट करें, दिमाग में सोचें कि इन चीज़ों के पढ़ने से हमारे भारतवर्ष का भला होगा या बुरा? ये ही मुख्य चीजें हैं जो हमारी भावी पीढ़ी पर असर कर सकती हैं। इन्ही चीजों से नुकसान होने वाला है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों को ऐसी स्कूलों में न पढ़ने दें। एक माननीय सदस्य मेरे मित्र जिन्होंने इस स्कूल की तारीफ में सब कुछ कह दिया उनसे निवेदन है कि यदि वे स्वयं अपने बच्चों को उन स्कूलों में भेजते हैं तो वे आज से ही उनको वहाँ भेजना बन्द करदें।

दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करनी है कि राजस्थान सरकार ने आजकल कुछ ऐसी स्कूलों को अपने आधीन कर लिया है जिनको दूसरे प्राइवेट आदमी चलाया करते थे और यह काम किए करीब एक साल पूरा हो गया, पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन अध्यापकों का Fixation नहीं हुआ और उनके बाद में जितने अध्यापक नियुक्त हुए हैं उनकी तनख्वाह उनके मुकाबले में ज्यादा हो गई, उनकी अभी तक इन्टरव्यू पी. एस. सी. के द्वारा नहीं हुई। एक समय किसी को सेठ-साहूकार के स्कूल में ५०) रुपया तनख्वाह लेने को बाध्य होना पड़ा था, उन लोगों के बी. ए., एम. ए. होने पर भी किन्हीं मजबूरियों से उन्होंने इतनी तनख्वाह में काम करना भी स्वीकार किया, पर उनकी आज भी वही तनख्वाह है, उनकी हालत पर आज कोई ध्यान नहीं दिया जाता जबकि उनके बाद में मेट्रिक पास लोगों को, इन्टरमीजिइट पास लोगों को साठ-साठ रुपये दिये गये। पर वे ग्रेजुएट होकर भी आज विचारे बारह महीनों से ऐसे ही पड़े हैं पर तनख्वाह का उनके सामने कोई सवाल नहीं और जैसा कि श्री एच. के. व्यास ने बताया उनके बिल तनख्वाह के एक-एक महीने के जाते हैं और उनको मन्जूर होने में पाँच-पाँच और छः छः महीने लग जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं सरकार का ध्यान इधर आकर्षित करता हुआ, माननीय अध्यक्षजी, आपकी मार्फत इन सरकारी मन्त्रियों से निवेदन करूँगा कि इन अध्यापकों की सर्विसेज़ का एकीकरण करके उनकी तनख्वाह के बिलों का निर्णय जल्दी से जल्दी करें।

दूसरा, मुझे दुख के साथ कहना पड़ेगा कि राजस्थान सरकार ने बावजूद इसके कि कई बार उनको इस बात से सूचित किया गया कि राजस्थान में जितने भी अपोइन्टमेन्ट्स होते हैं, तबादले होते हैं वे कुछ एक पार्टी के लोगों के कहने से होते हैं पर इन सब बातों को जो हम कहते हैं वे लोग

[श्री भैरूँसिंह (दांतारामगढ़)]

यह कह कर दर गुजर कर देते हैं कि क्योंकि यह तो विरोधी दल के लोगों का कहना है, तो ऐसी हर बात को विरोधी सदस्यों की बात कहकर सारी की सारी चीज़ को ओझल कर दिया जाता है, उसकी सत्यासत्यता पर कोई विचार तक नहीं किया जाता; इस पर जवाब महज यही मिलता है कि ऐसा कहने वाले विरोधी हैं ये और केवल विरोध करने के खातिर ऐसा कह देते हैं। पर अध्यक्ष महोदय, आज मैं इस बात का प्रबल प्रमाण दूँगा कि किस तरह से इन तबादलों के अन्दर इन सत्ताधारी लोगों का हाथ होता है ? छोटा सा मामला है।। एक चार लाइन की चिट्ठी है जिसे मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। यह एक ऑफिसर का ऑर्डर है चार लाइनों का। उसमें लिखा है :—

"As your verbal instructions dated 28/9/53 it is informed that no post of matric is vacant at Dasa ki Dhani, where Shri Kan Singh may be transferred from P. S. Sabalpur as recommended by Shri Balbir Singh M. L. A. An additional post may Kindly be allowed from amongst the reserve posts in Dasa ki Dhani and orders for the transfer of Shri Kan Singh from P. S. Sabalpur to Dasa ki Dhani may kindly be intimated.

Shri R. K. L. Bhatnager Sahib Is. Sikar
S/o M. M. Sharma.
Dasa"

No. 668 F / 6/x/53

अध्यक्ष महोदय, इस ऑर्डर को मैंने एक माननीय मन्त्री महोदय को भी बताया था, पर यह एक नमूना है पक्षपात का और नमूना है राजस्थान सरकार के सीकर के शिक्षा विभाग की दलबन्दी का। वहाँ कैसी दलबन्दी है इस विभाग में यह इससे साफ जाहिर है।

यह दासा की ढाणी एम. एल. ए. साहब का निजी गाँव है और जिस आदमी की सिफारिश की गई है वह हैं उनके निजी रिश्तेदार। तो मेरा निवेदन करना यह है कि यह एक प्रकार का ऐसा एग्ज़ाम्पल है इससे जाहिर है कि अगर एक-एक व्यक्ति के appointment एवम् Transfer को देखा जावे तो मालूम होगा कि सिवाय दलबन्दी के आधार पर अपोइन्टमेन्ट करना और ट्रान्सफर करना; इसके सिवाय कहीं कुछ चीज़ नहीं मिलेगी। और इतना ही नहीं, पर अब ट्रान्सफर होते हैं तो यह भी कह दिया जाता है कि फलाँ आदमी राजनैतिक समस्या में भाग लेता है। उसकी छान-बीन करने का कोई सवाल नहीं। उनको तो किसी तरह से उसका ट्रान्सफर कर देना है जो उनकी दलबन्दी का न हो, कुछ भी आरोप लगाकर। उसका तबादला करते हैं सीकर से झुंझुनू, झुंझुनू से अलवर और इसी तरह से और-और जगहों पर उसे भेजते रहते हैं। अलवर से यदि किसी के तबादला की बात हो गई तो सीकर भेज दिया। एक बीस-तीस रुपया पाने वाला मुलाजिम अलवर से अगर सीकर आवेगा तो माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी यह अन्दाज लगा सकता है कि वह बिचारा बीस-पच्चीस रुपया पाने वाला मामूली सी स्थिति वाला व्यक्ति क्या तो स्वयं खावेगा और क्या अपने बाल-बच्चों को वहाँ परदेश में आकर खिलावेगा। उसका तो आने जाने में ही काफी रुपया

Page No.156

[श्री भैरूँ सिंह (दांता रामगढ़)]

खर्च हो जावेगा। उनकी सुख-सुविधा और सहूलियत का किसी को कोई खयाल नहीं है। पर महज इन नेताओं को खुश करने के लिए इन्सपेक्टर लोग भी फौरन बिना सोचे-समझे उनका ट्रान्सफर कर देते हैं। तो माननीय अध्यक्षजी, आपके द्वारा मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के ट्रान्सफर और अपोइन्टमेन्ट्स सरकार अगर दलबन्दी के आधार पर करती रही तो इस सरकार के प्रति काफी असन्तोष लोगों का जो इस समय है वह और भी बढ़ेगा और इस असन्तोष के कारण कोई भयंकर विस्फोट होने की संभावना बढ़ेगी। अब मुझे जो एक बात और निवेदन करनी है वह है अध्यक्ष महोदय,.....

(८ बजने पर)

श्री जवानसिंह—On a point of information, Sir, are we continuing upto 9 P. M. or what? Are we not adjourniug?

श्री अध्यक्ष (श्री भैरूँ सिंह को संकेत करके)—How long will you take?

भैरूँ सिंह—मैं तो थोड़ी सी देर और लूँगा। (थोड़ी देर ठहरकर) मैं कल भी कन्टिन्यु कर सकता हूँ, अगर माननीय अध्यक्ष महोदय इसके लिए इजाजत दें तो।

श्री अध्यक्ष—If you want 10 minutes I can give you today.

श्री भैरूंसिंह—कल सात मिनिट ही दे दीजिये साहब।

श्री श्रीदास गोयल—इम्पोर्टेन्ट मैटर है तो और भी दो चार बोल सकते हैं। कल ही रखिये साहब।

श्री भैरूँ सिंह—सब की भावनाओं की कद्र करना चाहता हूँ और इसलिए चाहता हूँ कि कल कन्टिन्यू करूँ।

श्री अध्यक्ष—It is very interesting. We would like you to conclude.

श्री भैरूँ सिंह—I will make it interesting tomorrow also.

श्री अध्यक्ष—Before dispersing I want to give one information that the Hon'ble Members should pick up certain papers from the Notice Office today about the agenda for tomorrow or day after, cut motions etc. They should take this trouble.

We now adjourn for tomorrow at 8-30 A M.

[सदन की कार्यवाही १२ बज कर १० मिनट (मध्यान्होत्तर) पर, दिनाँक २४ मार्च, १६५४ के साढ़े आठ बजे तक के लिये स्थगित हुई।]

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक—२३ मार्च, १६५४

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।